राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 02] **पन्द्रहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का तेईसवां दिवस** **[संख्या: 12**

शुक्रवार,

19 जुलाई 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सदन में +++ आ गये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नीचे बैठें।

देवली-उनियारा में रोजड़ों से फसल को नुकसान

230. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में रोजड़ों, नील गायों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा फसलों को नील गायों से बचाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): जी हां। विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में रोजड़ों, नील गायों की संख्या बढ़ रही है एवं उनके द्वारा कृषकों की फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सरकार द्वारा रोजड़ों, नील गायों से फसलों के बचाव हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 से राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन अन्तर्गत लघु सीमान्त कृषकों को लक्षित कर कांटेदार तारबंदी कार्यक्रम चालू किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन के अन्तर्गत नील गाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिये सभी श्रेणी के कृषकों को लक्षित कर

(कृषि मंत्री)

सामुदायिक आधार पर कांटेदार/चैनलिंक तारबंदी कार्यक्रम चालू किया गया है, जिसमें कम से कम 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल हो एवं तीन कृषकों का समूह हो। तारबंदी हेतु पैरीफेरी (परिधि) कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रुपये 40 हजार, जो भी कम हो, प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय है।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): धन्यवाद महोदय। सर, इस योजना की जो कंडीशन है, वह यह है कि कम से कम पांच हैक्टेयर जमीन हो। सर, वहां पर पांच हैक्टेयर तो किसी के है ही नहीं, दो-दो, तीन-तीन बीघा हैं और फिर उसमें तीन कृषकों का समूह हो। सर, क्या होता है, जैसे ही आप तारबंदी करते हो, पीछे वाले का रास्ता बंद हो जाता है तो गांव वाले करने की ही नहीं देते। मेरा सरकार से आग्रह यह है कि सरकार अपने पैसे से इस सैंक्चुअरी की क्यों नहीं तारबंदी कर देती कि जानवर बाहर नहीं आ सकें।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह तारबंदी की जो योजना है, यह समूह में इसलिए रखी गयी है कि गांव में जिस तरह का वातावरण रहता है, एक व्यक्ति की तारबंदी नहीं की जा सकती, क्योंकि रास्तों के अवरुद्ध होने का डर रहता है, तो एक समूह बनाकर इस योजना को भारत सरकार के सहयोग से, 60 प्रतिशत भारत सरकार की लागत है और 40 प्रतिशत राजस्थान सरकार की लागत है, इसलिए इसको लाये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, मेरा अनुरोध यह था, जैसा मंत्रीजी स्वयं फर्मा रहे हैं कि किसानों में सहमति नहीं बनती, रास्ते बंद हो जाते हैं, इसलिए किसान का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह जो सैंक्चुअरी है, यह सरकारी है, और इसके आस-पास अनेक होटल वाले और सरकार मिलकर सैंक्चुअरी को ही फेंस कर दें ताकि जानवर बाहर ही नहीं आ पाएं तो मेरी समझ में यह और भी अच्छा सुझाव होगा।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है। इसका परीक्षण करवाया जाएगा, क्योंकि यह बात सही है कि इससे काफी नुकसान होता है। परीक्षण करवाकर कोई भावी योजना के लिये विभाग को कहा जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 231.

श्री वासुदेव देवनानी।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 232.

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 233.

श्री रोहित बौहरा। **(अनुपस्थित)**

अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 234.

श्री गोविन्द प्रसाद।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 235.

श्री बाबुलाल झाड़ोल।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 236.

श्री संदीप शर्मा।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): प्रश्न संख्या 237.

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, युवा एवं खेल राज्य मंत्रीजी। (अनुपस्थित)

बहुत अच्छा, कम से कम आवाज तो निकली।

अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या-238.

श्री पब्बाराम।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए: कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या-239.

(श्री अध्यक्ष)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 240.

श्री सुमित गोदारा।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 241.

श्री जोगेश्वर गर्ग।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री गोपाल लाल मीना।

जमवारामगढ़ में फसल ऋण माफी

242. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा सहकारी बैंकों/भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों के फसली ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में अब तक कितने किसानों की कितनी-कितनी ऋण राशि माफ की गयी? सहकारी बैंक/भूमि विकास बैंक का पृथक्-पृथक् गांववार नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा कैम्प लगाकर ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किये गये हैं? यदि हां, तो कितनी राशि के प्रमाण पत्र वितरित किये गये? ग्राम सेवा सहकारी समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक, कामर्शियल बैंक से जिन किसानों ने ऋण लिया है, उनका ऋण माफ करने का भी विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गांववार, नामवार व राशिवार केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा माफ किये गये ऋण की विगत परिशिष्ट-1(1) पर व प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा माफ किये गये ऋण की विगत परिशिष्ट-1(2) पर संलग्न है।

(2) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समितिवार कुल राशि 1305.73 लाख के प्रमाण पत्र वितरित किये गये हैं, जिनका समितिवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) कृषक ऋण माफी के संबंध में जारी आदेश क्रमांक प.17(15) सह/2018 जयपुर, दिनांक 19.12.2018 की क्रियान्विति हेतु कैबिनेट के निर्णय दिनांक 29.12.2018 की पालनार्थ आदेश दिनांक 01.01.2019 द्वारा एक उच्च स्तरीय अन्तर्विभागीय कमेटी का गठन किया गया।

उक्त समिति ने अनुशंसा की - राष्ट्रीयकृत बैंक, शिड्यूल्ड बैंक तथा आर.आर.बी. से जुड़े कृषक, जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हैं और अपना अल्पकालीन फसली ऋण नहीं चुका पा रहे, उनका दिनांक 30.11.2018 की स्थिति में 2 लाख रुपये की सीमा तक का अल्पकालीन फसली ऋण, जो एन.पी.ए. हो गया है, को माफ करने के लिये बैंकों से परामर्श कर one time settlement scheme (OTS) लायी जाए। समिति की अनुशंसा के निर्णय की क्रियान्विति हेतु सहकारिता तथा आयोजना विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है तथा दिनांक 10.03.2019 के आदेश द्वारा एक समन्वय समिति का गठन भी किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय मंत्री महोदय, मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि भूमि विकास बैंक में चार भाइयों का लोन था, उसमें एक का माफ हो गया और तीन का नहीं हुआ। एक व्यक्ति मर गया, उसकी मृत्यु हो गयी, उसके पोस्टर छपवाकर वहां पर चिपका रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भूमि विकास बैंक चांदपोल वाली शाखा है उसमें रामावतार शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, प्रश्न। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): उसका लोन माफ क्यों नहीं हुआ?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी सुन लें पहले। प्रश्न पूछें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): प्लीज यह बताने की कृपा करें।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): आधार आधारित प्रमाणीकरण के आधार पर नि:संदेह जो प्रमाणित व्यक्ति सही पाये गये, उन्हीं का माफ हुआ है और अगर आपके वहां की कोई वेदना है तो आप प्रश्न लाकर बताएं, नि:संदेह उसको भी विभाग में दिखवा लिया जाएगा और पीड़ित व्यक्ति को राहत दी जाएगी।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): ओवरड्यू है इसका। ओवरड्यूज का होगा या नहीं होगा?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): आप आकर विगतवार बता दें, क्योंकि आधार आधारित प्रमाणीकरण के आधार पर तो सबका कर दिया गया है। आपके कोई विशेष परेशानी इस मामले में आयी है। ऐसी कोई शिकायत और कहीं से मिली नहीं है। आपके यहां की शिकायत है तो बताएं, उसका निराकरण कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 243.

सतीश पूनियां।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 244.

श्रीमती जाहिदा खान। (अनुपस्थित)

अगला प्रश्न। श्री बलजीत यादव। प्रश्न संख्या 245.

मंत्रीजी अनुपस्थित हैं।

अगला प्रश्न। श्री अमीन खां।

पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

246. श्री अमीन खां (शिव): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पशु चिकित्सालय कितने हैं? ऐसे कितने पशु चिकित्सालय हैं जिनमें पशु चिकित्सक नहीं है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में कितने पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अमीन खां)

(3) क्या सरकार उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त चल रहे चिकित्सकों एवं कंपाउण्डरों के पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) प्रदेश में वर्तमान में 35 बहूद्देशीय पशु चिकित्सालय, 785 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय तथा 1710 पशु चिकित्सालय स्वीकृत हैं। इन पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला बाड़मेर में 181 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्वीकृत हैं, जबकि जिला जैसलमेर में 59 उपकेन्द्र स्वीकृत हैं। इनका तहसीलवार संख्या विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। रिक्त पदों को उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि हमारी एक तहसील गडरा रोड में खानयानी, राणासर, सजन का पाट, देतानी, इनमें पशु चिकित्सालयों में डाक्टर नहीं हैं। इनमें डाक्टर तो छोड़ो, कम्पाउंडर तक नहीं हैं। यह पद आप कब तक भरा दोगे?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कल ही 39 पशुधन सहायकों की नियुक्ति का आदेश विभाग ने निकाला है। यह प्रकरण पहले न्यायालय में था। इसका फैसला हो चुका और विधि विभाग से फाइल हमारे पास आयी है और कल ही उनको मंजूरी दे दी गयी है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि जल्दी ही यह पद भर दिये जाएंगे।

श्री अमीन खां (शिव): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 247.

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 248.

श्री सुभाष पूनिया।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 249.

श्री गोपाल लाल शर्मा।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 250.

श्री कन्हैया लाल।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 251.

श्री बिहारी लाल।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री गणेश घोघरा।

डूंगरपुर में प्रदूषण रोकने की कार्ययोजना

252. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि हाल ही में डूंगरपुर जिले मे प्रदूषण स्तर की जांच के नतीजे सामने आये हैं? यदि हां, तो डूंगरपुर जिले का प्रदूषण स्तर कितना पाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में प्रदूषण स्तर अत्यन्त चिन्ताजनक स्थिति में है? यदि हां, तो इसके निवारण हेतु क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भविष्य में डूंगरपुर में प्रदूषण स्तर सामान्य करने हेतु कोई ठोस कार्यवाही किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी हां। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा डूंगरपुर शहर में 21 मई, 2019 को डाक बंगला, अशोक नगर व जिला उद्योग केन्द्र, डूंगरपुर में प्रदूषण स्तर (RSPM) की जांच की गयी है जिसके अनुसार आंकड़े परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक 2009 के अनुरूप पाये गये हैं। नमूनों की जांच के परिणाम परिशिष्ट 'अ', 'ब', 'द', 'य' पर संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। डूंगरपुर शहर में 21 मई, 2019 को की गयी जांच के

(राज्य मंत्री, वन)

अनुसार आंकड़े परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक 2009 के अनुरूप पाये गये हैं। नमूनों की जांच के परिणाम परिशिष्ट- 'अ', 'ब', 'द', 'य' पर संलग्न है।

(3) जांच के परिणामों के अनुसार वर्तमान में डूंगरपुर में वायु की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि नगर परिषद् द्वारा जो भी थैलियां हैं, प्लास्टिक है, जो भी गंदगी है, भण्डारिया घाटा का गांव है वहां पर कचरा डाला जा रहा है और वहां एक मिनट भी खड़े नहीं रह सकते, ऐसी बदबू मार रही है लेकिन यह खाली आंकड़ों में या कागजों में दे दिया...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सर, प्रश्न ही पूछ रहा हूं कि क्या सरकार उसको उठाने की मंशा रखती है, विचार रखती है?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): नगरपालिका ने जो सॉलिड वेस्ट है, बाकायदा उनका स्थान कर रखा है, वहीं निश्चित स्थान पर ही डालते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगला प्रश्न।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदयजी, नगरपालिका में, नगर परिषद् में लोग रहते हैं तो गांवों में क्या लोग नहीं रहते हैं, क्या उनका उससे स्वास्थ्य खराब नहीं होगा? जमीन एक्वायर कर ली है, सब जमीन घेर ली है, आदिवासियों की पूरी जमीन छीन ली लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये, प्रश्न।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यही पूछना चाहता हूं कि पर्यावरण बिगड़ रहा है, गांवों में जो लोग रह रहे हैं उनकी हालत खराब हो रही है, तो सरकार क्या कदम उठाएगी? यह पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय मंत्री जी।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, राज्य के जो आठ बड़े शहर हैं जयपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर, भिवाड़ी, पाली,

(श्री सुखराम विश्नोई)

अजमेर, इन जगहों पर तो यंत्र लगे हुए हैं, बाकी जगह जहां-जहां शिकायतें आती हैं वहां मैनुअली जाकर जांच करते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर।

विराटनगर में नवीन खेल स्टेडियम

253. श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नया खेल स्टेडियम बनाये जाने के लिए क्या नियम/मानदण्ड निर्धारित है? नियम/मानदण्डों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के विराटनगर कस्बे में नया खेल स्टेडियम स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): (1) समन्वित स्टेडियम (खेल संरचना) विकास कार्यक्रम-2015 के तहत स्टेडियम निर्माण का प्रावधान किया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट - 'क' पर संलग्न है।

(2) स्टेडियम निर्माण हेतु चरणबद्ध तरीके से बजट की उपलब्धता व गुणावगुण के के आधार पर राज्य सरकार द्वारा इनके निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की जाती है। वर्तमान में विराटनगर कस्बे में नया खेल स्टेडियम स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ देश की सरकार और राज्य की सरकारें खेल को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं और हर जगह कहा जाता है कि खेल खेलने से जीवन स्वस्थ होता है दूसरी तरफ उपखण्ड लेवल पर विधान सभा क्षेत्र हैडक्वार्टर पर भी स्टेडियम नहीं है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार ऐसी कोई पालिसी, ऐसा कोई नियम लाना चाह रही है कि उपखण्ड लेवल पर स्टेडियम हो, जिससे आमजन को सुविधा मिले।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, तहसील और उपखण्ड लेवल पर यह पहले से पालिसी है कि 200

(श्री अशोक)

मीटर का एथलेटिक ट्रैक, बास्केटबाल, वॉलीबाल, टेनिस, खो-खो, कबड्डी मैदान, कार्यालय भवन, दर्शक दीर्घा, जिम्नेजियम नियत प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाता है। आपके यहां भी, आप प्रस्ताव दीजिएगा, बजट की उपलब्धता के ऊपर करवाया जाएगा।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जयपुर से दिल्ली के बीच में ऐसा कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है। हमारे युवा, काफी लोग मिलिट्री में, सेना में जाते हैं, काफी पुलिस की भर्ती में जाते हैं, उनके खेलने के लिए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है तो कब तक आपके बजट की उपलब्धता होगी जिससे वहां के क्षेत्र के युवाओं को खेल स्टेडियम उपलब्ध हो सके?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): अब बजट की उपलब्धता कब तक होगी, यह एक निश्चित तारीख तो मैं नहीं दे सकता हूं लेकिन जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। प्रश्न 233, श्री रोहित बौहरा।

खनिज के माध्यम से राजस्व वसूली का लक्ष्य

233. श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा) एवं **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार खनिज के माध्यम से प्रदेश में राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित करती है? यदि हां, तो गत पांच वर्ष में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त लक्ष्यों के मुकाबले प्रतिवर्ष कितना राजस्व प्राप्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त लक्ष्यों से कम राजस्व वसूली के लिए क्या कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है? यदि हां, तो कौन-कौन और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: खान मंत्री जी। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी, प्लीज।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खनिज के माध्यम से राजस्व वसूली हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। गत पांच वर्षों में निर्धारित लक्ष्य का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि रुपये करोड़ में)

वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित बजट अनुमान**
2014-15	3860.00	3566.00
2015-16	4135.00	4250.00
2016-17	5200.00	4200.00
2017-18	5200.00	4900.00
2018-19	5800.00	6000.00

(2) उक्त लक्ष्यों के मुकाबले प्रतिवर्ष राजस्व प्राप्ति का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**राजस्व प्राप्ति**
2014-15	3635.46
2015-16	3782.11
2016-17	4233.74
2017-18	4521.52
2018-19	5301.48

(3) वर्ष 2014-15 व वर्ष 2016-17 में विभाग द्वारा संशोधित बजट अनुमान से अधिक राजस्व प्राप्ति की गयी है। शेष तीन वर्षों में भी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजस्व वसूली के पूर्ण प्रयास करते हुए अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति की गयी है। खनन राजस्व, खनन किये गये खनिज की मात्रा पर निर्भर करता है, जिसकी मांग बाजार से निर्धारित होती है। अत: तीन वर्षों में संशोधित बजट अनुमान से कम राजस्व वसूली हेतु भी अधिकारी/ कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।

(4) जी हां।

श्री अध्यक्ष: जी नहीं। मंत्री जी, जी हां, नहीं। जी नहीं।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री) (4) जी नहीं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी परमिशन से

(श्री रोहित बौहरा)

पूछना चाहूंगा कि इसमें जो पैट्रोलियम की रायल्टी हमारे पास आती है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन तभी पता पड़ेगा जब हमारे पास पैट्रोलियम रायल्टी का पूरा यह देंगे। 2014-15 में, 2015-16 में, 2016-17 में, 2017-18 तब जाकर इसमें डिफरेंस पता पड़ेगा कि पैट्रोलियम रायल्टी से इतना आया और खनिज रायल्टी से इतना आया। इसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, प्रश्न, माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): हुकुम, यह मेरा सप्लीमेंट्री है, I want to ask कि मेरी रायल्टी में जो आपकी पैट्रोलियम की रायल्टी है, उसमें आपको कितना पैसा मिला? मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण द्वारा जो मूल प्रश्न पूछा गया है वह खनिज राजस्व से सम्बन्धित है, जिसकी सूचना प्रश्न के मूल उत्तर में उपलब्ध करा दी गयी है।

चूंकि पूरक प्रश्न पैट्रोलियम और कच्चे तेल से सम्बन्धित है, एम.एम.डी.आर. एक्ट 1957 की धारा 3 में वर्णित खनिज की परिभाषा के अनुसार खनिज शब्द में खनिज तेल पैट्रोलियम सम्मिलित नहीं है। खनिज तेल पैट्रोलियम के खनन के नियंत्रण हेतु, विनियमन हेतु पृथक् से पैट्रोलियम एक्ट 1934 व पैट्रोलियम नियम 1976 अस्तित्व में है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न में जो जवाब था वह केवल खनिज की रायल्टी के सम्बन्धित था, पैट्रोलियम की मैं माननीय सदस्य जी को अवगत करा रहा हूं।

वर्ष 2012-13, राजस्व लक्ष्य 5050 करोड़ और राजस्व प्राप्ति 5069.88 करोड़ रुपये। वर्ष 2013-14, राजस्व लक्ष्य 5750 करोड़ और राजस्व प्राप्ति 5953.11 करोड़ रुपये। वर्ष 2014-15, राजस्व लक्ष्य 5400 करोड़ रुपये और राजस्व प्राप्ति 4849.57 करोड़ रुपये। वर्ष 2015-16, राजस्व लक्ष्य 2800 करोड़ और राजस्व प्राप्ति 2341.43 करोड़। 2016-17, राजस्व लक्ष्य 2750 करोड़ और राजस्व प्राप्ति 2331.73 करोड़ रुपये। 2017-18, राजस्व लक्ष्य 2900 करोड़ और राजस्व प्राप्ति 2579.08 करोड़ रुपये।

श्री अध्यक्ष: बैठें, माननीय सदस्य, बैठें। मंत्री जी बोल रहे हैं। मंत्री जी, बोलें।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): वर्ष 2018-19, राजस्व लक्ष्य 3825 करोड़ और राजस्व प्राप्ति 3883 करोड़। वर्ष 2019-20, राजस्व लक्ष्य 4250 करोड़ और 30 जून, 2019 तक राजस्व प्राप्ति 959.60 करोड़ रुपये रहा है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): साहब, अब आपने जो खनिज की रायल्टी के फीगर्स दिये, एक जगह आपका 5400, 5700, 5050, यह आपने फीगर्स दिये। फिर आपने एकदम से बजट में 2000, 2800 और फिर आपने 2900 किया और फिर आपने यह 4200 किया। ऐसा क्या हुआ कि आपके डिपार्टमेंट ने इसमें कुछ भी नहीं किया। आपने कहीं तो 5000 का बजटेड बताया, फिर 2800 का बजट बताया। इसका क्या रीजन था कि आपने एकदम आधी रायल्टी कर दी। आपने बजट में भी आधी रायल्टी कर दी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): ऐसा क्या रीजन था कि आपको आधा करना पड़ा? मेरा मतलब यह है कि क्या आपका प्रोडक्शन कम हुआ या आपकी इंटरनेशनल प्राइसेस कम हुई? यह क्या रीजन था कि जो आपका बजटेड फीगर था पैट्रोलियम रायल्टी के ऊपर, वह आपको आधा करना पड़ा। इंटरनेशनल प्राइसेस या अपना प्रोडक्शन कम हुआ?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): अध्यक्ष महोदय, तेल का भाव अन्तरराष्ट्रीय बाजार के अनुसार निर्धारित होता है। रेट अन्तरराष्ट्रीय बाजार में जब कम होती है तो राजस्व का कम अनुमान होता है। जब रेट अधिक होती है तो अधिक अनुमान होता है। उसी के अनुरूप यह लक्ष्य तय किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

नदबई के उच्चैन में स्टेडियम का निर्माण

237. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नदबई के उच्चैन में स्टेडियम के निर्माण करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह भी सही है कि उच्चैन में पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है? यदि हां, तो स्टेडियम का निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): (1) वर्तमान में उच्चैन में स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। भविष्य में समुचित प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

(2) जिला क्रीड़ा परिषद की उच्चैन में कोई भी भूमि उपलब्ध नहीं है।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो सरकार खेल के मामले में युवाओं को काफी प्रोत्साहित कर रही है और दूसरी तरफ अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि उच्चैन में कोई स्टेडियम प्रस्तावित नहीं है। एक घटना का मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया प्रश्न पूछें।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): घटना अभी 11 तारीख को हुई है। बहुत भयानक घटना हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी से संबंधित है। भरतपुर जिले में हाल ही में कुम्हेर के पास धनवाड़ा-सिरसई रोड पर सुबह लगभग 5 बजे के आसपास योगा करने के लिए एक परिवार के 6 लोग गये हुए थे। एक कार ने 6 के 6 लोगों को वहां कुचल दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह बहुत दुखद है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें। प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न पूछें।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए ही माननीय मंत्री जी से पूछ रहा हूं कि क्या सरकार कोई ऐसी मंशा रखती है, जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, यह घटनाएं कम हो जाएं और स्टेडियम का निर्माण हो जाए।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्चैन पंचायत हैड क्वार्टर है। 2015 के नियमों के अनुसार स्थानीय स्तर पर नरेगा के माध्यम से खेल मैदान का विकास हो सकता है। इसके अलावा यदि प्रस्ताव आएगा तो बजट की उपलब्धता पर हम करा पाएंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): जमीन की उपलब्धता के लिए मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि इसके लिए जमीन हम उपलब्ध करा सकते हैं।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): अध्यक्ष महोदय, मैं फिर माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यदि जमीन भी उपलब्ध हो जाती है तो पंचायत हैड क्वार्टर पर नियमों के तहत नरेगा से ही खेल मैदान का निर्माण हो सकता है लेकिन अगर प्रस्ताव आएगा तो मैंने जैसे पूर्व में

(श्री अशोक)

बताया कि बजट की उपलब्धता होने पर हम लोग उसके ऊपर विचार जरूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री दानिश अबरार।

कामां में वृक्षारोपण का लक्ष्य

244. श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर) **(श्रीमती जाहिदा खान (कामां)** के स्थान पर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र कामां में वर्तमान में कितने कार्य किस-किस श्रेणी के चल रहे हैं? कौन-कौनसे स्वीकृत कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाये हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2018-19 में वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य था? उसमें से कितना कार्य पूर्ण हो चुका है व अब कितना शेष है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष: वन राज्य मंत्री जी। 244, वन राज्य मंत्री जी।

राज्य मंत्री, वन (श्री सुखराम विश्नोई): (1) विधान सभा क्षेत्र कामां में कार्यालय उप वन संरक्षक भरतपुर के अधीनस्थ क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैम्पा अंतर्गत 90 हैक्टयर क्षेत्र में दो वृक्षारोपण कार्य स्वीकृत हैं। वृक्षारोपण कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ए' अनुसार है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कामां में कार्यालय उप वन संरक्षक भरतपुर के अधीनस्थ क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2018-19 में नाबार्ड III योजना में 50 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य था, जो कि पूर्ण हो चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि भविष्य में भी इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम को और बढ़ाने का कोई प्रावधान है या नहीं?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): इस वर्ष 2019-2020 में 90 हैक्टेयर में वृक्षारोपण किया जाएगा। फिर मांग के और वित्तीय स्थिति के अनुसार वृक्षारोपण किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री बलजीत यादव।

खेल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

245. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार द्वारा पुरस्कृत करने के क्या नियम हैं व इनके चयन के क्या मानदंड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार द्वारा राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम, 2016 के अनुसार अनुदान राशि देय की जाती है। नियम की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। सरकार द्वारा पुरस्कृत किये जाने वाले खिलाड़ियों के चयन के मानदण्ड उक्त नियमों में वर्णित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि एवं उनकी सुविधाओं को बढ़ाने का इरादा क्या सरकार रखती है? अगर हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वालों का 75 लाख, रजत पदक जीतने वालों को 50 लाख, कांस्य पदक जीतने वालों को 30 लाख रुपये पुरस्कार के रूप में दिये जाते हैं। जो कि भारत सरकार की जो पुरस्कार राशि है, उसके बराबर है। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक को 30 लाख, रजत को 20 लाख और कांस्य पदक विजेता को 10 लाख की पुरस्कार राशि है। इसी प्रकार बाकी अन्तरराष्ट्रीय खेलों के लिए दिए जाते हैं। वह मैंने आपको डेटा दिया हुआ है। निश्चित रूप से कुछ प्रदेश हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, जहां पर यह राशि राजस्थान से और केन्द्र सरकार से भी ज्यादा है। बजट के डिस्कशन में माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने यह प्रस्ताव आया था। भविष्य में हम इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को निवेदन करेंगे और अन्य प्रदेशों के मुकाबले इसको बढ़ाने का प्रस्ताव रखेंगे। इसके पश्चात् हम आपको बता देंगे कि कितना बढ़ रहा है।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से मंत्री जी से और पूछना चाहता हूं कि अनेक अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की दुर्दशा एवं गांव में ग्राउंड, स्टेडियम की कमी के कारण खेलों के प्रति युवाओं का रुझान घटता जा रहा है। क्या सरकार युवाओं का रुझान खेलों के प्रति बढ़े और गांवों में स्कूल ग्राउंड बनें, ऐसा कोई इरादा रखती है? अगर हां, तो क्या मेरे बहरोड़ में भी मांढण, गंडाला, नीमराणा में कोई ग्राउंड या स्टेडियम बनाने का सरकार इरादा रखती है?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): अध्यक्ष महोदय, खेलों को बढ़ावा देने के लिए निश्चित रूप से सरकार इरादा रखती है। इसके तहत पूर्व में नौकरियों में 2 प्रतिशत तक का प्रावधान किया गया था लेकिन उसके नियम इतने जटिल बना दिये गये कि उन नियमों के तहत 2 प्रतिशत भी खिलाड़ी और पदक विजेता नौकरियां नहीं पा सके। हमने उन नियमों में बदलाव किया है। वह फाइल प्रोसेस में है। बहुत जल्दी नियमों में बदलाव होगा। जितने खिलाड़ी हैं, उनका अधिकार है 2 प्रतिशत नौकरी पाने का। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हर नौकरी के अंदर कम से कम 2 प्रतिशत खिलाड़ियों को नौकरियां मिल जाएंगी। उसके सारे नियम हमने आसान कर दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक नई खेल नीति बन रही है। उस नई खेल नीति में जितने भी विवाद होते हैं और खिलाड़ियों को हताशा होती है, उनको हल किया जाएगा। बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 3 घोषणाएं और की हैं। जो खिलाड़ी हैं उनकी पेंशन योजना, जो अपकमिंग मैडलिस्ट हैं, खिलाड़ी हैं और प्रदेश का टैलेंट हैं, देश-विदेश में राजस्थान का नाम रोशन करते हैं, उनके लिए स्कालरशिप योजना और एशियन गेम्स की तर्ज पर, बड़े-बड़े गेम्स की तर्ज पर राजस्थान गेम्स भविष्य में राजस्थान में होंगे। यह बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी है।

आप जो स्टेडियम की बात पूछ रहे हैं, निश्चित रूप से आज भी पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर स्टेडियमों की कमी है। भविष्य में बजट की उपलब्धता के आधार पर सरकार यह मंशा रखती है कि ज्यादा से ज्यादा खेल स्टेडियम हों। बच्चों को खेल का वातावरण मिले। राजस्थान में भविष्य के अंदर हर युवा, हर बच्चा जो इस प्रदेश के अंदर पैदा हो, उसको खेल का अधिकार मिले। भविष्य में इस प्रकार की खेल नीति के माध्यम से हम लोग, माननीय मुख्य मंत्री और राजस्थान सरकार इस सपने को साकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 11.30 बजे, 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(12.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है-

(1) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से ब्यावर (अजमेर) को जिला न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर जिले में टिड्डियों द्वारा फसलें चौपट करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर (झालावाड़) के भीमसागर बांध की नहरों एवं माइनरों के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में चरागाह एवं आबादी भूमि विनिमय न होने से आमजन को होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में।

(5) श्री हमीर सिंह भायल एवं सात अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर लगे अभियंताओं द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से जयसमन्द झील को भरने वाली नदियों से भारी मात्रा में हो रहे बजरी के अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से प्रदेश में अफीम उत्पादक कृषकों के डोडा चूरे को सरकार द्वारा खरीदने के स्थान पर नष्ट किए जाने के आदेश के कारण किसानों को हो रही आर्थिक हानि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से जहाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में भारतमाला परियोजना के तहत अवाप्त की गयी किसानों की जमीन की मुआवजा राशि को बाजार दर से चार गुना अधिक दिये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोखा के पुलिस थाना जसरासर में मृतक श्याम सुन्दर हत्याकाण्ड प्रकरण में पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में फसल बीमा 2016 से 2018 तक की बकाया राशि न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से प्रदेश में एक प्रसिद्ध समाचार पत्र द्वारा भ्रूण लिंग परीक्षण गिरोह का पर्दाफाश किये जाने के उपरांत भी गिरोह के खिलाफ सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने के असमर्थ हूं।

(13) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण की कृषि भूमि पर बसी हुई आवासीय कालोनी के ऊपर से गुजर रही 33 हजार व 11 हजार K.V. की विद्युत लाइनों से होने वाली दुर्घटना की आशंका से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में शहीदों के माता-पिता को राज्य सरकार द्वारा कोई सहायता न प्रदान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती अनिता भदेल एवं श्री बलजीत यादव को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री गोपाल लाल मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के वन्य क्षेत्र में स्थित गांवों की जमीनों की खरीद-फरोख्त पर लगी रोक हटाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री गुरदीप सिंह, सदस्य की ओर से राजस्थान जल निकास अधिनियम 1955 के अंतर्गत दिनांक 17 मई, 2010 को जारी अधिसूचना से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(3) श्री अभिनेश महर्षि, सदस्य की ओर से रतनगढ़ से सालासर-खाटूश्यामजी वाया रींगस-जयपुर के धार्मिक स्थलों को रेल मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से नगरपालिका सूरतगढ़ में सीवरेज कार्यों में हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(5) श्री गोविंद राम मेघवाल, सदस्य की ओर से पंचायत समिति खाजूवाला में बीएडीपी योजना के अंतर्गत पाकिस्तान सीमा से 10 किलोमीटर क्षेत्र तक करवाये जा रहे विकास कार्य के दायरे को 50 किलोमीटर तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर एवं नगर परिषद, ब्यावर के अधिकारियों की मिलीभगत से ब्यावर शहर में अवैध नक्शे स्वीकृत किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री प्रताप लाल भील, सदस्य की ओर से यूआईटी, उदयपुर के पैरीफेरी क्षेत्र में आने वाले कतिपय ग्रामों को पुन: ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से पंचायती राज में एलडीसी भर्ती 2013 में त्रुटिपूर्ण नियमों के कारण नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में ट्रोमा अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से प्रदेश में आयुष नर्सेज को एलोपैथी नर्सेज के समान वेतन एवं भत्ते दिये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर के कतिपय गांवों में इन्टरनेट हेतु मोबाइल टावर लगवाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से गिरिजा व्यास पैट्रोल पम्प के पीछे स्थित रिद्धि-सिद्धि काम्प्लैक्स के वेस्टेज पानी की निकासी का स्थायी समाधान किये जाने के सम्बन्ध में।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा क्योंकि आज शिक्षा की डिमाण्ड है।

(पढ़ी मानी गयीं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

पर्ची

आज दिनांक 19 जुलाई, 2019 को शून्य काल में बोलने हेतु 32 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	**नाम माननीय विधायक**	**विषय**
1.	श्री अशोक लाहोटी	राज्य में बार-बार हो रहे निकाय व पंचायत चुनाव के कारण बार-बार आचार संहिता लगने से विकास कार्य बाधित होने के सम्बन्ध में।
2.	श्री संयम लोढ़ा	सिरोही जिले के मंदिरों में नागरिक सुविधाओं के अभाव व जिला कलेक्टरों की रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।
3.	श्री गोविन्द प्रसाद	विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के पहाड़पुरा व चांदपुरा भीलान रोड पर क्षतिग्रस्त पुलियाओं के निर्माण के सम्बन्ध में।
4.	श्री रामलाल शर्मा	चौमूं कस्बे में आये दिन होने वाले तनाव का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

श्रीमती अनिता भदेल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

अजमेर दक्षिण में आवासीय क्षेत्र में हाईटेंशन विद्युत लाइनों से दुर्घटना की आशंका

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक ज्वलंत समस्या के लिए मुझे बोलने की अनुमति दी उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 जुलाई की घटना है। इस दिन रिया देवनानी डाटर आफ जितेन्द्र देवनानी, जिसकी उम्र मात्र 10 वर्ष है, खेलते-खेलते उसने गलती से छत के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन लाइन के तार को पकड़ लिया, इससे उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गयी। उसका सीधा हाथ कंधे से डाक्टरों ने काट दिया। उसका पूरा शरीर 70 प्रतिशत जल गया, पेट की आंतें जल गयीं। एसएमएस हास्पिटल के डाक्टरों ने बड़ी मुश्किल से उसको बचाया है। अब उसकी हालत यह है कि वह न तो जीने में है और न मरने में। उसके पिताजी बहुत गरीब हैं, नितांत गरीब हैं और सब्जी का ठेला चलाकर अपना जीवन-यापन करते हैं। ऐसी स्थिति में उस अबोध बालिका का पूरा जीवन बर्बाद हो गया, वह बालिका उन पर डिपेंड हो गयी, वह स्कूल भी नहीं जा सकती। अब ऐसी स्थिति में एवीवीएनएल सिर्फ 2 लाख 15 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के दे और यह कह दे कि बाद में और देखा जाएगा तो क्या मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं कि उसकी मृत्यु हो जाएगी तब देखा जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समस्या हाउसिंग बोर्ड कालोनी, वार्ड नम्बर 42 के नाका मदार क्षेत्र की है। वह हाउसिंग बोर्ड कालोनी जो नियोजित ढंग से बसाई जाती है, ऐसी नियोजित ढंग से बसाई जाने वाली कालोनियों में भी 11 हजार और 33 हजार केवी की हाइटेंशन लाइनें छतों से गुजर रही हैं। यह मुझे समझ नहीं आता कि कैसा नगर नियोजन है और कैसा एवीवीएनएल है जो आवासीय कालोनियों में से इन लाइनों को गुजारता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से सिर्फ इतना-सा निवेदन और सुझाव है कि राज्य सरकार पर भी भार नहीं आएगा, केन्द्र सरकार के इंटीग्रेटेड पावर डवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपया दिया गया है जिसके तहत भूमिगत लाइनें करने का काम

(श्रीमती अनिता भदेल)

एवीवीएनएल कर रहा है तो बोर्ड को सौन्दर्यीकरण करने के नाते से उन लाइनों को भूमिगत करने के बजाय ऐसी लाइनों को भूमिगत किया जाए जो छतों के ऊपर से गुजर रही हैं और जिनके लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं होता है। मैं उन जगहों का उल्लेख कर रही हूं जहां से ये लाइनें गुजर रही हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, धन्यवाद।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर दक्षिण में लगभग 50 हजार से एक लाख तक की आबादी वाले आदर्श नगर, गणेश नगर, धोलाभाटा, विराट नगर, ऐसे खूब सारे क्षेत्र हैं जहां से ये लाइनें गुजर रही हैं तो मेरा आपको सुझाव है कि आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपका कुछ पैसा उसमें लगना नहीं, उस प्रोजेक्ट में आप इसको भूमिगत करवा दीजिए तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है और लोगों की जिन्दगियों को बचाया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया बोलने के लिए, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बलजीत यादव।

शहीदों के माता-पिता को राज्य सरकार द्वारा देय सहायता

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने शहीद के माता-पिता की समस्याओं पर बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

शहीद की पत्नी को तो सहायता मिलती है, लेकिन जिसका बेटा मर जाता है, उन माता-पिता को कोई सहायता नहीं मिलती है, न केन्द्र की तरफ से और न ही राज्य की तरफ से। समाज में अनेकों उदाहरण ऐसे देखने को मिलेंगे। मेरे क्षेत्र में भी चूंकि सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हैं और शहीद बहुत बड़ी संख्या में हैं। मैं जानता हूं कि कम उम्र की शहीद की विधवा की दूसरी शादी हो जाती है तो जो भी उसे सहायता मिलती है, वह सारी की सारी उसके साथ चली जाती है और शहीद के जो माता-पिता हैं, उनके पास एक रुपया भी नहीं होता।

अनेकों केसेज में तो ऐसा देखने को मिलता है कि उनके पोते-पोती जो होते हैं, उन्हें उस शहीद के माता-पिता पालते हैं। उनके पास उन्हें खिलाने-

(श्री बलजीत यादव)

पिलाने, पालने-पोसने को, पढ़ाने-लिखाने को कुछ भी पैसा नहीं होता है। एक तरफ तो बेटा चला जाता है, दूसरी तरफ बहू भी चली जाती है और तीसरी तरफ उन्हें कोई सहायता भी नहीं मिलती है, इसलिये वे खून के आंसू रोने को मजबूर रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस मां ने नौ माह पेट में रखकर उस जवान को पैदा किया, उसे बार्डर पर भेजा और उसने देश की रक्षा के लिये अपनी जान की बाजी लगा दी, जान दे दी, शहीद हो गया तो उस मां का ख्याल भी सरकार रखे, क्योंकि उसी मां ने उस शहीद को पैदा किया था।

मैं सरकार से मांग करता हूं जल्द से जल्द सरकार कोई ऐसी स्कीम लेकर आए कि शहीद के माता-पिता को कुछ आर्थिक सहायता मिले या फिर जो उसकी विधवा को मिलता है, उसकी आधी सहायता उसके माता-पिता को भी मिले ताकि वे बेघर न रहें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शहीदों से जुड़ा हुआ मामला है। माननीय सदस्य ने बहुत ही गंभीर मामला उठाया है। मैं आपके जरिये सदन को और माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि शहीदों के माता-पिता को 3 लाख रुपये की सहायता की जाती है, उनके खाते में जमा कराये जाते हैं और उसके ब्याज से उनका काम भी चलता है। इसके अलावा शहीदों के माता-पिता की जो पेंशन है, जो अविवाहित शहीद हो जाता है, उनके माता-पिता की पेंशन पहले 1500 रुपये थी, उसे हमारी सरकार ने अब 10.07.2019 से बढ़ाकर 3 हजार रुपये कर दिया है।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मंत्री जी, यह सहायता बहुत कम है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): फिर भी इस मामले में सरकार बहुत गंभीर है और अभी हमने जो सैकंड वर्ल्ड वार के शहीद थे, उनकी पेंशन भी 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये कर दी है। शहीदों के मामले में सरकार बहुत गंभीर है। कहीं भी किसी भी सदस्य को अगर ऐसा लगे कि शहीदों के माता-पिता या परिवार को कोई परेशानी हो रही है, आप हमें अवगत कराएं। पूरा सदन, पूरी सरकार उन शहीद परिवारों के साथ है। जो भी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सकती है, वह सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक लाहोटी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

निकाय व पंचायत चुनावों के दौरान आचार संहिता लगने से बाधित विकास कार्य

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने शून्य काल में मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं उसके लिये आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे विषय पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जब पूरे देश में 'एक देश, एक चुनाव' का विषय चल रहा हो। प्रदेश में हम तीन बार निकाय के चुनाव करवाते हैं और तीन बार ही पंचायतों के चुनाव एक ही चरण में करवाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यह बात तो सही है और हम पंच से लेकर राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तक के चुनाव करवाते हैं, इसीलिये हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इन तीन चरणों के चुनावों में प्रत्येक बार लगभग चालीस से लेकर पचास दिनों की आचार संहिता लगती है और अभी इस बार जितने भी जवाब माननीय मंत्रियों ने दिये, सबने यह चिंता भी व्यक्त की कि आचार संहिता के कारण बार-बार विकास बाधित होता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि क्यों नहीं सरकार इसकी पहल करे, मुख्य मंत्री जी इसकी पहल करें और हम पूरे देश में एक रोल माडल प्रस्तुत करें। हम 'एक राज्य, एक चुनाव' के सिद्धांत पर एक ही महीने में पहले पखवाड़े में पंचायती राज के, दूसरे पखवाड़े में स्थानीय निकाय के चुनावों को करवाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन चुनावों में जो ड्यूटी लगती है, वह सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों की लगती है, सुरक्षा बलों की लगती है। शिक्षा भी बाधित होती है, युवाओं का भविष्य भी खराब होता है। सुरक्षा बलों की ड्यूटी लगने से बार-बार हमारा आम जन-जीवन भी अस्त-व्यस्त होता है और हमारी सुरक्षा पर भी इसका फर्क पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, इस चुनाव को करवाने से पहले 1950 से 1967 तक पूरे देश में एक बार में चुनाव होते थे, पर धीरे-धीरे राजनीतिक खींचतान, निर्वाचित प्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त के कारण ये बंद हुए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि 'एक राज्य, एक चुनाव' होते हैं तो इससे काले धन पर रोक

(श्री अशोक लाहोटी)

लगेगी, राजनीति में अपराधीकरण पर रोक लगेगी, चुनावों में व्यापक सुधार होगा और एक समावेशी लोकतंत्र का हम निर्माण कर पाएंगे। इतने बड़े देश में जब 'एक देश, एक कर' यानी जीएसटी लागू हो सकता है तो मैं समझता हूं कि यदि सरकार की मंशा होगी, इच्छा शक्ति होगी और थोड़ा आपका दबाव भी होगा तो निश्चित रूप से 'एक राज्य, एक चुनाव' को अपनाकर हम पूरे देश में एक रोल माडल स्टेट बन सकते हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

सिरोही के मंदिरों में नागरिक सुविधाओं का अभाव

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिरोही जिले के 51 मंदिरों की तरफ सदन का और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय राजस्थान में देवस्थान विभाग अलग से काम करता है। इनके अपने मंदिर हैं, लेकिन सिरोही जिले में 51 ऐसे मंदिर हैं जो राज्य सरकार की सम्पत्ति नहीं हैं, लेकिन उन मंदिरों का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में एक देवस्थान बोर्ड बनाकर फैमिली ट्रस्ट बना दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सालों में धर्मावलंबियों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से उनकी शिकायतों के आधार पर अलग-अलग सरकार में अलग-अलग जिला कलेक्टरों ने बार-बार राज्य सरकार को अवगत कराया कि इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। लोगों को किसी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है। यह अति प्राचीन मंदिर है, जिसका 1425 ईस्वीं में सिरोही के तत्कालीन शासक राव सहस्त्रमल ने जीर्णोद्धार और विकास किया था।

सिरोही के धर्मावलंबी चाहते हैं कि सारणेश्वर महादेव के उस प्रसिद्ध तीर्थ पर तालाब का विकास हो, धर्मशाला का नवीनीकरण हो, परकोटे के भीतर और बाहर विकास हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे सिरोही जिले के लोग जब आपस में मिलते हैं तो नमस्कार नहीं करते। वे कहते हैं, 'जय सारणेश्वर जी री' 'जय सरलुआनाथ री' और सबके अपने-अपने व्यापार में सारणेश्वर जी का हिस्सा है। आज वे सारे धर्मावलंबी चाहते हैं कि अपनी मेहनत का पैसा उस तीर्थ के विकास में लगाएं। सांवलिया जी का प्रसिद्ध मंदिर है, घांची समाज के लोग चाहते हैं कि उन्हें उसका दायित्व दिया जाए। वे करोड़ों रुपये लगाकर

(श्री संयम लोढ़ा)

उसका विकास करने को तैयार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के शासन सचिव को सबसे पहले 1997 में तत्कालीन एसडीओ ने कलेक्टर के जरिये पत्र लिखकर अवगत कराया कि सार्वजनिक सम्पत्तियों के प्रबंधन के लिये यह बोर्ड सही काम नहीं कर रहा है। इसके अधीन सम्पत्तियों का उचित रखरखाव नहीं हो रहा है। बोर्ड द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 17, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 की पालना नहीं की गयी है, देवालय की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रबंध नहीं हैं।

उसके बाद फिर जिला कलेक्टर ने शासन सचिव को पत्र लिखा कि हर वर्ग के लोगों को इस ट्रस्ट में शामिल कीजिए। निजी संस्था बना देने से संस्था के संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। आय-व्यय का दुरुपयोग हो रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट ने 14 मई, 2004 को सिरोही के कलेक्टर को आदेश दिया कि इस देवस्थान बोर्ड को कंट्रोल कीजिए। तत्कालीन जिला कलेक्टर ने 5 जून, 2004 को एक आदेश जारी किया कि सभी मंदिरों की आय-व्यय व गतिविधियों पर नियंत्रण एसडीओ और तहसीलदार के जरिये रखा जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राजस्थान सरकार इस पर पहल करती है तो पूरे सिरोही जिले के धर्मावलंबी तैयार बैठे हैं। सारणेश्वर महोदव तीर्थ पर 25 करोड़ रुपये जनता की ओर से लाकर आपको उपलब्ध कराऊंगा। सांवलिया जी का मंदिर अगर आप घांची समाज को देते हैं तो 5 करोड़ रुपये उस मंदिर के लिये लाकर मैं सरकार को दूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से विनती करूंगा कि आप इस पर पहल करें, जिससे सिरोही जिले के धर्मावलंबियों को सारणेश्वर जी की सेवा का अवसर मिल सके।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, वह बहुत ही गंभीर है। राजस्थान लोक न्यास अधिनियम की धारा 48 के तहत जिला कलेक्टर सिरोही के द्वारा देवस्थान बोर्ड, सिरोही की जांच कराने की घोषणा करता हूं। जिला कलेक्टर डेढ़ माह की अवधि में जांच करके सरकार को रिपोर्ट पेश करेंगे और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगामी निर्णय लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहरथाना में क्षतिग्रस्त पुलियाओं का निर्माण

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्य काल के दौरान मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना जिला झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है लेकिन वर्षा के मौसम में वर्षा के कारण कई मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं जिससे नागरिकों एवं आमजन को, धार्मिक स्थलों पर जाने वाले पदयात्रियों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे घाटोली कस्बा से केलखोयरा महादेव के बीच बहने वाली धार गंगा नदी पर बनी पुलिया पर कम बारिश में ही मार्ग अवरुद्ध हो जाता है जिस पर पूर्व में भी कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं जिससे आम आदमी का जीवन संकट में रहता है। ऐसी स्थिति में बीमारी एवं डिलीवरी में लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। ऐसी स्थिति मनोहरथाना के चांदपुरा भीबान से आंवलेड़ा के बीच खाल की पुलिया तथा मनोहरथाना मेन रोड से पहाड़पुरा के बीच की पुलिया बहुत ही क्षतिग्रस्त है। ऐसी स्थिति में देवरी जागीर से हरनावदा शाह मेन रोड तक पहुंचने के बीच परवन नदी पर हाई-लेवल पुल बनाया जाए जिससे किसानों को उचित लाभ मिल सके और मनोहरथाना से राजगढ़, मध्य प्रदेश सीमा रोड के बीच खाताखेड़ी हाई लेवल पुलिया बनाई जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): इससे आवागमन में सुविधा रहेगी और बरसात के दिनों में मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा। बरसात के दिनों में ये मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं और जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। मैं, माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से इन पुलियाओं का नया निर्माण कराने का सुझाव देता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री रामलाल शर्मा।

चौमूं में होने वाले साम्प्रदायिक तनाव का समाधान

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, दो-तीन घटनाओं की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज मेरा पूरा चौमूं कस्बा एक बारूद के ढेर के ऊपर है और जरा सी भी अगर चिंगारी लगती है तो कभी भी विस्फोट हो सकता है।

(श्री रामलाल शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, 4.11.2014 को कत्ल की रात के दिन बाजार के अन्दर बल्ब तोड़े गये, लाइटें तोड़ी गईं, तिरपाल फाड़े गये और फिर तनाव हुआ। इसी तरीके से अक्टूबर, 2017 में नया बाजार में मोहर्रम का जुलूस निकला, मोटर साइकिलों के शीशे तोड़े गये, मोटर साइकिलों को गिराया गया, फिर तनाव हुआ। 3 दिसम्बर, 2017 को एक समुदाय विशेष के व्यक्ति द्वारा, साइकिल लेकर जा रहा था, एक महिला को टक्कर लगी, उसके बाद में तनाव हुआ और फिर 144 धारा लगायी गयी। 17 अप्रैल, 2018 को नव वर्ष का जुलूस निकला, उस जुलूस के बाद में विष्णु एडवोकेट से मारपीट की गयी, फिर झगड़ा हुआ और मुकदमा दर्ज हुआ। अध्यक्ष महोदय, अभी 24 मार्च, 2019 को नव वर्ष आयोजन समिति द्वारा एक वाहन के साथ 20-25 लोग मन्दिर निमंत्रण के लिए जा रहे थे तो उस वाहन को रोका गया, उस वाहन के शीशे तोड़े गये, उनके साथ मारपीट की गयी और उसके बाद में जयपुर पुलिस आयुक्तालय के कमिश्नर, दो एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी सहित कई पुलिस का जाब्ता वहां पहुंचा, धारा 144 लगायी गयी और उस तनाव को कम करने के लिए कम से कम 8 से 10 दिन तक फोर्स रही। अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सीधा इतना सा निवेदन है कि दोनों समुदायों को बुलाएं।

जिस समय दशहरे का जुलूस निकलता था और जिस समय ताजिये शुरू किये गये उस समय के चौमूं की आबादी सिर्फ 5 हजार थी। अध्यक्ष महोदय, आज आबादी बढ़कर 70 हजार हो गयी, भौगोलिक स्थिति से भी आज गलियां सिकुड़ गयीं, वाहन बहुत अधिक हो गये, रास्ते के अन्दर अवरोध पैदा होता है। मेरा सदन के माध्यम से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि दोनों समुदायों को बुलाएं, आपस में बिठाएं और बिठाकर आज की वर्तमान परिस्थितियों के अन्दर कौनसा मार्ग उचित हो सकता है, कौनसा मार्ग अनुचित है, उस मार्ग को तय करने का काम करें ताकि आने वाले समय के अन्दर कोई विस्फोटक स्थिति पैदा न हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, मंत्री महोदय, फिर मोहर्रम का त्यौहार आ रहा है और मुझे फिर आशंका है कि मोहर्रम के त्यौहार के अन्दर कोई अप्रिय घटना नहीं हो जाए इसलिए सरकार सतर्क रहे और सरकार को आगाह करता हूं कि अगर कोई भी अप्रिय घटना घटी तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: 131 चेंज कर रहे हैं। मंत्री जी को जाना है इसलिए, मदन जी, पहले आप उठा लें। मदन दिलावर जी, पहले आप उठा लें। उनको जाना है जल्दी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

रामगंज मण्डी में विभिन्न प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र के गांवों में श्मशान घाट, खेल मैदान, मरे हुए पशु डालने हेतु स्थान, मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु जमीन आरक्षित करने के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी के गांवों में श्मशान घाट की भूमियों पर वर्तमान में कोई भी अवैध अतिक्रमण नहीं हैं। विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में किसी भी आरक्षित श्मशान घाट की भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। ग्राम पंचायतों द्वारा श्मशान हेतु भूमि आबंटन, आरक्षण हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत नियमानुसार आबंटन, आरक्षण की कार्यवाही की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में स्थित स्कूलों के खेल मैदानों पर अतिक्रमण नहीं है। विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी के तहसील रामगंज मण्डी के सलाड़ा खुर्द, साहरवाड़ा, लख्मीपुरा, सावल खुर्द, मोडक स्टेशन, खीमच, नमाना, तेलवा खेड़ी, चेचट स्थित विद्यालयों पर आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामगंज मण्डी में खेल मैदान नहीं है। इसके लिए भूमि आबंटन प्रस्ताव प्राप्त कर नियमानुसार आबंटन की कार्यवाही की जाएगी।

विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी के गांवों में मृत जानवरों को डालने हेतु भूमि आबंटन नहीं है। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षित करने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, अनुशंसा पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत नियमानुसार भूमि आरक्षित की जाती है।

राजस्व भूमियों में कृषि सुधार से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का आबंटन, अनुमति देने का प्रावधान नहीं है। कुम्भ कार्य आदि प्रयोजन हेतु मिट्टी खुदाई का कार्य खनन की श्रेणी में आता है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि मटका हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मटका, सुराही में शुद्ध पानी मिलता है। गांवों में इसको कुम्हार बनाते हैं लेकिन कुम्हारों के लिए मिट्टी लाने के लिए कोई भी जमीन आरक्षित नहीं होने के कारण से सारे कुम्हार समाज के लोग अधिकांश बेरोजगार हो गये हैं और लोगों को अच्छा मटका उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके कारण से वे बोतल बन्द पानी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके कारण से कई बीमारियां हो रही हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, आपने कहा कि यह खनन नीति में आता है, मैं कोई भट्टों के लिए मिट्टी लाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खिलौने बनाने और मटके बनाने के लिए आरक्षित करने की बात कर रहा हूं ताकि राजस्थान के लाखों लोगों को रोजगार भी मिल जाए और करोड़ों लोगों को मटका रखने से शुद्ध पानी मिले। क्या आप यह आरक्षित करेंगे?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है कि राजस्थान भर में सब गांवों में जानवर हैं। पशु सब लोग पालते हैं और पशु मरते भी हैं। मरने के बाद वे पशु को कहां ले जाए? जब चर्मकार कहीं भी ले जाकर डालता है तो झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, मन-मुटाव होते हैं, कई जगह मारपीट होती है तथा कई जगह हत्या तक हो जाती है। मेरा निवेदन है कि सभी गांवों में जहां पर पशु होते हैं उनके मरने के बाद डालने का स्थान निश्चित किया जाए। जमीन आरक्षित की जाए ताकि झगड़े न हों, दुर्गन्ध न फैले, बीमारियां न हों। क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल तो गिद्ध भी गायब हो गये हैं और गिद्ध गायब होने के कारण से वे अधिक दिनों तक पड़े रहते हैं इसलिए हैजा और बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। इन बीमारियों से बचाव के लिए और उन लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए उनके लिए भी जमीन आरक्षित करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि श्मशान की भूमि पर, स्कूलों की भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। मेरे पास यह सरकार का पत्र है जिसमें लिखा गया है कि फुटेट में, तेलियाखेड़ी में, उण्डवा में और रामगंज मण्डी में तो अतिक्रमण है। इसके अलावा भी मेरे पास कई सारी जानकारियां हैं जहां अतिक्रमण हैं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि क्या श्मशान की भूमि और स्कूल मैदान की भूमि पर अतिक्रमण हैं उनको हटवा देंगे और हटवा देंगे तो कब तक हटवा देंगे? यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने कई सकारात्मक सुझाव दिये हैं। विशेषकर जो माटी की बात की है जिससे हमारे लघु उद्योग हैं, कुम्हार जो मटका बनाते हैं और पीने के पानी की भी चिंता की है कि बोतलों के माध्यम से पीते हैं जो स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। आपका यह सुझाव है, इसको मैं प्रशासनिक तौर पर एग्जामिन करूंगा, आपको भी बुलाऊंगा और जो कोई भी रास्ता निकलेगा, माइनिंग मिनिस्टर साहब को भी साथ में बिठाकर प्रक्रिया के तहत इसको माइनिंग से निकालकर उस प्रजापत समाज के लिए अगर इनको बाहर निकाल सकेंगे तो बिल्कुल प्राथमिकता से मैं करूंगा और आपने ये जो सुझाव दिये उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

पशुओं के मरने के सम्बन्ध में जो आपने चिन्ता जाहिर की है, शहरों के अंदर तो व्यवस्था है। पहले गांव छोटे हुआ करते थे, तब गांव के बाहर इकट्ठा कर लिया जाता था। सरकारी जो व्यवस्था है, पशुओं की हडिड्यों के ठेके भी हम लोग करवाते हैं। शहरों की तर्ज पर गांवों में क्या हो सकता है, उसके लिए भी आपस में बैठकर चर्चा करके इसका रास्ता निकालेंगे। श्मशान घाट और कब्रिस्तान के ऊपर यदि कोई अतिक्रमण होता है तो यह अपने लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक चीज है। हम लोगों का समाज के नाते सबका दायित्व बनता है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्व विभाग के सभी कर्मचारी प्राथमिकता से जहां कहीं भी कब्जे हैं, किसी के भी कब्जे हैं, उनको हटाने के लिए प्राथमिकता से कार्य करेंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): एक मिनट सर, जहां कब्जा नहीं, परन्तु आबंटित नहीं है, आरक्षित नहीं है, उनको भी आबंटित करने की घोषणा...

श्री अध्यक्ष: नहीं माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज माननीय सदस्य बैठें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): तालाब की मिट्टी एमपी में जा रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, प्लीज बैठें। यह तरीका नहीं है। मदन जी पूछ लें आखिरी प्रश्न। प्लीज, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह

(श्री मदन दिलावर)

निवेदन करना चाह रहा था कि कई स्कूलों के मैदान के लिए जमीन आबंटित नहीं है, कई श्मशान के लिए जमीन आबंटित नहीं है। उनको जल्दी से जल्दी आबंटित करने के प्रस्ताव मंगवाने के लिए निर्देशित करें, संबंधित को।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): आपके विधान सभा क्षेत्र राजस्थान में कहीं से भी श्मशान और कब्रिस्तान के अगर प्रस्ताव आएंगे तो उसको प्राथमिकता से करवाया जाएगा। अभियान के तहत, जब कभी भी राजस्व अभियान होगा, इसको प्राथमिकता से करेंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। 131, ज्ञानचंद पारख साहब।

विद्युत तंत्र की दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को सहायता

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 131 के अंतर्गत विद्युत से होने वाली दुर्घटनाओं में मृतक के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि में हो रही अड़चन को लेकर माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर डिस्काम में विद्युत तंत्र से घटित होने वाली दुर्घटनाओं वाले मृत्यु के प्रकरणों में जांच कमेटी गठित कर जांच करायी जाती है एवं विद्युत दुर्घटना कारित होने के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि दस्तावेजों की जांच के उपरान्त आश्वस्त होने पर कि दुर्घटना का कारण विद्युत वितरण निगम के विद्युत तंत्र की खामी अथवा स्थितिजन्य ही रहा है तो ऐसे प्रकरणों में सहायता राशि नियमानुसार 5 लाख रुपये तक मृतक के आश्रितों को दी जाती है।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम में वर्तमान में लम्बित प्रकरणों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। पाली जिले में गत 5 वर्षों में 24 निजी व्यक्तियों की दुर्घटना में मौत की एवज में 1 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दी जा चुकी है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संरक्षण चाहूंगा आपका, मेरा जो ध्यानाकर्षण है, वह इस बात को लेकर है कि जो विद्युत तंत्र की कमी से दुर्घटना होती है, उसमें तो आप राशि देते हो, उसमें कतई कोई कोताही नहीं होती। पर, कई प्रकरण ऐसे भी होते हैं, जिसमें आप मानते हो कि आपकी कमी नहीं है। क्योंकि, जांच करने वाला अधिकारी भी

(श्री ज्ञानचंद पारख)

आपका ही है। आप भी पैसे देते नहीं हो और मृतक के परिजन जो मुख्य मंत्री सहायता कोष से आवेदन करते हैं, वहां उनके आवेदन यह कहकर खारिज कर दिये जाते हैं कि ये विद्युत दुर्घटना है और आप नियमानुसार विद्युत विभाग में आवेदन करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर कच्चा घर है छपरे का, वहां शोर्ट सर्किट से आग लगती है और उसके अंदर पड़ी मोटर साइकिल भी जल जाती है। उसकी टंकी जलने से विस्फोट होता है और 18 साल की एक लड़की, अविवाहिता, चम्पा नाम है उसका, उसकी उस दुर्घटना में डैथ हो जाती है।

माननीय मंत्री महोदय जी की बात सही है कि इनके तंत्र की कमी नहीं है, पर जो जिला कलेक्टर के यहां से पत्र आता है क्योंकि यह शोर्ट सर्किट से आग लगी है, इसलिए, विद्युत विभाग में जाएगा और ये राशि देय नहीं है। ऐसे 17 प्रकरण हैं। घर के अंदर शोर्ट सर्किट से या किसी और विद्युत करंट आने से दुर्घटना हुई और वे भी सारे के सारे यह कहकर लौटा दिये गये कि आप विद्युत विभाग में दो और विद्यत विभाग में दिये, तो उनके नियम, आपके नियम बिलकुल स्पष्ट, आपके तंत्र की गलती नहीं है। पर, कुछ प्रकरण ऐसे भी हैं, जहां कुछ संदेहास्पद केस हैं।

एक कन्हैया लाल सांसी है। पाली में दो साल पहले बहुत जोरदार बारिश आयी थी, पूरी बस्ती में पानी भरा हुआ था। आपका बिजली का पोल पानी में डूबा हुआ, उससे करंट फैल गया, सर्विस लाइन गिर गई और उससे उसकी मौत हो गयी। मौत तो सर्विस लाइन के गिरने से हुई है, यह बात तय है और दोनों विभाग उसको फुटबाल बना रहे हैं। मुख्य मंत्री सहायता कोष, वह मना कर रहे हैं, आप भी मना कर रहे हो, तो ऐसे प्रकरण के जो दुर्घटना में मृतक हैं, एफआईआर की कापी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कापी है, जो भी आपके प्रावधान में है, चाहे आप मुख्य मंत्री सहायता कोष से दिलवा दो और चाहे आप विद्युत विभाग से दिलवा दो। वे सहायता राशि के प्रकरण खारिज कर दिये गये हैं। उन प्रकरणों में किसी न किसी ओर से सहायता मिल जाए, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कन्हैयालाल पुत्र श्री धन्नाराम जी के बारे में जो जिक्र किया, यह दुर्घटना दिनांक 03.09.2017 की है। हमारे पास सूचना आयी 03.04.2018 को और दुर्घटना मृतक की स्वयं की लापरवाही के कारण घटित हुई। हमारे अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर और जिस जगह पर करंट आना बताया गया वहां कोई घरेलू कनेक्शन अथवा सर्विस लाइन भी नहीं थी, फिर भी चूंकि इन्होंने कलेक्टर अथवा माननीय मुख्य मंत्री सहायता कोष से कोई अर्जी दी है तो मैं संबंधित कलेक्टर को कहूंगा कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उनका जो प्रश्न है, एक मिनट बैठें, उनका प्रश्न यह है कि डायरेक्ट विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, पर बरसात में करंट के कारण डैथ हो गयी तो डायरेक्ट तो विभाग मानेगा नहीं, क्योंकि वह मौत बिजली के कारण हुई है तो विद्युत विभाग भी कम्पंसेशन नहीं देता है और मुख्य मंत्री सहायता कोष में भी नहीं आता है। आप विभाग को निर्देशित करें, इस तरह की घटना में यदि विद्युत विभाग नहीं दे सकता है तो मुख्य मंत्री कोष से मिलना चाहिए, इस तरह के डायरेक्शन दे दें, जिससे उस आदमी को रिलीफ मिले, यही आपका प्रश्न है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): ये तो एक प्रकरण हो गया। 17 प्रकरण ऐसे हैं, उसमें थोड़ा आप आदेश करवा दो।

श्री अध्यक्ष: जनरल बात करें। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। आपने जो ध्यानाकर्षण किया है इस तरह के केसेज में विभाग इस तरह रहे कि यदि विभाग के परव्यू में नहीं आ रहा है तो उनकी गलती नहीं है, पर इन -डायरेक्ट जो कहते हैं न, vicarious responsibility है क्योंकि बिजली के कारण हुई तो कहीं न कहीं बिजली responsible है, may not be department. उसको मुख्य मंत्री जी से भी नहीं मिले, इससे भी नहीं मिले, किसी न किसी से उसको सहायता मिले, उस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): लेकिन जो केस खारिज कर दिये, वे केस री-ओपन करवा दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त, मैं अलाउ नहीं करूंगा। आज हाउस में डिबेट करानी है। माननीय प्रताप सिंह जी, वार्षिक प्रतिवेदन।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक की पृथक् संपरीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2017

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-33(4) के अंतर्गत मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक की पृथक् संपरीक्षा रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य, पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक, श्री लालचन्द कटारिया।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करता हूं।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री अध्यक्ष: मांगों पर चर्चा, माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आज का विषय सबकी रुचि का विषय है, समय का थोड़ा ध्यान रखें, जिससे हम समय पर डिबेट कर सकें। माननीय शिक्षा मंत्री जी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,28,25,39,77,000/- (तीन सौ अट्ठाईस अरब पच्चीस करोड़ उनतालीस लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 24 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्ष: अनुदान की मांग पर विचार। श्री वासुदेव देवनानी।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर चर्चा प्रारम्भ हो रही है। शिक्षा देश के भविष्य का आधार है और यह मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए भी आवश्यक है। हमें ध्यान देना होगा, सन् 1966 में गठित कोठारी आयोग ने कहा था कि केन्द्र और राज्य सरकारें नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त शिक्षा अपनाएं। इसीलिए हमें नयी पीढ़ी को केवल साक्षर नहीं बल्कि शिक्षित भी बनाना है और शिक्षित का अर्थ केवल डिग्री या 12वीं तक पास नहीं है लेकिन उसे गुणवान और संस्कारवान भी हमको बनाना है। इसके लिए जो वर्तमान में केवल आई.क्यू. पर ध्यान दिया जा रहा है, केवल इन्फोर्मेटिव शिक्षा दी जा रही है। इन्फोर्मेटिव शिक्षा के साथ इमोशनल ई.क्यू. व एस.क्यू स्प्रिचुअल भी आवश्यक है। स्प्रिचुअल अर्थात् किसी पूजा पद्धति से नहीं है लेकिन स्प्रिचुअल का अर्थ है कि विद्यार्थियों में बचपन से ही करुणा, सेवा, त्याग, समर्पण, प्रेम, सहकार, अनुकम्पा, अनुशासन जैसे गुणों व भावनाओं का विकास हो। संवेदनशीलता उसके मन में आये कि वह किस प्रकार से समाज में रहे, किस प्रकार से अपने समाज व देश के बारे में चिन्तन कर सके और वर्तमान में जिस प्रकार की समाज में बुराइयां आ रही हैं, इसमें भी मेरा मानना है कि जब तक स्प्रिचुअलिटी नहीं आएगी तब तक बच्चियों के साथ और बाकी जो विकृतियां हैं यह बचपन से ही, वहां कानून अपना काम करेगा और बाकी विभाग अपना काम करेंगे। लेकिन बचपन से ही उसमें संस्कार भाव हो इसके लिए मैं आग्रह करूंगा शिक्षा मंत्री जी से कि उसके लिए स्कूल में ही बच्चों को यदि भैया, बहन कहने का जिस प्रकार कई स्कूलों में

(श्री वासुदेव देवनानी)

कहा जाता है अन्य एनजीओज के विद्या भारती में। यदि स्कूल में कहेंगे तो उसको लगेगा कि मेरी बहन है उसके मन में बहन का एक भाव आएगा। अटपटा लग सकता है कुछ लोगों को लेकिन इसके पीछे जो भाव है उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि शिक्षा के अन्दर राजनीति को नहीं लाना चाहिए। राजनीति में शिक्षा आये यह तो आवश्यक है, जो लोग राजनीति में रहते हैं वे शिक्षित हों और शिक्षा से युक्त हों, लेकिन शिक्षा के अन्दर राजनीति न हो ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार शायद इसका उलटा कर रही है। जैसे मैं कहूं कि आपको योग दिवस से ईर्ष्या क्यों है? क्या इसी से राजस्थान श्रेष्ठ बनेगा? प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयासों से आज भारत ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व के अन्दर 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन बढ़-चढ़कर किया जा रहा है। चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय, किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाले हों सारे विश्व में माना है, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग ने अचानक एक आदेश जारी कर दिया। स्कूल हमने इस कारण से 19 जून को खोलने शुरू किये लेकिन आपने एक आदेश जारी किया कि स्कूल में 24 जून को अध्यापक आएंगे और 1 जुलाई को बच्चे आएंगे ताकि 21 जून के योग दिवस के अवसर पर भाग न ले सकें। जब समाज का दबाव आया तो आपने यह तो कहा कि बच्चे आ जाएं लेकिन जब बच्चों की स्कूल में छुट्टी है तो कौन बच्चा आएगा। कह दिया, अपने नजदीक के स्कूल में जाएं। आप यदि राजस्थान भर से...

(12.43 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

संख्या मंगवाओगे तो वह संख्या नगण्य होगी। वास्तव में इतने लाखों विद्यार्थी जो 85 लाख विद्यार्थी स्कूलों में पढ़ रहे हैं यदि वे योग में भाग लेते तो आपका क्या बिगड़ता? चूंकि योग दिवस मोदी जी ने शुरू किया है इसलिए हम उसमें भाग नहीं लेंगे। स्टेट में अभी योग दिवस हुआ। अजमेर में हमारे चिकित्सा मंत्री ने किया, उसमें कितने लोग आये? कई विधायक और मंत्री लोग किसी योग दिवस पर गये नहीं। कहीं नगण्य गये। निकालो आप, हमने कोटा में किया था उसमें 1 लाख 8 हजार सम्मिलित हुए जो विश्व का एक रिकार्ड है लेकिन आप बताइये राजस्थान में कितना हुआ? (व्यवधान) घर पर कर रहे हैं, यह नहीं है।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, स्थान पर पधारें आप।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपको समझना होगा कि योग से शरीर, मन, बुद्धि और आध्यात्म इन चार तत्वों से संतुलित और समन्वित शिक्षा प्राप्त होने पर ही ...(व्यवधान) मुझे ज्ञान है आपका जब नंबर आये आपके मंत्री जी बोल देंगे, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): विद्यार्थियों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा। माननीय सभापति महोदय, योग स्कूल में बच्चे के लिए भी आवश्यक है। शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। मन का होता है, बुद्धि का होता है। आपको चार दिन पहले स्कूल खोलने में तकलीफ क्या थी? लेकिन चूंकि भाजपा के शासन में 19 जून को खुलता था इसलिए हम चेंज करेंगे। यह सोच बदलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस कभी भी शिक्षा के प्रति गम्भीर नहीं रही।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): वह मैं बता रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज आप इंटरवीन न करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्योंकि मेरे पास आज आपके शिक्षा मंत्री जी ने इसी कुर्सी पर बैठकर जो भाषण दिया था वह है। मैंने भी जो उत्तर दिया था वह मेरे पास है। एक-एक बात इनकी भी जिक्र करूंगा और मेरा भी बताऊंगा, फिर भी आपको कुछ पूछना है तो स्वागत है आपका।

माननीय सभापति महोदय, आजादी के बाद अधिकांश समय ये लोग सत्ता में रहे। पर हाल क्या है, जो हमें 2013 में विरासत में मिला सरकारी स्कूलों में 52 परसेंट पद खाली। 12वीं के स्कूल केवल 37 परसेंट पंचायतों में थे। आजादी के बाद 63 परसेंट पंचायतों में 12वीं में पढ़ने से वहां के बच्चे वंचित थे। राजस्थान में शैक्षिक दृष्टि से हम भारत में 26वें नंबर पर थे और विद्यालय भवनों की जर्जर हालत थी। इस प्रकार की हालत देखकर लगता है कि आखिर हमने इतने वर्षों में किया क्या। प्रश्न है, इसलिए इस पर विचार और चिन्तन-मनन करना चाहिए। मैं शिक्षा में राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो तथ्य है उसे तो आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। यह ठीक है कि शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा परिवार है उस समय 86 हजार स्कूल थे। चार लाख से अधिक अध्यापक थे और 85 लाख से अधिक विद्यार्थी थे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, जिनको आसन ने इजाजत दी है उनके अलावा किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इतने ही प्राइवेट स्कूलों में। बहुत-बड़ा परिवार है शिक्षा परिवार। इसे ठीक करना और रखना बेहद चुनौतीपूर्ण है हमारे लिये भी और आपके लिए भी। लगातार कुछ न कुछ काम हुए लेकिन उसे गति देकर ठीक करने का काम आप और हमारा सबका है। वर्तमान शिक्षा मंत्री जब पहले यहां बैठा करते थे तो इन्होंने खूब कटाक्ष किये, वह आज मैं लेकर आया हूं। बड़ी-बड़ी बातें कीं। अब गेंद आपके पाले में है। देखते हैं आप उस पर क्या करते हैं। यह आपकी परीक्षा की घड़ी है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य के मध्यम और गरीब परिवारों के बच्चे अधिकांश सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। उसमें सस्ती, अच्छी, गुणवत्तापूर्ण, संस्कारवान शिक्षा मिले यह हमारा कर्तव्य है। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं लेकिन सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा बनी वह हम सबके लिए चिन्तनीय है। मुझे परिस्थिति का ज्ञान था इसलिए मैंने मेरे सामने लक्ष्य तय किये। एजुकेशन शब्द का अर्थ क्या है उसको मैंने व्यवहार में लाने का प्रयत्न किया। ई का मतलब एनरोलमेंट, डी का मतलब डिजिटलाइलेशन, यू का मतलब यूनिफोर्मिटी। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। आदर्श स्कूल बने, क्लास रूम बने। सी का मतलब करिकुलम, ए का मतलब एकेडेमिक इम्प्रूवमेंट, टी का मतलब टीचर्स अवेलेबिलिटी, आई का मतलब इंटीग्रेशन, ओ का मतलब optimum use of the resources, एन का मतलब नेशनलिज्म। यह है हमारा एजुकेशन। इसको यदि ध्यान में रखेंगे तो आपकी सारी समस्याओं को हल करने में आपको आगे सहायता मिलेगी। मैं केवल शब्द तक नहीं गया, मैंने कहा कि हम लोग पहले रिफोर्म करेंगे, फिर प्रफोर्म करेंगे उसके बाद ट्रांसफोर्म करेंगे। इन तीनों बिन्दुओं के लेकर एजुकेशन के विषय को लाना शुरू किया।

सभापति महोदय, जब विद्यार्थी होंगे तो स्कूल चलेंगे। 2012-13 तक नामांकन लगातार गिर रहा था। आंकड़े उठाकर देख लें। प्रतिवर्ष तीन से चार लाख विद्यार्थी कम हो रहे थे। 72 लाख से भी कम होते जा रहे थे। स्कूल तो बहुत थे, 86 हजार स्कूल। लेकिन स्थिति क्या थी। 142 स्कूलों में जीरो

(श्री वासुदेव देवनानी)

नामांकन। 4164 स्कूलों में 15 से कम। पांचवीं का स्कूल है, तीन-तीन विद्यार्थी एक-एक कक्षा में है और 28 हजार स्कूलों में 15 से 30 बच्चे आठवीं के स्कूल में। यह स्कूलों की दर्दनाक स्थिति थी। कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल थे और फिर छठी में जाने के लिए टीसी कटवाओ। फिर 6ठी से 8वीं तक का स्कूल, 9वीं में फिर कटवाओ, आखिर विद्यार्थी को दो-दो बार टीसी कटवानी पड़ती थी। माननीय सभापति महोदय, हमारी कुल पंचायतें 9895, हमने बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सारी पंचायतों के स्कूलों को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल बनाया। यानी आज 100 परसेंट, उसमें से 9700 पंचायतों में सीनियर सैकण्डरी स्कूल बन गये, बाकी जहां 200 मिडिल थे, उनको सैकण्डरी में बदला। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं बिलकुल इजाजत नहीं दूंगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): जहां मिडिल थे, उनको सैकण्डरी में और जहां प्राइमरी थे, उनको हमने मिडिल में बदला। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, प्लीज विराजिए।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): 000

श्री सभापति: विराजिए। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। आसन पैरों पर है। आसन पैरों पर, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। एक भी शब्द अंकित नहीं होगा। किसी भी माननीय सदस्य का शब्द अंकित नहीं होगा। शिक्षा जैसे विषय पर गंभीरता नहीं है। पूरा राजस्थान चिंतित है। उन गरीब परिवारों को पूछिए जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिये बाध्य होते हैं केवल इसलिए कि सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। यदि आप और हम बैठकर इस पर कोई सारगर्भित चर्चा कर लेंगे, अच्छे सुझाव दे देंगे, अच्छी सारी व्यवस्थाएं सुधार लेंगे, इसमें किसी को एतराज है क्या? फिर गंभीरता बरतिए, यह अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात कहना। इंटरवीन करने का उद्देश्य क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: प्लीज आप विराजिए, आप विराजिए। कृपया आप सहयोग करे। बिना आप सबके सहयोग के यह संभव नहीं होगा। बार-बार क्यों कहना पड़ता है?

श्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं बिलकुल इजाजत नहीं दूंगा। माननीय सदस्य, विराजिए आप। माननीय सदस्य, गंभीरता बरतें आप। आसन आपसे अपेक्षा रखता है, आप सीनियर आदमी हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): 000

श्री सभापति: प्लीज विराजिए।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। एक भी शब्द अंकित नहीं हो रहा है। क्या अपेक्षा रखूं आप लोगों से? माननीय सदस्य, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, आसन आपसे अपेक्षा रखता है कि हाउस आर्डर में रहे, आपके सहयोग के बिना नहीं होगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, कृपया माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें। इधर जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, वह अपनी बात कहें, आपस में अच्छे सुझाव आएंगे। आप सब यू-ट्यूब पर लाइव हैं। बार-बार खड़े होकर बाध्य होकर मुझे आप लोगों को रोकना पड़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? कृपया आप सहयोग करें। प्लीज माननीय सदस्य, मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि कृपया आप अपने आसन पर विराजे रहेंगे। बारबार आप इंटरवीन नहीं करेंगे, यह मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। माननीय सदस्य श्री देवनानी जी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने सीट पर बैठकर जोर-जोर से कहा था 22 हजार स्कूल बंद कर दिये। अब आप 22 हजार कब खोल रहे हैं, जरा अपने भाषण में यह उत्तर देंगे तो अच्छा लगेगा। आपने खुद ने स्वीकार किया ...

श्री सभापति: आप आसन की तरफ देखकर बात कहें, आप इनको इन्वाइट मत कीजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह बताएं अपने उत्तर में, इनसे आग्रह है। उस समय जिनकी आपत्ति आई थी, हमने 2500 स्कूल वापस शुरू किये थे। अब आपने कहा है कि समीक्षा करवा रहे हैं और आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि केवल 2800 स्कूलों के प्रस्ताव आये हैं। यानी बाकी स्कूल तो बंद किये थे, इसको तो मानो, तो शायद समस्या का समाधान होने लग जाएगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: जो-जो माननीय सदस्य बीच में इंटरवीन कर रहे हैं, मैं

(श्री सभापति)

उनको पहले कह देता हूं, मुझे समय का भी ध्यान है और चेहरे भी याद रहेंगे। जब बोलने का वक्त आएगा तो ...(व्यवधान) आप बैठिए, बैठिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: मैं बिलकुल इजाजत नहीं दे रहा हूं। विराजिए आप विराजिए आप। मैं नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करूंगा कि आप ...(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए आप। बैठिए, बैठिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: बैठिए आप। जरूरी नहीं आप बार-बार इंटरवीन करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिए आप। आसन आपसे अपेक्षा रखता है अच्छे व्यवहार की, विराजिए। बैठिए आप, बैठिए आप। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): 000

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए आप। यह मेरा काम है, मुझे करने दीजिए आप। विराजिए, विराजिए ...(व्यवधान)

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): 000

श्री सभापति: ...(व्यवधान) आसन पैरों पर है, निर्देश मानिए। आप परम्पराओं का पालन करें। आप सारे वरिष्ठ लोग हैं, इतने दिन बाद तो जो पहली बार आये वह भी समझ गये होंगे कि आसन आपसे क्या अपेक्षा रखता है। मैं पुन: आपसे अपेक्षा रखता हूं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। सभापति महोदय, मैं इस सदन में बहुत पुराना सदस्य हूं और विपक्ष के नेता भी बहुत पुराने सदस्य हैं। कभी भी आसन के बारे में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कमेंट नहीं करता जो आसन की गरिमा और सम्मान के विरुद्ध हो। अभी जिस तरीके से माननीय सदस्य ने टिप्पणी की और जिस तरह से आवेश में बोले, उनको माफी मांगनी चाहिये और नहीं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। क्योंकि आसन की गरिमा, हम सबकी

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

गरिमा है, हम सब उनका सम्मान करते हैं, इसलिए माननीय सदस्य ने जो बोला है उसके लिये वह सदन में क्षमा प्रार्थी के रूप में क्षमा मांगें अथवा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बार-बार आसन आपसे आग्रह कर रहा है। आसन के पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं हैं जो आपके सहयोग के बिना इस सदन को परम्परा और शांत रूप से चला सके। आप सबका सहयोग होगा तो सदन चलेगा। मैं चुपचाप बैठा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से जो समय निर्धारित किया गया है, उसमें मैं अपनी तरफ से आपसे आग्रह करूंगा, आप विराज जाएं। यदि आपको इसी हल्ले-गुल्ले में ही बोलना है, यह भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, सारगर्भित चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा है अंकित नहीं हो रहा है। मैं फिर अपेक्षा करता हूं कि यह आसन तब तक गरिमामय है जब तक आप आसन की गरिमा बनाये रखेंगे। मैं पुन: आपसे अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, विनम्र आग्रह करता हूं, अपेक्षा रखता हूं आपसे, मैं भी पिछले 30 वर्षों से इस सदन में बैठ रहा हूं। मैं भी आपकी उम्र में रहा हूं लेकिन मेरा तजुर्बा मुझे आज इस बात के लिये प्रेरित करता है कि आप और मैं मिलकर पूरे राजस्थान में एक संदेश देने में कामयाब रहें कि पूरा सदन राजस्थान के उन बच्चों के लिये जो गरीब परिवार के हैं, जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, उनको सरकारी स्कूल में कैसे अच्छी शिक्षा मिले, आप इस पर सारगर्भित चर्चा करें। पूरे राजस्थान की तरफ से कल एक मैसेज आना चाहिये कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात से चिंतित थे और उन्होंने आज सारगर्भित चर्चा करके इस बात को साबित किया है कि उनके भविष्य का फैसला राजस्थान की सरकार और प्रतिपक्ष, दोनों मिलकर करेंगे और उनके हित में करेंगे। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं, मुझे बार-बार आपको इंटरवीन नहीं करना पड़े, बार-बार नहीं टोकना पड़े। मेरा यह विनम्र आग्रह है, कृपया आप शांत भाव से बैठें। जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनको भी सुनें और मन में एक संकल्प लेकर बैठें। आप पैसे वाले हैं, आपके बच्चे उन सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, मैं सबको जानता हूं लेकिन उन परिवारों के बारे में आप सोचिए जिनके बच्चे मजबूर हैं उन स्कूलों में जाने के लिये जो सुबह से लेकर सायंकाल दरी पर बैठकर अपने घर आ जाते हैं। स्कूल में जाकर झाडू लगाते हैं। न वहां पर चपरासी है, न शिक्षक है। आप क्या चाहते हैं वह बच्चे वैसे ही रहें? फिर हम किस बात की सेवा का संकल्प लेकर

(श्री सभापति)

यहां आये हैं? प्लीज, मैं अंदर से आहत हूं इस बात से। शिक्षा जैसे अहम विषय पर, मैं अंदर से आहत इस बात के लिये हूं कि आप इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। प्लीज, शांत भाव से बैठें और माननीय श्री देवनानी जी, आप अपनी बात कहें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, इंटीग्रेशन के साथ स्कूलों का स्टेटस बढ़े, आदर्श हो, उत्कृष्ट स्कूल करने का हमने तय किया। हर पंचायत में कम से कम एक आदर्श स्कूल बने, एक उत्कृष्ट स्कूल बने। मैं यह नहीं कहता कि पूरे बन गये, यह लगातार एक प्रक्रिया का अंग है। लेकिन हमने ईमानदारी के साथ उसको बनाने का प्रयत्न किया और उसका लगातार क्रम जारी रखेंगे तो इन गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। हमने स्मार्ट क्लास रूम बनाने की शुरूआत की है, स्मार्ट क्लास रूम बनने शुरू हुए हैं। यह सब चीजें होनी शुरू हुई हैं लेकिन इसको जारी रखने की आवश्यकता है। फिर स्टेटस बढ़ाने के लिये आपने जल्दबाजी में सोचा कि बीजेपी की नकल करें, तो आपने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले। खोले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसकी व्यवस्था तो करो। हमने भी स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल खोले। स्वामी विवेकानंद माडल स्कूल में हमने 6-6 करोड़ रुपये लगाये। नई अच्छी बिल्डिंग बनी, बच्चों को सीबीएसई से जोड़कर उसको पढ़ाने की व्यवस्था की। एक जिले में जो एक हिन्दी मीडियम का स्कूल था, उसे रातों रात आपने अंग्रेजी मीडियम का स्कूल कर दिया। वहां न बैठने की व्यवस्था है, हिन्दी मीडियम के बच्चे जो पढ़ रहे थे उनका क्या होगा? कह दिया कि पास के स्कूल में चले जाओ। पास में स्कूल है या नहीं है, इसकी भी चिंता नहीं की। कमरे हैं या नहीं हैं, इसकी भी चिंता नहीं की। इस प्रकार जल्दबाजी में केवल नकल से कोई काम नहीं होता। मंशा कितनी भी अच्छी हो लेकिन आप उसके लिये बजट तो रखो, उसकी व्यवस्थाएं तो ठीक ढंग से रखो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

(13.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा तब चलती है जब बजट बढ़ता है। हमने 2017-18 से लेकर 2018-19 में शिक्षा पर बजट बढ़ाया था 33.41 परसेंट और आपने अभी कितना बढ़ाया है, आपने बढ़ाया है 10.52 परसेंट। इस 10.52 परसेंट से क्या होगा, यह तो जो स्टाफ हैं, उनके इंक्रीमेंट में ही चला जाएगा या आपने जो नये पद सृजित किये हैं, उनके वेतन में चला जाएगा।

(श्री वासुदेव देवनानी)

आपका एक पैसा भी कहीं परिवर्तन के लिये नहीं लगेगा। हमारे टाइम पर टोटल बजट का शिक्षा पर बजट 18.4 परसेंट था और आपने जो किया है, वह 18.11 प्रतिशत है। यहां टोटल बजट का प्रतिशत भी घटा दिया। आपने शिक्षा पर बजट घटा दिया, उच्च शिक्षा पर घटा दिया तो आखिर कैसे होगा।

आपने घोषणा तो की है कि 14 हजार से अधिक कक्षा-कक्ष बनाएंगे। प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय बनाएंगे और केवल 23 भवनों का निर्माण करेंगे और 83 भवनों की मरम्मत करेंगे। हमने क्या किया, 86 हजार से अधिक कक्षा-कक्ष बनाये। 25,1572 नवीन स्कूल भवन बनाये। आप तो 23 बनाने के लिए जा रहे हो। 8613 शौचालय बनाये। आपने क्रमोन्नत के लिए बजट में क्या प्रोविजन रखा है कि 50 नये प्राइमरी स्कूल खोलेंगे। 60 प्राइमरी स्कूल से यूपीएस बनाएंगे। 100 यूपीएस से सैकण्डरी और 500 सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी। हमारे समय में क्या हुआ? आप जरा आंकड़े निकालो, आपके विभाग के ये तथ्य हैं। मैं अपनी ओर से एक शब्द नहीं जोड़ रहा हूं। हमने 6556 स्कूलों को सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी किया। इसके साथ आपने 2009-10 से 2013-14 तक केवल 1323 किये। कहां 1323 और कहां 6556, आप जरा तुलना तो करें। 888 स्कूलों को सैकण्डरी स्कूल बनाया, 157 को यूपीएस बनाया। आप 50-60 करके ही अपने में ही गुणगान करेंगे कि हमने बहुत कुछ शिक्षा के लिये किया है।

सभापति महोदय, हमने एक ऐतिहासिक काम किया कि आंगनबाड़ियों को स्कूल के साथ जोड़ा। उन आंगनबाड़ियों के जुड़ने के कारण आज जो बच्चा प्री-प्राइमरी से आना शुरू होता है, वह स्कूल के वातावरण में ढलने लगता है। नई शिक्षा नीति का जो प्रारूप बना है, उसमें हमारे इंटीग्रेशन को जोड़ दिया गया है। स्टाफ पैटर्न को उसके साथ जोड़ा है। नया जो फार्मूला है 5+3+3+4 का, 5 का मतलब प्री-प्राइमरी, एल.केजी, हायर केजी, पहली और दूसरी, इस पांच का यूनिट बनेगा। तीसरी, चौथी, पांचवी का यूनिट बनेगा। छठी, सातवीं, आठवीं का एक यूनिट होगा। नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं का एक यूनिट होगा। इस प्रकार से शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिये शिक्षा नीति में जो प्रारूप आया है, वह निश्चित रूप से हमारी सोच के आधार पर है कि आंगनबाड़ी को उसके साथ जोड़ें।

अब स्कूल में स्वच्छता की बात करें। माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने दिशा दी और विद्यालयों को स्वच्छता की ओर प्रेरित किया। हमने

(श्री वासुदेव देवनानी)

नियमित धनराशि दी। शिक्षकों, अभिभावकों का हमें सकारात्मक सहयोग मिला। स्वच्छ विद्यालयों की दृष्टि से पूरे भारत में राजस्थान तीसरे नंबर पर आया। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। शिक्षा मंत्री जी आपको समझना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि आज पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। यदि आपने अपने मस्तिष्क को साफ नहीं रखा तो जनता आपको जल्दी साफ कर देगी। इस प्रकार की सोच आप रखिये।

माननीय सभापति महोदय, स्कूल में बच्चे आते हैं। अध्यापकों की बात होनी चाहिए। सफाई की बात हो गयी, बिल्डिंग्स की बात हो गयी, लेकिन स्टाफ पैटर्न। आज तक क्या था, कौन अध्यापक, कितने कहीं। 100 विद्यार्थी हैं तो दो अध्यापक हैं। कहीं 5 विद्यार्थी हैं तो 10 अध्यापक हैं। सब्जैक्ट का अध्यापक नहीं, अंग्रेजी वाला गणित पढ़ा रहा है। इसलिए हमने स्टाफ पैटर्न बनाया। आरटीई के तहत जितने पद होने चाहिए, उतने रखे। पहले अपर प्राइमरी स्कूल में सब्जैक्टवाइज अध्यापक नहीं होते थे, उसके लिए हमने तय किया, लेकिन इन सबके साथ हमने नई नीतियां कीं। आपने तो बड़े जोर-शोर से एक भाषण दिया था कि लाखों रिक्तियां हैं। शिक्षा मंत्री जी, जब यहां बैठते थे और इन्होंने कितनी घोषणा करवायी है, 21 हजार 500, यानी रिक्तियां कितनी हैं, जरा व्यावहारिकता समझो। आप पता नहीं, उसको कब तक भरोगे। आपका पुराना रिकार्ड अच्छा नहीं है। 1998 से 2003 का, 2008 से 2013 तक, यदि बताएंगे कि कितनी नियुक्तियां कीं तो अपने आप स्थिति साफ हो जाएगी। हमने 1 लाख 48 हजार पद शिक्षा में भरे। आपको सूची चाहिए तो मैं सूची उपलब्ध करा दूंगा। उसमें से कुछ बचे थे, पोस्टिंग हमारे से नहीं हुई तो आप पोस्टिंग दे रहे हैं।

हमने कितनी पदोन्नतियां कीं। डीडी के पद केवल 8 या 9 हुआ करते हैं। हमने डीडी के पद 54 बनाए। डीईओ एक-एक जिले में एक-एक हुआ करता था, एक प्राइमरी में, एक सैकण्डरी में, डी.डी. के पद 33-33 किये। डीईओ 253, हमने ब्लाक लेवल तक डीईओ का पद सृजित किया है। प्रिंसीपल कितने लगाये, 13987, हैडमास्टर 4400, लैक्चरर का कितना प्रमोशन किया, 37948 और सैकिण्ड ग्रेड में 45883, इसके अलावा बाकी पदों में कुल 1 लाख 23 हजार पदोन्नति दीं। आप अपने रिकार्ड से आंकड़े उठाकर देख लें। इसमें एक भी कम हो तो बता देना, यानी इतनी पदोन्नतियां करने के बाद ...(व्यवधान) आपके पांच साल भी देखेंगे। अपन यहां मिलेंगे।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): फिर विद्यार्थियों का स्कूल में एनरोलमेंट बढ़े, नामांकन रहे, उसके लिए हमने सुबह विद्यार्थियों के लिए अन्नपूर्णा दूध की व्यवस्था की, जिसमें पहली से पांचवीं तक डेढ़ सौ एमएल और छठी, सातवीं, आठवीं को दो सौ एमएल। आपके आने के बाद आज स्कूलों में हैड मास्टर को दूध के पैसे देने के लिए आप राशि उपलब्ध नहीं करा रहे हो। सभापति महोदय, तीन-चार महीने हो गये। बच्चों के लिए दूध की कठिनाई हो रही है या फिर इनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गयी कि बच्चों के दूध की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं।

स्कूल की अवस्था क्या थी? स्कूल फैसिलिटी ग्रांट 5 हजार, 7 हजार और 12 हजार मिलती थी। उससे स्कूल में चाक और डस्टर खरीदना भी कठिन था। हमने आकर इसे स्कूलों में बच्चों के नामांकन के साथ जोड़ा। यदि 1 से 15 बालक हैं तो साढ़े बारह हजार रुपये, 16 से 100 तक हैं तो पच्चीस हजार रुपये, 101 से 250 हैं तो पचास हजार रुपये, 251 से 1000 हैं तो पिचहत्तर हजार रुपये और एक हजार से ऊपर हैं तो एक लाख रुपये तक की स्कूल फैसिलिटी ग्रांट हमने उपलब्ध करायी है, तब जाकर स्कूल की व्यवस्था ठीक हुई। इसी कारण से हमने पैसे की चिंता नहीं की है, हमने बाकी से सहयोग लिया। चाहे एमएलए, एमपी, जो उस समय थे और अभी भी जो हैं, उन्होंने खूब सहयोग किया। इसके साथ चाहे नरेगा से सहयोग मिला, डीएमएफटी से मिला। हमने लोन भी लिया। इस तरह से हमने स्कूलों के कमरों की रचना की। स्कूल में एक अच्छी परम्परा विद्यादान कोष भी हमने बनाया है। यानी एक व्यवस्था सुधरे। यह राजनीति का विषय नहीं हैं। इसमें बीजेपी और कांग्रेस नहीं आती लेकिन इस प्रकार व्यवस्था सुधारने की आज आवश्यकता हुई। इसके फलस्वरूप स्कूलों का नामांकन 12 लाख बढ़ा। आप जाकर अपना रिकार्ड चैक करेंगे तो आपको ध्यान आएगा लेकिन नामांकन तक ही सीमित नहीं रहे, गुणवत्ता भी बढ़ायी। आपके 2013-14 के बोर्ड के जो परीक्षा परिणाम हैं, वे 58 परसेंट हैं, 2017-18 में 76 परसेंट, 2018-19 में इससे आगे 80 परसेंट तक गये। 12वीं के रिजल्ट तो 91 परसेंट तक गये और 12वीं कला के जो रिजल्ट्स आये हैं, आप भी इस बार रिजल्ट्स निकालकर आये हैं। हालांकि, दो महीने में रिजल्ट कोई आपके कारण नहीं बढ़े। ये तो पुराने हैं। आपके तो हम अगले साल मूल्यांकन करेंगे। प्राइवेट स्कूल से भी अधिक हमारी सरकारी स्कूलों के आज रिजल्ट आये हैं। बच्चियों के बारे में

(श्री वासुदेव देवनानी)

चिंता की जाती थी। बच्चियों के स्कूलों में क्वालिटी नहीं बढ़ती। जो बच्ची 75 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करती है, उसको गार्गी पुरस्कार देते हैं। आपके समय वह संख्या केवल 44 हजार थी और इस साल वह संख्या 1 लाख 46 हजार है। यह हमारी बच्चियों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। ये सब हमारे प्रयत्नों के आधार पर हुए।

फिर डिजिटलाइजेशन, हमने डिजिटलाइजेशन करना शुरू किया। कल्ला जी बैठे हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं। ये शिक्षा मंत्री रहे हैं। आपके डायरेक्ट्रेट के हालात तो पता है। आज भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। उसको लगातार सुधारने की आवश्यकता है। हमने भी किये हैं। नये शिक्षा राज्य मंत्री जी भी करेंगे, लेकिन वहां पर जो टीचर्स का रिकार्ड था, वह रिकार्ड एक बस्ते में बांधकर लाते थे। कौन, कहां काम कर रहा है, पता ही नहीं है। जब ट्रांसफर हो जाए, प्रमोशन हो जाए तो ढूंढना पड़ता था। हमने इसका डिजिटलाइजेशन किया शाला दर्पण और शाला दर्शन के माध्यम से। शाला दर्पण में 13 हजार 886 स्कूलों के 46 लाख विद्यार्थी और 2.06 लाख अध्यापकों का रिकार्ड है। शाला दर्शन में 49 हजार स्कूलों के 39 लाख विद्यार्थियों के और 1.70 लाख अध्यापकों के रिकार्ड हैं। एक क्लिक पर सारा पड़ा है। जिसका चाहिए वह एक क्लिक पर है। इसका डुप्लीकेशन नहीं हो सकता कि विद्यार्थी वहां भी शो कर रहा है और यहां भी शो कर रहा है। आंकड़े हम विधान सभा में दे रहे हैं या कहीं और प्रदर्शित कर रहे हैं। ई-ज्ञान पोर्टल भी लगाया। पेरेंट्स की समस्याएं भी उनसे मांगी और हमने वहां पर क्यू-आर कोड भी शुरू किया। बच्चे को क्यू -आर कोड क्लिक करते ही रेफरेंस सामग्री मिल जाती है। यही डिजिटलाइजेशन हमने करना शुरू किया।

फिर हमने तय किया कि प्रशासनिक ढांचे का सुदृढ़ीकरण करेंगे। हमारे शिक्षा मंत्री बैठे हैं। स्थिति क्या थी? प्राइमरी स्कूल की कोई मानिटरिंग ही नहीं। जब चाहे तब आओ, जब चाहे तब चले जाओ। हमने पीईईओ यानी पंचायत एलीमेंट्री एजुकेशन आफिसर बनाया। सीनियर सैकण्डरी स्कूल के प्रिंसीपल को इसकी जिम्मदारी दी, उससे प्राइमरी स्कूल की उपस्थिति भी ठीक होने लगी। अध्यापक भी जाने लगे, जिसके आधार पर एक अच्छी मानिटरिंग होकर गुणवत्ता और उपस्थिति में सुधार आया है। मान्यता में बहुत गड़बड़ होती थी। हमने आनलाइन मान्यता शुरू की।

(श्री वासुदेव देवनानी)

पेरेन्ट्स को जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक स्कूल व्यवस्थित नहीं चल सकता। हमने पेरेन्ट्स-टीचर मीट शुरू किया तीन महीने में। उसमें भी मदर्स को जोड़ा जाए। चार में से एक मदर्स टीचर मीट को शुरू किया। कई प्रकार की व्यवस्थाओं में सुधार करते-करते आज स्कूल इस स्थिति में आए हैं कि पेरेन्ट्स इसमें अपने आपको ज्यादा जोड़ने का प्रयत्न करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार से अपेक्षा थी कि हम नंबर दो तक तो ले आए हैं, अब आप इसको नंबर एक तक ले जाने के लिए लगें। लेकिन यह तब होगा जब सकारात्मक प्रयास हो लेकिन आप उलझ गये राजनीति में। आपने केवल पाठ्यक्रम बदलना, साइकिल का रंग बदलना, इसमें अपने आपको उलझा दिया। हमारी सरकार द्वारा किये गये प्रयासों को बदलने में, आपने तय कर लिया 6 माह में आपने 6 प्रहार किये। आपको जितने प्रहार करने हों, आप करना। हम भी उसका जवाब देंगे, जनता भी जवाब देगी, अभिभावक भी जवाब देंगे। पाठ्यक्रम बदलना सरकार का अधिकार है। सरकार बदल सकती है लेकिन सरकार की बदलने की प्रक्रिया तय है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत है कि बोर्ड का चैयरमेन सबसे पहले सिलेबस रिव्यू कमेटी बनाएगा। फिर वह करिकुलम कमेटी को दिया जाएगा। करिकुलम कमेटी, subject decides the syllabus, उसके बाद वापस करिकुलम कमेटी एप्रूव करेगी, उसका बोर्ड एप्रूव करेगा। उसके बाद सब्जैक्ट आथर्स उसकी किताबें लिखना शुरू करेंगे। आपने सारी प्रक्रिया को धता बताकर बदलाव करना शुरू किया क्योंकि आप राजनीति करते हैं। 2009 में आपने क्या किया, यहां माननीय एक मंत्री जी और बैठे हैं, क्या हुआ 2009 की बोर्ड की किताबों में सुभाष चन्द्र बोस, डाक्टर अम्बेडकर, राम और श्याम शब्दों पर काली स्याही पोती गयी। अभी लाया नहीं हूं, मैं आपको दिखा सकता हूं। यह सत्य है। मैंने पिछले समय दिखाया है। मैं लाऊंगा। आपको बदलाव करना क्या है? इस प्रकार की सोच लाने वाले, आगे बताएंगे। स्याही फेरी और यहां तक कि, मेरे पास पूरा रिकार्ड है, उसके बाद महाराणा प्रताप की बात करें। महाराणा प्रताप पर...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो-तीन मिनट में बात समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): दस मिनट लगेंगे पाठ्यक्रम की बात पूरी करने में। महाराणा प्रताप का, आपने महान बनाने से पहले स्टेटमेंट में मना किया। मैं बधाई दूंगा प्रताप सिंह जी को भी और अन्य माननीय

(श्री वासुदेव देवनानी)

सदस्यों को भी जिन्होंने पूरी तरह इसका दबाव बनाया। तब महान बनाने में इन्होंने मान लिया। अब कहते हैं कि हम उसे बढ़ा-चढ़ाकर लिख रहे हैं। बढ़ा-चढ़ाकर तो लिख रहे हो लेकिन किसके दबाव में? लोक सभा चुनावों में जो राष्ट्रवाद की जीत हुई है, उससे आपकी मनःस्थिति बदली है जिसके कारण से आप उसको रख रहे हैं। नहीं तो आप सत्तर साल तक...

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): मैं कोई इनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। एक जरूरी बात है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति महोदय, यह कहना कि हमारे दबाव में महाराणा प्रताप महान बने हैं, इन्होंने बनाया है क्या महान? महाराणा प्रताप को आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, किसी का अंकित नहीं होगा। किसी का अंकित नहीं होगा, विराजिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री सभापति: आसन पैरों पर है, आप विराजिए। कोई भी शब्द जो परम्पराओं से हटकर हैं, वह अंकित नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): वीर सावरकर, जिसको दो-दो बार आजीवन कारावास हुआ, उसको पुर्तगाल का पुत्र बताना, कितना हास्यास्पद है।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए। समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इस वीर ने कितने कष्ट सहे देश के लिए। उस क्रांतिकारी के पाठ पर आपने कई आपत्तियां दर्ज कीं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं उसके विवरण में नहीं जाता लेकिन इस तरह का अंग्रेजों के समय, रामप्रसाद बिस्मिल ने भी पत्र लिखा था। महात्मा गांधी का, रणनीति के तहत पत्र लिखे जाते हैं, सहयोग के। उसी तरह वीर सावरकर ने भी लिखा तो आपको वीर सावरकर को महान और क्रांतिकारी बनाने में क्या तकलीफ है?

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): वीर सावरकर की तो इंदिरा जी और गांधी जी ने सराहना की है। चाहिए, तो मैं कोट कर सकता हूं।

श्री सभापति: श्री राजकुमार शर्मा। डा. राजकुमार शर्मा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इनको यह ही नहीं पता कि जौहर और सती प्रथा क्या होती है? उस सती प्रथा को मना करने के बाद वापस स्वीकार किया।

श्री सभापति: विराजिए आप। विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री सभापति: बार-बार उत्तेजना पैदा करवा रहे हैं आप। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): दो मिनट में करूंगा। इन्होंने वैदिक गणित के बारे में ...(व्यवधान) और आज कांग्रेस वैदिक शिक्षा बोर्ड विज्ञान व संस्कृति को जन-जन तक पहुंचाने के लिए करने जा रही है। वैदिक गणित से तो पकोड़े तलने वाले नहीं, महान व्यक्ति तय होते हैं। फिर आपने एक बहुत बड़ी बात कहीं। आपने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को कहा, उसमें लिखा कि कुत्सित राजनीतिक दल की विचारधारा को पोषित किया गया है। यह कौन है कुत्सित राजनीतिक दल? यह जरा बताएं। बड़ी शर्मनाक बात है। आज लोकतंत्र में हम जीतकर आए हैं। कुत्सित राजनीतिक दल कहना, यह आप अन्याय करेंगे, हम नहीं सहेंगे।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए। डा. राजकुमार शर्मा। माननीय सदस्य विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। विराजिए आप।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री सभापति: कन्क्लूड कर दिया मैंने। समय बार-बार दे दिया। आप विराजिए। मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। मैंने दूसरा नाम पुकार दिया। प्लीज विराजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिए। विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिए। आसन आपसे अपेक्षा रखता है। आप स्वयं अध्यापक हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। शिक्षक हैं आप हम आपसे शिक्षित होने वाले हैं। प्लीज सहयोग करें। विराजें। डा. राजकुमार शर्मा।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर अपने विचार रख रहा हूं। हालांकि माहौल ऐसा बना दिया कि आपके इतनी शिक्षा देने के बाद भी जनहित के बारे में, गरीब बच्चों के बारे में आपने जो बोला हमने तो अक्षरश: उसका पालन किया लेकिन चलो अब उनका गला खराब हो गया। पानी पीकर जरूर आना गुरुजी वापस। सभापति महोदय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखकर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार दोनों को शिक्षा के दायित्व को निभाने के लिए पाबन्द किया। शिक्षा को हमने मूल अधिकारों में सम्मिलित किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी शासन की प्राथमिकता होती है। चाहे वह इनका शासन हो या हमारा शासन हो। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है और शास्त्रों में यहां तक कहा कि वह पशु के समान है अगर अशिक्षित है। यह हम सब लोग जानते हैं और बचपन से हमारे पिताजी एक बात कहते आए हैं कि पढ़ो क्योंकि पढ़ने के बाद आपने शिक्षा ग्रहण कर ली तो उसको संस्कृत में लिखा है-

न चौरहार्यं न च राजहार्यं

न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी।

(डा. राजकुमार शर्मा)

व्यये कृते वर्धते एव नित्यं

विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्॥

किसी के समझ में नहीं आया तो बता देता हूं कि विद्या वह धन है, जिसको न तो चोर चोरी कर सकता है, न राज उस पर कोई डाका डाल सकता है, न ही भाई बंटवारा कर सकता है, न ही शिक्षा में भार है, ज्ञान में भार नहीं है। खर्च करने पर एकमात्र शिक्षा का ज्ञान ही है जो बढ़ता है, बाकी सब तो घटता है, इसलिए सब धनों में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा को माना है।

शिक्षा से किसी भी देश, प्रदेश की उन्नति की पहचान होती है, पूरे विश्व के अंदर कि किस देश के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है या नहीं मिलती है। विद्या से ही मनुष्य में योग्यता और जीवन के संसाधन प्राप्त होते हैं। इसलिए कहते हैं कि-

विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रताम्।

पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम् ॥

यह संस्कृत में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि विद्या से नम्रता आती है, नम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से कर्तव्यों का निर्वहन होता है और कर्म से सुख की प्राप्ति होती है।

ये सब चीजें आज के वर्तमान के परिदृश्य में कहां खड़ी हैं, यह हम सब लोगों के लिए विचारणीय बिंदु है। माननीय सभापति जी ने दो बार, तीन बार सदन में खड़े होकर अपने आसन से यह सब बातें हम सदस्यों को बोली हैं। मेरे पूज्य गुरुजी और मेरे ही नहीं मेरे जैसे लाखों युवाओं के पूज्य गुरुजी आचार्य द्विजेश कुमार जी हमेशा कहते थे, जब मैं 1996-97 में उनके पास पढ़ता था, उस समय इंग्लिश में एम.ए. थे, आजादी से पहले के। वह कहते थे कि education is the most powerful weapon, which you can use to change the World. यह उस समय बोलते थे 1996-97 में। अभी क्या कह रहे हैं, वह अभी कह रहे हैं क्योंकि नेल्सन मंडेला ने कही थी यह बात, बार-बार उस वाक्य को कोट करते थे। लेकिन अब वह उस बात के आगे चाणक्य नीति पर आ गये। अब वह चाणक्य को कोट करने लग गये कि जिसके पास धन नहीं है, वह गरीब नहीं है। वह तो असल में रईस है जिसके पास विद्या है लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है, वह तो सब प्रकार से निर्धन है। विद्या कौनसी, संस्कारोन्मुखी। संस्कारयुक्त शिक्षा अगर हम बच्चों को देंगे तो हमारा हिन्दुस्तान बचेगा, ऐसा हमारे गुरु जी कहते हैं।

(डा. राजकुमार शर्मा)

आज जिस प्रकार के हालात बने हैं, आपने देखा, अभी आदरणीय गुरु जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। वह भी एक शिक्षक रहे हैं और मैं भी एक शिक्षक का लड़का हूं। गर्व के साथ कहता हूं कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। आज भी हमारे सरकारी स्कूलों की अच्छी स्थिति है, लेकिन कोई यह कहे कि हमारे आने के बाद ही सब कुछ हुआ है, तो गलत है। हमसे पहले, जब से देश आजाद हुआ है, जो भी प्रधान मंत्री रहे हों, जो भी मुख्य मंत्री रहे हों, जो भी शिक्षा मंत्री रहे हों या जिस भी विभाग के मंत्री रहे हों, सबने इस प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है लेकिन दुर्भाग्य है कि उस पाइंट पर तो आऊंगा जो अभी आदरणीय पूर्व मंत्री जी बोल रहे थे।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश को आजाद हुए सात दशक हो चुके हैं। जिस प्रकार से शिक्षा का चल रहा है, चर्चा चल रही है, आए दिन समाचार पत्रों में आप देखते होंगे कि जो भी अपराध हो रहे हैं उसमें जो बच्चे शामिल हैं वह या तो स्कूल के हैं या कालेज के हैं। ज्यादातर टैक्निकल कालेज के बच्चे हैं। अब वर्तमान समय में शिक्षा ज्ञान देने का माध्यम नहीं रहा, शिक्षण संस्थान अब सिर्फ शिक्षा माफिया बन गये।

मैं हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने गरीब बच्चों की पीड़ा को समझा। जैसा अभी आपने फर्माया कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर अपने बच्चे कहां से पढ़ पाएंगे, गरीबों के बच्चे कहां से पढ़ पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं डा मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में गरीब, आदिवासी एवं पिछड़े तबके को मुख्य धारा में लाने के लिए अपने आपको कमजोर समझने वालों को संबल देते हुए शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 को लागू किया जिसको तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2010 में राजस्थान में भी लागू कर दिया।

इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री मंत्री महोदय ने संकल्प दोहराया शिक्षा नीति का कि हम शिक्षा नीति बनाएंगे, इस विचार का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से और हमारे शिक्षा मंत्री महोदय से, विशेष तौर से उच्च शिक्षा और कला संस्कृति मंत्री, तीनों मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं। शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा से संबंधित सभी विषयों का गहन अध्ययन कर शिक्षक, शिक्षाविद् और शिक्षार्थी, मैं तीनों का नाम लेना चाहूंगा। बदलते परिवेश में आज शिक्षक

(डा. राजकुमार शर्मा)

शिक्षाविद् और शिक्षार्थी तीनों को लेकर सदन को गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। शिक्षक समाज का आईना होता है, उन्हें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारी को समझना होगा, तभी देश और समाज का विकास होगा। जरूरत है कि बच्चों को संस्कारयुक्त सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मिले और समाज से कुरीतियां दूर हों। माननीय सभापति महोदय, यह तभी सम्भव है जब हमारा शिक्षक चाणक्य की भूमिका में रहेगा। अगर वह चाणक्य की भूमिका में रहेगा तो निश्चित रूप से वह बच्चा आगे बढ़ पाएगा। अभी माननीय पूर्व मंत्री जी ने खूब बातें कहीं, आप खेल पर कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): समय देते तो बोलता।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अभी छोड़ो। आप बोले तो मैं बीच में नहीं बोला।

श्री सभापति: अपने स्थान पर जाइये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आपने संस्कृत शिक्षा पर कुछ नहीं बोला। क्या हालत हो गयी संस्कृत की। आपके राज में क्या हो गयी, संस्कृत और संस्कृति पर आप लोगों ने पूरे देश को गुमराह किया। संस्कृत और संस्कृति के नाम पर भाजपा ने पूरे देश को गुमराह किया। आपने संस्कृत पर एक शब्द तक नहीं बोला। अगर मैं आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के शब्दों पर जाऊं तो आपको +++। भाई साहब यह बोलते हैं जब भावुक होते हैं कि +++ +++, आपको भी आनी चाहिए। उप नेता जी ...(व्यवधान) क्योंकि आपके पड़ौस में बैठते हैं, आपको बताना चाहिए उनको।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, मैंने इनको +++ शब्द नहीं कहा। व्यक्तिगत कह रहे हैं +++ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इनको क्या अधिकार है। संस्कृति मंत्री दूसरे थे, मैं संस्कृति मंत्री नहीं था।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): संस्कृति मंत्री इसका उत्तर देगा।

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज विराजिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): चलो, वापस ले लेता हूं। गुलाब जी भाई साहब को गुस्सा आता है, इसलिए मैंने बोल दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए आप।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं कहना चाह रहा हूं कि आपका पूरे पांच साल जो चर्चा में रहा उस नीति की तो आपने बात ही नहीं की। हर उद्योग को देखा हमने राजस्थान में, तबादला उद्योग पहली बार देखा। आपने विकसित किया, पूरा तबादला उद्योग लगाया, +++ मेरा खुला आरोप है, सबूत चाहिए तो सबूत भी दूंगा उसके अंदर। मैं आपको सबूत भी दूंगा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मेरे पास सबूत है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): एक भी हो तो इस्तीफा ...(व्यवधान) व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं।

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय यह इस तरह से बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इतना बढ़िया सिस्टम ...(व्यवधान) आरोप लगा रहे हैं।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय पाइंट आफ आर्डर ...(व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह क्या तरीका हुआ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): पहले उनको बिठाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट आप विराजिए। जो भी वक्ता बोल रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र आग्रह है जब भी आपकी कोई आरोप लगाने की मंशा है, तो मेहरबानी करके नियमों में आइये, मैं ऐसे इजाजत नहीं दूंगा। ऐसे कोई शब्द अंकित नहीं किए जाएं जो आरोप के रूप में हो। कोई माननीय सदस्य किसी पर व्यक्तिगत आरोप और आक्षेप नहीं लगाएगा। सदन की परम्पराएं हैं, आपकी व्यवस्थाएं हैं, कार्य संचालन के नियम हैं, उनमें यह प्रावधान है कि किसी पर आरोप और आक्षेप आपको लगाना है तो आप नियमों में आइये, अगले को सूचना दीजिए, उसके बाद आरोप लगाइये। इसलिए खड़े-खड़े किसी पर आरोप लगाना कतई अच्छी परम्परा नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अब कोई भी आरोप नहीं लगाएंगे।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सभापति महोदय, आपके आदेश की पालना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पाइंट आफ आर्डर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: उनका अधिकार है, बोलने दीजिए। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आपके आदेश की पालना कर रहा हूं न, आसन की बात मान रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): उनको अधिकार नहीं है क्या ...(व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उनको अधिकार नहीं है क्या, यह गलत बात है।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें, सहयोग करें ...(व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट विराजिए। हां फर्माइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान नियमों के नियम 273 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह सदन नियमों से चलता है, प्रक्रियाओं से चलता है। आपने यह पुस्तक हमें दी है। नियम 273 में लिखा है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में प्रकिया...

श्री सभापति: बिना आपके मैंने स्वयं ने ही यह कह दिया कि कोई किसी पर आरोप नहीं लगाएगा और जिसको आरोप लगाना है वह नियमों में आएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप एक्सपंज करा दीजिए।

श्री सभापति: कह दिया। न तो कोई आरोप लगाएगा, न कोई आगे से इस तरह का अंकित होगा। मेहरबानी करें, इतनी बात कहने के बाद भी अगर आप गंभीर नहीं हैं...

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सभापति महोदय, आपकी बात मान ली, नियमों में आ जाऊंगा। नियमों से आऊंगा, सबूत के साथ आऊंगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय, आज की इस महती शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की आवश्यकता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे नहीं बोलें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): शिक्षा ज्ञान के लिए हो, जीवन ज़ीने के लिए नहीं हो। मानवता और प्रकृति के सृजन के लिए हो। विश्व के कल्याण और जीव-जन्तुओं के सह अस्तित्व के लिए होनी चाहिए इस शिक्षा नीति में स्वास्थ्य शिक्षा, आपत्तिकाल में आत्मरक्षा की शिक्षा।

सभापति महोदय, सूरत का वह मंजर याद दिलाना चाहूंगा, ऐसा खौफनाक मंजर जब हमने हमारे बेटे-बेटियों को वहां दस मंजिल से गिरते हुए, तड़पते हुए देखा। अगर हम हमारे बच्चों को आपत्तिकाल में आत्मरक्षा के गुर अगर नहीं सिखाएंगे तो इस तरह के हादसों से उन नौनिहालों का जीवन हम नहीं बचा पाएंगे।

पर्यावरण संरक्षण, रोजगारोन्मुख शिक्षा, संस्कार और संस्कृति की शिक्षा, राष्ट्र भक्ति और राष्ट्रीयता की शिक्षा। सभापति महोदय, राज्य में संस्कृत शिक्षा विभाग पृथक् से कार्यरत है जिसकी स्थिति विचारणीय है। विभाग के अपने अभाव, अभियोग हैं, परन्तु पूर्ववर्ती सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

मैं हमारे तीनों मंत्रियों से और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग को भी शिक्षा नीति में सम्मिलित किया जाना चाहिए, संस्कृत विभाग को भी। संस्कृत विभाग के मंत्री हमारे आदरणीय सुभाष जी भाई साहब बैठे हैं, इसको भी शिक्षा नीति में लाइये ताकि भला हो

(डा. राजकुमार शर्मा)

सके। यह वेद की बात कर रहे थे, ज्ञान की बात कर रहे थे, उनका हम संरक्षण कर सकें।

मैं मुख्य मंत्री जी को, हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी को, आदरणीय कल्ला साहब को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने सुपर30 फिल्म आई है उसको टैक्स फ्री किया। उसमें एक डायलाग है। जोरदार तालियां बजा दो, टैक्स-फ्री किया है। इसलिये कह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकरजी का विचार था, उस आनन्द कुमार का जो करैक्टर है, उसने उसमें निभाया है। गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देकर आई.आई.टी. तक भिजवाया है।

मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, निवेदन करना चाहता हूं, उसमें एक डायलाग है सभापति महोदय, कि सबसे बड़ा व्यवसाय शिक्षा का है। अगर किसी को कोई उद्योग लगाना है, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े-बड़े स्कूल खोलकर बैठे हैं। मैं तो एडमिशन कराने के लिये गया, पता चला कि उनकी है, मैंने कहा, फोन मैं तो नहीं कराऊंगा क्योंकि वे कह रहे हैं कि आप बाहर जाइये यहां से। जिन्होंने शिक्षा का व्यवसाय बना लिया, मैं उनके लिये निवेदन करना चाहूंगा कि निजी विद्यालयों और महाविद्यालयों की जो मनमानी चल रही है, सभापति महोदय, सदन इस पर गम्भीर विचार करे, चाहे पक्ष और विपक्ष के हों, इस दादागीरी को रोकना चाहिए।

सभी निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आर.टी.ई. के माध्यम से उनको एडमिशन देने थे। निजी विद्यालय, जो बड़े विद्यालय हैं, जो एप्रोच वाले हैं, जिन्होंने उद्योग-धंधा लगा रखा है, वे नहीं मानते। सभापति महोदय, अगर मान भी लेते हैं तो उनका एक अलग तबका दिखता है कि यह बच्चा आर.टी.ई. के माध्यम से प्रवेश होकर आया है तो उस संस्था का प्रधान, संस्था का मालिक उस बच्चे को बार-बार टार्चर करते हैं, उसके माता-पिता को टार्चर करते हैं और छोटे से बच्चों में भी यह भावना आ जाती है कि इनका सलेक्शन गरीब बच्चों की योग्यता के ऊपर हुआ है।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार ने कल एक डिसीजन लिया। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जयपुर स्थित एक स्कूल की मनमानी की वजह से, सरकार के आदेश की अवहेलना करने की वजह से इन्होंने मान्यता रद्द की। आप धन्यवाद के पात्र हैं। उनमें डर रहना चाहिए। आप देख लीजिये कि वह गरीब का बच्चा आर.टी.ई. के

(डा. राजकुमार शर्मा)

माध्यम से, जो कांग्रेस सरकार ने फायदा दिया, स्कूल में पढ़ने के लिये जाता है, उसको टार्चर करते हैं, उसके साथ उसके माता-पिता को टार्चर करते हैं। वह इसलिये किया जाता है कि यह बच्चा चुपचाप यहां से छोड़ कर चला जाए। आपको पता है, कई बार तो ऐसा लगता है कि यह स्कूल या कोई संस्था नहीं है, यह तो कोई इस तरह का मॉल है जिसके अन्दर जूते भी यहीं लो, टाई भी यहीं लो, खाना भी यहीं खाओ। आप सोचिए कि छह दिन की छह ड्रैसें। आपां खाकी नेकर पैरता, बी पर कारी लगाकर जाता। आज छह दिन की छह अलग-अलग ड्रैसें। अगर हास्टल में रहता है तो नाइट की अलग ड्रैसें। वह गरीब आदमी कैसे पढ़ा पाएगा। इन्होंने, जिस प्रकार का लूटने का कार्यक्रम कर रखा है, मैं सदन में सभी दो सौ माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हम सबको इसको लेकर गम्भीर चर्चा करनी चाहिए।

सरकारी आदेशों की अवहेलना करते हैं। आप और मन में सोच लो, हमारे में से कोई भी इन स्कूलों में जाता है या फोन करता है, चाहे मंत्रीजी क्यों नहीं हों, आप लोग खुद क्यों नहीं हों, तो वहां पर कैसा व्यवहार होता है, अपनी अंतरात्मा से मान लेना, मैं कहना नहीं चाहता। हम लोग तो इसलिये ज्यादा ग्रसित नहीं हैं कि यूनिवर्सिटी के हम जो भी अध्यक्ष रहे हुए हैं, हमें तो पता है कि उसको किस तरह से काम लेना है। हमें तो आता है, लेकिन एक सामान्य एम.एल.ए. जाए, पढ़कर कि मैं विधायक बोल रहा हूं। वह अगला कहे पहले कि विधायक क्या होता है। आप सोचो, मैं बताना नहीं चाहता, किस-किस को क्या-क्या बोला हुआ है, सबका सुना हुआ है। हमारे बारे में तो इनको पता है कि इनको कुछ कह देंगे तो पता नहीं अब क्या होगा। यह सच्चाई भी है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपका और हमारा सम्मान तो करें। काम करें या न करें, लेकिन सम्मान तो करें। गये हुए को आदर के साथ तो बिठाएं। फोन करते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता। तीन स्कूल तो ऐसे हैं, उनको मैं सौ फोन कर चुका, बहुत सारे फोन कर चुके। फोन नहीं उठाते थे, जाकर सामने खड़े हो गये तो उन्होंने कहा, मैं इसको सस्पैंड करूंगी, इसने मेरे को बताया नहीं कि आपका फोन आया है और वह कह रहा है कि भाई साहब, मैंने कान के पास ले जाकर दे दिया कि आप बात कर लो। मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे आत्म-सम्मान के लिये उन करोड़ों बच्चों की तरफ देखो और कोई न कोई लगाम लगाओ इनके ऊपर।

(डा. राजकुमार शर्मा)

माननीय यातायात मंत्रीजी, आप यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं। दबंग नेता हैं। निजी स्कूल 40-50 किलोमीटर तक बकरी-भेड़ों की तरह उन बच्चों को ठूंस लेते हैं सुबह पहले, पांच बजे ही, 10-20 किलो लाद देते हैं। उसका वज़न पांच किलो और दस किलो का थैला लेकर सुबह स्कूल-वाहन में बैठता है। फिर 2-3 घण्टे के बाद दूसरे गांव में पहुंचता है। वहां से दो बजे वापस बैठता है और पांच बजे वापस आता है। वह क्या पढ़ाई करेगा। फिर कहते हैं कि मास्टर ने थप्पड़ मार दिया, बेहोश हो गया। वह बेहोश ही होगा, उसको होश कहां से आएगा। खाने को कुछ मिलता नहीं, पीने को कुछ मिलता नहीं। स्कूल के अन्दर उसको कोई शारीरिक व्यायाम कराया नहीं जाता। स्कूलों में धक्के दिलाते हैं।

आपको मैं और बता दूं कि कितने-कितने रुपये लेते हैं, वे लोग उन बच्चों से पांच से दस हजार रुपये तक फीस वसूल करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सी जगहों पर उनका फिटनैस् परमिट तक नहीं है। आपको एक अभियान चलाना चाहिए। विशेष तौर से हमारी शेखावाटी में तो आप अभियान चलाइये। उसके अन्दर खड़े होकर हम साथ देंगे। अभियान चलाओ कि परिचालक, महिला परिचालक, जो भी हैं, उनके पास लाइसेंस तो है, परमिट तो है। इनसे सरकार को गाड़ियों के परमिट-टैक्स लेना चाहिए, जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके।

आपको पता है कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, वे छोड़कर भाग जाते हैं। सभापति महोदय, हम लोग चले जाते हैं, बीच में तो हम लोग कोई मदद भले ही कर दो या पचास हजार रुपये, लाख रुपये जो गवर्नमेंट की तरफ से कलेक्टर सहायता करता है, वह भले ही कर दे। बाकी वह स्कूल अपनी जिम्मेदारी से तुरंत मुकर जाता है। कोई भी जन-प्रतिनिधि जाएगा, वे लोग गेट ही नहीं खोलते, बाउंसर बुला लेते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन पर लगाम लगानी चाहिए।

फीस निर्धारण, हमारी सरकार के समय हमारे पूर्व न्यायाधीश जस्टिस शिव कुमार शर्माजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। उन्होंने रिपोर्ट भी दे दी थी। सरकार बदल गयी, आप आ गये। आप लोगों ने भी उन सिफारिशों को लागू नहीं किया। मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जस्टिस शिव कुमारजी शर्मा ने जो सिफारिश की है, कृपा करके उन सिफारिशों को आप

(डा. राजकुमार शर्मा)

लागू करें ताकि स्कूल और शिक्षा, जो सेवा का माध्यम था, वह माफियाओं के चंगुल से हम निकालने में थोड़ा-बहुत तो कामयाब हो सकें।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, देखो, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन जो आरोप लगाये हैं उनका जवाब देने का अधिकार तो हमें होना चाहिए। महाराणा प्रताप, बचपन में गांव के अन्दर नाटक किया था। महाराणा प्रताप के बचपन का रोल किया था, बड़ा रोल मेरे पिताजी ने किया था। आज गांव का बच्चा-बच्चा, महाराणा प्रताप, सुभाष चन्द्र बोस, चन्द्रशेखर आजाद, महारानी लक्ष्मी बाई, इनके बारे में आप लोग हमें बताओगे। क्या पेटेंट करवा लिया आप लोगों ने। आज अगर हम कोई भगवा कपड़ा पहनकर आ जाएं तो आप लोग यह कहते हैं, आज हमारे कपड़े क्यों, आपने बनाये हैं क्या वे कपड़े, आपका पेटेंट है क्या। तिलक लगाकर आएं, मां-भारती की बात करें तो बोलें कि मां-भारती की आप बात कर रहे हो, हमारी भाषा बोल रहे हो। भारत माता की जय बोलें तो बोलें कि हमारी भाषा बोल रहे हो, अब भारत माता की जय भी आपसे सीखना पड़ेगा। हमने देख ली आपकी राष्ट्र भक्ति, जब जम्मू-कश्मीर में आपने पी.डी.पी. के साथ सरकार बनायी। आपकी राष्ट्र भक्ति देखी, जब गोवा के अन्दर जो हमारे एम.एल.एज. थे तब वे देशद्रोही थे और आपके वह कौनसी एक सफाई-धुलाई की मशीन है, उसमें दिल्ली से धोकर भेज दिया, वे देशभक्त हो गये! आपकी राष्ट्र भक्ति को हम समझते हैं, छद्म राष्ट्र भक्ति, छद्म। हमारे दिल में है, हमारे खून में है, हिन्दुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आपने तो राष्ट्र भक्ति, उस सीन को भी, एक फिल्म के अन्दर सन्नी देओलजी ने क्या बोल दिया, उनको भी टिकट देकर आपने भुना लिया कि जहां जाएं, वहां भाषण देना तो आये नहीं और कहे हिन्दुस्तान-पाकिस्तान, हिन्दुस्तान-पाकिस्तान। इस देश में क्या हो रहा है, मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है। इनसे किसी ने पूछा बालाकोट के बारे में बताओ सन्नी देओलजी। बालाकोट के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना कह रहा हूं हिन्दुस्तान जिंदाबाद था और रहेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या, सर?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सभापति महोदय, अभी तो।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, प्लीज। (व्यवधान) दो मिनट में बात समाप्त करें अपनी।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा पर राजनीति की बात की। (व्यवधान) शिक्षा पर राजनीति किसने शुरू की। मैं आपको लम्बी लिस्ट दूंगा, माननीय सभापति महोदय के आदेश को मानते हुए और मैं नियमों के तहत आऊंगा। तबादला नीति के अन्दर, उस उद्योग के अन्दर, जो विकलांग थे, जो विधवा महिलाएं थीं, जो गम्भीर बीमारी से पीड़ित थीं उनको दूर-दराज क्षेत्रों में भेज दिया गया। उसका कौन जिम्मेदार है? यह अपराध किसने किया? इस अपराध की जनता ने आपको सजा दे दी। उन्हीं की बददुआएं थीं कि आप लोग विपक्ष में जाकर बैठे हो।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने कहा कि पाठ्यक्रम में बदलाव, कब कहा हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने, महाराणा प्रताप के बारे में कब कहा। एक बार तो कहा, कैसे आरोप लगाये, माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे शिक्षा मंत्रीजी के ऊपर कि महाराणा प्रताप को हम लोग कम दिखाना चाहते हैं। किसकी ताकत है इस देश के अन्दर जो महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा को कम आंक ले। अब डोटासराजी के लिए, भूल गये क्या, जब हम पिछली बार थोड़े सामने बैठते थे, आप लोग किस तरह से, पता है न आप लोगों को, ये वे ही शिक्षा मंत्री हैं। इन पर आरोप मत लगाइये। हम सब लोग, हमारे सबके दिल में, जान में, जिसने इस देश की आजादी के लिये अपनी कुर्बानी दी, अपने बदन की कुर्बानी दी, अपनी जान की, अपने प्राणों की जिसने कुर्बानी दी। हम उसके परिवार को, जब तक हमारी सात पीढ़ियां, देश हमारा अखण्ड हिन्दुस्तान, जब तक देश हमारा जीवित रहेगा, तब तक उनकी यादें और स्वाभिमान जिंदा रहेगा।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें माननीय सदस्य, कन्क्लूड करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं कहना चाहता हूं। आज इन्होंने एक और बात कही।

श्री सभापति: समाप्त करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): देखो, मैं वैसे नहीं बोलता हूं। डिमाण्ड एक शिक्षा पर बोलूंगा और एक बोलेंगे तो आगे बोलूंगा।

श्री सभापति: समय-सीमा है। समय की सीमा है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय।

श्री सभापति: समय पर सबको बोलना है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): इन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें, बैठिये आप।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): नहीं, मैं पांच मिनट लूंगा। लास्ट पांच मिनट। स्वच्छता अभियान, बच्चों के दिमाग में आप लोगों ने यह बैठा दिया कि पहले तो हम गंदगी में ही पड़े रहते थे। मोदीजी के आने के बाद ही झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान शुरू किया है। हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, मास्टरजी आते ही डंडा लेकर कहते थे कि झाड़ू उठाओ और लग जाओ तो हम सारे के सारे बुहारी निकालकर पूरा कचरा बाहर फेंककर आते थे। किसने नहीं निकाली झाड़ू? राजेन्द्रजी गुढा, जरा इनको बता दो। सबने निकाली, अपन ने निकाली झाड़ू। स्कूलों के अंदर किसने नहीं निकाली?

मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो स्कूलें बंद कीं, आपका तो पता नहीं कि आपके दबाव में हमने पाठ्यक्रम रोका या नहीं रोका, बदलाव को रोका या नहीं रोका लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोगों ने आपको मजबूर किया कि जो स्कूलें आपने बंद की थीं उन बंद स्कूलों को आप चालू करें और जो स्कूलें पी.पी.पी. मोड पर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करें। माननीय सदस्य, एक मिनट में बात समाप्त करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सर, अभी तो बाकी है। पी.पी.पी. माडल, शिक्षा के अंदर पी.पी.पी. माडल कौन लाया? माननीय सभापति महोदय, आप संरक्षण दे दो, कुछ नहीं है, एक-एक पन्ने का है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। सबको रिबेट देना पड़ेगा।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): पी.पी.पी. माडल कौन लाया? किसके दिमाग की उपज थी? आप लोगों ने शिक्षा को भी निजी हाथों में देने का फैसला करने की कोशिश की लेकिन जनता का दबाव और हम जब विपक्ष में थे, हमारा दबाव था इस कारण से आपको अपनी जगह पर वापस आना पड़ा और आपको आदेश देना पड़ा।

माननीय सभापति महोदय, मैं पी.टी.आई. भर्ती के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए-विराजिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): 1100 पदों की पी.टी.आई. भर्ती आप करवाएं। नए पद सृजित करके पी.टी.आई. भर्ती आप करवाएं।

(डा. राजकुमार शर्मा)

महोदय, भर्ती में खेल का महत्व खतम हो गया है। आदिवासी क्षेत्र या राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के अनुसार हमारे आदिवासी एरिये के अंदर भी सरकार को स्पोर्ट्स स्कूल एकेडमिक खोलनी चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो पांच साल इन्होंने बिलकुल एकदम खड्डे में डाल दी थी वापस हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की है कि वह वापस आकार लेगी और धरातल पर आएगी।

शारीरिक शिक्षा, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। प्लीज सहयोग करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): इन्होंने योग की बात कही। इन्होंने कहा कि आपने ईर्ष्या की, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। यह 36 मिनट बोले हैं, यह तो अभी तक 20 मिनट ही बोले हैं। हमारे सदस्य ज्यादा हैं, आप हमारी पार्टी का समय इनको दें।

श्री सभापति: मुझे पता है कितने मिनट हुए हैं। आप विराजिए। माननीय मंत्री महोदय, विराजिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं हायर एजुकेशन की बात करना चाहूंगा। माननीय हायर एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में मात्र 80 ऐसे पूरे राजस्थान के अंदर अधिकारी हैं नोन टैक्निकल, उनको आप यू.जी.सी. का वेतनमान दे दो क्योंकि वह लोग, जब हमारी सरकार ने शिक्षकों, लाइब्रेरियन और शारीरिक शिक्षकों को यू.जी.सी. वेतनमान का लाभ दे दिया है तो कई स्टेट्स, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र इनके लोगों को यह यू.जी.सी. का वेतनमान मिल चुका है और आप इनको भी फायदा पहुंचाओ। मैं निवेदन करूंगा कि पिछली सरकार ने इनको लटकाये रखा। अबकी बार आप जब रिप्लाई करें तो कृपा करके इन 80 लोगों को राजस्थान में, यह आपको दुआ देंगे और मैं इतना कह सकता हूं कि हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, सरकारी महाविद्यालयों में कम से कम 70 से 80 प्रतिशत प्राचार्यों के रिक्त पद हैं, हमारी सरकार इस पर फैसला लेकर इनको भरें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करें। माननीय सदस्य, प्लीज विराजिए। प्लीज, प्लीज।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बस एक मिनट में विराजिए, प्लीज सहयोग करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): 1998 की भर्ती ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराजिए। आप बार-बार में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप विराजिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): एक मिनट, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा। मैं आरोप लगाऊंगा तो आपको साबित कर दूंगा।

1998 की भर्ती के बारे में मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि 1998 की भर्ती को लेकर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज आप सहयोग करें। अंकित नहीं होगा। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। नहीं, अब सभापतिजी ने मुझे बुलवा लिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप जल्दी अपनी बात को समाप्त करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 1998 के, यह शेखावाटी से जुड़ा हुआ मामला है 1998 के कम से कम 1100-1200 हैं, वैसे यह 7780 हैं, इनका भला कर दो या आज मना कर दो। यह इतने सालों से धरने पर बाहर बैठे रहते हैं, या तो आज इनको कुछ देना है सरकार की तरफ से तो हां कर दो, वर्ना शिक्षा मंत्रीजी से कहूंगा कि या इनको आज मना कर दो ताकि कम से कम यह लोग अपने घर पर जाकर बैठें तो सही कि हमारी सरकार की तरफ से यह नहीं मिला।

अब मैं लास्ट में एक लाइन बोलकर मेरी वाणी को विराम दूंगा। बजट की बहस के दौरान आपने शुरूआत की और आपने कहा हमारी सरकार की तरफ, विशेष तौर से माननीय मुख्य मंत्रीजी की तरफ कि-

"जिनके घर शीशे के बने होते हैं, वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते।"

(डा. राजकुमार शर्मा)

माननीय उप नेताजी, मैं इतना ही कह सकता हूं कि

''बेगुनाह कोई नहीं यहां पर सबके अपने राज होते हैं,

किसी के छुप जाते हैं और किसी के छप जाते हैं।''

धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात अभी कही और उन्होंने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं, वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, यह उनके स्वयं के लिए ही लागू होता है। वह जिस दल में बैठे हैं, उनके लिए लागू होते हैं।

वह तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि स्वच्छता अभियान जिस प्रकार से देश के प्रधान मंत्रीजी ने शुरू किया और स्वच्छ भारत मिशन को यहां पर डिस्कस करके कह रहे हैं कि यह क्यों शुरू किया? यानी, आज के समय में कोई भी जागरूक नागरिक इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ है कि यह एक इतना अच्छा अभियान है जो देश के प्रधान मंत्रीजी ने शुरू किया, आज गली मौहल्ले तक लोगों की अवेयरनैस हुई है, लोग जागरूक हुए हैं। कचरा न हो, गंदगी न हो उसके बारे में पूरी तरीके से प्रयास किये जाते हैं और उसमें काफी हद तक सफलता मिली इसलिए मैं तो देश के प्रधान मंत्रीजी को बहुत बधाई दूंगी कि उन्होंने यह स्वच्छता अभियान शुरू किया। नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, थोड़ा संशोधन करें, इसकी बुराई न करें बल्कि इसमें पढ़े-लिखे अच्छे लोग तारीफ ही करते हैं तो मैं आपसे भी यही चाहूंगी कि आप तारीफ करें। जो अच्छा काम होता है, उसकी हमेशा तारीफ करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आज सदन के अंदर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक जन घोषणा पत्र जारी हुआ। जिस जन घोषणा पत्र को चुनाव के समय में बड़े जोर-शोर से कहा था कि जैसे ही हम इलेक्ट होकर आएंगे तो इसको लागू करेंगे। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसको एक सरकारी दस्तावेज बना दिया। जैसा कल भी मंत्रीजी ने अपनी रिप्लाई में कहा था कि चीफ सैक्रेटरी को यह दे दिया गया और कहा कि इसी के अनुसार हमारी सारी पालिसीज बनेंगी और सारे काम होंगे लेकिन इस घोषणा-पत्र के अंदर जो दावे किये हैं उसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

जन घोषणा पत्र की बिंदु संख्या-4 में लिखा कि प्रदेश के सभी वर्गों की समस्त छात्राओं और महिलाओं की प्रारम्भ से अंत तक राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में सम्पूर्ण शिक्षा माफ करेंगे। अब सम्पूर्ण शिक्षा माफ करेंगे, यह बात इन्होंने कही।

माननीय सभापति महोदय, कल ही 18.07.2019 को एक अतारांकित प्रश्न मैंने पूछा था जिसका मुझे रिप्लाई मिला। प्रश्न मेरा है कि राजकीय महाविद्यालय में छात्राओं से प्रतिवर्ष कितना शुल्क लिया जाता है और किस-किस शीर्ष में कितना-कितना शुल्क लिया जाता है? आपको यह जानकार बड़ा आश्चर्य होगा कि बात तो कुछ और कही जाती है कि सम्पूर्ण शिक्षा माफ करेंगे लेकिन प्रश्न के जवाब में मुझे यह दिया गया है कि इसमें शुल्क लिया जाता है और ट्यूशन फीस को छोड़ दें तो इसके अलावा 71 ऐसे शुल्क हैं जो शुल्क लिये जा रहे हैं। यह जो 71 शुल्क हैं इनमें कई तरह के शुल्क, उनका अगर देखें तो इसमें न्यूनतम यानी जो प्रधानाचार्य अपने स्तर पर, कालेज के लेवल पर शुल्क को तय कर रहा है। मिनिमम पार्ट भी देखें तो उसमें 1160 हैं और मैक्सिमम 7900 तक के शुल्क स्टूडेंट्स से, गर्ल्स स्टूडेंट्स से कालेज में लिये जाते हैं और उसको वहां के प्रिंसिपल कालेज डिसाइड करते हैं।

माननीय मंत्रीजी, आप यहां पर विराजमान हैं तो छात्राओं को नि:शुल्क शिक्षा देने का जो दावा आप कर रहे हैं, वह केवल भ्रमित करने का दावा है। यह बहुत गलत है। आप दावा तो करें कि हम फ्री कर रहे हैं और फिर आप यह कह रहे हैं कि हम सम्पूर्ण शिक्षा को मुफ्त करेंगे। अब सम्पूर्ण शिक्षा का अगर लेते हैं तो उसमें तो मेडिकल एजुकेशन भी आता है, इंजीनियरिंग कालेजेज भी आते हैं, मैनेजमेंट के कालेजेज भी आते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज आते हैं तो क्या यह सारी शिक्षा को मुफ्त करने की बात कर रहे हैं कि छात्राओं की सम्पूर्ण शिक्षा मुफ्त करेंगे? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मेडिकल कालेज की भी गर्ल्स की फीस लग रही है, इंजीनियरिंग कालेज की गर्ल्स की फीस लग रही है, सारी चीजें हो रही हैं लेकिन यह जो सिर्फ इस प्रकार का जन घोषणा पत्र है, यह जन घोषणा पत्र मुझे लगता है कि असत्य का पुलिंदा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। केवल जनता को गुमराह करने के लिए उस समय यह छपवाया गया और दे दिया गया सरकार में कि इसकी पालना करो। कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं यानी खाने के दांत

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

और हैं, दिखाने के और हैं, ऐसा इसमें लग रहा है। इसका दूसरा नाम रख देंगे अपन।

सभापति महोदय, अब यह जो कह रहे हैं, आपकी जानकारी के लिये बता दूं एस.एफ.एस. के बहुत सारे कोर्सेज अपने यहां कालेजेज में चल रहे हैं। एस.एफ.एस. के कोर्सेज की पूरी फीस ली जा रही है। गर्ल्स को कहीं पर एस.एफ.एस. कोर्स के अंदर रिलेक्स नहीं किया है कि आपसे फीस नहीं ली जाएगी। एस.एफ.एस. की तो ट्यूशन फीस भी ली जा रही है, कम्पलीट फीस उसकी ली जा रही है।

दूसरा ध्यान मैं दिलाना चाहूंगी कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या-10 पर, जहां इन्होंने कहा सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु महाविद्यालय में कोचिंग क्लासेज खोले जाएंगे। अब यह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो हम पहले भी करवाते थे। हमारी सरकार में माननीय सभापति जी, एक दिशारी योजना शुरू की थी और इस दिशारी योजना में वर्चुअल क्लासेज होती थीं। क्लासेज के अंदर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी और इस ट्रेनिंग के अंदर मैंटल एबिलिटी और मैथेमैटिकल एबिलिटी की क्लासेज होती थी, उसमें स्टूडेंट्स को तैयारी करवाते थे लेकिन वह कोचिंग क्लासेज कालेज आवर्स में नहीं होती थीं। आज की वर्तमान परिस्थिति में कोचिंग क्लासेज चलाएं, अच्छी बात है, लेकिन उन कोचिंग क्लासेज को चला रहे हैं डे-आवर्स में, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कोचिंग क्लासेज चलेंगी और वही समय कालेज की रेगुलर स्टडीज का है। एक तरफ तो हाई कोर्ट के आदेश की पालना में हम लोगों ने कहा कि एट-लिस्ट 75 परसेंट अटेंडेंस हर स्टूडेंट की होनी अनिवार्य है। अब 75 परसेंट अटेंडेंस हो, यह भी जरूरी है और दूसरी तरफ आप कालेज के रैगुलर टाइम में कोचिंग क्लासेज चलाएंगे। स्टूडेंट कोचिंग क्लास में जाएगा या रैगुलर क्लासेज अटेंड करेगा? यानी मंशा सरकार की क्या है, यह समझ में नहीं आ रहा। कोचिंग क्लासेज को चलाना है तो उसे सुबह जल्दी मोर्निंग में चलाओ या लेट ईवनिंग चलाओ, लेकिन कम से कम कालेज आवर्स में तो कोचिंग क्लासेज मत चलाओ। कालेज आवर्स में कोचिंग क्लासेज चलाने के पीछे क्या मन्तव्य है? जब मैंने कालेज के स्टूडेंट्स से बातचीत की और पूछा कि आप विरोध कर रहो हो, लेकिन यह ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा आया कि यह डे-आवर्स में और कालेज आवर्स में यह चला

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

रहे हैं तो पता चला कि उस कोचिंग क्लासेज के अंदर जो बुक्स लायी गयी हैं, और जिन बुक्स के ऊपर वह कोचिंग क्लासेज चला रहे हैं, वह व्यक्ति विशेष लोगों की किताबें हैं, उन किताबों से पढ़ाई करवाने की मंशा से वह कोचिंग क्लासेज चलाकर उन स्टूडेंट्स को रैगुलर क्लासेज से अलग करके कोचिंग क्लासेज में ला रहे हैं। इस प्रकार से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। न उनकी 75 परसेंट उपस्थिति होगी और फिर उसके बाद एग्जामिनेशन के टाइम पर उनको रोक दिया जाएगा कि आप परीक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगी माननीय मंत्रीजी से कि यह जो रैगुलर क्लासेज का टाइम है, उस समय तो कम से कम कोचिंग क्लासेज को न चलाएं जिससे स्टूडेट्स के अंदर यह कन्फ्यूजन न रहे कि हम रैगुलर क्लासेज अटेंड करना चाहते हैं या कोचिंग क्लासेज। मेरा इसमें आपसे निवेदन है कि आप इसको ठीक करें।

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब विद्यार्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिये विश्वविद्यालय में 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया और पूरे देश के अंदर केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा कि 10 प्रतिशत आरक्षण देना, जो हमारे सामान्य वर्ग के गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनकी आप कालेजेज के अंदर 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाएं, उन्होंने तो बढ़ा दीं। हमारे यहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जो किशनगढ़ के अंदर है, वहां तो 25 प्रतिशत सीट्स बढ़ गयीं और जितने भी प्रतिष्ठान जो केन्द्र से चलते हैं, उन्होंने तो उन सबमें 25 प्रतिशत सीटें बढ़ा दीं, लेकिन अपने यहां स्टेट में इसको लागू नहीं किया। अब स्टेट में लागू नहीं करने का क्या कारण है? यह पता नहीं। मैं चाहती हूं कि इसको जल्द से जल्द लागू करें और राज्य में भी सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिये माननीय मंत्रीजी जरूर इसमें देखें कि कैसे 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाएं ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और इकोनोमिक बैकवर्ड क्लास, इन सारे लोगों को इसका लाभ मिल सके। जब तक सीट्स नहीं बढ़ाओगे, आपने लागू तो कर दिया 10 प्रतिशत, यह आपका एक स्टेटमेंट पेपर के अंदर छपा था। आर्थिक आधार पर आरक्षण तो मिलेगा, मगर सीटें नहीं बढ़ेंगी। माननीय सभापतिजी, अगर सीटें नहीं बढ़ाएंगे तो उनको कैसे लाभ मिलेगा। यह कह रहे हैं कि हम देना चाहते हैं, लेकिन सीट्स नहीं बढ़ाना चाहते। अनलैस एण्ड अनटिल आप सीट्स नहीं बढ़ाओगे तो उसका फायदा नहीं

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

मिल सकता। अगर सीट्स बढ़ेंगी तो ही यह इफैक्ट होगा। उसका पूरा लाभ मिलेगा 10 प्रतिशत और ज्यादा उस कैटेगिरी के अंदर पढ़ पाएंगे, जो योग्य हैं।

इसके अलावा कालेज में स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थी एडमिशन के लिये गये। आपने सीट्स नहीं बढ़ायी इस बार। हर साल माननीय सभापति जी, कालेज के अंदर एडमिशन जब हम करवाते हैं तो वैसे तो एडमिशन आनलाइन होता है। इस आनलाइन एडमिशन के अंदर हम दो बार डेट्स और बढ़ाते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा तर्क है और वह तर्क यह है कि क्योंकि यह आनलाइन होता है, इंटरनेट के माध्यम से होता है। बहुत सारे गांवों के अंदर इंटरनेट की सुविधाएं प्रोपर नहीं होती हैं, तो पर्टिकूलर उस डेट के ऊपर स्टूडेंट फार्म नहीं भर पाता तो ऐसे स्टूडेंट्स को एक और सैकण्ड डेट भी दे देते हैं, थर्ड डेट भी दे देते हैं, ताकि उसके अंदर उसको प्रोपर एडमिशन मिल जाए। लेकिन इस बार की स्थिति बहुत खतरनाक हुई। कालेज शिक्षा के अंदर स्नातक के जो प्रथम वर्ष के अंदर एडमिशन लेने आये, उनकी डेट्स आपने नहीं बढ़ायी और वह डेट्स नहीं बढ़ाने की वजह से हमारे बहुत सारे विद्यार्थी एडमिशन लेने से वंचित रह गये। मैं अगर राजसमंद की ही बात करूं तो हमारे यहां द्वारकाधीश कन्या महाविद्यालय, जहां 200 के मुकाबले में केवल 173 ही एडमिशन हो पाये। कुंभलगढ़ का कालेज है हमारे राजसमंद जिले में, वहां 200 सीटें हैं प्रथम वर्ष के लिये, वहां केवल 73 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिल पाया। देवगढ़ का जो कालेज है, वहां 200 स्टूडेंट्स की सीट्स है, 200 स्टूडेंट्स के मुकाबले में 194 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिल पाया है। अब आप सोचो, एक तरफ आप कहते हो कि हम अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, कहां अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं? आप तो शिक्षा से वंचित कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं टोकना नहीं चाहता, पर ट्रेजरी बैंचेज की हालत देखो, तेरह आदमी बैठे हैं।

श्री सभापति: विराजिए, आप विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): खाली तेरह आदमी बैठे हैं। अगर हम बाहर चले जाएं तो अभी कोरम की घंटी बज जाए।

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य, मुझे पता है, आप ऐसा नहीं करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): थोड़ा तो देखो। इनको कहो, तेरह आदमी हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभी सुन रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, यह जो शिक्षा से वंचित किया, उसमें विद्यार्थियों के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है।

श्री सभापति: मुझे पता है आप कोरम की समस्या नहीं खड़ी करेंगे, विराजिये आप। मुझे पता है, आप ऐसा नहीं करेंगे।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सदन आपको ही चलाना है।

श्री सभापति: यह आपका विषय नहीं है, आप कहां बीच में कूद पड़े। आपका बीच में कूदना जरूरी नहीं है। यह आपका विषय नहीं है। माननीय सदस्या, आप बोलिए। यह आपका प्रतिनिधि है। हर बात में जब आप बोलते हैं तो वह खड़ा होता है बराबर।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, आपने वातावरण बड़ा हल्का कर दिया। माननीय सभापति जी, स्टूडेंट्स के साथ धोखा हुआ है, मंत्रीजी, इसको पूरी तरह से देखें। मुझे पता है कि जितना दबदबा हायर एजुकेशन में इनका होना चाहिए, उतना नहीं है, क्योंकि और दूसरे मिनिस्टर हैं टैक्निकल, वह थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमारे यहां तो हम एक ही थे, टैक्निकल एजुकेशन भी हमारे पास ही था और हायर एजुकेशन भी हमारे पास था। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, बैठे-बैठे नहीं बोलते प्लीज।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप तो इसमें देखें कि इस बार जो तिथि नहीं बढ़ायी गयी, उसकी वजह से जो सारे विद्यार्थी वंचित रहे उसके बारे में क्या योजना बनाएंगे। हर स्टूडेंट चाहता है कि वह गवर्नमेंट कालेज में पढ़े, क्योंकि गवर्नमेंट कालेज की एक अपनी क्रेडिबिलिटी है और गवर्नमेंट कालेज स्टूडेंट्स को वंचित रखे, यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जो इस बार पहली बार हुआ। हर बार हम दो-तीन बार डेट्स बढ़ाते हैं। इस बार इन्होंने डेट्स नहीं बढ़ायी उसका बहुत बड़ा खामियाजा यह हुआ कि अब प्राइवेट कालेजेज के अंदर उन बच्चों को रश करना पड़ रहा है। किसी के मां-बाप के पास उतने पैसे हैं या नहीं, वह उतनी उनकी फीस दे सकते हैं या नहीं दे सकते, लेकिन आपके इस निर्णय की वजह से प्राइवेट कालेजेज की तरफ उन

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

स्टूडेंट्स को मजबूरी में जाना पड़ रहा है। आप इसके बारे में विचार करें क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं। अगर सुधार कर सकते हैं तो निश्चित रूप से इसमें सुधार करें।

माननीय सभापतिजी, मैं प्रदेश की जो 26 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज के प्रति भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि उनमें से 11 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, जिनके पास स्थायी कुलपति नहीं हैं। अभी आप सोचो, एक तरफ यह कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं, यानी एक ऐसी शिक्षा जहां पर स्टूडेंट्स अगर एडमिशन लेना चाहे तो गवर्नमेंट कालेज में उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना चाहे तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर वी.सी. नहीं होगा। जिस यूनिवर्सिटी में वी.सी. नहीं होगा, उस यूनिवर्सिटी के क्या हाल हो रहे हैं, इसको देखिए आप। इन 11 यूनिवर्सिटीज में जो स्थायी कुलपति नहीं हैं, मैं उनका नाम पढ़ना चाहती हूं।

(14.00 बजे)

राजस्थान स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, झुन्झुनूं कृषि विश्वविद्यालय, एमपीयूटी, उदयपुर; कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर; कृषि विश्वविद्यालय, कोटा; कृषि विश्वविद्यालय; जोधपुर; कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर; संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर; कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा; आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर; राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा; पुलिस विश्वविद्यालय, जयपुर।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): आर.टी.यू. में लग चुका है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): कब लगा?

श्री सभापति: विराजिये, आप विराजिये। आपस में वार्ता नहीं करेंगे आप, बैठिये। आपका जब रिप्लाई हो तब बता देना आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अजमेर विश्वविद्यालय की तो यह स्थिति है, एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी में कुलपति लगाया था आर.पी. सिंह जी को और लगाने के बाद कोर्ट से स्टे आया, वह सारा ठप पड़ा है। पिछले आठ महीने से ज्यादा, दस महीने हो गये, वहां पर यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, वहां कोई काम नहीं हो रहा है, वहां पर परिक्षाएं नहीं

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

दे पा रहे हैं, हालत बहुत ज्यादा खराब है तो जो यूनिवर्सिटीज के हालात बना रखे हैं उन के हालात को सुधारने की आवश्यकता है।

हम लोगों ने हमारे टाइम में यूनिवर्सिटी के अन्दर पैसा दिया था। हमने 50 करोड़ रुपये हमारे बजट के अन्दर रखा था यूनिवर्सिटी के इन्फ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए राज्य सरकार के बजट से। इसके अलावा हम लोगों ने 100 करोड़ रुपये केन्द्र से रूसा के माध्यम से इन पांच यूनिवर्सिटीज को दिया था तो आप सोचो कि 20-20 करोड़ पांच यूनिवर्सिटीज को हम लोगों ने दिया। साढ़े बारह-साढ़े बारह करोड़ हम लोगों के टाइम में यूनिवर्सिटीज के अन्दर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए दिया लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी 2019-20 का बजट आया, यूनिवर्सिटी के ऊपर एक कौड़ी भी नहीं रखी गयी, यूनिवर्सिटी के डवलपमेंट के लिए एक पैसा उन्होंने स्वीकृत नहीं किया। यानी कैसा माहौल पैदा हो रहा है, आप हायर एजुकेशन को किस लेवल पर ले जाना चाहते हो? एक तरफ हायर एजुकेशन हमारी सरकार में सही रास्ते पर आ गयी, गाड़ी पटरी पर चढ़ गई, अच्छा काम होने लगा लेकिन अब तो पूरे तरीके से हायर एजुकेशन की गाड़ी पटरी से उतर रही है। विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, जो लैक्चरर्स के अपाइंटमेंट हो रहे थे, वे सारे अपाइंटमेंट रोक दिये गये।

अभी जब बजट का रिप्लाई दे रहे थे तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही कि जनजाति क्षेत्र के अन्दर हमने जो विश्वविद्यालय खोला था उस जनजाति विश्वविद्यालय को आप उदयपुर से बांसवाड़ा क्यों लेकर गये? अब आप मुझे बताएं कि उदयपुर से बांसवाड़ा क्यों लेकर गये, यह माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं, जो मुख्य मंत्री जी एक तरफ तो कहते हैं कि जनजाति क्षेत्र के अन्दर लोग बहुत काम करना चाहते हैं, लेकिन क्या काम किया जनजाति क्षेत्र के अन्दर? वो जो विश्वविद्यालय उन्होंने बांसवाड़ा का घोषित किया था 2008 से 2013 के बीच में, 2010 में जब घोषित किया तो तीन साल तक एकमात्र कुलपति सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के छात्रावास में आफिस बनाकर बैठे रहते थे, किसी तरीके की कोई गतिविधि उस जनजाति विश्वविद्यालय में नहीं होती थी। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत धन्यवाद दूंगी हमारी राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी को, जिनकी दूरदृष्टि थी, जिनकी एक अच्छी सोच थी, उन्होंने कहा जनजाति विश्वविद्यालय चलेगा तो जनजाति क्षेत्र के अन्दर चलेगा और इसलिए उस

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

विश्वविद्यालय को जब बांसवाड़ा में शिफ्ट किया तो बांसवाड़ा में शिफ्ट करने के साथ ही उसे भूमि भी आबंटित हुई। उससे पहले इन्होंने जब यूनिवर्सिटी दी, न भूमि दी, न भवन दिया न बजट दिया। हमने जब बांसवाड़ा में शिफ्ट किया तो 146 एकड़ जमीन दी उस यूनिवर्सिटी को। उसके लिए 12 करोड़ रुपये राज्य सरकार के बजट से दिये, साढ़े बारह करोड़ रुपये जनजाति विकास मद से दिये और आज वहां पर 30 शिक्षक, 42 गैर शैक्षिक पद पर, सारे टीचर्स और नोन टीचिंग स्टाफ को लगाया। उसकी स्थिति यह है कि उस क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के 120 कालेजेज एफिलिएट हुए हैं उस यूनिवर्सिटी के साथ में और 92 हजार स्टूडेंट्स उसके अन्दर रजिस्टर हुए हैं 280 विद्यार्थी पीएचडी कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी का यह कहना कि जनजाति विश्वविद्यालय आप बांसवाड़ा क्यों ले गये, माननीय मुख्य मंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छा हुआ कि यह विश्वविद्यालय वहां ले गये, जिनके लिए यह विश्वविद्यालय खोला गया था, उन आदिवासी स्टूडेंट्स को उससे बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है और बहुत बड़ी बात तो यह है कि यह पूरे प्रदेश में पहला विश्वविद्यालय है जहां पर एम.बी.ए. हिन्दी के माध्यम से किया जा रहा है। आज तक कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है कि जहां एम.बी.ए. को हम हिन्दी में पढ़ा रहे हों। एम.बी.ए. हमेशा इंग्लिश में पढ़ाई जाती है लेकिन उन आदिवासी बहुल क्षेत्र में उन बच्चों की अंग्रेजी अच्छी नहीं होगी, वे हिन्दी में अच्छे से समझ सकेंगे तो उस विश्वविद्यालय में एम.बी.ए. को हिन्दी में पढ़ाया जा रहा है। यह प्रदेश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है और अगर देखा जाए तो देश का यह दूसरा विश्वविद्यालय है जहां एम.बी.ए. को हिन्दी में पढ़ाया जा रहा है तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमने जनजाति क्षेत्र के अन्दर अच्छे विश्वविद्यालय को स्थापित किया।

श्री सभापति: पांच मिनट में कन्क्लूड कर दीजिए आप। माननीय सदस्य, आप पांच में कन्क्लूड करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): पांच मिनट?

श्री सभापति: पांच मिनट में कन्क्लूड करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मुझे कितने मिनट बोलना था?

श्री सभापति: आप 25 मिनट से बोल रहे हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): कहां 25 मिनट बोली?

श्री सभापति: मुझे पता है। मैंने जो कहा है वह करिये आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अच्छा, माननीय सभापति जी, आप बहुत नरम दिल के हैं तो थोड़ा सा समय दें क्योंकि एजुकेशन पर बोल रहे हैं तो पूरी तरीके से बात आनी चाहिए ताकि उसमें सुधार हो सके, हमारी इसके पीछे यही भावना है।

हमारे यहां पर इन यूनिवर्सिटीज के अन्दर जो हमारे यू.जी.सी. के नोर्म्स चलते हैं, उन यू.जी.सी. के नोर्म्स में 10 साल का जो प्रोफेसर का अनुभव रखता है वही वी.सी. बन सकता है और यू.जी.सी. के इस नोर्म्स को बी.जे.पी. की सरकार ने 2017 में इसी सदन के अन्दर नियम लाकर कानून बनाया कि हम लोग टैन ईयर्स के प्रोफेसर को ही वी.सी. बनाएंगे, लेकिन आज इसके अन्दर क्या हो रहा है? आपने पत्रकारिता के ऊपर विश्वविद्यालय बनाया लेकिन उस विश्वविद्यालय में जो वी.सी. लगाया, उन सारे नोर्म्स को आपने खतम कर दिया, टैन ईयर्स के अनुभव वाला प्रोफेसर वी.सी. नहीं है उसके अन्दर, तो यह क्या कर रहे हैं? यू.जी.सी. के नोर्म्स का भी पालन नहीं कर रहे। इस प्रकार की सरकार कि कोई नियम नहीं कुछ नहीं, जो मर्जी जिसको बनाना है उसको बना दो और इस प्रकार का काम चल रहा है।

माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहूंगी 2008 से 2013 में जब कांग्रेस का शासन था तो 71 ऐसे अनुदानित कालेजेज का आपने सरकारीकरण किया था। उसका रिजल्ट यह था कि जो आपने अनुदानित कालेज को गवर्नमेंट में लिया तो 750 टीचिंग स्टाफ, 680 नोन टीचिंग स्टाफ को राजकीय सेवा में समायोजित किया था लेकिन राजकीय सेवा में समायोजित करके लायबिलिटीज तो गवर्नमेंट पर ली लेकिन उन कालेजेज के जो असेट्स थे, जो बिल्डिंग्स थीं, जो उनकी जमीनें थीं, जो प्रिमिसेज थे, जो उनकी परिसम्पत्ति थी उसके प्रति भी बात नहीं कही तो वह सारी उन विशेष लोगों के पास ही रह गयी और केवल लायबिलिटीज ले ली।

अब फिर 2019-20 के बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम आठ एस.एफ.एस. के कालेजेज को गवर्नमेंट में ले रहे हैं। आठ एस.एफ.एस. कालेजेज को आप गवर्नमेंट में ले रहे हो, पहले आपने 71 अनुदानित को लिया था तो उसमें केवल लायबिलिटीज ली थी। मेरा यह कहना

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

है कि जो आठ एस.एफ.एस. कालेजेज को ले रहे हैं उसमें न-केवल लायबिलिटी लेना, इसमें आप असैट्स भी लेना।

यहां तकनीकी शिक्षा मंत्री भी बैठे हैं, इन्होंने अभी दो दिन पहले 17 तारीख का मेरा सवाल था, उसके जवाब में कहा, हमने पूछा था कि गवर्नमेंट कालेजेज जिनमें गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनाई है इन्जीनियरिंग कालेज की, वह गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई बिल्डिंग, गवर्नमेंट ने सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया तो उनको गवर्नमेंट क्यों नहीं लेना चाहती? मात्र 11 ही हमारे पास इन्जीनियरिंग कालेजेज हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, उनमें नये कोर्सेज नहीं चल पा रहे हैं, उन कालेजेज को आप गवर्नमेंट में क्यों नहीं लेना चाहते हैं? उस पर तो मंत्री जी ने जवाब दिया कि हम नहीं ले सकते लेकिन आठ जो एस.एफ.एस. मोड में हैं, उनको हम लेना चाह रहे हैं, दूसरे 71 हमने पहले लिये तो विशेष लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए तो कालेजेज लिये जाते हैं लेकिन गवर्नमेंट के इन्जीनियरिंग कालेजेज को गवर्नमेंट क्यों नहीं लेती है? उस पर भी विचार करो कि जो गवर्नमेंट के इन्जीनियरिंग कालेजेज हैं उनको लो ताकि स्टूडेंटस को कम फीस में अच्छी पढ़ाई मिल सके और अच्छा काम हो सके।

माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार की एक योजना है रूसा की योजना।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): रूसा की योजना में हायर एजुकेशन काउंसिल की स्थापना हुई थी और उसके बाद केन्द्र सरकार का 384 करोड़ एक बार, 184 करोड़ दूसरी बार, यह पैसा हमको केन्द्र सरकार से मिला था। आज हालत यह है, अभी यह कह रहे थे कि हम राजनीति नहीं करते तो आपने हायर एजुकेशन काउंसिल के वाइस चेयरपर्सन को हटा दिया और उस वाइस चेयरपर्सन को इसलिए हटाया कि बी.जे.पी. ने नोमिनेट किया था। इतने करोड़ों रुपये जो केन्द्र सरकार यहां राजस्थान में हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए उच्चतर शिक्षा योजना में दे रही है।

श्री सभापति: समाप्त करें। समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, 2 मिनट। मात्र 2 मिनट।

श्री सभापति: बिलकुल नहीं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति जी, मात्र 2 मिनट।

श्री सभापति: श्री अमित चाचाण।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति जी, केवल 2 मिनट।

श्री सभापति: समाप्त करें। प्लीज सहयोग करें। विराजें आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति महोदय, आप इसमें देखें।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: श्री अमित चाचाण। विराजिए माननीय सदस्य।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप सहयोग करें। अंकित नहीं हो रहा है। आसन पैरों पर है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है। क्या फायदा है बोलने का।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: श्री अमित चाचाण।

श्री अमित चाचाण (नोहर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24, शिक्षा, कला और संस्कृति की चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

मांगों पर 2-3 दिन से चर्चा हो रही है। हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यगणों ने बहुत सी बातें कीं कि पद रिक्त कर दिये। आपने यह व्यवस्था खराब कर दी। मशीनों के जंग लग गया। लेकिन शायद वह यह बात भूल गये कि पिछले 5 वर्ष आपने राज किया था। कांग्रेस पार्टी ने राज नहीं किया। कांग्रेस पार्टी तो पिछले 7 महीने से सत्ता में आई है। कांग्रेस पार्टी जो आमजन, मजदूर, किसान की पार्टी है, कांग्रेस सरकार, जो पंक्ति के अंतिम

(श्री अमित चाचाण)

छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, उसको आगे लाने का काम करती है। माननीय अशोक जी गहलोत ने सही कहा था कि बेपटरी गाड़ी को ठीक करना शायद हमारे ही हिस्से में है। सभापति महोदय, 5 वर्षों तक जो आपके कार्यकाल में व्यवस्था का ढांचा बिगाड़ा गया, आपने जो व्यवस्था को जर्जर किया, आपने जो व्यवस्था खराब की और आप अब चाहते हैं कि पहले 6 महीने में ही वह सही हो जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार का यह बजट, पहला बजट है, न कि आखिरी बजट। उसमें भी 3 महीने आचार संहिता के लग गये थे। यह पहला बजट माननीय अशोक जी गहलोत द्वारा पेश किया गया है। आप सदमे से बाहर आइए। आपने 5 साल शासन चलाया है। राजस्थान को ऐसे मोड़ पर खड़ा किया है कि आज आम नागरिक की पिछले 5 वर्षों में जो दुर्दशा हुई, वह आज खुशी मना रहा है कि हम ऐसा राज लाए हैं जो आमजन, मजदूरों और किसानों का राज है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे नोहर की बात बताना चाहता हूं कि आज जो माननीय विपक्ष के सदस्य हैं, वह बहुत चिंतित हैं शिक्षा के लिए। बहुत चिंतित हैं खेल के लिए। नोहर का नाम फुटबाल के माध्यम से पूरे देश में गूंजता था। नोहर के खिलाड़ियों ने राजस्थान का नाम पूरे देश में किया था। आपके विधायक महोदय ने ही, आपके ही सांसद महोदय ने 3 साल तक उसी स्टेडियम में, 10 हजार दर्शकों के सामने घोषणा की कि 11 लाख रुपये सांसद महोदय के कोटे से लगाए जाएंगे, 7 लाख रुपये विधायक कोटे से लगाए जाएंगे। 3 वर्षों में वह 1 रुपया तो नहीं लगा सके, लेकिन आपकी तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदया ने जो फुटबाल का ग्राउंड था, स्टेडियम था, जिस ग्राउंड ने नोहर के सैकड़ों लोगों को रोजी-रोटी से जोड़ा था, कितनी उनको नौकरियां मिली थीं, उसमें अपनी यात्रा के दौरान हैलीकाप्टर उतारकर उसकी ऐसी दुर्दशा की कि आज युवा पीढ़ी अपने आपको पीड़ित महसूस कर रही है। जिस ग्राउंड ने उन्हें रोजी-रोटी दी, जिस ग्राउंड ने नोहर का नाम रोशन किया, जिस ग्राउंड ने राजस्थान का नाम रोशन किया, भाजपा राज में 5 वर्षों तक उस ग्राउंड की ऐसी दुर्दशा हुई। यह बड़े ही अफसोस की बात है, बड़ी ही विडम्बना की बात है।

सभापति महोदय, बड़े अफसोस की बात है पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि जो यह रिजल्ट रहा है, वह तो हमारी वजह से रहा है

(श्री अमित चाचाण)

लेकिन जो व्यवस्था खराब हुई, वह आपकी वजह से हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि 6 महीने में हमने कौनसे पद रिक्त कर दिये? हमने 6 महीने में ऐसी कौनसी व्यवस्था खराब कर दी, जो कि इतनी अव्यवस्था फैल गयी। यह तो वही बात हो गयी कि उलटा चोर कोतवाल को डांटे। हम तो चाहते हैं कि राजस्थान अग्रणी राज्यों में आए। हम तो चाहते हैं कि राजस्थान का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए।

आपने अपने पिछले कार्यकाल में स्कूलें बंद कीं। आज जो शिक्षित नवयुवक है, उसको बेरोजगारी पर लाकर खड़ा कर दिया। जो स्कूल की बिल्डिंगें दानदाताओं ने, भामाशाहों ने बनाई थीं, उनके मनोबल का आज क्या हो रहा है? वह अफसोस कर रहे हैं कि हमने आखिर पैसा क्यों लगाया? शिक्षा के लिए क्यों हमने सारी बिल्डिंगें बनाईं? आज हमारी बिल्डिंगें असामाजिक तत्वों को अड्डा बन चुकी हैं। आज हमारी बिल्डिंगें जर्जर हो रही हैं। उनकी शिला पट्टिका पर जो भामाशाह का नाम, दानदाता का नाम लिखा गया था, उन पर आज धूल जमी हुई है। यह जानकर वह दानदाता, भामाशाह अपने आपको शर्मिंदा महसूस कर रहा है। यह किसका कार्यकाल था? आपका कार्यकाल था।

सभापति महोदय, आज यह कह रहे हैं कि शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में शिक्षा होनी चाहिए। यह बड़ा अफसोस है कि जो काम आप कर रहे थे, शिक्षा के माध्यम से राजनीति कर रहे थे और आज ज्ञान का पाठ हमें पढ़ाया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके और सदन के माध्यम से मेरे क्षेत्र के स्वर्गीय गौरीशंकर बिहानी के परिवार का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। उनके परिवार ने हमें चलने के लिए सड़कें दीं, पढ़ाई के लिए कालेज दिया, खेलने के लिए स्टेडियम दिया, पीने के लिए पेयजल योजना दी। बहुत से ऐसे मंदिर, धर्मशाला उनके ही परिवार की वजह से है।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद करता हूं तत्कालीन कांग्रेस सरकार का, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि वही तत्कालीन मंत्री, आज भी हमारे मिनिस्टर हैं बी.डी. कल्ला जी, इनके सानिध्य में हनुमानगढ़ जिले का पहला राजकीय महाविद्यालय नोहर में 1984 में 28 एकड़ जमीन के साथ तत्कालीन सेठ स्वर्गीय गौरीशंकर बिहानी जी ने अपनी पत्नी नर्मदा देवी बिहानी के नाम

(श्री अमित चाचाण)

शिलान्यास किया। 1987 में नया भवन बनाकर उसमें कालेज शुरू किया गया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 40 वर्ष बाद भी उसके अंदर 56 में से 33 पद रिक्त हैं। इसके कर्मचारी, अधिकारियों और व्याख्याताओं के पदों की पूर्ति की जाए। उस 28 एकड़ जमीन में से 5 एकड़ में हमारी कालेज की बिल्डिंग बनी हुई है, 5 एकड़ में खेल का ग्राउंड बना हुआ है। शेष बची 18 एकड़ जो बंजर भूमि है, उसमें अगर पानी की व्यवस्था हो जाए तो जैसी सरकार की मंशा है कि हरियाली लाई जाए, तो उसमें हरे-भरे पौधे लगाकर वहां हरियाली की जा सकती है। उसमें स्नातकोत्तर के खोले गये प्राणी शास्त्र और रसायन शास्त्र के विषयों के लिए प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाए।

सभापति महोदय, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यगणों को बताना चाहता हूं कि आज वह बहुत बड़ी बातें करते हैं कि 70 साल तक आपने क्या किया? लेकिन मैं याद दिलाता हूं कि पिछले 28 वर्षों में 18 वर्ष तक राजस्थान में भाजपा ने शासन किया है। कांग्रेस ने तो मात्र 10 साल शासन किया है। उसी 10 साल में हमारे कांग्रेस के यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने ऐसे-ऐसे कार्य किये कि आज उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में पूरे देश में लिखा जा चुका है। ऐसे काम माननीय अशोक जी गहलोत ने किये हैं।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं एक बार पुन: आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, शिक्षा वास्तव में एक बहुत सेंसिटिव सब्जैक्ट है। बहुत से हमारे साथी यहां शिक्षा पर बोल चुके हैं। मेरा विषय तो नहीं था लेकिन मांग संख्या 24 अति संवेदनशील होने के कारण इस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, गुरु शिष्य परम्परा आरम्भ से रही है। जैसा कि नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मैकाले के आने के बाद स्कूल सिस्टम आरम्भ हुआ। मैकाले सिस्टम ऑफ एजुकेशन आज भी चल रहा है। कोई डायरेक्ट या अलग से प्राइमरी से लेकर बारहवीं तक होता तब तो समझ में आता लेकिन आज के युग में रेगुलेट करने के लिए अलग-अलग आवश्यकता है। वह नहीं करने और बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में राजकीय

(श्री नरपत सिंह राजवी)

व्यवस्था नहीं होने के कारण प्राइवेट स्कूल्स एक मशरूम की तरह बढ़े हैं। अनरेगुलेटेड यह ग्रोथ हुई है। यह बात तो सही है कि व्यवसाय नहीं होना चाहिए लेकिन मिशनरी स्पिरिट से तो गुरुकुल व्यवस्था, गुरु शिष्य परम्परा के आधार पर जो चल रहे थे, उसी में है, बाकी मिशनरी स्पिरिट कहां है?

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य मेरे से एक-दो क्लास ही आगे थे। जो आदर उस समय गुरुओं का था वह आज है क्या? हमारी जनरेशन को हम सिखा क्या रहे हैं? फ्रायड के हिसाब से आज तक का सर्वाधिक psychologist रहा है, child psychology में, उसने कहा है, पहले तीन वर्षों में जितनी Vocabulary बच्चा सीखता है, जीवनपर्यन्त उस vocabulary का मुकाबला वह याद करने के बाद भी नहीं सीख पाता। system of education बदलना होगा, system of education में पहले सारी स्टडी करके कोई कमेटी बनाएं, जब करें तो समझ में आता है कि कुछ सुधार होगा। स्कूल फीस रैगुलेट करने की कोशिश की प्राइवेट स्कूल में, अभी तक तो ज्यादातर मानते नहीं हैं। right to education तो बहुत अच्छी बात है लेकिन right to education को मानता कौन है? सुप्रीम कोर्ट तक एक मुकदमा गया, जो मिशनरी स्कूल्स हैं वह माइनोरिटी के आधार पर, रिलीजन के आधार पर खोली है, उन पर वह लागू नहीं है। सरकारी स्कूल में तो आपके एक्जीक्यूटिव आर्डर की ही मान्यता हो जाएगी, कौन रोकता है उसको?

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि स्कूल शिक्षा की दशा और दिशा दोनों ही खराब हैं और बहुत सुधार की आवश्यकता है। निर्वाचित प्रतिनिधि थोड़ा अगर ध्यान दे दें तो उनके निर्वाचन क्षेत्र में सुधार हो सकता है। मैंने कक्षा-कक्ष भी खूब बनवाए और शिक्षा का स्तर यह है, शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर थोड़ा ध्यान दे दें तो सर्व शिक्षा अभियान का और अधिक पैसा इसमें मिलकर कक्षा-कक्षों की पूर्ति हो सकती है। मेरे यहां पर जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा तो दो सौ, ढाई सौ की छात्र संख्या जिन स्कूलों में थी, आज प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में भर्ती हो रहे हैं। ऐसी व्यवस्था अधिकांश स्कूलों में हुई है, कक्षा-कक्ष भी और बाकी सुविधाएं भी।

माननीय सभापति महोदय, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना अगर बच्चों के हित में है तो निश्चित तौर पर करना चाहिए लेकिन राजनीति के आधार

(श्री नरपत सिंह राजवी)

पर या सोच सही नहीं हो उस आधार पर करें तो मुझे थोड़ा कष्ट होता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, कक्षा आठ की इंग्लिश रीडर, इसमें फोटोग्राफ दे रखी है, अबाउट चित्तौड़, जौहर का एक चित्र दे रखा है, इसको हटाकर चित्तौड़ के किले का दे दिया। पूरे चैप्टर में मीनिंगफुल जो चेंज होना चाहिए वह नहीं हो पाया। वीर सावरकर के बारे में बात आई, निश्चित तौर पर जो जानकारी रखते हैं, वह अगर कुछ बात कहते तो समझ में आती। वीर सावरकर के बारे में इस तरह की बात करना और चैप्टर में चेंज करना, इससे बड़ा कष्ट होता है।

माननीय सभापति महोदय, स्कूली शिक्षा के बारे में तो बहुत कहा हुआ है, उच्च शिक्षा मंत्रीजी भी और संस्कृत शिक्षा मंत्रीजी भी यहां बैठे हैं। 27 राजकीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें से 12 में से वीसी ही नहीं हैं आपके, रजिस्ट्रार और फाइनेंस कंट्रोल के आधार पर वह सारे चल रहे हैं। अजमेर यूनिवर्सिटी के बारे में अभी बताया कि 11.02.2018 से हाई कोर्ट से रोक के कारण 02 अगस्त, 2019 तक तो वे निर्णय ही नहीं ले सकते। चाहे वह एक्जामिनेशन कंडक्शन का हो, चाहे वह एडमिशन का हो, चाहे रेगुलर डे-टू-डे आपरेशन का या एडमिनिस्ट्रेशन का हो। संस्कृत यूनिवर्सिटी की तो दशा और भी ज्यादा खराब है। माननीय सभापति महोदय, मैंने एक पत्र लिखा था उच्च शिक्षा मंत्रीजी को भी और राज्यपाल महोदय को भी। मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं, दो दिन पहले मैंने बता दिया कि अमुक आदमी का सलैक्शन होगा और सलेक्शन करने के लिए जूनियर मोस्ट एसोसिएटेड प्रोफेसर को वह रजिस्ट्रार का चार्ज दिया। महामहिम राज्यपाल के यहां से भी उसको डिक्लेयर नहीं करने के आदेश हो गये, हाई कोर्ट से स्टे हुआ, उसके बावजूद उसी आदमी का सलैक्शन हुआ जिसका मैंने दो दिन पहले बतौर नाम भी मंत्रीजी और राज्यपाल महोदय को लिखा है और हाई कोर्ट का स्टे आ गया। इस प्रकार से सलैक्शन होगा तो यह व्यवस्थाएं कैसे सुधरेंगी? मैंने लिखा था कि कम से कम आप एफआईआर तो दर्ज करवाओ जो दोषी हो, वह आठ महीने से गायब हो गयीं यूनिवर्सिटी से और गायब होने के बाद बिना अपनी लीव सैंक्शन करवाए वापस जोइन कर लिया। यह क्रिमिनल एक्ट है। इस तरह से नहीं हो सकता, ऐसा मैंने पहली बार देखा है।

माननीय सभापति महोदय, एक और निवेदन करना चाहता हूं, सूचना

(श्री नरपत सिंह राजवी)

का अधिकार, सूचना के अधिकार के तहत दो रुपये में हमको एक पेज की कापी मिलती है और दस रुपये के पोस्टल आर्डर के साथ आवेदन देते हैं। आज कापियों में जिस प्रकार से गड़बड़ हो रही है, एक छात्र अगर अपनी कापी को आरटीआई के तहत लेना चाहे तो 580 रुपये चार्ज करते हैं। सभी यूनिवर्सिटीज ऐसा कर रही हैं। यह छात्रों के साथ कुठाराघात नहीं है तो और क्या है? मैं कहना चाहता हूं कि आरटीआई में 580 की जगह 2 रुपये प्रति पेज ही लेना चाहिए जिस तरह से दूसरे लोग ले रहे हैं। इसी संस्कृत विश्वविद्यालय में एक कक्षा की परीक्षा हुई, रैगुलर छात्र थे, वीसी की उन पर मेहरबानी, उनके गुरु पर मेहरबानी नहीं थी, वे अपने एग्जाम में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए थे लेकिन दुबारा बिना किसी नियम के दूसरी बार जांच करवाई। पुनर्मूल्यांकन में अंकों में उनको फेल किया, फेल किया तो छात्रों ने कापियां मांगी, तब जाकर यह राज खुला। तीसरी बार मूल्यांकन करवाया और वह छात्र पास हुए। छात्रों के कैरियर के साथ जो खिलवाड़ करता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो तो और क्या दर्ज होना चाहिए? और जिसे सैकंड टाइम नोमिनेट किया वह एलीजिबल नहीं थी, एक लेडी है और वह एलीजिबल नहीं थीं। उसका रिकार्ड में दर्ज है। विधान सभा के प्रश्न में उत्तर दिया है, उस आर्डर शीट में लिखा है कि यह पात्र नहीं है लेकिन अपना बट निकालना था तो किसी तरीके से तो निकाल ही लिया। इस तरीके से अगर होगा तो वास्तव में शिक्षा का तो बंटाधार ही होगा और कुछ नहीं हो सकता।

माननीय सभापति महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में भी 27.07.2018 को एक पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हाई कोर्ट में कैसे-कैसे असत्य जवाब दे सकते हैं एफिडेविट के साथ, जितने भी रूल्स हैं, आरएसआर एडाप्ट करना है, उसके लिए भी सीनेट में एप्रूवल होना चाहिए। आरएसआर ले लिया सीसीए में पनिशमेंट देना है, या तो आप रूल बनाओ नहीं तो आप उसको एडॉप्ट करो, हाई कोर्ट में आरएसआर एडाप्ट किया और जवाब दिया कि हमने सीसीए भी अडाप्ट कर रखा है। उसका भी प्रत्युत्तर डेढ़ साल से मुझे विधान सभा के माध्यम से नहीं मिला है। हाई कोर्ट में जब गलत उत्तर दिया, उसके बाद में आरटीआई से कुछ इंफोर्मेशन निकाली, उसके आधार पर पता लगा। माननीय सभापति महोदय, लगभग 51 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इस सदन के माध्यम से एक्ट बनाकर पास हुई हैं, आज चल रही हैं लेकिन कोई रैगुलेटरी आथोरिटी या बाडी ऐसी नहीं है जो हमने बनाई।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

शिकायतें आतीं, जब मैं चिकित्सा मंत्री था तब डेंटल कालेज की और मेडिकल कालेज की भी शिकायत आई। मर्जी आए तब वे पूरक परीक्षा ले लेंगे, अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण कर देंगे और उत्तीर्ण छात्र को पास नहीं दिखाएंगे जब तक वह पैसा नहीं दे दे। आप कैसे रैगुलेट करोगे? आपने तो एक्ट बना दिया। कोई न कोई बाडी हमको ऐसी गठित करनी पड़ेगी जिससे छात्रों के साथ अन्याय नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, परिवीक्षा काल में नौकरी हमने भी की है। प्रतिनियुक्ति नहीं होती है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी, आपने तो इसकी अनदेखी करके क्रूरता से, चाहे वह व्याख्याता (विज्ञान) हो, दूसरे भी व्याख्याता हैं ज्ञान-विज्ञान के ही और तीसरे हिन्दी के। नाम मैं यहां लेना नहीं चाहता, लेकिन आपके घनिष्ठ हैं तो कम से कम कानून की तो आपको भी पालना ज्यादा करनी चाहिए थी। परिवीक्षा काल में कभी भी डैपुटेशन पर नहीं लेना चाहिए। अभी भी अगर आपको डिपार्टमेंट सही चलाना है तो डैपुटेशन का सारा सिस्टम ही आप कैंसिल करेंगे, तब जाकर सुचारु रूप से चलेगा।

सभापति महोदय, हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट 2008 में 9.80 परसेंट था, 2016 में 20.50 परसेंट हो गया। 110 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। NAAC Accreditation आपके समय 2013 में सिर्फ 14 कालेज की ही थी, हमने 2018 तक 71 कालेजों की कर ली। कम से कम एक्रेडिटेशन हो ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इन्क्यूबेशन सैंटर, स्किल डवलपमेंट, क्योंकि सिर्फ यह स्कूली शिक्षा मिल जाएगी और बच्चा आगे जाकर कुछ नहीं करेगा तो उसको फ्रस्ट्रेशन होगा। भारत सरकार ने जो योजनाएं शुरू कीं जैसे- स्टार्टअप इंडिया, स्किल डवलपमेंट, मेक इन इंडिया। ऐसी योजनाओं की पूर्ति करने के लिए राज्य सरकार को भी पहल करनी चाहिए। यह मेरा निवेदन करना था। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आज शिक्षा की मांग पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मुझे यह समझ नहीं आता कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों की सरकारों की प्राथमिकता में यह शिक्षा विभाग किस रूप में है? जब राजस्थान की सरकार

(श्री संयम लोढ़ा)

का गठन होता है तो हमें इतने महत्वपूर्ण महकमों के लिये, दोनों ही पार्टियों को कोई कैबिनेट मंत्री नहीं मिलता। आज देखें तो भी सारे राज्य मंत्री, चाहे उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा। पिछली सरकार देखें तो प्रोफेसर वासुदेव देवनानी, वे भी राज्य मंत्री। क्या शिक्षा जैसा इतना महत्वपूर्ण महकमा जिसमें हमारे सभी बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है हमारे प्रदेश का और देश का भविष्य जुड़ा हुआ है इतना बड़ा हमारा तंत्र है, उस तंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक पार्टियां एक कैबिनेट मंत्री भी नहीं दे सकतीं? आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं विनती करना चाहता हूं राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री जी से कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, बहुत काबिल हैं, कानूनविज्ञ हैं और तीसरी बार जीतकर आये हैं। जब दूसरी बार वाले लोग ही सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं तो शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण महकमे का मंत्री क्या कैबिनेट मंत्री नहीं होना चाहिए?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या आप ऐसा करने के लिये प्रस्ताव रख रहे हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं सुझाव दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): संकल्प ले आएं आप। हम भी आपका समर्थन करेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, अभी प्रोफेसर साहब बोल रहे थे....

श्री सभापति: इनके भविष्य की तो चिंता करें, आगे पद तो बढ़ाएं। डिप्टी ही डिप्टी रहेंगे क्या?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): समसा में पिछली सरकार में 5500 करोड़ रुपये 2018-19 में प्रस्तावित थे। अब इस समसा का गठन कैसे किया? मंत्री जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा गवर्निंग काउंसिल की चेयरमैन होंगी मुख्य मंत्री। मंत्री होंगे इसके उपाध्यक्ष। पांच साल में आपने बैठक की गवर्निंग काउंसिल की?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हां, बिलकुल की है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): की है तो रिकार्ड रख दीजिए आप। आपकी सरकार के मंत्री ने प्रस्ताव भेजा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपने चीफ

(श्री संयम लोढ़ा)

सैक्रेटरी की अध्यक्षता में बनायी है समसा की और प्रिंसिपल सैक्रेटरी को आपने वाइस प्रेसीडेंट बनाया है, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का अध्यक्ष मंत्री को बनाया जाए। आपकी मुख्य मंत्री ने उसे टर्न डाउन करके भेज दिया। इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या होगी?

आप सरकार में किसी को मंत्री भी बना रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण महकमा भी दे रहे हैं, जिस पर पूरे राजस्थान का भविष्य बना हुआ है और उसे उसी के विभाग की एग्जीक्यूटिव कमेटी का आप चेयरमैन भी नहीं बनाना चाहते? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, आप जब जवाब दें तो बताएं। बड़े-बड़े दावे तो आप कर सकते हैं, आंकड़ों की बाजीगरी भी कर सकते हैं, लेकिन क्या आप बताएंगे कि समसा के 5500 करोड़ रुपये में से 2018-19 में 1200 करोड़ रुपयों का तो आप उपयोग ही नहीं कर पाये, खर्च ही नहीं कर पाये आप।

माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वे समसा का बजट भी 5500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6100 करोड़ रुपये तक लेकर आए। माननीय सभापति महोदय, बहुत सी बातें छिपी हुई रह जाती हैं। राजस्थान का यह पवित्र सदन राजस्थान की जनता तक उन बातों को पहुंचाएगा। आपने तीन साल में साढ़े दस लाख साइकिलें खरीदीं और ओरेंज कलर आपने प्रस्तावित किया। उस कंपनी ने कहा कि ओरेंज कलर करवाने के लिये हमें कनाडा से रंग मंगवाना पड़ेगा। एक साइकिल पर यह रंग करवाने का 85 रुपये एक्स्ट्रा खर्च आएगा। आपने बिना वित्त विभाग की स्वीकृति के खाली वह रंग करवाने के लिये साढ़े दस करोड़ रुपये उड़ा दिये। भगवा रंग पर आपका कोई ठेका है जो आपने समझ रखा है कि आप जहां चाहेंगे, वहां लगाएंगे और उससे लोग आपको वोट दे देंगे। यह भगवा रंग इस भारतवर्ष का है। इस देश के बच्चे-बच्चे का है। इस देश के कण-कण में है। इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाकर राजस्थान की जनता को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्या, विराजिए। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं आपको। विराजिए। माननीय सदस्या, विराजिए आप। इंटरवीन न करिए। अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, 85 रुपया खर्च बिना कारण ज्यादा आता है, अब कम लगेगा 85 रुपया खर्च। हम राजस्थान की जनता का पैसा किसी पार्टी के राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, धर्म को उसका दास नहीं बनने देंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता है कि शिक्षा जैसा महकमा अच्छे ढंग से चले। हम यह मानते हैं कि जो आईएएस में सलैक्ट होता है, वह सबसे प्रतिभाशाली बच्चा है। हम यह मानते हैं कि राजस्थान की सर्वोच्च सेवा आरएएस में जो बच्चा सलैक्ट होता है, वह हमारा सबसे प्रतिभाशाली बच्चा है। आप शिक्षा विभाग को इसी तरह की सेवा क्यों नहीं देना चाहते? प्रोफेसर साहब बहुत पद बढ़ाकर गये। ब्लाक लेवल पर जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर का अधिकारी बैठा है। उसके नीचे दो और बैठे हैं ब्लाक स्तर के अधिकारी, प्रिंसिपल रैंक के आफिसर। क्या इतने पद बढ़ाने के बाद हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम जिला शिक्षा अधिकारी की सीधी भर्ती करें 50 फीसदी पदों पर? आज क्या स्थिति होती? जो आपने जिला हैडक्वार्टर पर प्रमुख शिक्षा विभाग का बैठा रखा है, चलाएं देकर उसे। यह हालत है। किसी के पैर में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है, किसी के कहीं दर्द है। ऐसे महकमा चलाएंगे? जब एक नयी सोच लेकर आये हैं कि हम ग्राम पंचायत के स्तर पर प्रिंसिपल रैंक का आफिसर पंचायत स्तरीय अधिकारी बनाकर बैठा रहे हैं। प्रिंसिपल रैंक का आफिसर, तब आप इस नयी सोच के साथ क्यों नहीं आते कि 50 फीसदी पदों पर जिला शिक्षा अधिकारियों की हम सीधी भर्ती करेंगे। आपकी क्वालिटी सुधर जाएगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने बड़े-बड़े इंजीनियरों के दबाव में यह कर दिया कि फलां महकमे का सचिव स्तर का अधिकारी इंजीनियर होगा, फलां महकमे का सचिव स्तर का अधिकारी फोरेस्ट सर्विस का होगा, फिर इन मास्टरों ने क्या गुनाह किया है। हमको बनाने वाले वे लोग हैं। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, मेरे स्कूल के हैड मास्टर, स्कूल के प्रिंसीपल, उन्होंने हम पर ध्यान नहीं दिया होता, हम पर मेहनत नहीं की होती, हमें सिखाया नहीं होता तो आज राजस्थान की इस विधान सभा में खड़े होकर आपको विनती

(श्री संयम लोढ़ा)

नहीं कर रहे होते। क्यों हम यह सोच लेकर नहीं आते कि हम विभागीय प्रमुख पद पर एक शिक्षक को बिठा दें। वैसे भी शिक्षा का, आईएएस होने का, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का क्या लेना-देना। एक शिक्षक जितना बेहतर समझ सकता है, जितना बेहतर जान सकता है लेकिन हमारे दिमाग में यह भरा हुआ है। कभी खेत में हल पकड़ा हो या नहीं पकड़ा हो, पर एग्रीकल्चर। सोच बदलिए, नई सोच के साथ आइए, आप एक नौजवान मंत्री हैं, पहली बार बने हैं, हम आशा करते हैं कि राजस्थान का शिक्षा जगत आपकी सेवा से लाभान्वित होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हम हमारी शिक्षा को किस तरफ ले जा रहे हैं। भौतिकी का नोबल पुरस्कार सी.वी. रमन को मिला। 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारी शिक्षण संस्थाओं में एक हलचल होती है, एक औपचारिकता पूरी करके हम रह जाते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन का रहस्य खोजा था उन्होंने और रमन प्रभाव के रूप में भी उनकी खोज को जानते हैं। लेकिन समाज को वैज्ञानिक नजरिये से लैस करने की हमारी क्या रणनीति है? हम बच्चों को किस तरह के विज्ञान के मूल्यों से जोड़ना चाहते हैं इसके मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा माननीय सभापति महोदय। मैं जब कालेज का विद्यार्थी था, शिवगंज जो मेरा होम टाउन है, उसकी गली में एक वृद्ध महिला बीमार हो गयी। मैं डाक्टर साहब को लेने के लिए हास्पिटल गया और उनसे मैंने विनती की कि डाक्टर साहब, वह महिला यहां आ नहीं सकती, आप मेरे साथ चलिये। डाक्टर साहब मेरे साथ बाहर निकले, घर के बाहर कदम रखा तो किसी ने छींक दिया, डाक्टर साहब हाथ पकड़कर वापस घर के अन्दर आकर बैठ गये कि रुको, छींक कर दी किसी ने। अब बताइये, हमारी विज्ञान की, वो मेडिकल की पढ़ाई कहां गयी? डाक्टर जानता है कि शरीर के कौनसे अंग में क्या होने से छींक आती है लेकिन उसके भीतर घुसा हुआ अन्धविश्वास, वह संकीर्णता, वह जड़ता, उसे इस डिग्री पर भी भरोसा करने का सोच नहीं देती। ऐसी अवैज्ञानिक शिक्षा का हम क्या करेंगे, माननीय सभापति महोदय, जो समाज में इस तरह के अन्धविश्वास को और मजबूत करने का काम कर रही है। घर से निकलते हैं, सामने दूध पिलाती हुई गाय मिले तो अच्छा शकुन, पानी की बाल्टी लिये हुए कोई मिले तो अच्छा शकुन, नहीं तो घर के अन्दर आकर बैठ

(श्री संयम लोढ़ा)

जाओ। यह हम सारे पढ़े-लिखे की क्या मानसिकता है? माननीय सभापति महोदय, सिरोही में हमारे एक मित्र ने नया मकाना बनाया था, उन्होंने बुलाया, इंजीनियर हैं वे, उन्होंने बताया था कि इतने बजे आ जाना, मैं जब वहां पहुंचा तो सब खड़े थे तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, अन्दर क्यों नहीं जा रहे तो बोले कि नहीं-नहीं, पंडित जी ने मुहूर्त इतने बजकर इतनी मिनट का निकाला हुआ है। अब आप बताइये, सभापति महोदय, एक इंजीनियर को मालूम है कि उसके मकान की फाउण्डेशन को कितने नीचे जाना है, उस पर कितना लोड आना है, कितना उसमें आयरन लगना है, कितना सीमेंट लगना है, कितनी बजरी लगनी है, कितनी कंकरीट लगनी है लेकिन उसको अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पर भरोसा नहीं है, उस पंडित के मुहूर्त पर भरोसा है। इसी वजह से विज्ञान और अभियांत्रिकी की तमाम पढ़ाई करने के बाद भी हम हमारे समाज को उस दिशा में नहीं ले पाये हैं माननीय सभापति महोदय।

मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा, अभी जिक्र हुआ, हमारे पूर्व मंत्री ने जिक्र किया जौहर का, एक और वक्ता ने जिक्र किया सती प्रथा का। माननीय सभापति महोदय, यह मनुष्य जाति है इसने हमेशा अपने नये-नये मूल्य बनाये हैं, हर युग के अपने मूल्य हैं। एक वह भी युग था जब रावण सीता जी को लेकर लंका में गया तो कई दिनों तक सीता जी अशोक वाटिका में रहीं, पर रावण जैसे व्यक्ति ने घूरकर भी नहीं देखा, उसकी तरफ नजर तक नहीं उठाई। क्यों? उस युग के मूल्य थे, स्त्री के सम्मान का एक अपना उस वक्त की मनुष्य जाति का सोच था माननीय सभापति महोदय। उसके ठीक बाद जब श्रीराम अयोध्या लौटे तो एक बहुत साधारण आदमी ने सीता जी के लंका प्रवास को लेकर प्रश्न कर दिया।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप कहो तो अभी बैठ जाऊं हुजूर।

श्री सभापति: चालू रखें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): तो श्रीराम ने उनका त्याग कर दिया। क्यों? उस वक्त के वह शासक के मूल्य थे। मनुष्य जाति ने मूल्य पैदा किए थे कि एक शासक के क्या मूल्य होने चाहिए। उसके बाद आप महाभारत काल ले लीजिए। भरे दरबार में शासक की मौजूदगी में एक स्त्री का चीरहरण हुआ और लोग खड़े-खड़े देखते रहे, ये उस वक्त के मूल्य थे। जब सती पद्मिनी ने अपने

(श्री संयम लोढ़ा)

प्राणों की आहूति दी तो वह उस वक्त के मूल्य थे कि जब स्त्री राष्ट्र हित में, समाज हित में, नारी जाति के सम्मान की सुरक्षा में इस तरीके की क्रिया करती थी। उस युग के मूल्य थे। आज हम एक अलग युग में हैं। आज भारतीय दण्ड संहिता के माध्यम से संचालित एक समाज है, उस समाज की अपनी सोच है।

माननीय सभापति महोदय, सदन में सबसे वरिष्ठ मंत्री के रूप में कल्ला साहब बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आपकी सरकार ने किसी पाठ्यक्रम में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया लेकिन बिना पढ़े, बिना जानकारी किये आपकी सरकार के मंत्री और आपके लोक सभा के प्रत्याशी सार्वजनिक रूप से इस तरीके की टिप्पणी करते हैं जिससे आपकी पार्टी डाक में जाती है तो यह बहुत निन्दनीय बात है, बहुत गलत बात है। क्या सरकार के मंत्री एक-दूसरे से पूछकर यह जानकारी नहीं ले सकते कि पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है? भारतीय जनता पार्टी की राग में राग मिलाकर खाली हीरो बनने के लिए बयान देना आवश्यक है? पूरे राजस्थान के लोगों को पीड़ा हुई, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कोई प्रयास हो रहा है कि रानी पद्मावती के सम्मान में कमी हो, हमारे महान योद्धा महाराणा प्रताप के सम्मान में कमी हो। इन चीजों की सावधानी रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि समाज में इसका बहुत लम्बा प्रभाव पड़ता है। जो हमारे पूजनीय हैं, वे हर युग में पूजनीय रहेंगे चाहे आज हमारा युग हो, चाहे हमारी आने वाली पीढ़ी का युग हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। हमारा बचपन कहां चला गया? आप और हम लोग भी बच्चे थे, क्या समय था, राठौड़ साहब, साइकिल के टायर के पीछे उसको भगाते हुए दौड़ना, माचिस के अच्छे-अच्छे चित्र कलैक्ट करना, वह करना। आज हम स्मार्ट टैक्नोलोजी तो ला रहे हैं, बच्चों की स्मार्टनैस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के मुताबिक एक साल में 10 से 14 वर्ष के 3594 बच्चों ने और 14 से 18 वर्ष के 9203 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। इस उम्र में आत्महत्या क्यों माननीय सभापति महोदय?

(श्री संयम लोढ़ा)

न कोई नौकरी की चिन्ता, न कोई सुरक्षा का खतरा। क्या हम अपनी पढ़ाई के माध्यम से बच्चों को यह समझा पा रहे हैं कि सफलता-असफलता जीवन के पड़ाव हैं, मंजिल नहीं है? इस भारतवर्ष की भूमि पर पूरी दुनिया को संदेश देने वाली, योगीराज श्रीकृष्ण ने उस गीता की रचना की थी जिसने युगों-युगों से हमारी पीढ़ियों को यह संदेश दिया है - 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन'.....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। प्लीज, सहयोग करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): लेकिन हम यह देखते हैं कि हमारा बच्चा एग्जाम में टापर आये, आईएएस बने, इंजीनियर बने, 500 में से 499 नम्बर लाये, 90 फीसदी से ज्यादा उसके नम्बर आने चाहिए, दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, बाम्बे के सेंट जेवियर्स में एडमिशन होना चाहिए। रोबोट बना दिया है हमने....

श्री सभापति: श्री रामलाल जाट।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अपनी दमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए। माननीय सभापति महोदय, थोड़ी कृपा रखो आप। हम तो सड़क के आदमी हैं।

श्री सभापति: आगे भी अभी बहुत से माननीय सदस्य बोलने हैं, प्लीज सहयोग करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): दो मिनट का समय दो आप, मैं खतम कर रहा हूं।

श्री सभापति: बहुत अच्छा रहे, लेकिन समय की सीमा है। समय तो सबके साथ ही अच्छा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा, प्रतिपक्ष के उप नेता से निवेदन करना चाहूंगा, सालों तक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 15 मिलते थे राजस्थान के शिक्षकों को, आपकी सरकार ने पिछली साल घटाकर 6 कर दिये। राजस्थान के शिक्षकों पर कृपा करो। मानव संसाधन मंत्रीजी को कहो कि पूर्ववत राजस्थान के शिक्षकों के पुरस्कार 15 की संख्या आनी चाहिए, जिससे हमारे राजस्थान के उन शिक्षकों का मनोबल ऊंचा हो सके, उनकी सेवाओं का सम्मान हो सके।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, बातें बड़ी-बड़ी की जा सकती हैं, पीपीपी मोड लाए थे, 17 हजार स्कूलें बंद करने के बाद पीपीपी मोड किसलिए लाए थे, अपने मनचाहे लोगों को स्कूलें दे सकें। वैसे ही जैसे आपने हास्पिटल दिये, सारे हास्पिटल्स का क्या हाल है तीन-तीन, चार-चार हजार रुपये पर, ठेकेदार वहां पर आदमी लगा रहा है। ये हमारी मेहनत से बनी हुई स्कूलें लूटने के लिए इन प्राइवेट लोगों को देना चाह रहे थे, वह तो दबाव था कांग्रेस पार्टी का कि आपको वह निर्णय वापस लेना पड़ा।

माननीय सभापति महोदय, पिछले पांच साल में देश में डेढ़ लाख स्कूल बंद हुए हैं, बहुत चिंता का विषय है, एक षडयंत्र है बहुत बड़ा और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री थे, उन्होंने शिक्षा पर सुझाव देने के लिए कमेटी गठित की थी जिसमें अनिल अंबानी भी मैम्बर थे और दो लोग उद्योगपति मेम्बर थे। उस वक्त उन्होंने रिपोर्ट दी कि शिक्षा के क्षेत्र से सरकार को पीछे हट जाना चाहिए। आज सारे दुष्परिणाम उस रिपोर्ट के तहत हम भुगत रहे हैं। शिक्षा जैसा बुनियादी अधिकार जो हमने दिया है, आज देश के अंदर माननीय सभापति महोदय, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट है, 8 करोड़ 80 लाख बच्चे शिक्षा से बेदखल हैं।

यह हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं, सदन के अंदर आत्म मुग्ध होकर अपनी गाथा गाते, 12वीं तक की स्कूल है, किसने निर्णय किया, राजस्थान सरकार की हैसियत थी? प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने यह निर्णय किया कि देश की हर ग्राम पंचायत के अंदर मैं 12वीं तक का स्कूल खोलूंगा और उस निर्णय के तहत पूरे हिन्दुस्तान की हर ग्राम पंचायत में 12वीं तक की स्कूल की व्यवस्था हुई है, खाली राजस्थान में नहीं हुई है। मैंने इसी सदन में माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य, प्लीज। प्लीज सहयोग करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं निजी स्कूलें हैं, माननीय मंत्री जी, आपके पास क्या सिस्टम है, उनको देखने का और उनको करने का...

श्री सभापति: सहयोग करें, माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आपसे विनती करूंगा कि आप पैरेलल

(श्री संयम लोढ़ा)

इन निजी स्कूलों पर निगरानी रखने के लिए अपना एक तंत्र विकसित करिए और मैं आपके माध्यम से एक आखिर बात उच्च शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी की 2003 से 2008 की सरकार में वसुन्धराजी निजी विश्वविद्यालय का प्रस्ताव लेकर आईं थीं। उनकी भूमि आबंटन का प्रस्ताव लेकर के आईं थीं, मैंने इसी सदन में विरोध किया था और कहा था कि पैसों वालों की नालायक औलादों को पिछले दरवाजे से लाभ पहुंचाने का षड्यंत्र है ये, मुझे बहुत अफसोस है कि उसके बाद की सरकारों ने भी आकर यही किया और आज ये निजी विश्वविद्यालय क्या कर रहे हैं...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये आपको जानकारी तक नहीं देते कि वे कौनसा कोर्स चला रहे हैं, लड़के सलैक्ट हो जाते हैं और आरपीएससी इस आधार पर उनको रोक देती है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इन प्राइवेट दुकानों पर खास ध्यान दो। शिक्षा को व्यापार बनने से बचाओ, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करो, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल जाट।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): सम्पूर्ण शिक्षा अभियान वाजपेयी जी की देन थी।

श्री सभापति: विराजिए विराजिए, माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री सभापति: बिना इजाजत के क्यों बोल रहे हैं आप? आसन ने इजाजत दी आपको? अंकित नहीं हो रहा, कोई अंकित नहीं होगा। श्री रामलाल जाट।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-24 शिक्षा, कला, संस्कृति पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आभार। शिक्षा की मांग पर माननीय सभी सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे, बहुत बहुमूल्य विचार। हम भी जब सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे, स्कूल के बाहर लिखा होता, ज्ञान के लिए प्रवेश, सेवा के लिए प्रस्थान। 'विद्या ददाति विनयं' ये सारी चीजें उन सरकारी स्कूलों से ही प्राप्त हुईं, संस्कार उन स्कूलों

(श्री रामलाल जाट)

से ही प्राप्त हुए। लेकिन आज समय बदला, चिन्ता का विषय, राजस्थान ही नहीं पूरे देश का एक विषय बन गया।

आज माननीय, इस पवित्र सदन में शिक्षा की मांग पर सब अपने-अपने सुझाव दे रहे हैं। सामाजिक बदलाव में शिक्षा अहम भूमिका निभाती है और सामाजिक बदलाव में अहम भूमिका निभाने में जो संस्कार वाली शिक्षा की दूरी बढ़ी, इस वजह से ही आज कई ऐसी चीजें, घटना, दुर्घटना घट रही है।

मैं, माननीय आपके माध्यम से मंत्रीजी को निवेदन करूंगा कि आज शिक्षा में नामांकन जरूर बढ़ा, कई कारण थे नामांकन बढ़ने के, आपने भी पूरा सहयोग किया, पिछली सरकारों ने भी किया लेकिन उसके बावजूद भी गली मौहल्ले में जो स्कूलें खुलीं, ढाणी में जो स्कूल खुली, आज दूरदराज के एरिये में शिक्षा का फायदा बच्चों को मिलने लगा। कई सरकारों ने बंद भी किया, चालू भी किया। एक कस्बे के अंदर, मौहल्ला या छोटा कस्बा है, अगर दो स्कूलें हैं, बंद करें तो ठीक है, लेकिन दूर-दराज की ढाणियां हैं, वहां के बच्चों के लिए आपको उन स्कूलों को वापस खोलना बहुत जरूरी है। जो आपकी मंशा है सरकार की, वह तभी पूरी हो पाएगी। छोटी-छोटी ढाणियों में, छोटे-छोटे गांवों में जो बंद पड़ी हुई स्कूलें हैं, उन्हें आप दुबारा वापस खोलें। नामांकन बढ़ोतरी के जो आंकड़े हैं, अध्यापक, ब्लाक शिक्षा अधिकारी हों या जिला शिक्षा अधिकारी, वे आप तक आंकड़े जरूर पहुचाते हैं, आंकड़े तो साक्षरता के भी आए हैं लेकिन साक्षरता और शिक्षा में बहुत अंतर है। आपको समझना पड़ेगा।

मैं एक समय की बात बताऊं अजमेर में जब अदिति मेहता, मैं उनका नाम कोट कर रहा हूं, कलेक्टर हुआ करती थीं, साक्षरता के लिए एक मिशन चलाया। जब वह गांव में जाती थीं तो वहां के सचिव, पटवारी कोई अनपढ़ नजर नहीं आए कलेक्टर को, स्कूल के कमरे के अंदर बंद कर देते थे, गांव वाले इस चीज को नहीं समझते थे। एक साक्षरता का अभियान चलाया था, उसी तर्ज पर आने वाली सरकारों ने भी चलाया, भैरोंसिंह जी उस समय मुख्य मंत्री थे। उसके बाद अशोक गहलोत जी आए, लगातार शिक्षा का स्तर बढ़ा, लेकिन उस समय स्कूलें काफी बंद हुई थीं, बाद में अशोक गहलोतजी ने उन स्कूलों को वापस खोला, पिछले टाइम में राजीव गांधी पाठशाला खोली, फिर पिछली सरकार आई, उसमें कुछ बंद हुई, कुछ वापस चालू हुई। मैं आपसे निवेदन करूंगा नामांकन बढ़ोतरी के कई कारण हैं, लेकिन उन स्कूलों को अगर

(श्री रामलाल जाट)

वापस खोलेंगे तो जो बच्चे वंचित हैं, वे पूरा उन स्कूलों का फायदा ले पाएंगे और सामाजिक बदलाव तभी हो पाएगा, जब शिक्षा का ज्ञान होगा।

कुछ प्रश्न हैं, शिक्षा के स्वरूप का प्रश्न है, शिक्षा की गुणवत्ता का प्रश्न है, आज शिक्षा के अंदर ज्ञान संबंधी प्रश्न है, इन सब चीजों के प्रश्न तभी हल हो पाएंगे। जो क्वालिटी की शिक्षा है, वह आज स्कूलों के अंदर नहीं मिल पा रही है। पढ़ा जरूर अच्छा रहे हैं मास्टर जी, लेकिन बच्चों को सिखा नहीं पा रहे हैं। यह स्कूलों के अंदर बहुत बड़ी कमी है इस कमी को सुधारने का आज मौका है, उसको माननीय शिक्षा मंत्रीजी अगर सही करेंगे तो निश्चित रूप से सामाजिक बदलाव आ पाएगा।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज पर्यावरण संबंधी शिक्षा, ट्रैफिक रूल संबंधी शिक्षा, क्लासरूम में जो पढ़ाते हैं। आज एक पुलिस वाला कोई हैलमेट नहीं लगाता, उसको रोकता है, किसी की गाड़ी का लाइसेंस नहीं, उसको पुलिस वाला रोकता है। वहां रसीद काट दी जाती है। हैलमेट की पैनल्टी काट दी, लाइसेंस की पैनल्टी की रसीद काट दी, लेकिन हैलमेट नहीं आता है। गवर्नमेंट के आंकडों में, पैसा जरूर ट्रेजरी में आ रहा है, लेकिन उस आदमी को फायदा नहीं हो रहा है, उस पुलिस वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उस आदमी के लिए वह पुलिस वाला काम कर रहा है।

उसको शिक्षा में जानकारी नहीं है, अगर शिक्षा में ही इसे शामिल किया जाए और कुछ प्रश्न ऐसे हर परीक्षा के अंदर आएं, पर्यावरण हेतु पेड़ लगाने संबंधी, ट्रैफिक के रूल्स संबंधी, चाहे उनके 10 नम्बर, 5 नम्बर अनिवार्य कर दें, हर स्कूल के अंदर, शिक्षा के अंदर, हर सब्जैक्ट के बच्चे उनको पढ़ेंगे और उन चीजों को सीख पाएंगे, तभी कुछ फायदा हो पाएगा।

माननीय सभापति महोदय, आज मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिखा नहीं पा रहे हैं। मैं एक उदाहरण बताऊं आपको। आज 80 साल का कोई आदमी है, उसके दिमाग में यह चीज है, वह 80 साल का हो गया, फिर भी उसको पढ़ाया, दो और दो चार होता, वह लास्ट तक याद रखता है। लेकिन, बाकी चीजें भूलने की हो गयीं, आज की नई शिक्षा में, इस सिस्टम को बदलने की बहुत बड़ी जरूरत है। इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा।

(श्री रामलाल जाट)

(15.00 बजे)

आज समाज अच्छे डाक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे प्रोफेसर की मांग करता है वह तभी संभव हो पाएगा जब अच्छी क्वालिटी की शिक्षा आप दे पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आज पढ़ाने में इतना कंट्राडिक्शन हो चुका है इसमें बदलाव की बड़ी आवश्यकता है। आज जो ग्रामर पढ़ाई जाती है जिसमें आप खुद देख सकते हैं विलोम शब्द पढ़ाते हैं आकाश-पाताल, स्त्री-पुरुष, मालिक-नौकर। जबकि ये एक सृष्टि है अगर इसी में विलोम शब्द पढ़ाया जा रहा है तो इसको बदलने की आवश्यकता है। स्त्री-पुरुष एक सांसारिक जीवन है जिसमें एक मां का रूप होती है, पिता का रूप होता है। आकाश और पाताल दोनों एक होते हैं तभी ये चीजें सम्भव हो पाएंगी, पूरी सृष्टि बन पायेगी, लेकिन जो पढ़ाने में दिक्कतें हैं उन्हें बदलने की आवश्यकता है। आज कुछ अखबारों में भी छपता है रिजल्ट आने पर। जब स्कूल का रिजल्ट आता है चाहे सैकण्डरी स्कूल का हो, चाहे हायर सैकण्डरी स्कूल का हो, तब यह कहा जाता है कि बच्चियां बच्चों से कई कदम आगे हैं। बच्चे पिछड़े हैं तो यह कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। आज अख़बार वालों को भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि शिक्षा को बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर इसमें अच्छे सुझाव देंगे तो ही हो पायेगा। नेचर के बारे में भी आज डीजल, पैट्रोल, दूध ये सारी चीजें पढ़ाई में आएं। आज डीजल का भाव अस्सी रुपये हो रहा है, पैट्रोल का भाव हो रहा है। दूध का भाव है। आज उस बच्चे को यह नहीं पता कि दूध किस जगह से आ रहा है। डीजल किस जगह से आ रहा है। डीजल में खर्चा कितना हो रहा है। दूध में खर्चा कितना हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, यह सारी चीजें बच्चों को पढ़ाई जाएंगी तो ही जाकर सम्भव हो पायेगा। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं आज बच्चे को चीज सिखाते हैं एक जेंटलमेन की परिभाषा दी जाती है कि जेंटलमेन कैसा हो। टाई लगी होगी, सूट होगा वही जेंटलमेन। उसके सामने किसान खड़ा कर दिया जाता है तो वह बच्चा उसको जेंटलमेन नहीं कहेगा। उसको केवल किसान मानेगा। इन परिभाषाओं को बदलने की आज शिक्षा के अन्दर आवश्यकता है। पचास साल पहले के जो स्कूल थे, उनमें और आज में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। आज कई तरह के टीवी चैनल हैं, मोबाइल है, हजारों गेम्स हैं उन सब चीजों में बदलाव हुआ है। आज भारी बस्ते का बोझ छोटे से बच्चे पर लाद दिया जाता

(श्री रामलाल जाट)

है। उस बच्चे को आज सिखाने की आवश्यकता है। तीन साल के बच्चे को स्कूल में भेजने लग गये। इस बारे में सोचने की आवश्यकता है कि पांच साल के बच्चे को, पहले के समय में भी तीन से पांच साल के बच्चे को संस्कार की शिक्षा दी जाती थी। आज उन सब चीजों से वंचित हो चुके हैं इसलिए आज हम सभी को ये दिक्कतें आ रही हैं। शिक्षा को एक आंदोलन के रूप में खड़ा करना पड़ेगा। आंदोलन गांवों में कोई लड़ाई-झगड़े का नहीं है। आज धार्मिक आंदोलन नहीं, राजनीतिक आंदोलन नहीं लेकिन इन आंदोलनों में पढ़ाई का आंदोलन हो, तभी जाकर शिक्षा में हम सब लोग आगे बढ़ पायेंगे।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि शिक्षा की जो नीति है उसमें बदलाव करने की बड़ी आवश्यकता है। पहले के समय में सरकारी स्कूल, ट्रस्टी स्कूल हुआ करते थे। आज स्कूल का व्यापार हो गया है। इसमें मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं। आज शिक्षा के कई ऐसे अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अपनी बातें कही हैं कि शिक्षा अपनी मातृ भाषा में होनी चाहिए। गांवों में आज अंग्रेजी माध्यम भी है, आप कोई भी भाषा पढ़ाओ लेकिन बच्चे को ज्ञान अपनी मातृ भाषा से ही आ पायेगा। इस मातृ भाषा को अगर अपन सब्जैक्ट में लेंगे तो ही बच्चा पढ़ पायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं इन सभी चीजों के साथ ही कहना चाहूंगा कि आज अच्छी शिक्षा की मांग है। जाति, गुलामी, बिखराव, धर्म, ये सब तभी खतम हो पायेगा जब अच्छी क्वालिटी की शिक्षा हम दे पायेंगे और उसके लिए बहुत-बड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है। मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि 1998 में जो चयनित शिक्षक हैं, वे पिछले 21 सालों से न्याय के लिए भटक रहे हैं। उनमें कई लोग कोर्ट में गये उनको तो आपने फायदा दे दिया, शेष वंचित शिक्षक हैं, उनके प्रतिनिधिमंडल सभी विधायकों के घर पर जाकर मिल रहे हैं। हम एरिया में जाते हैं तो बच्चे वहां मिलते हैं। उनका भविष्य खराब हो गया है। उनका भी समावेश करें तो निश्चित रूप से फायदा होगा।

इसके साथ ही शिक्षा के लिए एक दूध योजना चालू हुई मैं आपको उस बारे में बताना चाहता हूं। हम लोगों ने तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय जी को भी निवेदन किया। आज कोई भी आदमी एक पीआईएल अगर कोर्ट में लगा दे तो यह दूध की योजना बंद हो जाएगी। यह अच्छी योजना है लेकिन

(श्री रामलाल जाट)

भारत सरकार का जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसमें आप रॉ मैटेरियल में बिना पाश्च्युराइज्ड दूध पिला ही नहीं सकते हो। हमने उस समय भी निवेदन किया और आपको भी निवेदन कर रहे हैं कि आप इसमें दूध या बना हुआ पाउडर बच्चे को दें। कितना फैट होना चाहिए, कितना कंटेन्ट हो तो ही बच्चों को पूरा पोषाहार मिल पायेगा। आज स्कूल के मास्टर जी, गांव में कई जगह डेयरी है, कई जगह प्राइवेट दूध है, वहां से ले रहे हैं, कई पानी मिला रहे हैं लेकिन बच्चों को पूरा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आप इसमें ध्यान दें पाउडर दें या दूध से बना हुआ कोई प्रोडक्ट दें या पाश्च्युराइज्ड दूध दें क्योंकि आपका एक्ट यह चीज बोल रहा है लेकिन आप उन चीजों में भटक रहे हैं और इस चीज की जानकारी अधिकारियों को है या नहीं लेकिन इस योजना में ऐसा करें ताकि किसान के दूध पैदा करने से गाय भी बचेगी और बच्चों को पोषाहार भी मिलेगा इस दूध योजना से।

इसके साथ एक और है कि ब्लाक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी आपने जो लगा रखे हैं माननीय सभापति महोदय, 80-80 हजार, 1-1 लाख रुपये की तनख्वाह के लगे हुए हैं। आफिसों में कई टीचर्स भी लगा रखे हैं। उनकी जगह आप कोई एमबीए के लड़के लगाओ तो आप उन शिक्षकों को दूसरी जगह स्कूलों में भेज पाओगे और वेकेंट पोस्टें पूरी भर पायेंगे। 5-5, 7-7 आज ब्लाक शिक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी के वहां टीचर लगे हुए हैं जबकि वहां एक एलडीसी का काम किया जा रहा है। यह सारी चीजें आज आपके सामने हैं तो मेरा इस मांग के मौके पर माननीय सभापति जी, आपसे निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय जी इन पर ध्यान देंगे। निश्चित रूप से कुछ बदलाव करेंगे तभी जाकर शिक्षा का पूरा फायदा हम सभी लोग उठा पायेंगे। यह बात कहते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग। श्री धर्मनारायण जोशी। माननीय सदस्यगण, यदि सभी माननीय सदस्य जिस तरह से बोल रहे हैं उस तरह से बोलेंगे तो रात के 11.00 बजेंगे और माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश हैं कि हाउस किसी भी तरह से 9-9.30 बजे तक समाप्त किया जाए तो अब आगे जो भी माननीय सदस्य बोलें, सात मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे बोलने के पहले कानून क्यों लगाया?

श्री सभापति: आप स्टार्ट करिये, घड़ी देख रहा हूं मैं।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, मुझे थोड़ा कंसीडर करें। आज शिक्षा पर बोलने का मुझे अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका। अभी मेरे से पूर्व माननीय सदस्य शिक्षा में मूल्यों की बात कर रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण बात की उन्होंने। मैं बिलकुल ठेठ गांव का रहने वाला हूं। मुझे अच्छी प्रकार से पता है छठी से ग्यारहवीं तक पैदल चल करके परीक्षा पास करते थे इसलिए जो गांव की पीड़ा है वह जानता हूं मैं। हमारे शिक्षा के मूल्यों की जहां तक बात है माननीय शिक्षा मंत्री जी, हम लोग चाहे किसी भी दल की सरकार हो, 33 परसेंट वालों को पास कर रहे हैं यानी ज्ञान तो 33 परसेंट और अज्ञान उसका 67 परसेंट। वह पीढ़ी आगे जाकर क्या करेगी? मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इसको ठीक करना चाहिये सबसे पहले, क्योंकि आज आत्महत्या का विषय आया। कोटा में कोचिंग होती है। बच्चियां मर रही हैं। बच्चियां इसलिए मरती हैं, मां-बाप ने तय कर लिया कि उसको डाक्टर बनाना है और मां-बाप कर्जा लेकर पढ़ाई करवाते हैं कि बेटा, पढ़ाई करना, नहीं तो हम डूब जाएंगे। बेटा, पास हो जाना। अंत में कई बार चांस होता है, ऐसा कि मान लो बेटी पास नहीं हुई तो आत्महत्या कर लेती है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि बच्चों पर प्रेशर भी कम किया जाए। वर्तमान युग में श्रृंगेरी पीठ के वर्तमान शंकराचार्य जी का मैंने जीवन पढ़ा तो पाया कि सात वर्ष की उम्र में भगवान कृष्ण के एक हजार नाम लिखे उन्होंने। ऐसे इंटेलीजेंट बच्चे इस पीढ़ी में भी आ रहे हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि गरीबों के लिए आप, मैं शिक्षा में राजनीतिक कोई बात नहीं करना चाहता। भैरोंसिंह जी की जब सरकार थी तो उस गरीब के लिए, मैं आदिवासी क्षेत्र से आता हूं, एक किसान के बेटे के जब जुलाई में स्कूल खुलते हैं तो वह हल चलाता है और तीसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, बच्चा कहता है कि पापा मेरी गणित की किताब नहीं है तो वह शहर जाता था। उसको बुक-सेलर कहता था कि चार दिन बाद पुस्तक आएगी तुम्हारी। उसको पुस्तक नहीं मिलती। उस समय माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया मंत्री थे, भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मंत्री थे, राजस्थान में एक योजना चालू की सब बच्चों को मुफ्त में किताबें मिलेंगी। क्या एक भी सदस्य ने इसकी प्रशंसा की? एक आदेश से राजस्थान में सारे मिडिल स्कूल खुले। मैं हमारे विधान सभा के अध्यक्ष जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि गरीबों का ध्यान रखकर उन्होंने एक आदेश से राजस्थान में 12 हजार राजीव गांधी स्कूल खोल दिये। क्या हम एक दूसरे की बड़ाई नहीं कर सकते हैं? क्या हम शिक्षा पर भी केवल

(श्री धर्मनारायण जोशी)

यहां राजनीति करेंगे? आपको आश्चर्य होगा, पिछली सरकार ने एक आदेश से हर पंचायत हैड क्वार्टर पर सीनियर स्कूल खोल दिया। आज शिक्षा की क्या स्थिति है? बच्चों को अगर सुविधा मिलेगी तो बच्चा पढ़ेगा। आज गांव में जाओ पिताजी की साइकिल बेटी लेकर घूम रही है, स्कूटी लेकर घूम रही है, यह सुविधा किसने दी?

भर्तियों के बारे में विनम्र प्रार्थना है, माननीय मंत्री महोदय, लड़का पढ़ता है, लड़का बीएड करने जाता है। बीएड का प्री एग्जाम होता है, वह बीएड करता है, बीएड के बाद नौकरी के लिये वह फिर एग्जाम देता है, फिर उसकी नौकरी लगती है। हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते हैं कि बीएड में उसकी भर्ती के समय व्यवस्था हो जाए। गुजरात में सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे ही बीएड की परीक्षा पास हो सरकार उसको अपाइंटमेंट लैटर दे दे? हर बात के लिये उसे एग्जाम देना पड़ेगा। आपको आश्चर्य होगा जो अध्यापक थर्ड ग्रेड में भर्ती होता था, वह थर्ड ग्रेड में ही मर जाता था। 9-18-27 का लाभ हमारी भैरोंसिंह जी की सरकार ने चालू किया, उसको वह ग्रेड मिली।

(15.12 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

इसलिए बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। कला संस्कृति के बारे में मेरा निवेदन है, अभी सभापति जी आसन पर पधार रहे हैं। कला की बात सीखनी हो तो इनसे सीखो। मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है महेन्द्रजीत मालविया जी का एक कार्यक्रम रखो, गले में ढोल बजाकर लोक कला क्या होती है, महेन्द्र मालविया जब गाते हैं तो हजारों लोग नाचते हैं, कला सीखनी है तो इनसे सीखो, यह है कला।

मुझे क्षमा करे, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसम्बर, 1885 को हुई किसने की? ए ओ ह्यूम, उसका कोई नाम नहीं लेता है। उस अंग्रेज ने स्थापना की और यहां मैकाले पद्धति शिक्षा की लागू की। हमारे यहां ग्रास रूट पर गांव में क्या स्थिति है शिक्षा की, उस पर ध्यान नहीं दिया इसीलिए उस अध्यक्ष का कोई नाम नहीं लेता।

अभी करीब 10 दिन पहले एक आदेश निकला था। शिक्षा मंत्री जी ने उसको वापस ले लिया कि गांव में अध्यापक घरों पर जाकर 50 बच्चों का मल इकट्ठा करेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय सभापति महोदय एक मिनट, माननीय सदस्य, ऐसा न तो कोई आदेश निकला है और न हमने वापस लिया। इसकी आपको पूरी जानकारी नहीं है। वह केवल मात्र अभिभावकों को यह समझाइश करना कि आपके कोई नमूने लेने आये तो आप दीजिए, आपके स्वास्थ्य का परीक्षण होगा। केवल समझाइश की बात थी, वह हमारा अभियान नहीं है, वह स्वास्थ्य विभाग कर रहा है।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, मेरे पास आदेश की प्रति है, मैं आपको आदेश की प्रति दिखा सकता हूं। मैंने उसी दिन स्थगन प्रस्ताव लगाया, अध्यक्ष जी से बात की मैंने ...

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, एनएचएम माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी की स्कीम है, उस स्कीम के तहत यह टीकाकरण का अभियान है जिसकी वजह से यह स्कूलों का अभियान चलाया जा रहा है।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): आप गायों को गिनने के लिये अध्यापक लगा दोगे, आप जनगणना के लिये अध्यापक को लगा दोगे? जिस गुरु के कारण आपको सम्मान मिलता है, जो भी गांव का काम होगा, आप बीएलओ लगा दोगे? माननीय मंत्री महोदय, मेरे पास आदेश की प्रति है और आपने वह आदेश वापस लिया, उसकी भी अख़बार की कटिंग मेरे पास है, मैंने कमरे में माननीय अध्यक्ष जी को दिखाई है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां छुट्टियां होती हैं, छुट्टियों के लिये मंत्री आता है कभी चार दिन की गर्मी की छुट्टियां घटा दीं, कभी सर्दी की। हमारे यहां छुट्टियां होती हैं, मैकाले शिक्षा पद्धति में अंग्रेजों ने गर्मियों की छुट्टी की। गर्मी की छुट्टियां इसलिए की कि उस समय उनको भारत में गर्मी बहुत लगती थी, इंग्लैंड जाना पड़ता था। हमारे यहां भैरोंसिंह शेखावत साहब की पिछली सरकार ने दीपावली की छुट्टियां बढ़ाई, माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया ने, छुट्टियां इसलिए बढ़ाई कि दीपावली के समय किसान का एक फसल बुआई का और एक फसल लेने का समय है। कभी चार दिन की छुट्टियां उसमें घटा दीं, कभी उसमें बढ़ा दीं, इसमें भी राजनीति चल रही है।

माननीय सभापति महोदय, एक कक्षा में पढ़ाया जाता है प्रताप जीते, एक कक्षा में पढ़ाया जाता है प्रताप हारे। एक कक्षा में पढ़ाया जाता है प्रताप का युद्ध अनिर्णीत रहा। आपकी तरफ से कुछ नहीं है, पहले से ही चल रहा है यह। माननीय मंत्री महोदय, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह हमारे समय की नहीं है, पढ़कर आया करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके स्प्रिंग लगी हुई है क्या? जवाब दो तब बता देना, ज्यादा ही ज्ञान है तो जवाब दो तब बता देना। लिख लो आप।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय मंत्री महोदय, मैंने आप पर आरोप नहीं लगाया है, पहले से ही चल रहा है। आप उसमें सुधार कीजिए। 8वीं तक बच्चा फेल नहीं होगा, आपने किया 8वीं तक बच्चा फेल नहीं होगा। मेरा आप पर बिलकुल आरोप नहीं है। 8वीं तक बच्चा फेल नहीं होगा, मैंने कांग्रेसी मित्रों से व्यक्तिगत पूछा यह क्या कानून लाये हो, क्या करें मजबूर हैं, हम तो आपके साथ हैं। यानी वह कानून उनको पसंद नहीं है, उसके बाद भी उस कानून को लागू किया।

वासुदेव देवनानी जी ने पिछली बार, भले ही कितना ही आपने उनको रोका हो, उन्होंने काउंसलिंग करके 1 लाख 9 हजार पदोन्नतियां कीं और उन पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे उदयपुर के खेल अधिकारी कार से आ रहे थे, रास्ते में एक बच्चा बकरियां चराते हुए मिल गया। उन्होंने बच्चे को पूछा, क्या नाम है आपका, उसने कहा लिम्बाराम। 15-16 का बच्चा, आप उसको अच्छी प्रकार से जानते हैं, तीरंदाज। वह बच्चा गुलेल से पत्थर फेंक रहा था। उन्होंने जहां कहा वह वहीं पत्थर मार रहा था। वह उस बच्चे को लाये और लाकर उसको प्रशिक्षण दिया। उस बच्चे ने ओलम्पिक में जाकर पदक लाकर हमारे भारत का मस्तक ऊंचा किया, ऐसी प्रतिभा जनजाति क्षेत्र में है। मेरी आपसे प्रार्थना है जनजाति क्षेत्र में स्कूल 11वीं तक है, वहां ऐसी व्यवस्था कीजिए कि प्रातःकाल दो घंटे कोई शारीरिक शिक्षक उनको तैयारी कराए।

हमारे मित्र थे राजसिंह जी डूंगरपुर, उन्होंने मुझे बताया कि मैं चंडीगढ़ में कोचिंग करा रहा था, कपिल देव वहां फुटबाल खेल रहे थे। उनके पसीने आ रहे थे तो वह छाया में आकर बैठे। मैंने कपिल को पूछा कि आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो। वह दूसरे दिन क्रिकेट में आ गया और संसार का माना हुआ खिलाड़ी हो गया कपिल देव। प्रतिभा गांवों में है, ठेठ वहां बैठी है। आपसे मेरी प्रार्थना है इस ओर ध्यान दें।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

कला क्षेत्र में उदयपुर में बहुत बड़ी संस्था है भारतीय लोक कला मंडल। माननीय मुख्य मंत्री जी ने महात्मा गांधी के नाम से कोई केन्द्र चालू करने की घोषणा की। मेरी आपसे प्रार्थना है हर जिला केन्द्र पर जो गांव की प्रतिभाएं हैं, लंगा बंधुओं की प्रतिभाएं हैं, हमारे कालबेलिया नृत्य की प्रतिभा है, हमारे तेरह ताल की प्रतिभा है, उन प्रतिभाओं को उभारकर जिला केन्द्र पर ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र खोलें, इससे गांवों की प्रतिभा ऊपर आएगी।

मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है आपने बोलने का अवसर दिया, एक अंतिम बात और निवेदन करनी है। आप कहते हैं शिक्षा में राजनीति नहीं है। अजमेर में एक आंदोलन चल रहा है और वह आंदोलन इसलिए चल रहा है वहां गवर्नमेंट कालेज के ब्लाक में राजीव गांधी ब्लाक, जवाहर लाल नेहरू ब्लाक, इंदिरा गांधी ब्लाक, लाल बहादुर शास्त्री ब्लाक के नाम से नामकरण कर दिया, इसलिए वहां पर आंदोलन चल रहा है। कर दिया, कहां आपत्ति है, परंतु आप कह रहे हैं कि राजनीति नहीं कर रहे हैं। वहां पर शिक्षा में आंदोलन चल रहा है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): सभापति महोदय, केवल एक मिनट। माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा को एक छत के नीचे लाइए। सब प्रकार की शिक्षा का शिक्षा मंत्री एक हो। आपसे मेरी प्रार्थना है। आपके राष्ट्रीय नेता से किसी ने राजकोट में प्रश्न पूछा था कि एनएसएस क्या होता है तो उन्होंने कहा कि पता नहीं। आप एनएसएस के कार्डिनेटर हैं। उसके संरक्षक अशोक जी गहलोत हैं। आपने आदेश निकाला है। आपने यह आदेश निकाला है कि एनएसएस का कोई भी कार्यक्रम होगा, वह कार्डिनेटर की परमीशन के बिना नहीं होगा, यह राजनीति नहीं है तो क्या है?

श्री सभापति: अब जल्दी से समाप्त करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): यह राजनीति नहीं तो क्या है? करिये, लेकिन सामान्य लोगों के हितों की जो बात है, उसमें राजनीति नहीं होगी तो बहुत अच्छा होगा। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सूचना

जयपुर के जे.डी.ए. सर्किल में सड़क दुर्घटनाओं से मौतें

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। सभापति महोदय, दो दिन पहले जेडीए सर्किल पर भयंकर दुर्घटना हुई थी, उसमें दो लोगों की मौत हुई थी। दो माताओं की कोख सूनी हुई थी। आज बिड़ला सर्किल के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है। एक स्कूटी सवार 20 फीट ऊपर उठकर 40 फीट दूर जाकर गिरा है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है सरकार निर्देशित करे कि इन चौराहों पर जो अकाल मौतें हो रही हैं, इन मौतों का सर्वे कराए। ब्रेकर लगाने हैं तो वे लगाएं या चौराहे वापस बनाने हैं तो वापस बनाएं, लेकिन इन मौतों को रोकने का काम करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें। श्री हीराराम जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री हीराराम (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-24 के ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा से ही सर्वांगीण विकास सम्भव है। संविधान के निर्माता डा. भीमराव अंबेडकर साहब ने भी अपने मूल मंत्र में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व बताया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षा के विकास बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस कड़ी में हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदय ने भी अभी बजट में 32 महाविद्यालय खोले हैं। मैं उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय, मैं मेरे बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा की समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श करना चाहूंगा। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी और मंत्री जी दोनों विराजे हैं, मैं उनका ध्यान मेरी समस्याओं के ऊपर आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मेरे बिलाड़ा क्षेत्र में, जब अशोक गहलोत साहब दूसरी बार मुख्य मंत्री बने थे तो उन्होंने राजकीय डा. भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय खोला था। अब स्थिति यह है कि इसमें मात्र एक कला संकाय है, जिसमें कुल स्वीकृत पद 23 हैं। वर्तमान में कार्यरत 8 हैं और 15 पद रिक्त हैं। प्राचार्य भी नहीं है। अंग्रेजी व राजनीतिक विज्ञान के व्याख्याताओं के पद व अन्य पद भी रिक्त हैं। जब वसुन्धरा जी की सरकार

(श्री हीराराम)

बनी तो इन्होंने भी लाइब्रेरी, ट्यूबवैल व खेल के मैदान की घोषणा की थी, लेकिन वे भी आज दिन तक सम्भव नहीं हो पायी। लाइब्रेरी नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए महाविद्यालय में जल्दी से लाइब्रेरी का निर्माण हो तो छात्र-छात्राओं के हित में अच्छा रहेगा। साथ ही, इस महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं को फ्लोराइडयुक्त पानी पीने से कई बीमारियां हो रही हैं। इस कारण टांका-ट्यूबवैल का निर्माण होना जरूरी है। साथ ही, विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता है क्योंकि विज्ञान संकाय के लिये छात्र-छात्राओं को बहुत कठिनाई का सामना करके जोधपुर व अजमेर जाना पड़ता है एवं अपने गांव से दूर होने के कारण छात्र-छात्राओं का मनोबल आगे की पढ़ाई करने के लिये कमजोर हो जाता है, जिससे वे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां नगरपालिका पीपाड़ शहर में मात्र एक बालिका महाविद्यालय संचालित है। उक्त महाविद्यालय में भी, जब अशोक जी गहलोत मुख्य मंत्री थे तो उनके द्वारा शिक्षा विकास समिति की ओर से विज्ञान विषय शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इसमें यह था कि महाविद्यालय द्वारा शिक्षा विकास समिति के माध्यम से सैल्फ मोड पर विज्ञान विषय शुरू कर दिया गया, जिसके कारण छात्राओं को महाविद्यालय में विज्ञान विषय के अध्ययन हेतु 15120 रुपये का शुल्क देना पड़ रहा है। यह महाविद्यालय लगभग 25-30 ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और वहां के गरीब तबके के परिवार की करीबन 822 छात्राएं इस महाविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। उनमें विज्ञान विषय पढ़ने वाली छात्राओं के लिए इतनी बड़ी राशि चुकाना बहुत मुश्किल है। इस कारण कई छात्राओं को विज्ञान विषय पढ़ने की इच्छा होते हुए भी वंचित होना पड़ता है। हमारी सरकार भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे रही है ''बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ''। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हैं और नि:शुल्क शिक्षा की भी घोषणा की गयी है। माननीय सभापति महोदय, निवेदन है कि वर्तमान में विज्ञान विषय की महती आवश्यकता को देखते हुए महाविद्यालय में शिक्षा विकास समिति के माध्यम से सैल्फ मोड पर संचालित विज्ञान विषय को नियमित करवाने की कृपा करें। आपका बहुत-बहुत आभार होगा।

(श्री हीराराम)

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक विद्यालय खोले गये, लेकिन राजस्व गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनको माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया गया है, अगर क्रमोन्नत कर दिया जाए तो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत कर दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का महत्व बढ़ेगा। जैसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रावर और खारिया मिठापुर जहां पर बालिकाओं की संख्या ज्यादा है, रावर में अगर बालिकाओं के अलग से विद्यालय खोला जाए तो बालिकाएं शिक्षा से वंचित नहीं होंगी और राजकीय माध्यमिक विद्यालय खारिया मिठापुर को उच्च माध्यमिक विद्यालय में एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय पितावास को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने से बालिकाओं में शिक्षा की रूचि बढ़ेगी। इससे महिला शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा और एक अच्छे समाज का भी विकास होगा। इसके साथ ही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर दिया जाए तो शहरी और ग्रामीण परिवेश में बदलाव होगा।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिलाड़ा को माध्यमिक विद्यालय में, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, आदर्श नगर, बिलाड़ा को माध्यमिक विद्यालय में, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सांखलों का बेरा, पीपाड़ शहर को माध्यमिक विद्यालय में, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मीरा बास को माध्यमिक विद्यालय में, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय होलपुर को माध्यमिक विद्यालय में, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ी कलां को माध्यमिक विद्यालय में, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बुरकासनी को माध्यमिक विद्यालय में, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुरिया को माध्यमिक विद्यालय में, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुरा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करें तो शिक्षा का स्तर अच्छा होगा और बालिकाएं भी अपना शिक्षा का स्तर आगे बढ़ाएंगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): सेठ चंपालाल हरकचंद्र कोठारी राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीपाड़ शहर में अभी एक भामाशाह ने 45 लाख में एक स्कूल बनाया है। अभी हाल ही में उस स्कूल का उद्घाटन मेरे द्वारा करवाया गया और उन्होंने कहा कि अगर ये स्कूल माध्यमिक में प्रमोट कर दिये जाएं

(श्री हीराराम)

तो जो सारा खर्चा होगा, वह मैं करूंगा। माननीय सभापति महोदय, अभी 6-डी के अनुसार स्थानांतरण कर दिये गये, उसी के अनुसार भी हमारे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारे पद रिक्त पड़े हैं, उसके लिए भी मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): माननीय अभी मेरे फिटकासनी में बालिकाओं की संख्या दो हजार है। मैं मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि फिटकासनी में भी विद्यालय खोल दिया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: पब्बाराम जी।

श्री पब्बाराम (फलौदी): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। जब से मानव सभ्यता है तब से किसी न किसी रूप में व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है और हमारी शिक्षा वैदिक काल से कभी-भी राज्य के ऊपर निर्भर नहीं रही। कालान्तर में हम पूर्ण रूप से शिक्षा के लिए राज्य के ऊपर निर्भर हो गये। निश्चित तौर से हर सरकार ने प्रयास किये कि शिक्षा बेहतर हो, इसका प्रसार हो। हम भी कांग्रेस की सरकार के समय जो विद्यालय थे, उसके अंदर पढ़कर आए। उस समय की गुणवत्ता, परंतु एक्सपांशन आफ एजुकेशन, एजुकेशन का एक्सपांशन इतना कर देना और उसकी मानीटरिंग नहीं करना और उसके इंस्पेक्शन सिस्टम को सही नहीं करना, इस कारण से शिक्षा के क्षेत्र में बीच में जो पराभव देखने को मिला, उसका मंजर मैं आपको बताता हूं।

2013 से पहले की बात है। उस समय मेरे पूरे क्षेत्र में दसियों जगह तालाबंदी चलती थी, शिक्षक नहीं हुआ करते थे। एक विद्यालय की बात बताता हूं। सीनियर सैकण्डरी विद्यालय, टेपू और टेपू में विषय विज्ञान, विज्ञान का विषय और शिक्षक एक, और वह भी शारीरिक शिक्षक। शिक्षक का नाम कोट करूंगा, आपका रिकार्ड देख लीजिए, खींवसिंह, शारीरिक शिक्षक। यह उस समय की शिक्षा का मंजर था। आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये मानव संसाधन का जो वितरण था, वह सही नहीं होने के कारण हुआ। कारण, हम लोग पिछली पूर्व की सरकार में भी समानीकरण नहीं कर पाए। यानी कि जितने स्टूडेंट्स हों उसके आधार पर शिक्षक लगें। मैंने देखा है एक विद्यालय शहर का है, 12 तो स्टूडेंट हैं, 15 शिक्षक हैं। वह आ नहीं रहे, कोर्ट के स्टे से

(श्री पब्बाराम)

चले गये। मैं धन्यवाद देता हूं पूर्व मंत्री देवनानी जी को, वह हमारे यहां पर स्टाफिंग पैटर्न लाए हैं। यानी कि स्टाफ स्टूडेंटस के हिसाब से ही होगा। अगर स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो शिक्षक बढ़ेंगे। सारे पद समाप्त किये और 15-15 शिक्षक जो 10 के ऊपर बैठे थे, उनको वापस गांव में जाना पड़ा। आज जो शिक्षा के अंदर स्थिति बनी है, हम दूसरे पायदान पर पूरे हिन्दुस्तान में आए हैं। ये कोई वैसे ही नहीं आ गये। मैं पिछली सरकार जो आपकी सरकार थी तालाबंदी की सरकार कहूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है, हमको वहम है कि पुन: हम उसी तरफ तो नहीं जा रहे हैं। इस बार डीपीआर की सरकार है। यानी कि बार-बार डीपीआर शब्द का प्रयोग हो रहा है। शिक्षा विभाग सौभाग्यशाली है कि आपने हमारे कक्षा-कक्ष देने के अंदर डीपीआर नहीं लिखा।

इसी प्रकार से पूरी बाप पंचायत समिति और पूरी पंचायत समिति फलौदी के अंदर चार प्रिंसिपल थे और उस समय में डीडीओ यानी ड्राइंग डिसबर्सिंग अफसर, शिक्षकों के वेतन आहरण और वितरण करने के लिए गजटेड अफसर चाहेगा, लगभग 40 स्कूलों के ऊपर चार व्यक्ति थे। दूसरे विद्यालय का, दूसरे विद्यालय में जाकर विड्राल करवाना पड़ता था, यह परिस्थिति थी। अभिभावक पेट काटकर वहां पर भेजते हैं। जब पढ़ाई सही नहीं होती है तो कोशिश करते हैं और प्राइवेट विद्यालयों की तरफ रुझान बढ़ा। लोग वहां पर अपने छात्रों को भेजने लगे। विद्यालय अनार्थिक होते चले गये। हमको यह परिस्थिति दी गयीं। उसके बाद में शिक्षकों की नियुक्ति करने का सवाल आया। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि इसमें चार लाख कर्मचारी शिक्षक हैं। इस बेड़े को संभालना हर एक के बस की बात नहीं है। नियमों में बांधना बहुत जरूरी है। जब नियमों में बंधा है, काउंसलिंग के द्वारा जाएगा, माननीय सभापति महोदय, हमारे बारू, टेकरा दूर-दूर के विद्यालय जो धोरों और टीबों के अदंर है, वहां पर कभी प्रिंसिपल नहीं गया। आज वहां पर 60 से 70 प्रतिशत पद भरे हुए हैं। वहां पर अच्छी शिक्षा मिल रही है और अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। कारण यह है कि मानव संसाधन का, शिक्षकों का समान वितरण पिछली बार किया गया और वे लोग वहां पर पहुंचे। वहां पर आज हर स्कूल में प्रिंसिपल है। इसी व्यवस्था को जारी रखिए। यह हमारे शिक्षा के हित की बात है, हमारे प्रदेश के हित की बात है।

6डी के तहत पिछली बार शहर के शिक्षकों को मुक्त रखा गया था। इस बार आपने उनको शामिल कर दिया तो लोग जाकर कोर्ट से स्टे लाए।

(श्री पब्बाराम)

आपने उसको G.O. (Govt. Order) के द्वारा बाहर भेजा। इस बारे में थोड़ा विचार आप दोबारा कर लें तो ठीक रहेगा।

अभी कोट किया गया कि मनमोहन सिंह जी ने इतना कर दिया, तो आपकी सरकार थी, कौन मना करता था, उस समय ही कर देते। भैरोंसिंह जी शेखावत थे, उस समय सभी पंचायतों पर, कहीं पर भी कोई राजनीति नहीं की गयी। सभी पंचायत मुख्यालयों पर मिडिल स्कूल किये गये। पिछली वसुन्धरा जी की सरकार थी, उस समय में सैकण्डरी स्कूल सभी पंचायत हैडक्वार्टर पर की गयी और अभी पिछली सरकार थी, कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं किया गया। सभी जगह सीनियर सैकण्डरी विद्यालय किया गया। 1 से लेकर 12 तक की सारी एक के नीचे आएगी और मानिटरिंग का सिस्टम बनाया गया। पीईओ बनाया गया यानी कि ब्लाक शिक्षा लेवल का अधिकारी आपके गांव में बैठता है। वह उन प्रशिक्षकों के सारे सर्विस रूल्स, सर्विस पत्रिका पर इन्द्राज करता है। वही सब देखता है, मानिटरिंग देखता है, वाट्सएप के जरिये उसकी हाजिरी मंगा लेता है, हाजिरी सुनिश्चित करता है। शिक्षा में गुणवत्ता आनी शुरू हो गयी। मैरिट में बच्चे आने शुरू हो गये। ये फर्क पड़ता है। मन में कुछ करने की होनी चाहिए। 5600 एक साथ, कुल मिलाकर 5800, 8000 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया। सिस्टम से किया गया। माननीय सभापति महोदय, हमारे वहां पर सिस्टम था। 150 बच्चे अगर मिडिल स्कूल में हो गये और 30 बच्चे अगर 8th क्लास में हैं, सारे के सारे विद्यालयों को क्रमोन्नत करके सैकण्डरी किया गया था। कहीं पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। अभी आप 500 विद्यालय सीनियर सैकण्डरी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सभी जगह सीनियर सैकण्डरी करेंगे। हमने नई पंचायतें थीं, वहां पर मिडिल से सैकण्डरी किया। एक बार क्रमोन्नत हो गया। मेरे वहां पर पांच ऐसे विद्यालय हैं जहां पर सैकण्डरी है, क्योंकि वे मिडिल थीं, सैकण्डरी की, उसके ऊपर सीनियर सैकण्डरी कीजिए। क्या आपका लक्ष्य उन सभी जो वंचित विद्यालय हैं, उनको सीनियर सैकण्डरी करना है? इन 500 में से या म्हारी-म्हारी बकरियां न दूध दही पाऊं, अपने हिसाब से करेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, कुछ बातें, मैं मेरी डिमांड रखना चाहता हूं।

श्री सभापति: आप जल्दी समाप्त करें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): सदस्य बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस मिनट बोलें हैं। मैं शिक्षक हूं और शिक्षक होने के नाते आपका संरक्षण चाहता हूं। पांच मिनट।

श्री सभापति: पांच मिनट तो टोटल ही सबको बराबर दिया जा रहा है। आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): दो-तीन मांगें हैं मेरी। माननीय सभापति महोदय, हम लोग पर्यावरण-पर्यावरण करते हैं। पर्यावरण का पायोनियर, जिस समय पर्यावरण का एबीसीडी नहीं जानता था, 280 साल पहले, अमृता देवी विश्नोई महिला ने खेजड़ी नामक वृक्ष को बचाने के लिए अपने पूरे परिवार, अपनी दो बेटियां, अपने पति और स्वयं को, उन क्रूर शासकों के आगे, कुल्हाड़ी के आगे अपना शरीर देकर उस खेजड़ी को बचाने का प्रयास किया और एक प्रकार का कारवां चल पड़ा। 363 लोग शहीद हुए। इस घटना का जिक्र ग्रीन पीस के अंदर भी किया जाता है। माननीय, इसको आप अपने पाठ्यक्रम में लीजिए। लोगों के अंदर जागरूकता आएगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। अगला नाम जगदीश चन्द्र जी।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय महोदय, दो मिनट में मैं अपनी बात को पूरी करूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य हो गया। आप समाप्त करें। प्लीज हो गया। अगला नाम पुकारा जा चुका है।

श्री पब्बाराम (फलौदी): प्लीज दो मिनट का समय।

श्री सभापति: आप बैठ जाइए। विराजिए आप।

श्री पब्बाराम (फलौदी): मिड-डे-मील वाली बहिनों के लिए मैं निवेदन करूंगा। वे 1300 रुपये ले रही हैं। कोई 1300 रुपये में 500 बच्चों का भोजन बना सकती है क्या? आपने आंगनबाड़ी के लिए किया, केन्द्र ने किया है, आप तो उन माताओं के लिए कीजिए, आपका भला होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। जगदीश जी, आप स्टार्ट कीजिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी): दूसरी बात और...

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापति: जगदीश जी स्टार्ट करिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):000

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, इस खास विषय पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मुझसे पूर्व बहुत से सम्मानीय सदस्यों ने अपने विचार रखे।

श्री सभापति: दस मिनट से ऊपर एक मिनट भी नहीं होगा। सभी का समय बराबर है।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सभापति जी, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया। मेरा टाइम तो खा गये सारा।

श्री सभापति: मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूं।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सबसे पहले तो मैं ...(व्यवधान) हमने तो माननीय सभापति महोदय, सदियों से ढांचे बनाए हैं। जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं। हमने तो लोगों के लिए बनाए हैं और हम तो लोगों के लिए ही हैं। हमारा काम तो सर्व करना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री को इस बात की बधाई देना चाह रहा हूं कि शिक्षा में बजट का इजाफा किया गया है वह निश्चित रूप से बहुत ही आवश्यक था, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने हायर एजुकेशन के लिए मुख्य मंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति की योजना बनाई है, वह भी जोरदार स्कीम है। उसके लिए भी बधाई।

हमारे ज़िले के तीन महाविद्यालयों को जिन्हें डी-नोटिफाई कर दिया गया था, रायसिंहनगर, करणपुर, संगरिया, दुबारा से चालू किया है, उसके लिए हमारे शिक्षा मंत्री जी और सरकार के मुखिया बधाई के पात्र हैं।

महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती है, मैं राजस्थान सरकार और हमारे शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाह रहा हूं कि जिस चीज की काफी साल से कमी महसूस की जा रही थी, शिक्षा के नाम पर इस देश में भेदभाव होता था, राजस्थान की सरकार ने महसूस किया। हमारे मुख्य मंत्री जी ने महसूस

(श्री जगदीश चन्द्र)

किया, पहली बार राजस्थान के अंदर सरकारी स्कूल अंग्रेजी माध्यम से खोलने की शुरूआत की गयी, उसके लिए मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई।

माननीय सभापति महोदय, मुझे 2018 का बजट भी याद है, विपक्ष के नेता बैठे हैं, मैं उसकी चर्चा करना चाह रहा हूं। 2014 का बजट भी मुझे याद है। 2014 का बजट हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने पेश किया, तब एक घोषणा की थी कि प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर भारत सरकार के माध्यम से आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे। मुझे इस बात का अफसोस है कि पांच साल सरकार को हो गये, 2014 का बजट और 2018 का बजट, पांच साल में कितने आदर्श विद्यालय खुले हैं, राजस्थान की जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है।

शिक्षा के बारे में सदन के अंदर जिस तरीके की चिंता व्यक्त की, मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाह रहा हूं कि पिछले 50 साल के अंदर शिक्षा के सुधार के लिए अलग-अलग कमेटी बनी। प्रोफेसर यशपाल ने एनसीईआरटी को सुधारने का प्रयास किया। प्रोफेसर कोठारी की कमेटी बनी उसमें नई शिक्षा नीति की बात की गयी। अल्टीमेटली आज से 50 वर्ष पहले जिस बात की चर्चा करते थे वही चर्चा हम दुबारा से कर रहे हैं।

2004 से 2014 तक हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। सबसे गहन चिंता की बात यह है कि 2004 से 2014 के बीच हिन्दुस्तान ब्रेन ड्रेन हुआ है, यहां से पढ़े लिखे लोग इस देश से बाहर जाने स्टार्ट हो गये हैं। बाहर यूनिवर्सिटी और कालेज सस्ते दामों में पढ़ा रहे थे, हिन्दुस्तान का ब्रेन ड्रेन होना स्टार्ट हो गया। पिछले पांच वर्षों में, जो सरकार दिल्ली में बैठी है, आप अगर शिक्षा के स्तर को देखोगे तो एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है हिन्दुस्तान की, जो अन्तरराष्ट्रीय लेवल की हमारी यूनिवर्सिटी हो। उसके लिए सीधे-सीधे तौर पर मैं दिल्ली की सरकार को जिम्मेदार मानता हूं।

पहली बार देश के एचआरडी मिनिस्ट्री में दसवीं पास शिक्षा मंत्री भारत सरकार का, हायर एजुकेशन का मिनिस्टर, इससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती। यह चिंता का विषय है। बड़े-बड़े भाषण हो रहे थे, मैं इन लोगों के भाषण सुन रहा था ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): भाषण करना अलग बात है। इस देश

(श्री जगदीश चन्द्र)

के अंदर जिस तरीके से हायर एजुकेशन को आपने बर्बाद किया है उसके लिए भी आप लोग जिम्मेदार हैं। आपने यूपीएससी को बर्बाद किया, आपने यूजीसी को बर्बाद किया, आपने एनसीईआरटी को बर्बाद किया। उसका रिजल्ट यह हुआ कि देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जवाहर लाल नेहरू, जहां रिसर्च होती थी, रिसर्च स्कालर पैदा होते थे, उसको बंद करने का प्रयास आपके माध्यम से हुआ, जिसमें आप कामयाब नहीं हो पाए। आपने तर्क दिया कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली का, जहां अलग किस्म के लोग पैदा होते हैं, आतंकवादी पैदा करने की संस्था आपने डिक्लेयर की, इससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती क्योंकि उस विश्वविद्यालय के साथ पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाम है। आपने प्लानिंग कमीशन को खतम किया, आपने इस मकसद से किया कि पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाम इस प्लानिंग कमीशन के साथ जुड़ा हुआ है।

आज नीति आयोग को बने हुए पांच साल हो गये, छठा साल शुरू हो गया। आप विचार कीजिए कि नीति आयोग की कितनी बैठकें हुई। कितनी बार शिक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की गयी, इस बात को आप महसूस कीजिए कि किस स्तर पर आप लोग बैठे हैं।

आप सांस्कृतिक परिवर्तन की बात कर रहे हो, आप महसूस कीजिए कि आप भारत को कहां ले जाना चाह रहे हो। जहां आपको अंग्रेजी स्कूल खोलने चाहिए थे माइनोरिटी की बस्ती में, वहां मदरसे खोलने की तैयारी कर रहे हो ताकि लोग अनपढ़ के अनपढ़ ही रहें और देश की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सकें। यह आपका प्रयास है, यह आपकी मंशा है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे आपसे एक बात और निवेदन करनी है। इन्हीं के राज में एक कमेटी बनी थी गुरु गोविन्द जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कैलाश सारड़ी, जिनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। जिस कमेटी में, राजस्थान के विश्वविद्यालयों में अलग-अलग पद भरे हुए थे जिसमें कंट्रोलर, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कुल मिलाकर 80 पद हैं। कमेटी ने सिफारिश की थी यूजीसी के समान इनको वेतन मिले लेकिन पिछली सरकार ने, इन्हीं के वीसी थे, इन्हीं की कमेटी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। आज उन लोगों को यूजीसी के समान वेतन नहीं मिल रहा। यह बहुत अफसोस और बहुत चिंता की बात है जो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं।

(श्री जगदीश चन्द्र)

माननीय सभापति महोदय, मुझे एक निवेदन और करना है, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। आप सही मायने में शिक्षा के बारे में चिंता कर रहे हो, आपको अन्तरराष्ट्रीय लेवल पर जाना है, भारत को 21वीं सदी में ले जाने की बात कर रहे हो, 21वीं सदी उसी देश की होगी जिस देश का नालेज बढ़ेगा। नालेज बढ़ेगा तो कान्फिडेंस बढ़ेगा और नालेज शिक्षा के माध्यम से ही किसी भी देश का बढ़ता है। आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए, इस बात को महसूस करना चाहिए कि आज इतने लंबे समय के बाद भी हर साल बजट आता है और शिक्षा पर चर्चा होती है और हम कोई न कोई आयाम शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। आप पुन: विचार करें।

मैं माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपने एक ज़िले में एक अंग्रेजी का स्कूल खोला है, मेरी आपसे प्रार्थना है, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप तो आगे बढ़िए और राजस्थान के प्रत्येक ग्राम पंचायत में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोलिए ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें। दुनिया के लेवल पर जा सकें और अपनी प्रतिभा दिखा सकें, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): मुझे अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में आपसे निवेदन करना है। मेरा विधान सभा क्षेत्र अन्तरराष्ट्रीय बोर्डर पर है, 17 ग्राम पंचायतें जीरो लाइन से दस किलोमीटर के अंदर हैं। पंजाब लगता हुआ है दो तरफ। हमारे स्कूल हैं जिनको अपग्रेड करने के लिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धींगतानिया, ग्राम पंचायत नूरूपुरा आठवीं से दसवीं करने का। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हाथियावाली, ग्राम पंचायत खेरूवाल आठवीं से दसवीं करने का। राजकीय विद्यालय अमरगढ़, ग्राम पंचायत करडवाला दसवीं से बारहवीं करने का। इसके साथ-साथ एक बोर्डर का गांव है। अन्तरराष्ट्रीय सीमा से सात किलोमीटर पर मटीलीराठान, जहां सब्जैक्ट खोलने का निवेदन कर रहा हूं, हिन्दी साहित्य, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान।

(श्री जगदीश चन्द्र)

(15.49 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ में मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा एक पंजाबी गांव है खाराचक पंचायत है, पूरा गांव पंजाबियों का गांव है वहां संस्कृत विषय लगा रखा है। मेरा आपसे निवेदन है कि पंजाबी के टीचर की वहां भर्ती करें और राजकीय बालिका सीनियर सैकण्डरी, सादुलशहर गवर्नमेंट का एक स्कूल है।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सरकार की सारी स्कीमें गरीबों के लिये होती हैं। सारी सरकारी स्कीम्स गरीबों के लिये होती हैं। सरकारी स्कूलों में कोई बड़े लोग नहीं पढ़ते। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरकार ऐसा बिल लेकर आये, कम से कम, जन-प्रतिनिधियों के बच्चे, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे उन सरकारी स्कूलों में जरूर पढ़ें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): एक मिनट, एक मिनट लूंगा।

राजकीय महिला महाविद्यालय, सादुलशहर में स्नातकोत्तर पी.जी. हिन्दी और राजनीति विज्ञान का संकाय शुरू करने का निवेदन करना चाह रहा हूं। यूजी.सी. में पंजाबी ...(व्यवधान) और पंजाबी के लैक्चरर नहीं हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री बाबुलाल खराड़ी।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): यह संकाय शुरू करने का मैं निवेदन करूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस मांग संख्या 24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

सभापति महोदय, शिक्षा में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में पेज नम्बर 30, आपने शुरुआत की सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यालय सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत हम कक्षा-कक्ष बनाएंगे। सभापति महोदय, आप कक्षा-कक्ष भी बनाएंगे, विद्यालय भी खोलेंगे और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी आप उनको मदद करेंगे।

(श्री बाबुलाल)

सभापति महोदय, आज काफी चर्चा हुई। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने नैतिक मूल्यों की बहुत जबर्दस्त बात कही। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है, इसके लिये जिम्मेदार कौन है? बहुत लम्बे समय तक हिन्दुस्तान की धरती पर कांग्रेस का शासन रहा और शासन के बाद में जो शिक्षा नीति हमारे देश में लागू की गयी मावली से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने थोड़ा सा जिक्र किया। लार्ड मैकाले, उसने इस देश में घूम-घूम करके अध्ययन करके पता लगाया कि हिन्दुस्तान पर लम्बे समय तक राज करना है, गुलाम करना है तो क्या किया जाए। उन्होंने देखा कि शिक्षा नीति में हम परिवर्तन करेंगे तब जाकर कुछ पाएंगे। उन्होंने जा करके उन शासकों से कहा कि मुझे कुछ समय चाहिए तो हम हिन्दुस्तान में लम्बे समय तक राज कर सकते हैं।

सभापति महोदय, उन्होंने पूरा अध्ययन करने के बाद में, शिक्षा नीति की क्या हालत हो गयी। हिन्दुस्तान में हम सस्ते बाबू पैदा करेंगे, मालिक पैदा नहीं करेंगे इसीलिये हम आज क्या पढ़ाते हैं। 'ग' से 'गंगा' नहीं पढ़ाएंगे, 'ग' से 'गणेश' नहीं पढ़ाएंगे। कारण 'गणेश' का नाम आ जाएगा, 'गंगा' का नाम आ जाएगा, साम्प्रदायिकता फैलेगी, सम्प्रदाय की बू आती है। इसी कारण आज हमारे नैतिक मूल्य गिरे हैं। इसके लिये जिम्मेदार कौन हैं?

हमारे देश में पहले घरों के दरवाजे पर लिखा रहता था 'अतिथि देवो भव', आने वाले अतिथि को हम देवता मानते थे। धीरे-धीरे समय आता गया, बदलता गया, 'भले पधारो', फिर 'वैलकम', आज क्या लिखा रहता है 'कुत्तों से सावधान'। हमारी क्या गिरावट आयी है, सभापति महोदय, इतनी हमारी गिरावट आयी है, उसके लिये जिम्मेदार कौन है?

आज हमारे यहां औरतों में झगड़े होते हैं तो व्यंग्य के रूप में कहते हैं, तू सती सावित्री है क्या। 'सावित्री' का उदाहरण पढ़ना हो तो गरुड़ पुराण में अंतिम अंतरे में पढ़ लेना। आप सबको ज्ञान होगा। ये हमारे देश के नैतिक मूल्य थे। श्रवण कुमार, जिसने अपने माता-पिता को चार धामों की यात्रा के लिये कंधे पर ढो करके सारे चार-धामों की यात्रा करायी। वे नैतिक मूल्य थे। आज हम कहां जा रहे हैं।

अभी सादुलशहर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने जे.एन.यू. का जिक्र किया था, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। हमारे हिन्दुस्तान का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। आज वहां पर 'कश्मीर की आजादी तक हम लड़ते रहेंगे, इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह', यह नारे लगते हैं।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): आप पकड़ते न उनको।

श्री बाबुलाल (झाडोल): ये नारे लगते हैं।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): पकड़ते।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): पकड़ लिया।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): किसको पकड़ लिया?

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सबको पकड़ लिया।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री बाबुलाल (झाडोल): इसके लिये जिम्मेदार कौन हैं। (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): बाकी को भी पकड़ लेंगे।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री बाबुलाल (झाडोल): सभापति महोदय, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। मैं शिक्षा पर मेरे क्षेत्र की कुछ मांगों पर आना चाहूंगा।

श्री सभापति: चर्चा नहीं करें आप।

श्री बाबुलाल (झाडोल): आपने कहा कि युवाओं की बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिये विभिन्न विभागों द्वारा 75 हजार पदों की भर्तियां करेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार को कहना चाहता हूं कि हमारे यहां 4500 शारीरिक शिक्षकों की भर्तियां निकालीं। उनकी परीक्षा हो गयी। उनके दस्तावेजों की जांच हो गयी। यह कब हुआ था? 2018 में, होने के बाद में आज वे शारीरिक शिक्षक, अपने, कब भर्ती करेंगे हमको, कब रोजगार मिलेगा, इसके इंतजार में वह खड़े हैं। बार-बार ज्ञापन दिये, आंदोलन किये। सरकार इस ओर भी ध्यान दे।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, एक मिनट में।

श्री बाबुलाल (झाडोल): आगे चल करके, 2012 में आप ही की सरकार थी। आपने तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिये भर्तियां निकालीं। आपने 136 अंक तथा अंतिम कट-आफ 143 के बीच के, ये तो आपने ले लिये लेकिन इसमें सामाजिक विज्ञान विषय के जो अध्यापक लेने थे, वे आपने नहीं लिये। मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि आप जल्दी निकालें ताकि बेरोजगारों की समस्या दूर हो।

दूसरा मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, हमारा झाड़ोल क्षेत्र

(श्री बाबुलाल)

पिछड़ा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में भी, और वहां पर विद्यालय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर सीनियर स्कूल ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बाबुलाल (झाडोल): एक मिनट लूंगा, एक-दो मिनट। विद्यालय सारे खोल दिये। आज विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। वहां कौन पढ़ाएगा। वहां का बच्चा डाक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, बैंकिंग सेवा में जाना चाहता है। वहां पर ये सब्जैक्ट नहीं हैं, यह विषय नहीं हैं। झाड़ोल क्षेत्र में पांच विद्यालयों में विज्ञान वर्ग है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बाबुलाल (झाडोल): सभापति महोदय, विज्ञान वर्ग भी खोलें, कामर्स भी खोलें और सब्जैक्ट टीचर, विषय-विशेषज्ञों को वहां लगा करके उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में आप मदद करें।

दूसरा, मेरा अंतिम पाइंट है कि हमारे यहां विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है। हमारे गुजरात से लगते हुए पंचायत में मैं गया और उन स्कूलों की हालत देखी। बहुत पुराने स्कूल भवन बने हुए हैं। उन पर पट्टियां लगी हुई हैं। कभी भी वे विद्यालय भवन गिर सकते हैं। बालकों के लिये यह बहुत चिंता का विषय है। इसलिये उन स्कूलों को नया बनाया जाए।

दूसरा, एक विद्यालय हमारे उमरिया पंचायत में है। वह विद्यालय अभी बरसात में गिर गया। यह हालत है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय से बात कर लेना। विराजिये, विराजिये।

श्री बाबुलाल (झाडोल): इसलिये, सभापति महोदय, मुझे आपसे कहना है कि विद्यालयों के भवन निर्माण करवाएं ...(व्यवधान) और उसके बाद में शिक्षकों की भर्ती कराएं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: विराजिये। श्री बलवान पूनियां। विराजिये, आप विराजिये। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। आप माननीय मंत्री महोदय से बात कर लेना।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24 पर चर्चा करते हुए मैं यह बात कहना चाहता हूं कि 'शिक्षा पर जो खर्चा

(श्री बलवान पूनियां)

हो, बजट का दसवां हिस्सा हो।' यह नारा हम विद्यार्थी जीवन से, एस.एफ.आई. में काम करते थे, तब भी लगाते थे। दीवारों पर लिखते थे। मैं तो खुद विद्यार्थी राजनीति से यहां पहुंचा हूं। आज भी विद्यार्थियों की यह मांग रहती है कि जी.डी.पी. का 6 प्रतिशत, केन्द्रीय बजट का 10 प्रतिशत और राज्य बजट का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च हो।

(16.00 बजे)

कोठारी कमीशन 1964 में बना था, उसने भी यह सिफारिश की थी कि शिक्षा पर जी.डी.पी. का 6 प्रतिशत खर्च होना चाहिए। केन्द्र के इस साल के बजट में जी.डी.पी. का केवल 3.4 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। आप आश्चर्य करेंगे कि वर्ष 2014-15 में यह 4.3 प्रतिशत था और वर्ष 2018-19 में यह घटकर 3.74 प्रतिशत हुआ है। 2019 के अंतरिम बजट में यह 3.5 प्रतिशत और 2019-20 के बजट में यह 3.4 प्रतिशत केन्द्र में रहा है।

दुनिया का एक छोटा सा देश क्यूबा है। उसका बजट शिक्षा पर जी.डी.पी. का 12 प्रतिशत है। गर्भ में जब बच्चा आता है उससे लेकर कब्र तक जब जाता है तब तक मुफ्त चिकित्सा और शिक्षा, नर्सरी से पीएच.डी. तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान क्यूबा ने कर रखा है इसीलिए हमारे यहां पर फिर से शिक्षा में केरल ही आदर्श माडल बना है और केरल बजट का 15 से लेकर 18 प्रतिशत खर्च करता है। वर्ष 2017-18 में 18 से 23 साल के केवल 25.8 प्रतिशत युवा उच्च शिक्षा में पंजीयन करवा पाते हैं। हमारे यहां पर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं पिछली सरकार ने अपने अंतिम बजट में भादरा समेत जो 18 कालेज खोले थे बिना भवन के, धन्यवाद है कि इस साल इस सरकार ने उनको भवन देने का काम किया है। इस बजट में नये 32 राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी की लेकिन आज भी राजकीय कालेज एक-एक लैक्चरर के भरोसे चल रहे हैं या फिर लेक्चरर, जैसे सारे साथी भाग लेते हैं तो सारे साथियों की यह मांग रहती है कि वहां स्कूल में भवन नहीं है, कालेज में भवन नहीं है, लैक्चरर नहीं है, और तो और इस सदन में बैठने वाले सात बार जीतकर आने वाले माननीय सदस्य, जिनकी विभाजन संख्या-138 है, वह लिख रहे हैं कि- 'विधान सभा क्षेत्र चूरू के विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के लिये।' इस पर यह यहां पर चर्चा करना चाहते हैं। बड़ी-बड़ी डींगें इधर हांक रहे थे, उनका यह मांग-पत्र है,

(श्री बलवान पूनियां)

कटौती प्रस्ताव में यह लिख रहे हैं। यह लिख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में आज भी प्रिंसिपल नहीं है, लैक्चरर नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार हम सब लोग हैं इसलिए हम यह चाहते हैं कि शिक्षा पर हमारा बजट बढ़े और विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा दी जाए। कालेज लैक्चरर की भर्ती की जो घोषणा हुई है, वह पिछली सरकार की तरह ज्यादा लंबी नहीं चले। एकदम रफ्तार के साथ एक हजार लैक्चरर लगाने की सरकार ने जो हिम्मत की है, उनको लगाएं और जल्दी से उनके साक्षात्कार और परीक्षा सब कुछ कमप्लीट करवाएं।

सरकारी स्कूलों की दयनीय हालत है। कक्षा-कक्ष की दयनीय हालत है। अधिकतर स्कूलों में भौतिक संसाधन नहीं हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने स्कूलों के नाम के आगे आदर्श और उत्कृष्ट विद्यालय लिखवाये थे, यह वही बात है जो किसी जमाने में कहा गया था कि 'फील गुड' करो यानी आप भूखे हो तो आप यह महसूस करो कि आपने हलवा खाया हुआ है। आपको यह महसूस हो रहा है कि आपको एसिडिटी होने वाली है। ऐसे ही आदर्श विद्यालय नाम रखा गया इसलिए सिर्फ नाम से नहीं, हमें काम से परिचय विद्यार्थियों को करवाना है, समाज को करवाना है ताकि स्कूलों की हालत सुधरे और प्रत्येक स्कूल में डिजिटल क्लास रूम, लाइब्रेरी, खेल मैदान, प्रयोगशाला, शुद्ध पेयजल, शौचालय, स्टाफ क्वार्टर की व्यवस्था करनी होगी। यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी रहेगी।

जिला प्रशिक्षण संस्थान 'डाइट' उच्च उद्देश्यों को लेकर स्थापित किये गये थे लेकिन जिला शिक्षक प्रशिक्षण 'डाइट' जो कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थित हैं, इनमें खूब सारे पद खाली पड़े हैं। जिन स्कूलों के शिक्षकों को स्थानांतरित किया जाता है, पिछली सरकार ने इन पदों को भरने की प्रक्रिया तो शुरू की थी पर मानक इतने हार्ड रखे कि आज तक यह पद भर नहीं पाए जिससे आज भी यह पद खाली हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव करनपुरा, बिराण, जोगीवाला में कई विज्ञान संकाय, निनाण में विज्ञान और एग्रीकल्चर संकाय, झांसल और मलसीसर में कृषि संकाय खोले जाने की मांग भी है। मैं जिस सरकारी स्कूल निनाण स्कूल में पढ़ा हूं 12वीं तक एग्रीकल्चर में, आज एग्रीकल्चर के तीनों अध्यापकों की, लैक्चरर की वहां पर सीट खाली पड़ी है। आज से नहीं, सात साल से खाली है। यह पोजिशन दोनों सरकारों की स्थिति

(श्री बलवान पूनियां)

में रही है इसलिए मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं कि अभी एक बहुत बढ़िया स्कूल रन कर रहा था, रामगढ़ का 16 DPN, जिसके अंदर आज भी लैक्चरर की मांग को लेकर लोग बार-बार ज्ञापन दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं।

शिक्षा मंत्री महोदय, आपके शिक्षक आपके कार्य से खुश हैं लेकिन कई दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। आपको सरकार में नम्बर वन रैंक का मंत्री भी लोग बता रहे हैं। मैं पम्प नहीं मार रहा हूं, इसमें लिखा है, कई शिक्षकों से आया है। आपने शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना पर अभी तक सकारात्मकता नहीं दिखाई है इसलिए थोड़े-थोड़े आपसे नाराज भी हैं। शिक्षकों की मेहनत की कमाई को बाजार के हवाले करना जायज नहीं है। हम यह बहाना कर लें कि साहब, केन्द्र नहीं मानेगा। केन्द्र नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। नहीं, राज्य मजबूती के साथ में खड़ा हो तो केन्द्र भी एक दिन आपका हो जाएगा। क्या बात हो गयी, गया तो गया, आ जाएगा इसीलिए ओ.पी.एस. को आप लागू करेंगे। शिक्षकों के ट्रांसफर के मामले में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात को एक मिनट में समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): नहीं, दो मिनट तो देनी पड़ेगी। साहब, विधायक दल का नेता हूं, दल छोटा है तो क्या हुआ।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): शिक्षकों के ट्रांसफर की चर्चाएं आप लगातार कर रहे हैं। चुपके-चुपके थोड़े-बहुत ट्रांसफर हो भी रहे हैं। शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु स्थाई ट्रांसफर नीति का आप निर्माण करें। असाध्य पीड़ित रोगी, विधवा, परित्यक्ता, पति-पत्नी के प्रकरण में ट्रांसफर आवेदन से ही हो, पोस्टिंग उनको ढंग से मिले, म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी आप तुरंत आदेश करें और आप बढ़िया सी नीति लेकर आएं। आप ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं करें कि बंशीधर बाजिया का मुझे फिर से जिक्र इस सदन के अंदर करना पड़े।

हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर जिले के हजारों नौजवान सुदूर राजस्थान के उस क्षेत्र में रहते हैं जो टी.एस.पी. क्षेत्र बताया जाता है। टी.एस.पी. क्षेत्र के लिए 2014 में यह आदेश हो गया था कि वहां पर जो बाहर

(श्री बलवान पूनियां)

के लोग रह रहे हैं उनको बाहर निकाला जाएगा और टी.एस.पी. क्षेत्र के लोगों को वहां पर नियुक्ति दी जाएगी। उससे एक तो आदिवासी क्षेत्र के लोग नौकरी लगेंगे और एक वह लोग जो आठ, दस, बारह साल से टी.एस.पी. क्षेत्र में बैठे हैं वह अपने घरों की तरफ चले जाएंगे इसलिए माननीय सभापति महोदय के मार्फत शिक्षा मंत्रीजी मैं आपको कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री रामनिवास गावडिया।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): थोड़ी सी बात और रह गयी। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी जो डिग्री बेच रही है और सनराइज यूनिवर्सिटी, अलवर जो डिग्री बेच रही है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री रामनिवास गावड़िया। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): एक मिनट। लास्ट एक मिनट। मैंने पहले कभी तो जिद की नहीं, आज एक मिनट, लंबा विषय है।

इन दोनों यूनिवर्सिटीज की आप जांच करवाएं। भादरा में एक इंडोर स्टेडियम खोलकर हम देंगे, बंद किये गये स्कूलों को आप खोलने का कष्ट करेंगे क्योंकि हम लोगों से वादा कर चुके हैं कि जो स्कूल पिछली सरकार ने बंद किये थे उसमें से पांच-पांच, सात-सात स्कूल तो हर विधान सभा क्षेत्र में, हर विधायकों को पूछकर, नाम भी दे दिये गये, अब लोग पूछ रहे हैं कि साहब, 19 तारीख हो गयी, 20 तारीख तक प्रवेश की तिथि है इसलिए बंद किये हुए स्कूलों को खोलने के लिए आज रात को ही आप जरूर कोई बड़ा काम करेंगे। तबादला उद्योग पर रोक लगाएंगे और नई नीति बनाएंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): जो कार्यक्रम दम तोड़ रहे हैं उनको वापस लेकर आएंगे। कोचिंग सेंटरों के लिए आप कानून बनाएंगे, कोटा और सीकर में जो एजुकेशन हब बना है लेकिन वहां पर विद्यार्थियों की जो आत्महत्याएं बढ़ रही हैं उनको रोकने की तरफ भी आप कदम उठाएंगे।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): एक छोटी सी मांग है। तृतीय श्रेणी की शिक्षक भर्ती, 1998 में नियुक्ति की उच्च वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग मैं करता हूं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में

(श्री बलवान पूनियां)

कुलपति +++ और प्रोफेसर +++ द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच की मांग मैं करता हूं। संविदा व्याख्याता संघर्ष समिति के मांग पत्र के अनुरूप 2008 में कार्यरत संविदा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। श्री रामनिवास गावडिया। अब अंकित नहीं होगा।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री सभापति: हां, आप मंत्री महोदय से मिल लेना। श्री रामनिवास गावडिया।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, वैदिक युग से लेकर आज दिन तक हमारे देश ने शिक्षा में संस्कारों को, नैतिक मूल्यों को इतना महत्व दिया है कि इसी वजह से हमारा देश विश्व गुरु कहलाया।

माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को परबतसर की जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने बजट भाषण में परबतसर में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और उच्च शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा और राजस्थान में 32 नए महाविद्यालय खोलने की जो घोषणा बजट भाषण में हुई यह इस बात को दर्शाता है कि हमारी सरकार शिक्षा को लेकर कितनी संवेदनशील है।

माननीय सभापति महोदय, हमें काफी जगह देखने को मिला, पढ़ने को मिला कि एक प्रदेश का आम किसान का बेटा पढ़-लिखकर ऐसे पद पर जाए, जहां से प्रदेश की नीतियों का निर्माण होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि शिक्षा जैसे विभाग के मंत्री के रूप में एक किसान का बेटा मौजूद है तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को निश्चिंत रहना चाहिए कि शिक्षा के माध्यम से आने वाले पांच सालों में राजस्थान प्रगति करेगा।

माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी ने शाला दर्पण की जो घोषणा की है, जिसमें स्टाफ कार्नर का भी एक आप्शन दिया है। इससे पूरे प्रदेश के शिक्षकगणों में खुशी का माहौल है। जब भी हम लोग गांवों में जाते हैं तो

(श्री रामनिवास गावड़िया)

आज शिक्षा मंत्रीजी के लिये जो लोगों में चर्चाएं हैं, वह वास्तव में काबिले-तारीफ है कि एक किसान का बेटा शिक्षा मंत्री के पद पर बैठकर इस राजस्थान में सबसे ज्यादा काम कर रहा है। इस बात के लिये मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

आज अभी पूर्ववर्ती सरकार के शिक्षा मंत्रीजी बोल रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने योग का बहिष्कार किया। मैं इस सदन के सामने बात रखना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, योग और शारीरिक व्यायाम की शिक्षा प्राचीन समय से हमारे स्कूलों में दी जा रही है, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि जब पेट में खाने के लिये दाने नहीं हैं और इनकी सरकार ने नोटबंदी के माध्यम से लोगों की जेब खाली करा दी तो योग याद नहीं आता साहब। इन्होंने एक बाबा को पकड़ा और उसने इस पूरे देश को योग का मंत्र दिया। दिलचस्प बात देखिए साहब, आज वही बाबा व्यापार में लग गया और पूरे देश को योग में लगा दिया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि स्कूल में जो साइकिलें वितरित की जा रही थीं, उसमें इन्होंने भगवा रंग देकर 8 करोड़ 30 लाख रुपये का बजट, जो जनता की गाढ़ी कमाई थी, उसका दुरुपयोग किया है। उसका जवाब आज भी राजस्थान की जनता इनसे मांग रही है।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने यूनिफार्म बदलने का काम किया, स्कूलों में पाठ्यक्रम बदलने का काम किया और जिन लोगों ने, इस देश की महान आत्माओं ने इस देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दे दिया, उन लोगों का नाम पाठ्यक्रमों से हटाने का काम किया। लेकिन मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस देश के लिये बलिदान दिया, उनको यह लोग पाठ्यक्रमों से हटा सकते हैं, हमारे दिल से नहीं निकाल सकते।

माननीय सभापति महोदय, आज सुबह माननीय सदस्य जब खुद के श्रीमुख से कह रहे थे कि हमने साढ़े 22 हजार स्कूलें बंद कर दीं, शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, इनको वापस चालू करवाइए और इन्हीं के माननीय सदस्य जोर-जोर से ठहाके लगाकर हंस रहे थे। मैं कहता हूं आपके माध्यम से, इस बात के लिये इनको शर्म आनी चाहिए कि एक तो इन्होंने साढ़े 22 हजार स्कूल बंद कर दिये और उसके बाद इस तरह का यहां पर माहौल बनाया जा रहा है, राजस्थान की साढ़े सात करोड़ की जनता इन लोगों से जवाब मांग रही है।

(श्री रामनिवास गावड़िया)

मैं आज भी राजस्थान विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूं। पूर्ववर्ती सरकार में इन लोगों ने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को, हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी को बंद किया और यहां सदन में तत्कालीन गृह मंत्रीजी बैठे हैं, यह लोग राजस्थान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर आये थे और हमने इनको काले झण्डे दिखाये थे, क्योंकि हमारे प्रदेश का नौजवान सड़कों पर उतरा हुआ था। लेकिन, इन्होंने क्या किया, हम लोग जेल काटकर आये चार-चार दिन तक।

सभापति महोदय, आज प्रदेश की जनता इन लोगों से जवाब मांग रही है कि जिस शिक्षा नीति की यह लोग बात करते हैं, हमेशा से किसान को, नौजवान को इन्होंने ठगा है। आज मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा..

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): जब वह अपना रिप्लाई दें तो मैं चाहूंगा कि जो आज बड़ी प्राइवेट स्कूलें हैं जिनमें लाखों की फीस वसूली की जाती है। उन स्कूलों से पब्लिक नाम हटाया जाए, क्योंकि पब्लिक तो उसी के नाम के आगे लग सकता है, जहां गरीब का बेटा पढ़ सकता है, गरीब की बेटी पढ़ सकती है। यह माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा।

माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आंगनबाड़ी पोषाहार की जो पारदर्शिता है, उसको बनाये रखने के लिए चाकसू में जो पायलट प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया, उसके लिये मैं सरकार को बधाई दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बात रखना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार के माननीय मंत्रीजी सुबह कह रहे थे कि 26वें स्थान से दूसरे स्थान पर शिक्षा जगत में राजस्थान आया और उसी का विज्ञापन बड़े-बड़े अखबारों में लगा। भरतपुर का एक गांव है। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): मंगलाधोरा, उसका एक बच्चा है नितिन, उसकी फोटो उस स्कूल के विज्ञापन पर लगी हुई थी, जब उस बच्चे से पूछा गया कि बेटे, आपके स्कूल में किस तरह की पढ़ाई की जाती है तो उस विज्ञापन में एक बड़ा सा एड लगा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था कि हमारी स्कूल में उचित फर्नीचर मिलता है।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग। (अनुपस्थित) श्री विट्ठल शंकर अवस्थी। विराजिए।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की बात रखना चाहूंगा एक मिनट में।

श्री सभापति: आप लिखकर दे दीजिए माननीय मंत्री महोदय को।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): एक मिनट के लिये।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, सहयोग करें। विराजिए। विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। आप मंत्री महोदय को लिखकर दीजिए। माननीय सदस्य, प्लीज विराजें।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप नये सदस्य हैं, आप सहयोग करिये। विराजिए आप। विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): 000

श्री सभापति: विट्ठल शंकर अवस्थी। माननीय सदस्य, कुछ समय सीमा है, उसके बाद फिर कोई माननीय सदस्य आग्रह नहीं करेंगे। समय की मर्यादा है। चार माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे और अभी आप लोग सारे के सारे बोलेंगे तो, जो मैंने समय निर्धारित कर रखा है सात मिनट का, उसके हिसाब से आपको पांच घंटे चाहिए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अभी 10 मिनट बताकर गये हैं सभापति महोदय हमको।

श्री सभापति: आप सात मिनट में समाप्त करेंगे, यह आसन की व्यवस्था है। माननीय श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मांग संख्या-24-शिक्षा, कला और संस्कृति पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपका आभार। मैं अपनी बात की शुरूआत शास्त्र के एक श्लोक से करना चाहता हूं-

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

'न चौर चौर्यम् न च राजहार्यं, न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी।
व्यये कृते वर्धते एवं नित्यं, विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्।।'

मैं आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो शास्त्र की उक्ति है, इसको अगर आपने बच्चे की शिक्षा के शुरूआत में पढ़ाने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से इस देश के लिये आप भला करेंगे। इसका अर्थ यह होता है कि शिक्षा एक ऐसा धन है, जिसको न चोर चोरी कर सकता है। न चोर चोर्यम् न च राजहार्यं, न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी। न राज्य का इस पर कोई टैक्स लगता है। कितना भी विद्वान बनेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। न भाइयों में इस धन का बंटवारा हो सकता है और सबसे बड़ी बात है यह कोई बोझ वाली चीज भी नहीं है। जितना विद्वान होगा, उतना विनम्र होगा, वह बोझ से दबेगा नहीं। सबसे बड़ी बात है इसको जितना खर्च करोगे, उतना बढ़ेगा। इस तरह से शिक्षा के बारे में हमारे प्राचीन ऋषियों ने, मुनियों ने कल्पना की थी, ऐसी शिक्षा आज सर्वथा समाप्त हो चुकी है और आज हम जो शिक्षा दे रहे हैं, उस शिक्षा के माध्यम से केवल और केवल हम पेट भरने की शिक्षा देने जा रहे हैं। जिस तरह से आज हमारे बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में हो रहा है, अधिकांश शहरों में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की जो प्रवृत्ति चली है, लाख-लाख रुपये का डोनेशन, दो लाख रुपये का डोनेशन देकर, जिसकी शुरूआत में नींव अगर हम भ्रष्टाचार से डालेंगे, उस शिक्षा का आगे जाकर क्या विकास हो सकता है, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं।

सभापति महोदय, आज जिस तरह का व्यापार प्राइवेट विद्यालयों ने शुरू किया है, आज सबसे बड़ा धंधा चिकित्सा और शिक्षा को माना जाता है। गोविन्द गुरु, कृपा करके आप मेरी बात को सुनें। अगर आपमें थोड़ी भी शिक्षा के प्रति चिंता है तो शिक्षा और चिकित्सा को जो व्यापार बनाया जा रहा है उसको अगर आपने रोका तो आप राजस्थान का बहुत भला करेंगे। यह मैं आपसे निवेदन करता हूं। जिस तरह के डोनेशन और प्राइवेट स्कूलों को जिस तरह की छूट मिली हुई है, मनमर्जी की फीस, मनमर्जी का पाठ्यक्रम, मनमर्जी की पुस्तकों का, बैग और किताबें खरीदना, यहां से खरीदो, ड्रैस खरीदना है यहां से खरीदो, जिस तरह की लूट मची हुई है इसको रोकने का हमारे राजस्थान में निश्चित रूप से प्रयास होना चाहिए जिससे शिक्षा को एक नई दिशा मिल सके।

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

गत सरकार ने जिस तरह से शिक्षा के लिए काम किया, मैं कहता हूं कि वे एक आदर्श स्थिति बनाकर छोड़ कर गये हैं, आपको विरासत में देकर गये हैं। पूरे 70 साल की आजादी के बाद 4 हजार 500 पंचायतों में सीनियर सैकण्डरी स्कूल थे, एक आदेश से 6 हजार 500 नई स्कूलों को सीनियर सैकण्डरी में परिवर्तित करवाया, जो एक इतिहास है। 70 सालों में 4 हजार 500 और एक आदेश से 6 हजार 500 नये सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलना। हमको पता है जब हमने हमारे गांव सीनियर सैकण्डरी स्कूल खुलवायी थी तो तीन-तीन विधायक चेंज हो गये थे, हमारी चप्पलें घिस गयी थीं। रोज नेता के पास जाते थे कि हमारे स्कूल में जरूरत है, साहब, हमारे सीनियर बनाओ। जूते घिस गये थे लेकिन सीनियर नहीं बनी थी। एक आदेश से, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपयी ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरूआत करके सड़क से राजनीति को दूर किया इसी तरह से शिक्षा से राजनीति को दूर करने का कार्य पूर्ववर्ती भा.ज.पा. सरकार ने और शिक्षा मंत्री ने किया है। हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस तरह एक आदेश से, देश में ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जो बिजली से रहित होगा, उज्ज्वला गैस योजना का उन्होंने प्रस्ताव पारित किया, इसी तरह से मेरा निवेदन है कि एक आदेश से अब राजस्थान को जरूरत है कि किस तरह से सौ प्रतिशत साक्षर बना सकते हैं। जो यह आंकड़ेबाजी का खेल है, उस मकड़जाल से निकल कर वास्तविक साक्षरता जिसको कहते हैं किस तरह हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, एक आदेश पारित होना चाहिए जिससे राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में देश में सबसे प्रथम स्थान पर जाकर खड़ा हो।

सभापति महोदय, 2013 तक जो गत कांग्रेस सरकार थी, मैं उस वक्त भी विधायक था और जो स्कूलों की हालत थी, किसी विद्यालय में एक टीचर, किसी विद्यालय में दो टीचर, 400-400 बच्चे दो-दो टीचर, पांच साल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा के तंत्र को सम्पूर्ण रूप से बदला गया और काउंसलिंग की व्यवस्था शुरू की जिससे शिक्षकों की नियुक्ति में राजनीति और भ्रष्टाचार दोनों समाप्त हुआ, आप उस व्यवस्था को लागू रखें जिससे शिक्षा में राजनीति और भ्रष्टाचार समाप्त हो सके। यह मेरा आपसे निवेदन है।

पूर्ववर्ती सरकार ने एक और जोरदार निर्णय किया कि सरकारी स्कूलों में जिले में एक विद्यालय ऐसा होगा उसमें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करायी जाएगी।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, एक मिनट में।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): उस विद्यालय का यह परिणाम आया, मेरे भीलवाड़ा शहर में राजेन्द्र मार्ग स्कूल है, पिछले साल वहां अंग्रेजी माध्यम से सीनियर स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई थी और आज यह हालत है कि उस स्कूल में प्रवेश के लिए लोग सिफारिशें करवाते हैं। यह जो प्रयोग किया गया है निश्चित रूप से हमारी सरकारी शिक्षा के लिए बहुत जोरदार प्रयोग है और प्रत्येक जिले में, मैं तो कहता हूं प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक ऐसा विद्यालय होना चाहिए जिसमें अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा हमारे सरकारी स्कूलों में दी जाए।

सभापति महोदय, भीलवाड़ा शहर में चार कालेज हैं, एमएलवी गवर्नमेंट गर्ल्स कालेज, एमएलवी बॉय कालेज, लॉ कालेज और एग्रीकल्चर कालेज।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरे भीलवाड़ा के चारों कालेजों में व्याख्याताओं की बहुत कमी है, कृपा करके जिस भी तरीके से आप उनमें व्याख्याता की भर्ती कर सकें, कृपा करके लगाएं।

श्री सभापति: सुश्री दिव्या मदेरणा। (अनुपस्थित)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, अंतिम बात।

श्री सभापति: श्री रोहित बौहरा।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, अंतिम बात।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): धन्यवाद।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एजुकेशन पर मैं अपनी बात आपका जो निर्धारित समय है उसमें ही पूरी कर दूंगा। मैं सबसे पहला पाइंट कह रहा हूं कि यहां पर सब लोग स्कूलों की बात कर रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा यह है कि वहां पर बच्चों को जो मिड-डे-मील दे रहे हैं, the quality of the mid-day meal. यदि कोई भी आदमी आकर देखेगा तो अच्छे-अच्छे स्कूलों में आप वह खाना खाना पसंद नहीं करोगे। मेरी इतनी-सी विनती है कि अक्षय पात्र एक एन.जी.ओ. है पूरे

(श्री रोहित बौहरा)

जयपुर जिले को, भीलवाड़ा जिले को और कई जिलों में वे खाना बांटते हैं और उनकी एक मैकेनाइज्ड किचन है, वे लोग मैकेनाइज्ड किचन से खाना बांटते हैं। शिक्षा मंत्री महोदय से मेरी विनती है कि जितना पैसा खाना बनाने के लिए मास्टरों में देते हैं उतना पैसा अपने को अक्षय पात्र को ट्रांसफर कर देना चाहिए। उन्हीं की गाड़ियां लगती हैं, उन्हीं से ट्रांसपोर्ट होता है तो उससे जो आपके मास्टर दिन भर घबराते रहते हैं कि हमें खाना बनाना पड़ता है, हम पढ़ाने में टाइम नहीं दे पाते तो स्कूल के जो-जो मास्टर खाना बनाने में लगे रहते हैं, वे बच्चों की पढ़ाई में लगे रहेंगे।

दूसरी चीज मैं कहूंगा कि हमने लड़कियों के लिए बाथरूम्स बनवा रखे हैं। यदि उन बाथरूमों की कंडीशन आप देख लोगे तो आप उन बाथरूमों में घुस भी नहीं सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जितने गर्ल्स टायलेट्स स्कूलों में हैं और यह पार्टी से उठकर, मेरे खयाल से इधर से भी लोग चाहेंगे कि गर्ल्स टायलेट पर काम हो। हम लोग भी चाहेंगे कि गर्ल्स टायलेट पर काम हो, टाइलिंग हो और वे स्वच्छ रहें। कोई न कोई ऐसा सिस्टम हो, सिस्टम है क्योंकि स्कूल में उनका एक अलग से फंड होता है, उसमें बाथरूम की सफाई करने वाला सफाई कर्मचारी लग सके, सुबह-शाम उसकी सफाई हो सके जिससे कि क्लीन जगह बच्चे टायलेट के लिए जा सकें।

तीसरी चीज, पूरे सिस्टम में बी.जे.पी. के पिछले राज में, इनके ऊपर मैं कोई छींटाकशी नहीं करना चाहता, पिछले पांच साल में इन्होंने कम्प्यूटर लैब्स हर ट्वैल्थ स्टैन्डर्ड के स्कूल में बना दीं। कम्प्यूटर लैब्स तो बना दीं, कम्प्यूटर लगा दिये, टीवी लगा दिये पर कम्प्यूटर का एक टीचर इन्होंने अपाइंट नहीं किया। आपने करोड़ों रुपया इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर दिया पर उसमें पढ़ाने वाला आपको आज तक नहीं मिला। मैं अपनी सरकार से विनती करता हूं कि शिक्षा मंत्री जी इस पर ध्यान दें। सब शिक्षा मंत्री जी यहां ही बैठे हैं, शिक्षा मंत्री जी इस पर ध्यान दें कि यदि हमारे पास बजट नहीं है, हम टीचर नहीं लगा सकते हैं तो हम आडियो-विजुअल एड से उन बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा दें जो कि आज के जमाने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। यदि आपने बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा नहीं दी तो मैं यह कहता हूं कि आगे आने वाले जमाने में आप उन बच्चों को शिक्षा से ही महरूम कर देंगे।

चौथी चीज मैं कहता हूं ईस्टर्न राजस्थान में, हमारा जो ईस्टर्न

(श्री रोहित बौहरा)

राजस्थान है वहां हमें ट्वैल्थ के स्कूल क्योंकि हर पंचायत में हैं, वे खुले हुए हैं, हमें पांचवीं से आठवीं तक के स्कूल और आठवीं से दसवीं तक के स्कूल, ईस्टर्न राजस्थान की यह मांग है, पूरे यह चार-पांच डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा मांग इसी की है।

दूसरी चीज, कालेज एजुकेशन मिनिस्टर साहब से कह रहा हूं कि हमारे राजस्थान में पोद्दार इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एक एम.बी.ए. इंस्टीट्यूट है जो यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान के नीचे चलता है, क्योंकि मैं वहां से पढ़ा हुआ हूं इसलिए मैं कह रहा हूं हमारे जमाने में जो उसकी कंडीशन थी और आज के जमाने की जो कंडीशन है, वे बिलकुल बहुत ही ज्यादा पूअर कंडीशन में है। वहां से जो लड़के पास होते हैं, कम्पनियां उनके इन्टरव्यूज लेने, इन-कैम्पस इन्टरव्यू लेने तक नहीं आती हैं। मंत्री महोदय, मेरा कहना है कि आप इस पर ध्यान दें, यह one of the oldest institute, which is dying institute now. आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, अच्छे टीचर्स लगाने चाहिए। आपने वहां फंड नहीं दे रखा, उस फंड को दीजिए। राजस्थान में एक ही इंस्टीट्यूट है जिसको अपने को अच्छी तरह से चलाना चाहिए।

मैं दूसरी बात करना चाहता हूं ब्रेन ड्रेन के ऊपर। आज सेन्ट्रल गवर्नमेंट की भी यह पालिसी में गलती है और स्टेट गवर्नमेंट की भी गलती है। जिन्होंने भी गलती की है पांच साल में गलती की है, we're not able to open a lot of IITs all around India. हमने आईआईटीज में ध्यान ही नहीं दिया है। हम नई आईआईटी खोल ही नहीं पा रहे हैं और न ही एग्जिस्टिंग आईआईटीज में सीटें बढ़ा पा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि बच्चे विदेश जाकर एजुकेशन ले रहे हैं। एक बार बच्चा विदेश चला जाता है तो वहां के सिस्टम्स ऐसे डवलप हो जाते हैं कि यहां से ज्यादा तनख्वाह उसको मिलना शुरू हो जाती है, तो पता पड़ता है कि ब्रेन ड्रेन हो गया। यहां के जो अच्छे पढ़ने वाले लड़के थे, जिनको 1 नम्बर, 2 नम्बर कम से आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला, उसने फोरेन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना शुरू कर दिया। नुकसान किसका हुआ? नुकसान अपने देश का हुआ।

सभापति महोदय, एक यह जो पालिटिकल चीज है, बीजेपी वाले हर बार योग दिवस को ऐसा मनाने की कोशिश करते हैं कि और कोई पार्टी नहीं है जिसने योग किया हो। मैं इनको बताना चाहता हूं कि आज से 25 साल पहले, हमारी पहले प्रेयर होती थी स्कूल में और फिर एक ड्रम बजाते थे, उसमें

(श्री रोहित बौहरा)

हम पीटी करते थे। उसके बाद सूर्य नमस्कार करते थे। यह कोई नई चीज नहीं है जो आपने की है। आपने सिर्फ इसका एडवरटाइजमेंट किया है, और कुछ भी नहीं किया है। बाकी तो हम लोग आज 25 साल से योग करते आ रहे हैं। मेरे खयाल से यह आपको आज तक किसी ने बोला नहीं है।

श्री सभापति: 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप बात करते हैं, आपने जैसे राष्ट्रीयता की बात की। उसका ठेका तो मेरे खयाल से आपने ही ले रखा है। सही बोला उन्होंने कि इसका ठेका आपके ही पास है। हमारी तो भारत माता है ही नहीं। सब ठेका आप ही के पास है। ऐसी ठेकेदारी प्रथा को बंद कर दीजिए। दूसरे लोग भी जानते हैं कि राष्ट्रपिता कौन हैं। राष्ट्रीयता क्या है। सबको पता है।

यह योग वाली बात मैं सिर्फ इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आपने सिर्फ इसका एडवरटाइजमेंट किया। हमारी सरकार एडवरटाइजमेंट में बिलीव नहीं करती है। हम लोग जमीन पर काम करना चाहते हैं।

एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक एलएलबी का कोर्स है।

श्री सभापति: एक मिनट में बात समाप्त करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, आधे मिनट में खतम कर रहा हूं। 5 साल का एलएलबी का कोर्स है। वह अभी आक्सीजन पर चल रहा है। मंत्री महोदय, आप इस पर ध्यान दीजिए।

दूसरा, मैं कह रहा हूं कि ब्रज विश्वविद्यालय को आपको पैसा देना पड़ेगा। ब्रज विश्वविद्यालय हमारे ईस्टर्न राजस्थान के बच्चों को केयर करता है। उसमें अभी बिल्डिंग नहीं बनी है। स्टाफ की बहुत कमी है। टीचर्स की बहुत कमी है। आपको उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा जिससे कि वहां पर स्टाफ और टीचर आ सकें। तभी जाकर वह ब्रज विश्वविद्यालय भी चल सकेगा, नहीं तो वह नहीं चलेगा।

तीसरी चीज, यह जो 80 कर्मचारी हैं, जो यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं, जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, इनको यूजीसी की पे स्केल दे दीजिए। सिर्फ 80 आदमियों को आपने पे स्केल दे दी तो आप समझें कि आपने उनका काम कर दिया। सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुभाष पूनिया।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24 शिक्षा, कला और संस्कृति पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, झुंझुनूं जिले में सूरजगढ़ विधान सभा भौगोलिक दृष्टि से, जनसंख्या के आधार पर और मतदाताओं की संख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है। वहां बुहाना और सूरजगढ़ 2 एसडीओ मुख्यालय हैं। 2 पंचायत समिति मुख्यालय हैं। उसके बावजूद भी वहां कालेज नहीं है। मैं इसलिए आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से मांग करता हूं कि वहां अतिशीघ्र कालेज खोला जाए।

वह हरियाणा बार्डर से लगी हुई कांस्टीट्यूएंसी है। हरियाणा सीमा पर उसका कम से कम 100 किलोमीटर बार्डर, लुहारू से लेकर नारनौल तक पड़ता है। वहां के बच्चों को 80-100 किलोमीटर दूर खेतड़ी और झुंझुनूं सरकारी कालेज में जाना पड़ता है। वहां अनेक निजी शिक्षण संस्थान हैं, जिन्होंने अपनी कालेज खोल रखी हैं। उनकी फीस देने में काश्तकार सक्षम नहीं है। जिस तरह से 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा है, वहां का काश्तकार बेटियों को पढ़ाने में अपने आपको असहाय महसूस करता है, इसलिए वहां अतिशीघ्र कालेज खोला जाए।

सभापति महोदय, जैसा आपको विदित है कि राजस्थान प्रदेश में भी शिक्षा की दृष्टि से झुंझुनूं जिला अग्रणी है। मेरा आपसे आग्रह है कि बहुत जल्द सूरजगढ़ में कालेज की मांग जो कि वर्षों से चल रही है, उसको पूरा किया जाए। इस बजट सत्र में 32 महाविद्यालय दिये गये हैं। मैं तो सोच रहा था कि हमें भी मिलेगा। हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं। मैं अब भी आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे यहां कालेज खोलने का आदेश फर्माएं।

सभापति महोदय, दूसरा, यह है कि 1998 से एक परिपाटी पाठ्यक्रमों की अदला-बदली की चली आ रही है। जो भी सरकारें आती हैं तो पाठ्यक्रमों की अदला-बदली होती है। उसमें जनता के करोड़ों रुपये व्यर्थ हो रहे हैं। इस काम को भी रोका जाए। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम प्रयोगों, विकास और नवाचारों के लिए शिक्षा नीति की चर्चा हो रही है। शिक्षा को देश शिक्षित होने के साथ-साथ रोजगारमूलक भी बनाया जाए, यह भी मेरा आपसे आग्रह है। किताबी ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान भी हमारी नई शिक्षा नीति में

(श्री सुभाष पूनिया)

होना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी का यह स्वप्न कि 'हुनर का हर हाथ, रहे रोजगार के साथ', यह तभी सम्भव है जब प्राथमिक स्तर पर ही व्यावसायिक कौशल के पाठ्यक्रम भी बच्चों को पढ़ाये जाएं अन्यथा स्वप्न अधूरा ही रहेगा।

सभापति महोदय, राज्य में माध्यमिक स्कूलों में बाबुओं के पद सभी जिलों में खाली हैं। झुंझुनूं के लगभग 486 स्कूलों में 78 पद एलडीसी और 54 पद यूडीसी, वरिष्ठ सहायक के 490 स्वीकृत पदों में से 253 पद खाली चल रहे हैं। इसके अलावा व्याख्याता, प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के पद रिक्त हैं। मैं चाहूंगा कि इनको भी अतिशीघ्र भरा जाए ताकि स्कूलों का काम बाधित नहीं हो।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 6 पंचायत मुख्यालय आज भी सीनियर सैकण्डरी से महरूम हैं। उनमें भी जैसे भसावदा खुर्द, गाडाखेड़ा, लांबी अहीर, रायपुर अहीरान, पिलोद और सूरजगढ़ जो कि पंचायत समिति मुख्यालय भी है, वहां आज तक छात्रों का सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। यह भी अतिशीघ्र बनाया जाए।

सभापति महोदय, बहुत से स्कूलों का परिणाम 60 प्रतिशत से भी कम रहता है तो उन संस्था प्रधानों पर जहां 60 प्रतिशत से कम रिजल्ट रहता है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। यह मेरा आपसे आग्रह है।

सभापति महोदय, चौथा सवाल मेरा है कि शिक्षा के नाम पर बार-बार राजनीतिक आधार पर स्कूल खोलना और उनको बंद करना, इस रस्साकशी को बंद करने का काम करें।

सभापति महोदय, बालिकाएं तकनीकी शिक्षा में आज भी अपना योगदान दे रही हैं और राज्य में स्थापित राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर जो महिला तकनीकी शिक्षा के लिए उत्तर भारत में सबसे बड़ा केन्द्र है, लेकिन वहां की फीस निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के बराबर है। हम एक तरफ तो बालिकाओं का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। उनको पढ़ाते हैं। मैं चाहूंगा कि या तो इनको मुफ्त शिक्षा दी जाए नहीं तो सरकारी महाविद्यालयों के बराबर इसकी फीस की जाए।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): सभापति महोदय, मेरी अंतिम बात यह

(श्री सुभाष पूनिया)

है कि तकनीकी शिक्षा में कार्यरत सभी कार्मिकों को अभी तक सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला है। मेरी मांग है कि तकनीकी शिक्षा में भी सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए।

सभापति महोदय, प्रदेश के बहुत से विद्यालयों में आज भी बिजली कनेक्शन नहीं हैं। आवश्यक बिजली उपकरण भी नहीं हैं। बिजली के कनेक्शन और उपकरण उपलब्ध कराये जाएं। बहुत से विद्यालयों में शौचालयों की स्थिति भी खराब है इसलिए उनकी स्थिति भी सुधारें। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आज शिक्षा, कला और संस्कृति की मांग पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शिक्षा एक इंसान के भविष्य का निर्माण करती है। आज इस सत्र में, इस साल में हमारे राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में कैसे सुधार किया जाए, इस पर हम सभी मिलकर चर्चा कर रहे हैं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो हमें शिक्षा पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। शिक्षा पर जो राजनीति हो रही है उसको रोकना चाहिए। अगर हम इस राज्य के भविष्य का निर्माण करना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरा अनुभव कहता है, मैंने देखा कि सरकारें बदलती हैं तो विद्यालय हैं उनका कलर चेंज हो जाता है, विद्यालय में जो साइकिलें वितरित की गयी थीं उनका कलर चेंज हो जाता है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में पिछली बार जो स्थिति पैदा हुई, जब एक मां-बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजता है तो जो ड्रैस सिलवाता है, कपड़े सिलवाता है वह यह सोचता है कि मेरे बच्चे के जो कपड़े मैं सिलवा रहा हूं वह कम से कम दो साल तक स्कूल जाएगा तो काम आ जाएगी लेकिन पिछली बार जो ड्रैस थी उसका कलर चेंज किया तो उसकी वजह से हमारे क्षेत्र में कई बच्चों को परेशानी आयी। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कि यह जो सिस्टम है उसको खतम करना पड़ेगा और जो व्यापारीकरण हो रहा है शिक्षा का, पिछली सरकार में कई स्कूलें बंद कर दीं। शिक्षा को बढ़ावा देना उनका मकसद नहीं था, स्कूलें बंद करने का मेन मकसद था कि निजी क्योंकि निजी शिक्षा को बढ़ावा दें, व्यापारीकरण को बढ़ावा दें। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कि हर गरीब को, हर पीड़ित को अगर

(श्री राजकुमार रोत)

शिक्षा देना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें सुधरना होगा। आज कोई भी शिक्षक है, कोई भी अधिकारी है, कोई भी राजनीतिक दल का नेता है, उनके सभी के बच्चे कहां पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में। क्या हम यहां से सुधार नहीं कर सकते हैं कि जो शिक्षक हैं, लीडर हैं, जो जन प्रतिनिधि हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाए जाएं। अगर आज मैं जन प्रतिनिधि हूं मेरा, किसी अध्यापक का, सरकारी अधिकारी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएगा तो वहां शौचालय भी बन जाएगा, वहां नल भी लग जाएगा और भवन भी अच्छा बन जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, एक कानून बना हुआ है कि गरीब छात्रों को निजी स्कूलों में 25 परसेंट नि:शुल्क पढ़ाया जाए तो मैंने मेरे इलाके में देखा कि सभी निजी स्कूलों में आंकड़ों में तो यहां उपलब्ध करा दिया जाता है कि 25 परसेंट गरीब, बीपीएल परिवार के लोगों को, आदिवासी लोगों को, पीड़ित लोगों के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है तो यह जो व्यापारीकरण हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र की एक विशेष समस्या है, जो लड़के बीएड करने जाते हैं, बीएसटीसी करने जाते हैं तो उनको सीधा सीकर, शेखावाटी इलाका दे दिया जाता है। क्यों? वहां पर कालेजें हैं फिर भी नहीं दिया जाता है क्योंकि एक धंधा चल रहा है, मैंने भी बीएड की है सीकर से। उस एरिया में सिस्टम चलता है, आओ सैटिंग करो, पचास हजार रुपया दो और वापस चले जाओ। अगर हम हमारे राज्य का भविष्य निर्माण करना चाह रहे हैं तो इस तरह का जो सिस्टम चल रहा है, उसको बंद करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, अब आगे की कड़ी में शिक्षा से जुड़ा हुआ ही मामला है। हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र में 2013 में राज्यपाल की अधिसूचना पारित हुई थी और संशोधित होकर 2016 में फिर पारित हुई। उसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया, 45 प्रतिशत एसटी, 5 प्रतिशत एससी, 50 प्रतिशत सभी वर्गों के लिए। हाल ही में एक भर्ती हुई 2018 में रीट की, उसमें 50 प्रतिशत सीटें थी वह खाली रहीं, 1126 सीटें खाली हैं उसमें हमारी पात्रता 36 प्रतिशत वहां दी गयी है। जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें स्फ्ट लिखा हुआ है कि खाली सीटें रहेंगी, वह किसी भी वर्ग के पात्र व्यक्तियों से भरी जाएंगी लेकिन आज नहीं भरी जा रही हैं। उलटा यह हो रहा है कि जो

(श्री राजकुमार रोत)

नया एरिया जुड़ा 19.05.2018 को, विज्ञप्ति जारी हुई हमारे 12.04.2018 को, एक महीने पहले विज्ञप्ति जारी हुई है। जो विज्ञप्ति में नहीं शामिल है, विज्ञप्ति के अनुसार जो परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल नहीं है, उस अभ्यर्थी को हमारी वहां की सीटें हैं उन पर लिया जा रहा है। यह एक तरह का शिड्यूल्ड एरिया के साथ, आदिवासी अंचल के साथ अन्याय किया जा रहा है। हाल ही में फिर भर्ती हुई है नीट की, उसमें 4 सीटें जो आ रही थीं शिड्यूल्ड एरिया की, उनको बेच दिया गया। जो नीट के काबिल स्टूडेंट बना है, उसके मां-बाप को बहुत पसीना आया होगा, उसने अपने जेवरात गिरवी रखे होंगे, उसने अपनी जमीन गिरवी रखी होगी। माननीय सभापति महोदय, हमारे एरिये के साथ अन्याय हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है, हर जगह हो रहा है तो कम से कम शिक्षा में तो नहीं होना चाहिए इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विडम्बना है उसको दूर किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, अब आगे मैं बताना चाहता हूं कि विद्यालयों की क्या स्थिति है। हमारे एरिया में आज यह स्थिति है कि 70 प्रतिशत ऐसे विद्यालय के भवन हैं जहां आज बच्चे नहीं बैठ रहे हैं। रोज न्यूज पेपर में आता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, जो नये सदस्य हैं उनको बोलने का मौका दें।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: आप विराजिए, माननीय सदस्य। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं।

श्री सभापति: जिस माननीय सदस्य को इजाजत दे आसन, केवल उसी का अंकित होगा, बाकी किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, वहां की जो

(श्री राजकुमार रोत)

स्थिति है उसके बारे में न्यूज पेपरों में छपा है कि डूंगरपुर जिले में माध्यमिक शिक्षा कार्यालय नाकारा घोषित हो गया है। मतलब जिले का जो कार्यालय है वही नाकारा घोषित हो गया है तो फिर स्कूलों की क्या स्थिति होगी? वहां जो स्कूलें खुली हैं, अभी न्यूज पेपर में आया कि प्रार्थना सभा से 15 मिनट पहले स्कूल की छत गिर गयी। मतलब प्रार्थना सभा से 15 मिनट पहले स्कूल की छत गिर गयी, वह तो उनकी किस्मत अच्छी थी, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल मीना।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी कालेज शिक्षा में वहां डूंगरपुर जिला है और वहां पर एमएससी के लिए न तो वनस्पति विज्ञान है, न रसायन विज्ञान है, न मैथेमेटिक्स है, न फिजिक्स है, वहां पर केवल जियोलोजी से एमएससी कराई जा रही है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि वहां पर वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और मैथेमेटिक्स, फिजिक्स नये विषय खोले जाएं।

माननीय सभापति महोदय, आगे की कड़ी में वहां का जो सिस्टम है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि वहां पर साइंस सब्जैक्ट में....

श्री सभापति: आप बचा हुआ माननीय मंत्रीजी को लिखकर दे देना। माननीय मंत्री महोदय को लिखकर दे देना।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, बीस सैकंड, लास्ट बीस सैकंड। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी जो मामला चल रहा है।

श्री सभापति: समाप्त करें। अब अंकित नहीं होगा। श्री गोपाल लाल मीना।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें, विराजिए। आसन पैरों पर है। विराजिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): 000

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। मेरा फिर सभी से आग्रह है कि कहने पर आप विराजें, आसन के निर्देश मानें। अंकित नहीं होता है तो फिर बोलने से फायदा नहीं है। जो भी समस्या है वह आप माननीय मंत्रीजी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर बताएं।

श्री गोपाल लाल मीना। श्री महेन्द्रजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया गया।

श्री गोपाल लाल मीना।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज जिस विषय पर वाद विवाद है, यह समाज और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा के माध्यम से ही हम संस्कृति के दर्शन करते हैं और इसके कला शब्द भी साथ में जुड़ा हुआ है। मैं सर्वप्रथम उच्च शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय को पुन: खोला, इसके लिए आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार में जिस प्रकार से द्वेषतापूर्वक काम किये गये, पत्रकारिता विश्वविद्यालय हरिदेव जोशीजी के नाम से, अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, इन दोनों विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया। आज मैं कहना चाहूंगा कि ये विश्वविद्यालय खुलेंगे तो निश्चित रूप से जो छात्र हैं, उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां

(श्री गोपाल लाल मीना)

पर पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जी बोल रही थीं कि कुलपति की नियुक्तियों में राजनीति हो रही है, किन्तु ये भूल गयीं कि भाजपा सरकार द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय में एक ऐसी नियुक्ति की गयी, जो कि योग्य ही नहीं थे। माननीय उच्च न्यायालय ने उस नियुक्ति को गलत ठहराया। कुलपति को इस्तीफा देना पड़ा। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि आप राजनीति करते हैं, अब राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है या कांग्रेस करती है।

वसुन्धरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार में महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू जैसी राष्ट्र विभूतियों की भूमिका को नजर अंदाज किया गया। अब हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी द्वारा उनके योगदान का उचित वर्णन किया जाएगा। यह एक सराहनीय कदम होगा। आपको पता है राजीव गांधी पाठशाला, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया था, यह बंद करने का काम, उनका नामकरण करने का काम, नामों को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी किया है, करती आयी है, उनकी फितरत है। कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा काम न हो जिससे छात्रों को कोई ऐसा दु:ख प्रकट हो जिससे विभूतियों के वर्णनों में कोई कटौती करे, उन्हें तोड़-मरोड़कर लिखे। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। बीजेपी सरकार द्वारा नौकरियां एवं रोजगार देने का गलत प्रचार किया गया। इसकी पोल सीएजी ने खोलकर रख दी है। राजस्थान विधान सभा में नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक की रिपोर्ट ने रोजगार पर उनके दावे की हवा निकाल दी और सीएजी रिपोर्ट के अनुसार वसुन्धरा राजे ने नौकरियों की संख्या 1, 2 नहीं बल्कि 5 गुना तक बतायी है।

मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई काम करना है तो बढ़ा-चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंकड़े आते रहते हैं, सरकार के आंकड़े आप छिपा नहीं सकते, बोलकर नहीं बता सकते। वे रिकार्ड पर रहते हैं और रिकार्ड के आंकड़ों को कोई तोड़-मरोड़ नहीं सकता। सरकार आती है, जाती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): सरकार पदक जीतने पर पुरस्कार देती है, लेकिन अगर कोई युवा खिलाड़ी बनने के लिये आता है तो पूर्व सरकार ने वसूली शुरू कर दी। 'प्ले एंड प्ले' योजना शुरू की जिसमें अगर किसी को खेलना है तो पैसा देना होगा। यह वसूली बंद करनी चाहिए। दूसरा, 2005 में खेल का एक काला कानून लाया गया था तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा जिसमें खेल बर्बाद हो गये। खेल संघों में विवाद चल रहा है, नुकसान खिलाड़ियों का हो रहा है। ललित मोदी जी को अध्यक्ष बनाने के लिये यह जो खेल कानून लाया गया था, क्या आप इस तरह के कानून को बदलना चाहेंगे?

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्री बाबूलाल नागर।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): नहीं हैं वे सर, तब तक मैं बोल लेता हूं।

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): मैं एक और बात कहना चाहूंगा, 1998 में परीक्षा नियंत्रक, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कुल पद राजस्थान में 80 हैं, इन्हें छोड़कर सभी को लाभ मिल गया, इसलिये उच्च शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि इन्हें भी यूजीसी के वेतनमान का लाभ दिया जाए। इनकी कमेटी तुरंत बनाएं और इन्हें फायदा पहुंचाए। ये लोग 1998 से आज तक परेशान हो रहे हैं तो मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज ही इस बात की घोषणा करें और मैं लास्ट में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में सभी उपखण्डों पर सरकारी महाविद्यालय खुल गये, आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री से भी मैं निवेदन करूंगा कि जमवारामगढ़ में भी सरकारी महाविद्यालय खोला जाए।

श्री सभापति: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय को मिलकर देना आप कागज। श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): माननीय सभापति महोदय, आपने शिक्षा एवं कला संस्कृति पर इस सदन में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देश जब आजाद हुआ था, उस समय भारत की साक्षरता दर 18 प्रतिशत थी। कांग्रेस के लोग भाजपा पर आरोप लगाते हैं, भाजपा के लोग कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं।

सभापति महोदय, सच्चाई यह है कि जब-जब भी जिन-जिन पार्टियों की सरकार रही है, उन्होंने सकारात्मक प्रयास किये और उन्हीं प्रयासों का

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

परिणाम है जो आज हमारी 2011 में जनगणना हुई, भारत की साक्षरता दर 74 प्रतिशत हो पायी। साथ ही, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारा शिक्षा में तीन-चौथाई भाग तो शिक्षित हो चुका, लेकिन एक-चौथाई भाग अशिक्षित है। यह चिंता का विषय है हम सबके लिये। सदन के सभी सदस्यों के लिये भी यह चिंता का विषय है। विश्वस्तर पर यदि हम देखते हैं तो हमारा देश साक्षरता दर के मामले में 149वें स्थान पर है। यह हमारे लिये बहुत अच्छी बात नहीं है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब यहां अंग्रेजों का शासन था, उस समय 18 मार्च, 1910 को भारत माता के सपूत गोपाल कृष्ण गोखले ने मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव ब्रिटिश विधान परिषद् के सामने रखा था, लेकिन अंग्रेजों के मन में पूरा खोट था, उनके मन की ईर्ष्या थी कि भारतीयों को अगर शिक्षा दी जाएगी तो ये हमारी बराबरी करेंगे और हमें जल्दी भगा देंगे। 2002 में भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन आया, उस समय देश के प्रधान मंत्री अटल बिहारी जी थे, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल करने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया, वह बहुत बड़ी बात थी।

साथ ही, 2009 में जब प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी थे और राइट टू एजूकेशन का एक्ट वे लेकर आये, मैं उनकी भी प्रशंसा करता हूं। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, 'संगठित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो'। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो भी पीएगा, शेर की तरह दहाड़ेगा। आज शिक्षा का ही परिणाम है कि किसी भी जाति, बिरादरी के हों, इस सदन में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस प्रदेश की रियासतों पर शासन किया है और उनके सामने जो दूसरे लोग थे, वे फर्श पर नीचे बैठते थे, लेकिन आज उस शिक्षा और संविधान का परिणाम यह है कि हम सब एक साथ चेयर पर बैठकर राजस्थान की जनता के लिए विधान बनाने का काम कर रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। आदरणीय सभापति महोदय, ज्ञान हमें शक्ति देता है और प्रेम हमें परिपूर्ण बनाता है। ज्ञान और प्रेम दोनों एक साथ देने का काम इस विश्व में अगर कोई कर सकता है तो एकमात्र शिक्षक ही कर सकता है। उसके अलावा दूसरा

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

कोई नहीं है जो यह ज्ञान और प्रेम एक साथ हमें दे सकता हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज हमारे बीच गोपाल कृष्ण गोखले जी होते तो उन्हें सबसे बड़ा सुख मिलता। साथ ही, देश की आजादी के पहले बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने भी राइट टू एजूकेशन के लिये प्रयास किया था। मैं उन्हें भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

(17.00 बजे)

सभापति महोदय, जब हम चाहते हैं कि भारत के विकास की एक मजबूत आधारशिला रखी जाए तो सबसे पहले शिक्षा से जुड़े शिक्षक तथा छात्रों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। शिक्षा सेवा में शिक्षक ही ऐसी व्यवस्था है जो कम संसाधन होते हुए भी सर्वाधिक सफलतम परिणाम लाने में सफल रहता है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं एक छोटे से बाबू का दफ्तर अगर शहर के किसी कोने में है तो वहां कूलर की व्यवस्था भी हो सकती है, ए.सी. की व्यवस्था भी हो सकती है, वहां पंखे की व्यवस्था भी हो सकती है और पानी की व्यवस्था भी हो सकती है लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है, हालांकि यह अनवरत प्रयास है, बहुत सारा विकास हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में लेकिन दूर-दराज में जो स्कूल बसी हुई हैं न वहां शौचालय की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। विद्यालय का प्रधानाध्यापक बिजली की फाइल लगाने जाता है तो वह छह-छह महीने दर-दर भटकता है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हुए हैं, कोई ऐसा आर्डर निकालने की कृपा करें कि विद्यालय का प्रिंसीपल अलग से वहां कोई फाइल लगाता है तो 10 दिन या 15 दिन के अन्दर-अन्दर अगर विद्यालय में कनेक्शन हो जाए तो आपकी महती कृपा होगी।

सभापति महोदय, मैं आपसे बहुत संरक्षण चाहता हूं। मैं आपको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे कोई रही हो, छात्र हितों के लिए हमेशा कटिबद्ध रही है। बात करें हम मिड-डे मील की या अन्नपूर्णा दूध योजना की, जो भी सरकारें रही हैं, अलग-अलग योजना लागू करती हैं। 2018-19 में लगभग 1200 करोड़ रुपये खर्च किये हैं और हर सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम तय किये हैं।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा स्टाफ, इतना बड़ा

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

तंत्र और तीनों के तीनों हमारे राज्य मंत्री। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं, हमारे डोटासरा जी बैठे हुए हैं ऊर्जावान भी हैं, पारदर्शी भी हैं और व्यवहार में भी कुशल हैं, इनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, ऐसा मेरा आप लोगों से अनुरोध है।

बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा को आंदोलन बताया और इस आंदोलन को तभी हम सफल बना सकते हैं जब शिक्षक हमारा साथ दे। जब तक हमारा शिक्षक साथ नहीं देगा तब तक इसको आंदोलन के रूप में नहीं ले जा सकते।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): बस एक मिनट सर, ज्यादा नहीं। शिक्षक जगत सम्मान का भूखा रहता है। अगर हम उनका समय-समय पर सम्मान करेंगे तो मैं समझता हूं कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं पहले भारतीय राजस्व सेवा में अधिकारी के रूप में काम करता था, 2013 में इस राजनीति में आया, लगता था कि मैं कहां आ गया लेकिन जब सारी चीजें देखने को मिलीं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2015 में मेरे यहां 58 स्कूल हैं, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि मैंने 58 स्कूल में से 28 स्कूल ऐसी स्थापित की हैं सीसीटीवी कैमरे लगाकर और उस कैमरे के माध्यम से जो महुवा का अभिभावक है और बाम्बे में नौकरी कर रहा है तो बाम्बे में बैठे-बैठे अपने बच्चे को लाइव देख रहा है। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि माडल के रूप में जो आपने अंग्रेजी विद्यालय स्थापित किये हैं......

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): एक मिनट सर, मैं अपनी मांग रख दूं। माननीय, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां पांच सात स्कूल नोरंगवाला, सालिमपुर, टीकरी किलानोत, बाड़ा बुजुर्ग, हड़िया, खेड़ला बुजुर्ग, इन स्कूलों को सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत एवं बालाहेड़ी और रसीदपुर में साइंस फैकल्टी खोलने की कृपा करें। साथ ही, माननीय मंत्री महोदय, रसीदपुर विद्यालय ऐसा विद्यालय है जिसमें मोतीलाल गुप्ता जी ने पढ़कर विदेशी राजदूत के रूप में सेवा दी थी। उनकी भी यह मांग

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

है कि उनके विद्यालय में साइंस फैकल्टी खोली जाए और महुवा में कृषि विज्ञान खोलने की कृपा करें। आपने मुझे मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री सभापति: श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आदरणीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, शिक्षण संस्थाएं, चाहे राजकीय हों चाहे प्राइवेट हों, पूरी पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर जब बच्चा घुसता है तो खाली हाथ घुसता है और जब उस प्रांगण के बाहर निकलता है तो अपने साथ बहुत कुछ लेकर निकलता है। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी धर्मपाल जी कहते थे कि बेटा, शिक्षा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो जिन्दगी भर साथ रहेगी। अन्य चीजें बढ़ती जाएंगी, अन्य चीजें बिछुड़ती जाएंगी और जितना अधिक इसको बांटेगा उतनी ही अधिक बढ़ेगी।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने, हमारी सरकार ने क्या-क्या किया और आज जो सरकार राज के अन्दर है उन्होंने क्या नहीं किया। मैं मेरे क्षेत्र की मांग आपके बीच माननीय मंत्री महोदय के सामने रखना चाहूंगा। जब बजट पर बहस चल रही थी तो मैंने मेरे क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय मुण्डावर की बात की। जब मैंने वह मांग की तो मुझे उम्मीद थी कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी उस मांग को पूरा करेंगे और जरूर कहेंगे। आज दो साल हो गये हैं, उस राजकीय महाविद्यालय को भूमि आबंटित नहीं हुई है तो कम से कम इतना तो कह देते कि उस भूमि का जल्द से जल्द आबंटन कराकर वहां पर भवन निर्माण कराया जाएगा। आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से मेरा उनसे निवेदन है कि कृपा करके मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने का काम करें और इस मामले को व्यक्तिगत तौर पर आप खुद दिखवाकर राजकीय महाविद्यालय, मुण्डावर की भूमि का आबंटन कराएं और जल्द से जल्द वहां पर भवन निर्माण करवाने का काम करें।

आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण के अन्दर एशियन और नेशनल गेम्स की तरह राजस्थान गेम्स की

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

बात कही। आदरणीय सभापति महोदय, जैसा आप सब जानते हैं, मैं ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर यहां पर पहुंचा हूं और आज अपन ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो खेल मैदान का अभाव क्या, वहां तो खेल मैदान ही नहीं है। अपन राजस्थान गेम्स की बात करते हैं तो वहां का बच्चा तैयारी कहां करेगा? रोड पर करेगा? अच्छा होता, आदरणीय मुख्य मंत्री जी पहले कहते कि हम हरेक पंचायत हैडक्वार्टर पर खेल मैदान की स्थापना करेंगे और स्थापना के बाद वहां पर हरेक बच्चे को ट्रैनिंग दिलाकर राजस्थान गेम्स करवाएंगे जिससे हरेक बच्चा इक्वली क्वालिफाइड होगा और अपनी काबिलियत के आधार पर आगे जाकर जो भी पदक जीतेगा वह अपनी काबिलियत के आधार पर जीतेगा। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि कम से कम पंचायत हैडक्वार्टर पर एक अच्छा खेल मैदान विकसित किया जाए।

आदरणीय सभापति महोदय, यहां पर बहुत सारे मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, बहुत सारे विधायकगण बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा अपने दिल पर हाथ रखकर कह दें, हाथ उठाकर बता दें, एक भी व्यक्ति यहां पर ऐसा हो जो कह दे कि मैं मेरे बच्चे को इस सरकारी स्कूल में या कालेज में पढ़ा दूंगा। यहां पर बहुत सारे अधिकारी बैठे हुए हैं एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसका बच्चा सरकारी स्कूल के अन्दर जाता हो। क्या कमी है जिससे वे वहां नहीं जाते हैं? आदरणीय सभापति महोदय, सोचने की बात है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो आरपीएससी इन शिक्षकों का चयन करती है, वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले उनके बच्चों का उन स्कूल के अन्दर एडमिशन कराया जाए, उसके बाद उन अधिकारियों के बच्चों का एडमिशन कराया जाए जो उनको वहां आगे पोस्टिंग देते हैं, उसके बाद हम नेताओं के बच्चों का वहां पर एडमिशन कराया जाए जो वहां पर उनकी ट्रांसफर की डिजायर लेकर जाते हैं मंत्री के पास कि साहब, इस फलां व्यक्ति को आप यहां पर लगा दो। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि अगर आप यह व्यवस्था कर देंगे तो स्कूलों की व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। आज प्रदेश के अन्दर बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूल आगे बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से सरकारी संस्थाएं भी आगे बढ़ेंगी।

आदरणीय सभापति महोदय, गांव का व्यक्ति, गांव का पिता, गांव की मां आज अपनी बेटी को स्कूल भेजने में डरती है। कारण यह है कि वहां भवन जर्जर हालत में है, भवन की बाउण्ड्री नहीं है, वह डरता है कि कल को कोई

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

अनहोनी न हो जाए। अपन सब जानते हैं कि आज देश के अन्दर, प्रदेश के अन्दर रोज घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सारे भवनों की चारदीवारी करवाकर, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा लगवाकर वहां पर उसको सुरक्षित बनाया जाए जिससे आपको एडमिशन बहुत अधिक मिलेंगे।

आदरणीय सभापति महोदय, एक विशेष मांग ग्रामीण क्षेत्र में आने की वजह से माननीय मंत्री जी से करूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अन्दर मात्र कला संकाय खोला जाता है। आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मैं एक किसान परिवार से आता हूं और किसान क्षेत्र से विधायक चुनकर आया हूं तो आपसे विशेष निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृषि विज्ञान संकाय खोला जाए जिससे जो आने वाली पीढ़ी है, कम से कम खेती करने में उसकी रुचि बढ़ेगी और आगे जाकर अलग-अलग तरीके से वे नये प्रयोग करेंगे और खेती को बढ़ावा मिलेगा।

आदरणीय सभापति महोदय, मुण्डावर क्षेत्र के अधिकांश राजकीय विद्यालयों के अन्दर संस्कृत शिक्षा का अभाव है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको दिखवाकर जहां-जहां सरकार को जरूरत लगती है, कम से कम कुछ में तो संस्कृत शिक्षा आप खोलें।

आदरणीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बीजवाड़ चौहान एक ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर है। काफी लम्बे समय से वहां पर कृषि महाविद्यालय खोलने की बात चली थी, मैंने मुख्य मंत्री जी से निवेदन भी किया था। जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार दुर्व्यवहार की भावना से काम कर रही है, उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार नहीं करते हुए नजदीकी किशनगढ़बास के अन्दर जहां पूर्ववर्ती सरकार ने महाविद्यालय खोलने की बात की, उसी को चेंज कर कृषि महाविद्यालय कर दिया।

श्री सभापति: एक मिनट में बात समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बात पर गौर फर्माएं आपके डिपार्टमेंट के पास फाइल भी लम्बित होगी, आप इस पर गौर फर्माएं और निवेदन करना चाहूंगा कि राजकीय कृषि महाविद्यालय वहां पर खोला जाए।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

आदरणीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जिन्दौली गांव है और उसके साथ अन्य राजकीय विद्यालयों के अन्दर गणित और विज्ञान जैसे विषयों की कमी है। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि गणित और विज्ञान जैसे विषय हैं जिनमें बच्चे अधिक एडमिशन लेते हैं कालेज के अन्दर, स्कूल के अन्दर, वहां पर खोले जाएं।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं मेरी जन्मस्थली जाट बहरोड़ की बात करूंगा। वहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भूगोल विषय की काफी लम्बे समय से मांग चल रही है। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी खुद की जन्मस्थली है इसलिए निवेदन है कि वहां भूगोल विषय खोला जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आदरणीय सभापति महोदय, एक मिनट के अन्दर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सयाली कलां गांव है, जिसकी आबादी करीब दो हजार है। सिरोणी गांव है, जिसकी आबादी ढाई हजार करीब है, वहां पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। आपसे निवेदन है दोनों पंचायत हैड क्वार्टर हैं, वहां पर जल्द से जल्द राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, उनको क्रमोन्नत किया जाए और सोड़ावास के अन्दर राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय है, जो हाईवे के ऊपर पड़ता है, निवेदन है उसको राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आप क्रमोन्नत करें।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): यहां पर एक और निवेदन करना चाहूंगा जैसे मैंने सोड़ावास का आपको बताया, उस स्कूल के पीटीआई ने लगातार परिश्रम से देश और राज्य को वालीबाल के अच्छे-अच्छे खिलाड़ी दिए हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री गिर्राज सिंह।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि वहां पर जल्द से जल्द एक वालीबाल कोर्ट खोला जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: गिर्राज सिंह।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपको बैठने के लिए भी धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में एक राजकीय विद्यालय है और वहां पर 700-800 बच्चे हर साल एडमिशन लेने के लिए जाते हैं। स्थिति यह है कि वहां पर स्कूलों में इतनी क्षमता नहीं है, 160 बच्चों की क्षमता है। मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इस समस्या को देखते हुए उसमें सीटें बढ़ाई जाएं और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस विद्यालय को राजकीय पीजी कालेज में किया जाए। छात्रों को काफी परेशानी आती है पढ़ाई लिखाई में, सभापति महोदय, धौलपुर में कन्या महाविद्यालय, मैं मंत्रीजी से मांग करता हूं कि इसको भी पीजी कालेज कराया जाए। छात्राओं का मामला है, इसको ध्यान में रखा जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजकीय महाविद्यालय, बाड़ी में कामर्स विषय बढ़ाया जाए और साथ ही सभापति महोदय, मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि सारे पद इस स्कूल में खाली पड़े हैं, सिर्फ विद्यालय, कालेज डेपुटेशन से लगा देते हैं। पिछली बार तो कई आंदोलन भी हुए।

अभी शिक्षा मंत्री जी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, आपने कर क्या दिया, आपने सिर्फ स्कूल बंद करने के अलावा और किया क्या है? ये तो बताएं आपने क्या काम किया है? आपने स्कूल बंद कर दिये, आपने साइकिल के कलर भगवा कर दिये और आपने इसके अलावा किया क्या है?

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप महाराणा प्रताप की चिन्ता छोड़ो, मैं उसी समाज का हूं। आपसे ज्यादा चिंता हमें होनी चाहिए..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में वार्ता नहीं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप ये ढकोसलेबाजी बंद करो, आप ये ड्रामा बंद करो...

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य। आसन पैरों पर। विराजिए आप।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप महाराणा प्रताप की चिंता छोड़ो, हम बहुत लोग हैं, हमारा समाज बहुत है, महाराणा प्रताप की चिंता करने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं उसी समाज का हूं, ठीक है न।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप जो दिखावा करते हैं न, महाराणा प्रताप वाला, रानी लक्ष्मीबाई वाला, आप मेरा मुंह मत खुलवाओ। आप उन लोगों को सत्ता दे देते हैं, जो महारानी लक्ष्मीबाई के कातिल हैं। आप मेरे मुंह को क्यों खुलवाने चाहते हैं?

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं, आप इधर देखिए, आसन की तरफ, माननीय सदस्य।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अब कुछ और कमी रह गयी है सुनने के लिए? आपको और इतिहास बताऊं, रानी लक्ष्मीबाई का या पृथ्वीराज चौहान का? आप क्यों अपनी खामख्वाह..

श्री सभापति: आप अपने क्षेत्र की समस्याएं बताइए, टाइम हो जाएगा अभी।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अभी पूरी पोल खोलूंगा न, ग्वालियर से लेकर यहां तक पोल खुलेगी न, तो फिर सब उचकेंगे, इधर भागेंगे, बाहर भागेंगे, फिर आप यही करेंगे। आपको चिंता ज्यादा है महाराणा प्रताप की।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, क्षेत्र की समस्या बताइए, अब आप।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): बहुत ज्यादा चिंता वाले हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी पूर्व शिक्षा मंत्रीजी कह रहे थे, स्कूल हमने बंद नहीं की, हमने समायोजन किया है। सभापति महोदय, इन्होंने इतने स्कूल बंद किये कि छोटे-छोटे बच्चे जो दो साल, तीन साल, पांच साल के हैं वे दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर पढ़ने के लिए जाते हैं और आने-जाने के लिए कोई तो रोड पर से जाते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं और कई बच्चे ऐसे हैं, हमारा जंगल का एरिया है, आने-जाने में बहुत बड़ी परेशानी आती है, कभी बच्चों की पकड़ भी हो जाती है, यूपी-एमपी से लगा हुआ एरिया है।

सभापति महोदय, चम्बल का पानी भी बहता है वहां पर, काफी नदी निकलती हैं तो वहां बच्चों के आने-जाने में समस्या है। मैं मंत्री जी, मांग

(श्री गिर्राज सिंह)

करता हूं कि आप सभी विधायकों से चाहे वह कांग्रेस का है, बीजेपी का विधायक है, निर्दलीय या बहुजन समाज का है, किसी के हों सभी बच्चों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो स्कूल पहले बन्द किये हैं इन्होंने, ठीक है आप पूरे चालू नहीं कर सकते हैं, जो जरूरत के हिसाब से और जो दूरी है, उस हिसाब से आप उनको चालू कराएं। यह मैं सरकार से मांग करता हूं।

सभापति महोदय, बाड़ी में कन्या महाविद्यालय की मांग करता हूं। मंत्री महोदय आप घोषणा करें आज ही। अब आपका राज है अगर इस पीरियड में भी नहीं, तो सरकार में रहने का कोई मतलब नहीं है। आज आप घोषणा न करें तो मजा नहीं। जब मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी मेरे सैंपऊ में विद्यालय खोलने की, तो मैं आपसे भी मांग करता हूं। मंत्री होने के नाते आपसे भी, मेरा अधिकार बनता है कि कालेज की छात्राओं को ध्यान में रखते हुए, आप भी आज ही घोषणा करें। जब मुख्य मंत्रीजी ने 25 कर दिये, तो माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी को भी एक घोषणा करने का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं और हमारे विपक्ष के उप नेता वे भी आपसे मांग कर रहे हैं, वे भी आज टेबल ठोक रहे हैं। आपका साथ नहीं चाहिए...

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं, इधर।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, पिछली सरकार में जो विद्यालय इन्होंने बंद किये...

श्री सभापति: आप मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत वरिष्ठ हैं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): उनका थोड़ा ध्यान रखते हुए और सभापति महोदय, पंचायत हैडक्वार्टर पर जो सीनियर सैकण्डरी विद्यालय हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी पंचायत हैडक्वार्टर रह गये हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप थोड़ा उनका भी ध्यान रखें, उन्हें चालू कराएं। जो विद्यालय रह गये हैं, सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं, हर पंचायत हैडक्वार्टर पर, एक विद्यालय की घोषणा की है, तो वे भी चालू कराई जाएं।

सभापति महोदय, बच्चों की समस्या है, स्कूलों में पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है तो उनके लिए वाटर कूलर या आर ओ की व्यवस्था करायी जाए। सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सैंपऊ में..

श्री सभापति: अब एक मिनट में बात समाप्त करें अपनी।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अभी तो बोलने का टाइम आया है।

श्री सभापति: सहयोग करें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): जो कालेज की घोषणा की है, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर काफी पुरानी बिल्डिंग है। आप उसमें इसी साल सैंपऊ वाले विद्यालय को चालू कराएं और आगे बजट की व्यवस्था करें। इस बिल्डिंग को बनाया जाए, सैंपऊ से काफी एरिया लगा हुआ है। सभापति महोदय, अभी सामने वाले कह रहे थे कि हमने शिक्षा को इतना बढ़ावा दिया है। इन्होंने सभापति महोदय, सूर्य नमस्कार करा दो, अब क्या हम उठकर सूर्य को नमस्कार नहीं करते हैं, ये ही हमको सिखा रहे हैं। हम लोगों से नमस्कार करते हैं, ये हमको सिखा रहे हैं, हम इनके कहने से ही नमस्कार करेंगे। हम वंदे मातरम इनके कहने से बोलेंगे? हम भारत के नहीं हैं क्या, हम पाकिस्तान के नागरिक हैं? सभापति महोदय, सिर्फ इन्होंने साइकिलों का कलर, बच्चों की ड्रैस...

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं हो।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। प्लीज सहयोग करिये। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री सभापति: नहीं-नहीं, फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। अंकित नहीं होता है तो केवल आवाज ही होती है और आपको ही सुनाई देती है, बाकी किसी को सुनाई नहीं देती है।

श्री सभापति: श्री वाजिब अली।

श्री वाजिब अली (नगर): सभापति महोदय, मांग संख्या-24 पर आज आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया है उसके लिए धन्यवाद। मैं अपने क्षेत्र की स्कूलों की हालत और वहां की कुछ मांगों से सदन को आपके द्वारा अवगत कराने का प्रयत्न करूंगा। महोदय, शिक्षा की जो इम्पोर्टेंस है उसको बताने की जरूरत नहीं है। प्रगति के लिए प्रदेश की और देश की सबसे महत्वपूर्ण जो प्रणाली है हम कैसे अच्छे से व्यवस्थित कर सकें। मैं भरतपुर के नगर क्षेत्र से आता हूं। मेवात क्षेत्र है और वहां जो स्कूलों के हालात हैं वे बहुत

(श्री वाजिब अली)

अच्छे नहीं हैं। अक्सर स्कूलों में अध्यापकों की कमी रहती है। संसाधनों की बहुत बड़ी कमी है। बैठने के लिए फर्नीचर और दरी-पट्टी भी स्कूलों में नहीं है। ज्यादातर स्कूलों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। टायलेट्स की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है और कहीं है तो वह अनुपात के मुताबिक बहुत कम हैं।

महोदय, अभी खेलों की भी बात हो रही थी। एशियन गेम्स की तर्ज पर राज्य में खेल विकसित करना चाहते हैं, लेकिन ये प्रतिभाएं सामने कैसे आएंगी ग्रामीण क्षेत्रों में खेलने के संसाधन नहीं हैं। स्कूलों के अन्दर स्पोर्ट्स के टीचर हों, खेल मैदान को विकसित किया जाए, तब जाकर इन प्रतिभाओं को कुछ मौका मिलेगा कि आगे बढ़ सकें। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्कूल पहले बंद किये गये, उनमें से बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनके बंद होने से क्षेत्र के बच्चों को बहुत-बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और मैंने अपने क्षेत्र में नोटिस किया अक्सर कि जो स्कूल बंद हुए उनसे सबसे ज्यादा प्रभाव दलित, पिछड़े और माइनोरिटी के स्टूडेंट्स पर पडा है। गोविन्दपुर, चमनटीकरी, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां से दूसरे स्कूल चार-पांच किलोमीटर की दूरी पर हैं और वे स्कूल बंद होने से वहां की साक्षरता दर गिरी है। बच्चों ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। स्कूल में जो पोषाहार दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी की जांच हो। अक्सर तो हमारे क्षेत्र में पूरा दूध ही मिलावट का चलता है। पाउडर और यूरिया पता नहीं क्या केमिकल मिलाकर दूध बनाया जा रहा है और वही दूध बच्चों को भी पिलाया जा रहा है। पोषाहार की भी क्वालिटी चैक होनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, सब्जैक्ट्स का भी ध्यान हो। जिस क्षेत्र में जिस तरह के सब्जैक्ट्स की डिमाण्ड हो उस तरह के सब्जैक्ट्स वहां दिये जाएं। मैं मेवात क्षेत्र से आता हूं वहां उर्दू के सब्जैक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमाण्ड है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय मंत्री महोदय से कि क्षेत्रों में जहां से डिमाण्ड आ रही है वहां पर उर्दू चालू की जाए और जहां-जहां उर्दू है जहां रिक्त पद हैं उन्हें भरा जाए। अभी कुछ दिन पहले पता चला कि बहुत सारे उर्दू के जो पद थे उन्हें स्कूलों से हटा दिया गया। फिर छात्रों को पढ़ने के लिए क्या व्यवस्था की गयी? उसके लिए मैं मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि उन्हें भी व्यवस्थित किया जाए। ट्रांसफर्स की भी कोई पालिसी हो। जब से हम विधायक बने हैं, पहली बार

(श्री वाजिब अली)

सदन में चुनकर आये हैं। अक्सर टीचर्स सभी एमएलएज और मंत्री के यहां घरों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं कि साहब, हमारा ट्रांसफर कर दो। कोई तो नीति होनी चाहिए। बहुत से लोग अपने घर से सात-आठ सौ किलोमीटर दूर बैठे हैं। निश्चित तौर पर बहुत बार ऐसी परिस्थिति होती है कि उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में भी बहुत परेशानी होती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से दरख्वास्त करता हूं कि ट्रांसफर्स की कोई पालिसी हो, ताकि उन्हें पता हो कि हमें चक्कर न लगाने पड़ें और दलालों के द्वारा लुटना न पड़े। रिक्रूटमेंट पालिसी भी ठीक होनी चाहिए, महोदय। वोकेशनल एजुकेशन हमने स्कूलों में शुरू करवाई। लगभग 905 स्कूलों में व्यावसायिक अध्यापक लगे हुए हैं। करीब 1900 के आस-पास उनकी संख्या है और हमने उन्हें एनजीओ या थर्ड पार्टी के द्वारा रिक्रूट किया है। आज उनके हालात यह हैं कि कम से कम 6 महीने या 24 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है और उन सभी कंपनियों का अनुबंध पूरा होने वाला था जून में, अब शायद उन्हें कुछ वक्त के लिए और बढ़ा दिया गया है। डेढ़-दो साल से लोग वहां बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं और उन्हें अपने फ्यूचर का भी नहीं पता।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री वाजिब अली (नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बार बोल रहा हूं इसलिए आपसे निवेदन है कि मुझे मौका मिले। 1998 में एक रिक्रूटमेंट हुआ, वे लोग बीस साल से धरने पर बैठे हैं। चक्कर काटते-काटते उनके बाल सफेद हो गये। उनके पोता-पोती हो गये। महोदय, उनके लिए भी कुछ किया जाए।

मदरसा पैराटीचर्स की 7200 रुपये तनख्वाह है और वे घर से सात सौ किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं और सब क्वालीफाइड लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमए हैं, बीएड हैं। पहले भी चाहे आंगनबाड़ी के हों, चाहे पंचायत शिक्षा सहायक हो उनका मानदेय बढ़ा है। उनका बढ़ना चाहिए पर वे उनसे ज्यादा क्वालीफाइड हैं, कम से कम हम यह तो जस्टिस करें कि मदरसा एजुकेशन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, माइनोरिटी को एजुकेशन में बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम संसाधनों के साथ इस तरह अनजस्टिस करेंगे...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री वाजिब अली (नगर): बस बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं। महोदय, हमारे नगर में महाविद्यालय है उसमें टीचर्स की बहुत बड़ी कमी है। 18 में से सिर्फ 4 टीचर हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के संसाधन बढ़ें और कस्बा सीकरी के लिए मैं महिला महाविद्यालय की प्रार्थना करता हूं।

श्री सभापति: विराजिये माननीय सदस्य। आप मंत्री महोदय से मिल कर लिखकर दे दीजिये।

श्री वाजिब अली (नगर): बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री ललित कुमार ओस्तवाल।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या-24 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। शिक्षा की चर्चा इस सदन में हो रही है। मैं दो छोटी-छोटी बात कहकर अपनी बात को प्रारम्भ करूंगा कि अभी तक भी कई विद्यालयों में पीने का शुद्ध जल नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं हो, उसमें शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था कराएं। बच्चों के बैठने के लिए दरी-पट्टी और जो बड़ी क्लास है वहां फर्नीचर की व्यवस्था भी ठीक ढंग से नहीं है उन विद्यालयों में यह व्यवस्था भी कराएं। कई विद्यालयों के भवन पुराने हैं, कई वर्षों पहले बने हुए हैं उनकी हालत खराब है। कई जगह छत में सरिये दिख रहे हैं, नीचे सीमेंट गिर रही है। बच्चों के बैठने के काम भी नहीं आ रहे हैं वह भवन तो मेरा निवेदन है कि उन सभी भवनों का आप सर्वे करवा करके सभी की रिपेयरिंग पुख्ता करें। पंचायत सहायक हैं, ये दो विभागों के बीच में फंस रहे हैं, अभी भी उनका आदेश नहीं निकला है। निकलने की बात हुई थी उस समय। माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम आर्डर्स निकाल रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं निकले हैं तो उनके भी आर्डर निकालें और उनको परमानेंट करने का भी विचार करें।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं मेरे क्षेत्र की शिक्षा संबंधी कुछ बातें कहना चाह रहा हूं। मेरे डूंगला उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

महाविद्यालय नया खुले। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एकमात्र पंचायत मुख्यालय ऐसा है, जहां अभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, मूजवा और वह टीएसपी बैल्ट भी है, आदिवासी बैल्ट है। मूजवा में दसवीं का स्कूल है अभी, उसको दसवीं से बारहवीं तक का किया जाए और बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मंगलवाड़ है उसको माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नालवा जिला प्रतापगढ़ को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए। उच्च प्राथमिक विद्यालय नयाखेड़ा केवलपुरा को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय संस्कृत दोवड़ को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए। एक राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय निकूम में विज्ञान संकाय खोलने की कृपा करें। राजकीय माध्यमिक विद्यालय हरियाखेड़ी को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराएं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय सेठवाणा देलवास को भी उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने की कृपा करें।

राजस्थान में जब भी इस सदन में शिक्षा के मामले में कोई चर्चा हो तो 1993 से 1998 के कार्यकाल में जब हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब मुख्य मंत्री थे राजस्थान के, सम्माननीय कटारिया साहब शिक्षा मंत्री थे, उस समय उन्होंने पहली से आठवीं तक पढ़ने वाले सभी बच्चों की किताबें सरकार की तरफ से छापकर उन बच्चों को वहां भेजी थीं इसलिए उनका आभार जरूर व्यक्त करना चाहिये। उसके बाद 2003-08 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में थी, सम्माननीय वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री थीं, आदरणीय कालीचरण जी सराफ और वासुदेव जी देवनानी 2003-08 और 2013-18, दोनों समय शिक्षा मंत्री जी थे। राजस्थान के सभी विद्यालय, उन्होंने उस समय कोई भेदभाव नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक है या किस पार्टी का है, सारे पंचायत मुख्यालय पर 2003-08 में दसवीं के विद्यालय किये और 2013-18 में सभी विद्यालयों को बारहवीं किया। मैं उन सबका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, जय भारत, जय राजस्थान, जय चित्तौड़।

श्री सभापति: श्रीमती सफिया जुबेर।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूं। सबसे पहले मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद करती हूं जिन्होंने पूरे राजस्थान में 32 कालेज और मेरे जिले में चार खोले हैं, लेकिन अगर एक मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी खोल दिया होता तो सोने पे सुहागा होता। इसके अलावा बहुत से स्कूल क्रमोन्नत होंगे, नये स्कूल खुलेंगे क्योंकि मुझे लगता है जब कांग्रेस की सरकार आती है नये स्कूल खोलने की बात करती है, नई भर्तियों की बात करती है। शिक्षा का अधिकार भी कांग्रेस ने दिया था, लेकिन शिक्षा के अधिकार पर कैंची चलाने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया हजारों स्कूलों को बंद करके, जिनकी वजह से बहुत से बच्चे जो ढाणियों में पढ़ रहे हैं, वे शिक्षा से वंचित चल रहे हैं, क्योंकि पांच-पांच किलोमीटर दूर जाना छोटे बच्चों के लिए सम्भव नहीं हो पाता है। इसी के एवज में बहुत से प्राइवेट स्कूल वहां खुल गये जो नार्म्स पूरे नहीं करते थे। जिनके पट्टे भी नहीं थे, जो सिक्योरिटी के हिसाब से भी सही नहीं थे, लेकिन मैं इन्हें दोष नहीं देती हूं शायद इनकी पार्टी की पालिसी है कि यह सिर्फ भगवा रंग पर जमे पड़े हैं, चाहे साइकिल का रंग भगवा कर दें या कुछ भी कर दें। यह लोगों को भटकाने का काम करते हैं। योगा की बात करते हैं, मुझे ध्यान है तीस साल पहले हमारे सेन्ट्रल स्कूल में भी योगा की क्लास होती थी और योगा टीचर भी होते थे। तब सब जगह कांग्रेस की सरकार थी और योगा करना मुझे भी आता है। भारत माता के नारे मैंने स्कूल में खूब लगा लिये थे। वंदेमातरम भी मुझे पूरा आता है। लेकिन अगर मैं आप सबसे पूछूं कि अलग-अलग आप वंदेमातरम गाओ तो आप नहीं कर पाएंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन की तरफ बात करें।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): सभापति महोदय, सबसे पहले जो समस्या मुझे लगती है हमारे राजस्थान में, शिक्षकों को लेकर है। सबसे बड़ी उसमें खामी यह है कि हमारी कोई पालिसी नहीं है शिक्षा को लेकर। ट्रांसफर की पालिसी नहीं है। कैसे स्कूल क्रमोन्नत होंगे, उसकी कोई पालिसी नहीं है। टीचर के ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कोई नहीं हैं। प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स हैं, उनके लिए मोन्टेसरी टाइप की कोई ट्रेनिंग नहीं है। यह सच्चाई है कि हमारा देश एक डवलपिंग कंट्री है तो यहां लोग टीचर इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको

(श्रीमती सफिया जुबेर)

एक नौकरी मिल जाएगी। डवलप्ड कंट्री में टीचर वह बनता है जिसकी इच्छा बच्चों को पढ़ाने की होती है। बहुत बड़ा फर्क है जिसकी वजह से मुझे लगता है गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण इलाक़े इतने फैले हुए हैं कि दूर-दराज में हमारे टीचर्स रुकते नहीं हैं। इसके लिए सरकार को कुछ करना पड़ेगा ताकि वहां स्कूल में टीचर्स रुकें और वहां के बच्चों को पढ़ाएं।

इसके अलावा अगर मैं मेवात की बात करूं तो मेवात पर खास ध्यान देना पड़ेगा वरना यहां क्राइम बहुत अधिक बढ़ेगा क्योंकि जो समाज शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है वह पिछड़ गया है और क्राइम के रास्तों पर चलता है। मेवात में जो आवासीय विद्यालय हैं, मैं चाहूंगी वह 8वीं से 10वीं हो जाए। एक अगर रामगढ़ में कालेज खुल जाएगा, एक नगर में खुल जाएगा, कामां में तो खुल गया, बहुत बड़ा फायदा वहां रहने वाले लोगों को होगा।

इसके बाद अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूलों की तो प्राइवेट स्कूलों में इतनी अधिक फीस ले रहे हैं और मुझे लगता है कि सरकार की इस पर कोई लगाम नहीं है, यह सच्चाई है। दस-दस हजार रुपये एक महीने के लेते हैं और वह एक्स्ट्रा ऐसा क्या दे रहे हैं? उनके टीचर्स की क्वालिफिकेशन वही है जो सरकारी टीचर्स की है, उसके बावजूद इतनी अधिक फीस लेना, मुझे लगता है यह लोगों के साथ अन्याय है। इस पर आप लोगों को कुछ न कुछ लगाम लगानी चाहिये।

इसके अलावा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वहां तो चाहे कोई बच्चा कालेज अटेंड ही न करे, उसको डिग्री मिल जाती है। वहां बस एडमिशन लेने की देरी है, उसके लिए खूब अच्छा डोनेशन लेते हैं, एब्सेंट रहने के नाम से वह पैसे दे देते हैं और उसके बाद उनको डिग्री मिल जाती है। यानी प्राइवेट कालेज/यूनिवर्सिटीज हैं वह तो एक तरीके से डिग्री छापने की मशीन बन गये हैं। हमारे अलवर में एक मत्स्य यूनिवर्सिटी खुली है, कांग्रेस सरकार ने उसको शुरू किया था लेकिन उसका काम पूर्ववर्ती बीजेपी की सरकार में हुआ। उसमें इतने अधिक घोटाले हुए, कैसे भर्ती हुई, कैसे चली, क्या कंस्ट्रक्शन हुआ, उसका कुछ लेखा-जोखा नहीं है। इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी उस यूनिवर्सिटी की पूरी तरह से जांच होनी चाहिये। इसके अलावा हर जिले में अभी महात्मा गांधी स्कूल बनाये गये हैं जो इंग्लिश मीडियम हैं। इसमें मैं

(श्रीमती सफिया जुबेर)

चाहूंगी कि ये 33 स्कूल हैं, इन 33 स्कूलों में संस्कृत और उर्दू एज ए सैकिण्ड लैंग्वेज आपको रखना चाहिये क्योंकि ये भाषाएं हैं और मुझे लगता है लोगों को हमें इससे जोड़ना चाहिये। हमारी पुरानी भाषाएं हैं और हमारे बच्चे इन भाषाओं से दूर होते जा रहे हैं।

मदरसा पैराटीचर्स की बात करें, हालांकि अल्पसंख्यक विभाग का मामला है लेकिन टीचर्स हैं, शिक्षा दे रहे हैं। मदरसा भी एक प्रकार के स्कूल हैं और सरकार ने बात की है इन मदरसों को सशक्त करने की लेकिन जब तक मदरसा पैराटीचर्स को आप सशक्त नहीं करोगे वे कैसे अपना पूरा ध्यान पढ़ाने पर लगाएंगे। अलवर की बच्ची बाड़मेर में पढ़ाती है और सिर्फ सात हजार तनख्वाह लेती है, जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। मुझे लगता है सरकार को इन पैराटीचर्स का, मदरसा टीचर्स का मानदेय बढ़ाना चाहिये। सात, साढ़े सात हजार इनका मान नहीं बल्कि टीचरों का अपमान है और हमारी संस्कृति में यह कहा गया है कि जो गुरु होते हैं, भगवान के बाद दूसरा नंबर उन्हीं का आता है।

खास तौर पर मैं कहना चाहूंगी कि जो बीएड कालेज हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे सरकारी कालेज हैं, सबमें अटेंडेंस 75 परसेंट कम्पल्सरी होनी चाहिये क्योंकि बच्चे कालेज नहीं जाते, बीच में इधर-उधर हो जाते हैं और इसके लिए सब जगह बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाए। अगर एब्सेंट होते हैं तो उसके लिए अच्छा मोटा उनको फाइन भरना चाहिये।

आखिर में मैं कहना चाहूंगी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछली सरकार बहुत बातें करती थीं गुजरात माडल, गुजरात माडल। गुजरात में जो टीचर्स के ट्रांसफर की पालिसी का मामला है वह उन्होंने क्यों नहीं अपनाया। सिर्फ बातों से काम थोड़े ही चलेगा। ट्रांसफर की पालिसी तो गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, आन्ध्रप्रदेश में भी है। राजस्थान में इस पालिसी पर हमेशा बात होती है लेकिन कभी काम नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से रिक्वैस्ट करूंगी कि आज जब शाम को वह सदन में अपनी बात रखें तब इस पालिसी के बारे में जरूर कुछ न कुछ आश्वासन दें क्योंकि टीचर्स हम सब लोगों को घेर कर रखते हैं। सुबह चार बजे आ जाते हैं, रात के बारह बजे आ जाते हैं, सबको अपनी मनपसंद जगह चाहिये और महिला शिक्षकों की तो काफी अनदेखी भी हो जाती है। जब तक यह पालिसी

(श्रीमती सफिया जुबेर)

नहीं बनेगी, मुझे लगता है कि ठीक प्रकार से स्कूलों में काम नहीं होंगे और यह बहुत बड़ा इनकम्बेंसी फैक्टर किसी भी सरकार के खिलाफ इसलिए होता है क्योंकि टीचर्स के लिये हमारी कोई पालिसी नहीं है। मुझे लगता है कि विपक्ष के भी सारे विधायक इस बात से सहमत होंगे क्योंकि वे भी हमारे बराबर ही परेशान रहते होंगे। बल्कि अब तो वे बहाना लगा देंगे कि हमारी सरकार नहीं है। लेकिन हम लोगों को तो बहुत परेशानी इसको लेकर होती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): सभापति महोदय, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि मेरे इलाके में बहुत से स्कूल हैं जिन्हें बारहवीं होना है जैसे ढेरवाला बास है, गुंगडोद है, मेलापुरा है जिन्हें दसवीं होना है। नांगलटप्पा है, भुजाका है, ईसनकाबास है, नये स्कूल भी खुलने हैं, 5वीं से 8वीं भी होने हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे शिक्षा मंत्री मेरे इलाके के सभी कामों पर ध्यान देंगे। सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिरधारी।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति पर बोलने का मौका दिया। मैं अपनी सीधी मांग रख रहा हूं। श्री डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र ग्राम किरतासर, तहसील नोखा मेरा क्षेत्र पड़ता है। यहां पर प्राथमिक विद्यालय है, उसको क्रमोन्नत किया जाए। दूसरी मांग है कि विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के गांव कुंतासर, तहसील श्रीडूंगरगढ़ में भामाशाह द्वारा पूरा भवन बनाया हुआ है, वहां पर प्राथमिक बालिका विद्यालय खोला जाए। तीसरी मांग है विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के गांव कूंचासर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय खोला जाए। चौथी मांग है, विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के ग्राम केऊ बड़ी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए। पांचवीं मांग है, विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के गांव गुलचासर की राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाया जाए। छठी मांग है, महरामसर प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए। यह विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में आता है और तहसील नोखा है। सातवीं मांग रेड़ी उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय बनाया

(श्री गिरधारीलाल)

जाए। सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर राजस्थानी भाषा को 12वीं में ऐच्छिक विषय के रूप में और इसमें पीएचडी करने की भी छूट है, मेरा आसन के द्वारा सरकार से निवेदन है कि यह प्रथम कक्षा से शुरू की जाए। जैसे हमने कला और संस्कृति की बात की है तो हमारी राजस्थानी भाषा भी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अग्रिम रूप में रहेगी, यह कहते हुए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रूपाराम मकराना (अनुपस्थित)। श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत दुनिया में ऐसा देश है, जहां पर बड़ी तेजी से बदलाव हो रहा है और इसका माध्यम शिक्षा है। शिक्षा प्रदेश के भविष्य का आधार है, यह हम और आप सब सदस्य जानते हैं। मनुष्य के सर्वांगीण विकास में शिक्षा आवश्यक है। राज्य सरकार नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे और विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी जा रही है, इसमें सेवा का भाव त्याग, समर्पण और अनुशासन जैसे गुण और भावना पर विशेष जोर दे। सभापति महोदय, अभी चर्चा हो रही थी, योग दिवस के ऊपर बड़ी ईर्ष्या क्यों हो रही हैं। इस सरकार के विधायक और मंत्री इन कार्यक्रमों से दूर हो रहे हैं। सभापति महोदय, हमें गर्व होना चाहिए कि देश के प्रधान मंत्री जी ने योग शिक्षा को सम्पूर्ण विश्व में योग दिवस को, 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी यहां विराजमान हैं। बहुत ही चालाक हैं। पहले हमारी स्कूलें 19 जून को खुलती थीं, अब 19 जून की जगह बहुत ही चालाकी से 24 जून कर दिया और आदेश निकाल दिया कि 1 जुलाई को स्कूल खुलेंगे। बच्चे 21 जून को योग दिवस में अगर योग कर लें तो इन बच्चों का सम्पूर्ण विकास होगा।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार कभी भी शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं रही है। आजादी के बाद अधिकांश शासन कांग्रेस ने किया। पिछले 2013 में कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी थी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि 52 परसेंट अध्यापकों के पद खाली थे। जब सत्ता छोड़ी देश में राजस्थान शिक्षा के पायदान पर 26वें नंबर पर था। मैं धन्यवाद दूंगा, पूर्व मुख्य मंत्री

(श्री नारायण सिंह देवल)

आदरणीय वसुन्धरा राजे जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी को। उनके प्रयास से राजस्थान को नंबर दो पर लाये। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से मांग करूंगा आप प्रयास करें कि राजस्थान पूरे देश में नंबर दो से नंबर एक पर आये। निश्चित तौर पर हम आपकी भी पीठ थपथपाएंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा कि वर्तमान में पूरे राजस्थान में 86 हजार स्कूलें चल रही हैं, चार लाख से अधिक अध्यापक हैं और 85 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। राजस्थान के जो मध्यम और गरीब परिवार के बच्चे हैं, वे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को सस्ती, अच्छी, गुणवत्तापूर्ण और संस्कारवान शिक्षा कैसे मिले, यह हम सबका कर्तव्य है।

जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, स्कूलें तो बहुत थीं, परंतु उनकी स्थिति क्या थी? एक समीक्षा की गयी, पूरे राजस्थान में 142 स्कूल ऐसी थीं, जहां जीरो नामांकन था और 4164 स्कूलें ऐसी थीं, जिनमें 15 से कम नामांकन था और 2800 स्कूलें ऐसी थीं, जिनमें 15 से 30 नामांकन था। उन स्कूलों को मर्ज किया। हमारे शिक्षा मंत्री जी यहां विराजते थे। आपमें से कई अधिकांश सदस्य भी यहां थे। आप लोगों ने जोर-जोर से कहा और कांग्रेस के जन-घोषणा पत्र में यह कहा गया कि जो 22 हजार स्कूलें बंद की थीं, हम उनको चालू करेंगे।

अभी आप 2800 स्कूल फिर से खोलने का प्रस्ताव लाये। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो शेष स्कूलें थीं, जो हमारी सरकार ने बंद की थीं, वे आपके हिसाब से ठीक थीं, तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि सत्ता में आते ही आप राग नहीं बदलें। जो कांग्रेस के घोषणा-पत्र में आप लोगों ने वादा किया, उन स्कूलों को आप कब खोलेंगे? पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने शिक्षा में राजनीति नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, इसके लिए पोस्टिंग, प्रमोशन के लिए काउंसलिंग व्यवस्था की। मैरिट के आधार पर पोस्टिंग देने का बहुत अच्छा काम किया। सभापति महोदय, इस निर्णय की पूरे राजस्थान के शिक्षक बंधुओं ने बहुत तारीफ की। पूर्ववर्ती सरकार के समय में बी.एड.धारी या जो एस.टी.सी. कर रहे थे, उनको भी स्कूलों में ट्रैनिंग के माध्यम से जोड़ा, जिससे जो शिक्षकों की कमी थी, वह दूर हुई और बच्चों का उन स्कूलों से जुड़ाव हुआ।

माननीय सभापति महोदय, अभी बहुत जोस्जोर से बात चल रही थी

(श्री नारायण सिंह देवल)

कि प्राइवेट स्कूल फीस के माध्यम से लूट रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार के टाइम पर एक एक्ट लाया गया और 28 हजार स्कूलों में लागू भी किया गया। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आप इनके ऊपर और सख्त होकर कार्यवाही करें।

सभापति महोदय, पिछली सरकार की जो अन्नपूर्णा दुग्ध योजना थी, उसकी आज क्या हालत हो गयी है? दूध के जो सप्लायर हैं, उनको पैसा नहीं मिलने के कारण वह योजना भी अब लगभग बंद के कगार पर है।

2013-14 के बोर्ड के परीक्षा परिणाम के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उस टाइम में 58 परसेंट रिजल्ट था, 2017-18 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो यह 76 परसेंट रिजल्ट हुआ और 2018-19 में यह 80 परसेंट रिजल्ट आया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह हम सब की जवाबदारी है और आपकी विशेष रूप से जवाबदारी है कि 80 परसेंट से इसको आगे और कैसे बढ़ाएं?

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में 1 लाख 46 हजार बच्चियों को गार्गी पुरस्कार दिया था, जबकि इससे पूर्व की कांग्रेस सरकार में यह मात्र 44 हजार था। आज मिड-डे-मील की लोग बार-बार मांग कर रहे हैं कि हमारी सैलेरी बढ़ायी जाए। मैं कहना चाहूंगा कि अध्यापकों को पिछले दो-तीन महीने से सैलेरी नहीं मिल रही है। शिक्षा मंत्री जी, पूरे राजस्थान में 19560 विद्यालय ऐसे हैं, जहां पर बाउंड्री नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार ने नरेगा के तहत बाउंड्री बनाने की घोषणा की थी, उस काम को आगे बढ़ाएं। राजकीय महाविद्यालय रानीवाड़ा में 13 में 12 पद रिक्त हैं, उनको भरा जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री चेतन सिंह चौधरी।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि हर देश, हर प्रदेश का चरित्र बदलता नहीं है और एक चरित्र उसका होता है। मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि कालीदास और शेक्सपियर दोनों ही महान कवि थे लेकिन इंग्लैंड कभी कालिदास पैदा नहीं कर सकता और भारत कभी शेक्सपियर पैदा नहीं कर

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

सकता। फ्रांसीसी लेखक आंद्रे मोलरोक्स ने नेहरू जी से पूछा था कि आजादी के बाद आपके लिए जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, वह क्या है? नेहरू जी का जवाब था 'creating a just state by just means' यानी कि एक न्यायप्रिय देश बनाना और उचित साधनों से बनाना। सबसे बड़ी मुश्किलात है हमारे लिए। अगर जस्ट स्टेट या न्यायप्रिय देश बनाना है तो मेरा सभापति महोदय, यह मानना है कि उसमें शिक्षा की बहुत अहम भूमिका रह सकती है।

सभापति महोदय, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। इस माध्यम से सबसे बड़ा किरदार या भूमिका जिसकी रहती है, वह है शिक्षक। आज तक के इतिहास में जो सबसे बड़े शिक्षक रहे, वह हमारे अपने देश से अमर आत्मा गुरुदेव चाणक्य रहे। गुरुदेव चाणक्य का यह कथन कि प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं, उन्होंने इस कथन को सत्य करके दिखाया था। गांव के चबूतरे पर बैठे हुए एक युवक जिसको उठाया, शिक्षा दी, ट्रैनिंग दी और उसको भारत का सम्राट बनाया जिसे आज भी हम चन्द्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं। यही शिक्षक है जो भारत का भविष्य संवारते हैं।

आज शिक्षा पर चर्चा चल रही है। कल चर्चा चिकित्सा पर चल रही थी। लगातार ये बातें आती रहीं कि हमारे यहां पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स हैं या जो निजी संस्थाएं हैं, वे लूट मचा रही हैं चाहे वह प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वह प्राइवेट हास्पिटल हैं। हम लोग इस सदन में कब तक यह बातें करते रहेंगे? क्या हमारी यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम कुछ ऐसे स्कूल, कुछ ऐसी सरकारी संस्थाएं बना दें, जो प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट हास्पिटल के साथ प्रतिस्पर्धा करें, काम्पीटिशन करें। यह देखने को भी मिलता है। मेरे डीडवाना में फोगड़ी एक गांव है, उसमें एक स्कूल है। मैं मंत्री जी को आमंत्रित करूंगा कभी उस स्कूल में अपने सारे बड़े अधिकारियों के साथ आएं। सभापति महोदय, उस स्कूल में एडमिशन के लिए लाइन लगती है और कट आफ लिस्ट जारी होती है। उस स्कूल से आरएएस बने हैं, उस स्कूल से आईएएस बने हैं, बड़े-बड़े अधिकारी बने हैं। जब एक फोगड़ी जैसे गांव में हम ऐसा स्कूल तैयार कर सकते हैं तो हजारों-हजार गांव जो हमारे राजस्थान में हैं, उनमें जो सरकारी स्कूल हैं, वैसे ही उम्दा स्कूल क्यों तैयार नहीं कर सकते? हमारे पास जो शिक्षक हैं, वह बहुत उम्दा क्वालिटी के शिक्षक हैं। लेकिन कहीं कमी हमारी रह जाती है, हमारी इच्छा शक्ति में कमी रह जाती है। मैं आपके माध्यम से

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

सरकार से, मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अब जब शिक्षा की बात करें तो गुणवत्ता उसमें सबसे जरूरी स्टैण्डर्ड होना चाहिए। सोच रखनी चाहिए कि शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए।

सभापति महोदय, 1998 से 2003 के बीच में जब कांग्रेस का राज था तो मेरे विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में सबसे ज्यादा स्कूल खुले पूरे राजस्थान में और वहीं जब भाजपा का राज आया 2013 से 2018 के बीच में सबसे ज्यादा जो स्कूल बंद हुए वह मेरे डीडवाना के हुए। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इतिहास फिर से दोहराएं और जब यह बंद स्कूल वापस खुलें तो सबसे ज्यादा मेरे डीडवाना में खुलें, यह मेरी आपसे इल्तजा है, रिक्वैस्ट है। डीडवाना के राजस्व ग्राम एक कल्याणपुरा नाम से गांव है, एक गोंतलिया है। राजस्व ग्राम है और मात्र पूरे गांव में एक ही स्कूल था, पूर्ववर्ती सरकार ने उन राजस्व ग्रामों के स्कूलों को बंद कर दिया। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन स्कूलों को खोलें। इसके अलावा मेरे डीडवाना विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीणों की मांग को देखते हुए ब्लाक डीडवाना के बड़ौद, गोधरास, रूआ, नींबीखुर्द, हमीरपुर, अमरपुरा, डिकावा तथा ब्लाक मोलासर के कीचक, बावड़ी, भाड़ासर, चुगनी व बेरीकलां के जो सरकारी स्कूल हैं, उनको क्रमोन्नत करके मेहरबानी फर्माएं।

मंत्री जी बधाई के पात्र हैं जो बाल सभा जैसे नवाचार लेकर आए। बाल सभा भी गांव का जो गुवाड़ था उसमें बनवाई। हमारे जैसे जितने जन-प्रतिनिधि थे, मैं स्वयं चार बाल सभा में एक ही दिन में जाकर आया था। वहां पर गांव वालों से पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक इंटरेक्ट कर रहे हैं। वहां के लोकल जन-प्रतिनिधि हैं, वह इंटरेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऐसे नवाचार लगातार लेकर आते रहे तो हमारी शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। मैं निवेदन करूंगा कि ये जो शिक्षा सहायक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अटकी हुई भर्तियां हैं, इनका कहीं न कहीं निस्तारण करें। सात हजार रुपये में ये लोग बैठे हैं लगातार कितने ही सालों से। मेरी इनसे बात होती है, यकीन मानिये ये सिर्फ इस उम्मीद में बैठे हैं कि क्या पता सरकार हमें कभी पक्का कर दे? इनके ही साथी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट या निजी संस्था में जा रहे हैं 25 से 30 हजार पाते हैं। मंत्री महोदय, अपनी नरम निगाहें रखें। इन लोगों के भविष्य को बचाने में मदद करें।

श्री सभापति: एक मिनट में बात समाप्त करें अपनी।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): अब मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उच्च शिक्षा मंत्री जी यहां नहीं है। मेरे डीडवाना कस्बे के मध्य में 11031.521 वर्गमीटर में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय बना हुआ था जिसको हम एक नंबर स्कूल बोलते थे। 2003 से 2008 के बीच में जब भाजपा की सरकार बनी और मेरे यहां से विधायक जो मंत्री भी रहे, उन्हीं के कुछ लोग या जो भी मैं कहूं, उस निजी स्कूल को, उसकी भूमि एवं भवन को एक निजी महिला महाविद्यालय के नाम पर दे दिया गया। उसके विरोध के अंदर कुछ प्रबुद्धजन डीडवाना के हाई कोर्ट में गये और माननीय उच्च न्यायालय के सामने इन्होंने एफिडेविट दिया कि हम इस स्कूल को एक साल के भीतर खाली कर देंगे क्योंकि हमारी एक नई बिल्डिंग बन रही है। महोदय, एक साल निकल गया, दो साल, पांच साल निकल गये।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): एक मिनट का समय चाहूंगा साहब। वह स्कूल, वह बिल्डिंग खाली नहीं की गयी और उसके बाद जब वापस से भाजपा का राज बना 2013 में तो जिन लोगों ने, प्रबुद्धजनों ने यह बोला था कि यह जमीन जो निजी महाविद्यालय के नाम की जा रही है, यह सिर्फ उस 11031 वर्गमीटर जगह को हड़पने का एक तरीका है। वह सिद्ध हो गया और 2013 के अंदर हमारी एडिशनल सैक्रेटरी, शिक्षा की डीडवाना जाकर उस बेशकीमती करोड़ों रुपये की स्कूल की जमीन को मात्र 210 रुपये में उस निजी महिला महाविद्यालय के नाम लिखवाकर आ गयीं। अफसोस है कि छोटे गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल के लिए जो जमीन दी गयी, वह निजी महिला महाविद्यालय को दी गयी।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। श्री रामप्रसाद।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): यह जो एफिडेविट दिया गया था, उस एफिडेविट के खिलाफ हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि एक साल में खाली कर देंगे। एक मिनट साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इसको सरकारी महिला महाविद्यालय घोषित करें। राजकीय महिला महाविद्यालय घोषित करें और जिन लोगों ने इस जमीन को हड़पा है, उन लोगों को कठोर से कठोर सज़ा दें।

श्री सभापति: श्री रामप्रसाद।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): यह जो महिला महाविद्यालय है,

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

उसका जो संरक्षक मंडल हैं, उसके चार नाम आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा।

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): श्री वेणुगोपाल जांगिड, श्री हरिशंकर भाभड़ा, श्री हरिमोहन बांगड़, श्री यूनुस खान।

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य। सहयोग करें। अंकित नहीं होगा।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): 000

श्री सभापति: श्री रामप्रसाद ढिंढोर।

(18.00 बजे)

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): माननीय सभापति, आज मांग संख्या 24-शिक्षा, संस्कृति और कला के संबंध में चर्चा हो रही है। मैं इसके संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूं। संस्कृति हमारे जीवन ज़ीने का तरीका है मानसिक सोच का परिचायक है। किसी भी जन समुदाय का मानसिक सोच कैसा है, यह उसकी संस्कृति से झलकता है। आदिवासी संस्कृति प्रकृति से जुड़ी हुई है और प्रकृति के नियम क़ायदों से बनी है। मानव सृजित बंधनों से कम प्रभावित है। आदिवासी संस्कृति को समझने के लिए हमारी भीली भाषा को समझना जरूरी है। दक्षिण राजस्थान के भील समुदाय की संस्कृति कला को समझने के लिए भीली बोली को समझना जरूरी है।

राजस्थान सरकार में प्रथम शिक्षा आयोग दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में, 1963 में आयोग ने अनुशंसा की थी कि आदिवासी इलाक़ों में, आदिवासी बोली में प्रारम्भिक शिक्षा हो। अभी तक लागू नहीं करने से विद्यालयों के बच्चे ड्रोप ओवर होकर स्कूल छोड़ रहे हैं। कई शब्दों का हिन्दी और भीली बोली में अलग-अलग अर्थ होता है, जिससे बच्चे टोर्चर होते हैं, जैसे नीली स्याही का पैन, भीली बोली में नीली को हरा बोला जाता है।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि कक्षा पहली से पांचवी तक भीली बोली में, हिन्दी पर्यावरण, पाठयक्रम का कोर्स बने।

(श्री रामप्रसाद)

आदिवासी संस्कृति सहकारिता पर आधारित है। एक विषय आदिवासी संस्कृति से संबंधित सम्मिलित किया जाए।

इसी उपयोगी भावना को आगे बढ़ाते हुए, आदिवासियों की सहकारी समिति बनाकर सहकारी योजनाओं को आदिवासियों के हाथों में अमलीकरण हेतु देनी चाहिए। आदिवासियों की कला को आगे बढ़ाने के लिए जिला मुख्यालय पर कला संस्कृति केन्द्र खोले जाएं। आदिवासियों के अंदर धाड़ प्रथा लिलवन, हुन्डेल वगैरह है, उनको प्रोत्साहित किया जाए।

आज हम 21वीं सदी में हैं, शिक्षा के बारे में धरातल पर यह स्थिति बनी हुई कि आज भी सरस्वती वंदना स्कूल कालेजों में करते हैं, उस सरस्वती वंदना के बारे में यदि प्रिसिंपल या लैक्चरर को पूछा जाए तो वह जवाब देते हैं कि सरस्वती कौन थी, विद्या की देवी थी। लेकिन जब इनको पूछा जाए कि विद्या की देवी क्यों थी, कौन पिता थे, किससे शादी की थी, पति कौन थे, यह पूछने पर जवाब मिलता है कि हम नहीं जानते हैं। ऐसी शिक्षा, जो अंधविश्वास हो, सत्य पर आधारित नहीं हो, वैज्ञानिक नहीं हो, इस तरह से बच्चों को शुरूआती दौर में ही जिस तरह से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इस प्रकार की शिक्षा परोसने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से अलग व्यवस्था बनेगी। सरस्वती वंदना से जो हो रहा है, मैं समझता हूं कि उसका सबसे ज्यादा असर हो रहा है। आज मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। बाप बेटी के बलात्कार के केसेज आते हैं, बलात्कार के आते हैं, ऐसी संस्कृति हमारे सामान्य वर्ग में चल रही है उसको रोका जाना चाहिए जिससे बलात्कार वगैरह की घटनाएं नहीं हों। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार करें। हमारे सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में स्कूल और कालेज चल रहे हैं। स्कूलों में बहुत खराब स्थिति है। स्कूलों में 8066 स्वीकृत पद हैं और कार्यरत 5802 हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में बात समाप्त करें।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): राजकीय महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी, सागवाड़ा में छात्र-छात्राओं का कालेज दूर है, उसके लिए 50-60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहां पर विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोला जाए, जिससे गरीब बच्चों को दूर नहीं जाना पड़े और समय तथा धन की बर्बादी से बच सकें।

(श्री रामप्रसाद)

आरटीई एक्ट, 2009 के अनुसार निजी विद्यालयों में 25 परसेंट आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को एडमिशन दिए जाते हैं। उसमें पिछड़े वर्ग को आधार मानकर...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री छगनसिंह।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): आर्थिक आधार नहीं मानकर उसके बदले अनुसूचित जनजाति किया जाए जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री छगनसिंह (आहोर): सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। पूर्ववर्ती सरकार, वसुन्धरा राजे जी की सरकार में मंत्री देवनानी जी ने शिक्षा के कई नवाचार किये। उन्होंने काउंसिल के द्वारा मैरिट के अनुसार प्रमोशन किया। उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा आज के मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा जी ने भी की थी।

सभापति महोदय, उसके बाद भी शिक्षा में कई प्रकार की कमी है उसके संबंध में मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। एनसीईआरटी पाठयक्रम लागू है, वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी लागू किया जाए। पूरे राजस्थान में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के द्वारा ही आजकल कम्पीटिशन की तैयारी होती है। मैं चाहूंगा कि हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू हो, जिससे वह भी समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकें।

आईसीटी लैब, कम्प्यूटर के लैब, हर स्कूल में खुल चुके हैं लेकिन कम्प्यूटर शिक्षक नहीं हैं। पूरे प्रदेश में कृपया कम्प्यूटर शिक्षक लगाएं। विद्यालय क्रमोन्नत किये हैं उनमें कक्षा कक्ष की कमी है। जहां भी कक्षा कक्ष की कमी है वहां नये कक्षा कक्ष बनाये जाएं ताकि जिन छात्रों ने प्रवेश लिया है उनकी सही तरह से शिक्षा हो सके। पुराने विद्यालय बने हुए हैं, आरटीई के नियम के अनुसार छोटे आकार के कक्षा कक्ष हैं, आरटीई नियमानुसार उनके बड़े भवन बनाए जाएं ताकि कक्षा कक्ष की साइज बराबर बन सके।

(श्री छगनसिंह)

डाक व्यवस्था शिक्षकों को दी जाती है। डाक व्यवस्था दो तरह से ली जाती है, आनलाइन भी ली जाती है और आफलाइन भी। मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दोनों जवाब नहीं मांगकर आनलाइन जवाब मांगें जिसमें दो-दो शिक्षक काम पर लगे रहते हैं, एक शिक्षक ही काम कर सकेगा।

जब शिक्षा की बात हो रही है तो शिक्षकों को भी याद करना चाहिए। शिक्षकों के हित की बात भी ध्यान में रखना चाहिए। जो शिक्षकों का मेडिक्लैम होता है, मेडिक्लैम में इलाज लेते हैं तो पहले रुपये कैश देने पड़ते हैं। मैं चाहूंगा कि मेडिक्लैम की सुविधा कैशलेस की जाए जिससे शिक्षक अपना इलाज सही तरीके से करवा सकें। उनके पास पहले पैसे, टीचर्स के पास महीने में एक बार ही तनख्वाह बनती है और घरेलू खर्चे ज्यादा होते हैं तो शायद शिक्षक बचा नहीं पाते। अगर मेडिक्लैम में कैशलेस की सुविधा हो जाए तो मंत्रीजी, शिक्षक आपका हमेशा गुणगान करेगा। वैसे भी आप जब शिक्षा मंत्री बने थे, सबसे ज्यादा अगर कोई खुश हुआ था तो पंचायत सहायक खुश हुए थे क्योंकि आप हमेशा हिमायत करते थे, पंचायत सहायकों और विद्यार्थी मित्रों की हमेशा अगर पैरवी की है तो गोविन्द सिंहजी डोटासरा ने की है। उनमें अभी और भी और ज्यादा खुशी है कि पंचायत सहायक जो हैं, उन्हें अगर कोई परमानेंट करेंगे तो गोविन्द सिंहजी डोटासरा करेंगे। जल्दी इनकी भी घोषणा करेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री छगनसिंह (आहोर): मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में, मैंने पूर्व में भी मंत्रीजी को सूचना दी है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आलावा-ए, कुण्डली, देवानारी सेदरिया, देल्दरी का फाफरिया गांव, वहां पर प्रारम्भिक स्कूल नहीं है। वहां कक्षा-कक्ष बने हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से वहां कोई भी स्कूल नहीं है। चारों राजस्व गांव हैं और राजस्व गांव में एक भी विद्यालय नहीं है। कृपया इन्हें जल्दी से शुरू करवाएं, जिससे उन गांवों में भी बच्चे पढ़ सकें। इसके अलावा, बाघरा एक बड़ा कस्बा है। वहां पर बालिका विद्यालय नहीं है। सब बालिका विद्यालय को हमेशा ध्यान में रखकर पढ़ाई करवाते हैं। अगर बालिका शिक्षा की बात करते हैं तो बाघरा में बालिका माध्यमिक शिक्षा खोली जाए जिससे बालिकाओं को भी

(श्री छगनसिंह)

शिक्षा मिल सके। मैं तीन-चार विद्यालयों को क्रमोन्नयन के लिए आपसे अपील करूंगा कि छीपरवाड़ा, किशनगढ़, रेलिया गुढा, इन विद्यालयों को अगर आठवीं से दसवीं कर लें तो वहां के बच्चे, जो वास्तव में बाहर, दूर-दूर पढ़ने जाते हैं उनको भी शिक्षा मिल जाएगी।

हमारे उच्च शिक्षा मंत्री विराजे हैं। विराजे नहीं हैं, बाहर गये हुए हैं, लाबी में होंगे। उनसे भी मैं अपील करूंगा कि मेरे आहोर विधान सभा क्षेत्र के सियाणा गांव में अगर एक कालेज खोल दें, हमारे पूरे क्षेत्र में एक ही कालेज है तो उस क्षेत्र में कालेज बन जाएगा। कालेज बनने से, वहां के छात्र, जो बाहर जाते हैं, हमारे छात्र इतने धनाढ्य नहीं हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ किसान हैं। किसान होते हैं तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते। वे पढ़ने के लिये बाहर कहां से जाएं। अगर सियाणा में भी एक कालेज खुल जाये तो वहां के बच्चे आराम से पढ़ सकेंगे।

तकनीकी शिक्षा की बात करूं तो आहोर विधान सभा क्षेत्र में, आहोर उप खण्ड पर एक आई.टी.आई. कालेज खोलें, जिससे मुझे खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी। हमारे शिक्षा मंत्री विराजे हैं।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री छगनसिंह (आहोर): जी, मैं तो कर ही रहा हूं।

शिक्षक भर्ती, 2012 में, मुकेश टेलर के केस में उच्च न्यायालय ने फैसला लागू किया था कि सीट बढ़ानी है। आप इस पर संज्ञान लेकर 2012 के फैसले को, सीट बढ़ाकर उन बचे हुए जो योग्य छात्र हैं, टीचर हैं, उन्हें भी न्याय मिल सके। जय हिन्द, जय भारत माता।

श्री सभापति: श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने मुझे मांग संख्या 24 पर बोलने का मौका दिया। महोदय, राजस्थान की विधान सभा में हम राजस्थान के शिक्षा विभाग की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। महोदय, राजस्थान की पहचान हिन्दुस्तान में एक गरीब, पिछड़ा, अकालग्रस्त एवं सामंती सोच के प्रदेश के नाम से चर्चित है। अगर इससे हमें पीछा छुड़ाना है गरीबी से तो हमें एक अच्छी आधुनिक प्रगतिशील शिक्षा नीति अपनानी होगी। अच्छी शिक्षा से न सिर्फ छात्रों का ही भला होता है, बल्कि प्रदेश का, प्रदेश की जनता का भविष्य भी सुधरता है।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

शिक्षा के लिए, चाहे कालेज की शिक्षा हो, चाहे स्कूल की शिक्षा हो, कुछ चीजें अनिवार्य हैं। प्रथम छात्र, दूसरे अध्यापक और तीसरे शाला भवन। अब राजस्थान में आप देखिये, हायर सैकण्डरी स्कूल है। हायर सैकण्डरी को गांव की भाषा में बारहवीं तक के स्कूल बोलते हैं। मैंने किसी हायर सैकण्डरी स्कूल में 12 कमरे नहीं देखे।

अब आप देखिये अध्यापक, स्वीकृत संख्या बीस, उपस्थित पांच। इसमें छात्र कौन जाते हैं, जो गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं। अमीर लोग, वे तो अपने बच्चे-बच्चियों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। सिर्फ गरीब, और गरीब के साथ यह अन्याय हो रहा है। इन हालात में कैसे तो अच्छी शिक्षा हम प्रदान करेंगे, कैसे हमारे देश का भविष्य सुधरेगा, हमारे प्रदेश के बच्चों का भविष्य सुधरेगा। सरकार से मेरी मांग है कि कम से कम जो लड़कियों के स्कूल हैं, हायर सैकण्डरी स्कूल हैं, बच्ची जो हायर सैकण्डरी में पढ़ती है, बारहवीं क्लास में पढ़ती है, मैं मानता हूं 16-17 साल की हो जाती है। वह जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करती है। कम से कम लड़कियों के स्कूलों में तो फर्नीचर हो। वे सम्मानजनक तरीके से शिक्षा ग्रहण करें। पीने का शुद्ध पानी हो, उनको महिला शौचालय उपलब्ध हो ताकि ऐसा नहीं लगे कि शिक्षा एक बोझ है। बच्चे आकर्षित हों, वहां माहौल ऐसा हो।

मेरी कांस्टीट्यूएंसी में बच्चियों के पांच हायर सैकण्डरी स्कूल हैं। सब में आर्ट्स है। ये बच्ची जब बड़ी हो जाएगी, कालेज में जाएगी, साइंस है नहीं, कालेज सिर्फ दो ही हैं, एक देवली में, एक उनियारा में, 60-60, 70-70 किलोमीटर दूर, बच्चों को तो लोग भेज देते हैं, बच्चियों को जाने में दिक्कत आती है। मेरे क्षेत्र में, पूरे टोंक जिले में ट्रेन ही नहीं है। बसों की सेवा है, जो सरकारी बसों की सेवा न के बराबर है तो बच्चियां कैसे जाएंगी? साधनों के अभाव में, विषय के अभाव में हमारी बच्चियां बारहवीं के बाद घर पर ही रह जाती हैं, शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। मैं तो मानता हूं कि वह हमारे देश का, हमारे प्रदेश का एक बहुत बड़ा नुकसान है। सरकार से मेरी मांग है कि जितने मेरे हायर सैकण्डरी स्कूल्स हैं, बच्चियों के हायर सैकण्डरी स्कूल्स हैं, कम से कम उनमें आर्ट्स के साथ-साथ साइंस विषय भी हो ताकि हमारी बच्चियों को साइंस का अध्ययन करने की सुविधा मिले।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

इसी तरह जितने भी हमारे स्कूल हैं, उनमें पर्याप्त मात्रा में शिक्षा भवन हों, शिक्षा-कक्ष हों। अन्यथा आप देखिये बारहवीं तक स्कूल है और आठ कमरे हैं तो वह चार क्लासें कहां चलती होंगी? उससे हमारे बच्चे-बच्चियों का नुकसान होता है।

शिक्षक, जब शिक्षक है ही नहीं तो शिक्षा कौन प्रदान करेगा। शिक्षा ग्रहण कौन करेगा। हर कोई राजेन्द्र राठौड़ साहब जैसा नहीं है। ये तो आये डण्डा देकर, यूनिवर्सिटी में भी आये, प्रेसीडेंट भी बन गये, एम.एल.ए. भी बन गये। हर कोई इतना मजबूत नहीं है। हर कोई आदमी इतना मजबूत नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मेरी शिक्षा पर इन्होंने सवाल खड़ा किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, आप विराजिये। मैंने आपको इजाजत नहीं दी। विराजिये, प्लीज सहयोग करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इतना पढ़ा-लिखा इन्सान, सभापति महोदय। ये राजस्थान के लोग ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, विराजिये आप। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: आप विराजिये। मुझे पता है क्या अंकित करना है, नहीं करना है।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, मैंने पढ़ा-लिखा ही बताया था। पढ़े-लिखे, राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े प्रेसीडेंट रहे। इनसे लम्बा कोई प्रेसीडेंट नहीं हुआ कद्-काठी में।

श्री सभापति: आपकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। आपके पुराने दोस्त हैं।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): मेरा अनुरोध यह है कि पर्याप्त मात्रा में कक्ष हों, क्लास-रूम्स हों, पर्याप्त मात्रा में स्टाफ हो। पहले हमारे जमाने में सिर्फ साइंस की लैब्स होती थीं, लैबोरेट्री। आजकल आर्ट्स में भी ज्योग्राफी की लैब हो गयी है। किसी भी सरकारी स्कूल में ज्योग्राफी की लैब नहीं है। इसके अभाव में शिक्षा में फर्क पड़ता है, गुणवत्ता में फर्क पड़ता है।

मेरे क्षेत्र में बच्चियों के चार स्कूल हैं, जो दसवीं तक हैं। कम से कम बच्चियों के स्कूलों को, शिक्षा मंत्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, बच्चों के

(श्री हरीश चन्द्र मीना)
स्कूल आप छोड़ दें, पर जो बच्चियों के स्कूल हैं, दसवीं तक हैं, उनको क्रमोन्नत करके बारहवीं तक कर दें, आपकी बड़ी कृपा होगी।

इसी तरह से मेरे क्षेत्र में ज्यादातर लोग किसान हैं। वहां कोई उद्योग नहीं है, और कुछ नहीं है। जो हायर सैकण्डरी स्कूल बच्चों के हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को एग्रीकल्चर का शौक होता है। जिन स्कूलों में आर्ट्स है, उसमें कम से कम एग्रीकल्चर भी दे दें कि हमारे बच्चे एग्रीकल्चर विषय में रुचि रखते हैं।

स्कूल में पहले यह मानते थे कि शिक्षा बिना शारीरिक दक्षता के अपूर्ण है। अब आप देखिये जो स्कूल बनते हैं। कितने स्कूलों में तो खेल के मैदान हैं, और खेल मैदान हैं तो उसमें खेल की सुविधा किसमें है। यह बहुत अनिवार्य है। शिक्षा बिना शारीरिक शिक्षा के अधूरी रह जाती है। हमारे बच्चों का बौद्धिक विकास भी हो, शारीरिक विकास भी हो, ताकि हम लोगों को, सब लोग आगे चलकर राजेन्द्र राठौड़ साहब जैसे मजबूत आदमी बनें और हमारे देश को उन पर गर्व रहे।

अंत में, छोटी सी मेरी गुजारिश है कि पिछले पांच साल में भा.ज.पा. के कार्यकाल में एकीकरण के नाम पर जिन स्कूलों को बंद किया था, वह सबसे बड़ा अन्याय था। ये स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में बंद हुए, जहां गरीबों के बच्चे जाते थे। शहर वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। उनके अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो प्राइवेट में चले जाएंगे तो शिक्षा मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल हैं, उनको पुन: आप चालू कराएं ताकि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो।

सर, एक आखिरी डिमांड आपकी परमिशन से निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री महोदय, मेरे यहां पर बच्चियों की चार हायर सैकण्डरी स्कूल्स हैं। चार ही हैं मेरे पूरे क्षेत्र में। देवली में, दूनी में, अलीगढ़ में और उनियारा में, इनमें साइंस विषय करवा दें। लड़कियों की स्कूल है। आपकी बड़ी कृपा होगी, हमारी बच्चियों का भविष्य सुधरेगा।

इसी तरह चार स्कूल लड़कियों की जो दसवीं तक है, जिसको सैकण्डरी बोलते हैं। आवां में, नासिरदा में, नगर फोर्ट में और बनेठा में, कृपया इनको हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

सर, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री आलोक बेनीवाल।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने राजस्थान का अपमान किया है। हम गरीब हैं, डिप्रेशन में हैं, माननीय सभापति महोदय, यह हमारे राजस्थान का अपमान है।

श्री सभापति: आप विराजिए। माननीय सदस्य, आप विराजिए। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। आप विराजिए। कृपया शांत रहें। श्री आलोक बेनीवाल।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के विषय में आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं एवं साथ ही मां सरस्वती को भी नमन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बहुत लंबे समय से शिक्षा, कला एवं संस्कृति की मांग पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई वरिष्ठ माननीय सदस्यों सहित काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। हम तो पहली बार इस विधान सभा में उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर से शिक्षा पर आज जो बहस हो रही है, बहुत ही सार्थक बहस इसमें होनी चाहिए और एक अच्छा परिणाम इसमें निकले। हमारा जो प्रदेश है इसको शिक्षा के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ने का मौका मिले, ऐसे विचार हमारे सामने आएं और हम उन विचारों को समाहित करके हमारे प्रदेश में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को उसका लाभ मिले तब जाकर इस बहस को हम सार्थक मानेंगे।

शिक्षा अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने वाली वह शक्ति है जिसको हम भली-भांति जानते हैं। आज के शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारे कई विद्वान साथियों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं और हम ग्रामीण परिवेश से निकलकर आज इस विधान सभा में पहुंचे हैं। शिक्षा का आज जो ढांचा हमारा सरकारी क्षेत्र में है, उसमें निश्चित तौर से बहुत सी चीजों की आवश्यकता है जिससे कि वहां पर पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और एक सही दिशा में उनको ले जा सकें, वह अच्छे सांस्कारिक नागरिक बन सकें, देश

(श्री आलोक बेनीवाल)

और प्रदेश की प्रगति में उनकी भागीदारी हो, ऐसी शिक्षा की हमारे को आवश्यकता है।

निश्चित तौर से यह प्रदेश बनने के बाद में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे नवाचार हुए होंगे। स्कूलें खुलीं, शिक्षकों की भर्ती हुई, विद्यालयों का निर्माण हुआ, कमरों का निर्माण हुआ, प्रयोगशालाओं का निर्माण हुआ, पुस्तकालय का निर्माण हुआ, ऐसे अनेक काम लगातार जारी हैं लेकिन आज हमारे को यह सोचने की आवश्यकता है कि जो हमारी पूंजी है, जिनको इस देश का भविष्य कहा जाता है, छात्र और छात्राएं, उनको किस चीज की आवश्यकता 21वीं सदी में और आने वाले समय में पड़ेगी। निश्चित तौर से ग्रामीण परिवेश में चाहे वह प्राथमिक स्कूल हों, चाहे वह उच्च प्राथमिक स्कूल हों, चाहे माध्यमिक स्कूल हों या चाहे सीनियर सैकण्डरी स्कूल्स हों, सबसे पहले उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने की आवश्यकता है और साथ ही उनके वहां पर जो उपलब्ध साधन हैं, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे पेयजल की सुविधा हो, चाहे शौचालय निर्माण का काम हो, चाहे टीचर्स की नियुक्ति हो और जो भी मूलभूत उस विद्यालय की आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करे बगैर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना हमारे लिए सम्भव नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार लगातार नामांकन बढ़ाने के लिए नवाचार करती रहती है। अभी माननीय अशोकजी गहलोत साहब के नेतृत्व में सरकार बनी। आदरणीय गोविन्द सिंहजी डोटासरा साहब मंत्री बने, मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने एक तो बहुत अच्छा बजट शिक्षा के लिए रखा, उसके लिए उनको बधाई और माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी बधाई है। साथ ही, उन्होंने नामांकन बढ़ाने के लिए जो नवाचार किया, बाल सभाओं का आयोजन किया, प्रदेश स्तरीय बाल सभा का आयोजन मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में अमरसर में रखा गया, उसके लिए भी मैं इनको धन्यवाद करता हूं लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह देखा गया है जब भी नामांकन का समय आता है हमारे विद्यालयों के लिए तो हम दस दिन पहले उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस प्रक्रिया को एक महीने पहले शुरू करें और संबंधित विद्यालय के जो प्रिंसिपल

(श्री आलोक बेनीवाल)

हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उन सबकी आप यह व्यवस्था रखें कि एक महीने पहले ही उनका जो पूरा कार्य क्षेत्र है, उसमें घर-घर जाकर लोगों को उस विद्यालय के संबंध में पूरी जानकारी दें। उनसे आप जब तक पर्सनली नहीं मिलेंगे तो नामांकन बढ़ाना हमारे लिए सम्भव नहीं होगा।

साथ ही, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि जो उस विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने का भी काम करें। पूर्ववर्ती सरकार के माननीय मंत्री महोदय ने भी बताया कि हमने इतनी स्कूलें क्रमोन्नत कीं, इतनी हमने यह व्यवस्था की। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज जो कमी हमारे सरकारी स्कूलों में है, पहले उसकी पूर्ति करने का काम करें। माननीय मंत्री महोदय, चाहे उस विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे उसमें फर्नीचर की बात हो, चाहे वहां पर टीचर्स रखने की बात हो, आज यह देखा गया है कि हमारे जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें सब्जैक्ट टीचर्स की भी कमी आज की तारीख में है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मैं शनिवार और रविवार को मेरे इलाके में था। बहुत सारे, चार-पांच प्रिंसिपल्स को बुलाकर मैंने बात की थी। मैंने पूछा कि नामांकन की क्या स्थिति है? लेकिन, सब्जैक्ट नहीं होने के कारण कई बार जो छात्र-छात्राएं हैं वह हमारे सरकारी स्कूलों को छोड़कर प्राइवेट स्कूलों की तरफ चले जाते हैं, यह एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे मेरा क्षेत्र हो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में समाप्त करें।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): सर, एक मिनट बस। आपको हमारे को तो दो मिनट और देना पड़ेगा। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं हैं, उसमें हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है, उसमें सब्जैक्ट भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। छात्रछात्राओं को जो सब्जैक्ट चाहिए यदि आज वहां पर उपलब्ध नहीं है तो उसके कारण वह प्राइवेट स्कूलों की तरफ अपना रुख करते हैं, उसके अंदर भी हमारे को देखने की आवश्यकता है।

कई माननीय सदस्यों ने अभी निवेदन किया कि कम्प्यूटर शिक्षा हमारे कई माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चल रही है। मैं

(श्री आलोक बेनीवाल)

आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उन स्कूलों में परमानेंट कम्प्यूटर शिक्षक की अगर नियुक्ति करेंगे तब जाकर हमारा वह अभियान सफल हो पाएगा क्योंकि आज कम्प्यूटर शिक्षा हो या व्यावसायिक शिक्षा हो, उसके लिए हमारे को ट्रेंड टीचर्स वहां पर अगर उपलब्ध नहीं होंगे तो निश्चित तौर से उसका लाभ हमारे छात्र-छात्राओं को जो खास तौर से ग्रामीण परिवेश में पढ़ते हैं, उनको नहीं हो पाएगा।

मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि ग्रामीण परिवेश में ज्यादातर हमारी जो सरकारी स्कूलें हैं, उनमें छात्राएं ज्यादा पढ़ती हैं और छात्र कम पढ़ते हैं। इस बारे में भी आपको विचार करना पड़ेगा कि यह इतना भेद क्यों है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री जोराराम कुमावत।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): साथ ही, आपसे इतना निवेदन और करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो स्कूल बंद करे, उस बारे में भी आपको मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने बंद तो कर दिये लेकिन यह नहीं सोचा कि बंद करने का कारण क्या था?

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत। विराजिए।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): दो मिनट और चाहूंगा। मेरे क्षेत्र की जो मांग है मैं माननीय मंत्रीजी के सामने अपने लिखित प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत कर दूंगा। आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले तो मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में अध्यापकों की स्थिति आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 25 पद प्रधानाध्यापकों के रिक्त हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 12 पद प्रधानाध्यापकों के रिक्त हैं और राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 60 पद विषय अध्यापकों के रिक्त हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 प्रिंसिपल के पद रिक्त हैं और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 24 विषय अध्यापकों के पद रिक्त हैं।

(श्री जोराराम कुमावत)

निश्चित रूप से इतने पद खाली हैं तो शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी, अपने बच्चे कैसे पढ़ेंगे और उनकी क्या व्यवस्था होती होगी, यह भगवान भरोसे ही चल रहा है।

मैं मंत्रीजी को बताना चाहूंगा कि मेरे सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में बांगड़ी और बिठुडा को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खिन्दारा गांव का बिठिया, सुमेरपुर नंबर-एक, एंदलाबास, पिचावा, सांगवा, नवागुड़ा, धनापुरा बालिकाबुसी और खिंवादी को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता है। राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय नये स्वीकृत कराने की आवश्यकता है जिसमें रोजड़ा और खिंदारा गांव हैं। तीन-चार स्कूलों में नवीन कक्षा-कक्षों की आवश्यकता है- इंदिरा नगर, सांपा, भावनगर, सिंदरू में दो-दो कक्षा-कक्षों की आवश्यकता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अनोपुरा में चारदीवारी और शौचालय की आवश्यकता है। खिंवादी, खिमाड़ा और भावनगर में चारदीवारी की आवश्यकता है और कई स्कूलें ऐसी हैं जहां स्कूलों की छतें पुरानी हो गयीं, पानी टपकता है तो उनको रिपेयरिंग कराने की भी आवश्यकता है।

सभापति महोदय, पंचायत समिति सुमेरपुर में खेल स्टेडियम की आवश्यकता है। मेरा मंत्रीजी को आपके मार्फत निवेदन है कि यह सारे कार्य जल्दी से जल्दी करवाएं।

एक निवेदन और है विवेकानन्द माडल स्कूल, जो अभी संचालित है और वहां प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग तो बन रही है, लेकिन मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि उस माडल स्कूल में प्रवेश कब होगा? उसमें बच्चों का एडमिशन होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से उसको जल्दी चालू कराएं तो वहां बच्चों का भी फायदा होगा।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत उच्च शिक्षा मंत्री, माननीय भाटी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय है और उसमें तीन व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं- अंग्रेजी, इतिहास एवं संस्कृत और चार पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हैं, वह चारों के चारों रिक्त हैं। रिक्त पदों से व्यवस्था करवाने में थोड़ी बाधा आ रही है, थोड़ा जल्दी व्याख्याता लगाने की व्यवस्था कराएं।

(श्री जोराराम कुमावत)

सभापति महोदय, उच्च शिक्षा मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन है कि तखतगढ़ शहर में नगरपालिका क्षेत्र है, 25 हजार उसकी आबादी है और वहां पर एक भामाशाह ने कालेज खोलने के लिए कालेज की बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा देने को कहा है। यदि सरकार तखतगढ़ में कालेज की स्वीकृति दे दे, भवन वहां पर भामाशाह बनाने को तैयार है। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करूंगा कि वहां पर कालेज खुलवाने की व्यवस्था कराएं।

सभापति महोदय, वैसे जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है। शिक्षा जीवन का आधार है। शिक्षा मनुष्य की नींव है। शिक्षित मनुष्य ही चांद, सितारों, आकाश और समुद्र की गहराइयों तक पहुंचा है। वहां से कई तरह के शोध करके उन्होंने देश हित में आगे उपयोग में लिया है। देश की आजादी के बाद प्रदेश में शिक्षा की अत्यन्त खराब स्थिति थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और महात्मा गांधीजी के आदर्शों को मानते हुए कई सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम किये और समाज की अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक शिक्षा को पहुंचाने का काम किया।

सन् 1970 के आस-पास की बात है, जब मैं अपने गांव सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र के सिन्दरू गांव में पढ़ता था, तब वहां की स्थिति ऐसी थी कि बच्चों को जबरदस्ती स्कूल में भर्ती कराना पड़ता था। उस समय कांग्रेस का राज था। शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रचार-प्रसार के लिए गांव में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाये जा रहे थे। गांव के बिना पढ़े-लिखे बुजुर्ग, किसान, मजदूर दिन में अपनी खेती, मजदूरी करते थे। शाम को प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर उन्हें अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जाता था। दस-दस वर्षों तक प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाकर सरकार ने बजट खर्च किया, मेहनत की, लेकिन उन केन्द्रों पर पढ़ने वाले... (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): सभापति महोदय, अभी तो दो मिनट ही हुई है।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): उन लोगों ने एक से सौ तक की गिनती भी पूरी नहीं सीखी। हस्ताक्षर करना जरूर सीख गये। उस समय की सरकार की गलत नीतियों के कारण देश का धन और समय व्यर्थ गया। उस

(श्री जोराराम कुमावत)

समय की सरकार ने अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी होती और नई पीढ़ी को पढ़ाने का कार्य किया होता तो आज राजस्थान देश के शिक्षित राज्यों में अग्रणी रहता। आज शिक्षा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंच गयी है। देर आये, दुरुस्त आये। एक वह जमाना था, जब सरकार पढ़ाना चाहती थी, पढ़ने वाले नहीं थे। आज लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले नहीं हैं। स्कूल हैं, लेकिन अध्यापक नहीं हैं। विषय के अध्यापक नहीं हैं। कई स्कूलों में अध्यापकों की कमी है जिससे लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा रूचि ले रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिये। श्री मुकेश कुमार भाकर।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने शिक्षा, कला व संस्कृति की मांग पर मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया। आदरणीय सभापति महोदय, जब बात शिक्षा के क्षेत्र की हो, हम लोगों की कर्मस्थली या इस सदन में पहुंचने का रास्ता छात्र और युवा राजनीति रहा। आदरणीय सभापति महोदय, इस सदन में जब बात शिक्षा की हो और राजस्थान विश्वविद्यालय या छात्र राजनीति का नाम न आये तो मैं समझूंगा कि जो संघर्ष और जिन साथियों ने आज साथ देकर इस सदन में हम लोगों को पहुंचाया, उनके साथ अन्याय करने जैसा होगा।

आदरणीय सभापति महोदय, अभी हरीश चन्द्र जी मीना बोल रहे थे, आदरणीय राठौड़ साहब सदन में थे। चूंकि राजस्थान विश्वविद्यालय के वह अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा महेन्द्र चौधरी जी, महेश जोशी जी, आदरणीय अशोक लाहोटी जी और रामनिवास गावड़िया जी आदि अनेक नेता, राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति करके यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन आज सदन के माध्यम से मैं ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा उन सभी नेताओं का, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में अपनी पढ़ाई, अपनी प्रसिद्धि और अपने नाम के लिये जाना जाता था। सभापति महोदय, 2012-13 में जब विश्वविद्यालयों की रैंकिंग घोषित नहीं होती थी, उस समय डबल ए प्लस दर्जे पर राजस्थान विश्वविद्यालय था लेकिन, जब 2017 में रैंकिंग घोषित हुई तो 67वें पायदान पर राजस्थान विश्वविद्यालय था। मुझे बड़े अफसोस और दु:ख

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

के साथ सदन में कहना पड़ रहा है कि 2018 में जब रैंकिंग विश्वविद्यालयों की घोषित हुई तो आज वह 200वें नंबर से भी बाहर है। देश के 200 विश्वविद्यालय हैं, उनके अंदर भी राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम नहीं है।

सभापति महोदय, पिछले पांच सालों में, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे जितनी भी राजस्थान की अन्य यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें अनेक पदों पर जितनी भर्तियां हुईं, मुझे कहते हुए अफसोस है कि राजस्थान से ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा के लोगों को विश्वविद्यालय में भर्ती किया गया। मैं सदन से मांग करता हूं कि किन शर्तों पर, किन मापदण्डों पर उन लोगों को लिया गया, उसकी जांच और राजस्थान के जो बेरोजगार लोग हैं उनको न्याय दिलाने का काम आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री जी करें।

आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, आपने मंत्री बनने के बाद अच्छा कार्य किया है और आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में 32 महाविद्यालयों की घोषणा की है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि पूरी यूनिवर्सिटी में 80 लोग ऐसे हैं जो परीक्षा नियंत्रक, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट पर हैं, जिनको यू.जी.सी. मापदण्ड का वेतनमान नहीं मिलता। मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अंत में आज जब आप अपना भाषण पढ़ें तो उनके लिए एक कमेटी बनाकर उनको न्याय दिलाने का काम करें, मैं यह मांग इस सदन से करता हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री आदरणीय डोटासरा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि साइकिल और योग दिवस की बात सब लोगों ने की, शिक्षा मंत्री बनते ही पहली बार जो शिक्षकों के लम्बित मामले थे उन हजारों लम्बित मामलों का, शिकायतों का निस्तारण आपने किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हर जिला मुख्यालय पर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की घोषणा की। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो समाज उपयोगी योजना कक्षा 9 से 12 की कक्षाओं में पूर्व सरकार ने लागू की थी, उसका समायोजन कर राजस्थान का समग्र इतिहास, कला व संस्कृति, भूगोल, बाल

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

विकास और पर्यावरण जैसे संवेदनशील विषयों को उस पुस्तक में आप जोड़ें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, पूर्व में राजस्थान में भा.ज.पा. की सरकार रही, जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसे देश भक्तों को हटाकर इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय और अन्य को पाठ्यक्रमों में जोड़ने का प्रयास किया। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मंत्री जी, आपने शिक्षा मंत्री बनते ही इनकी तरह कोई भी भेदभाव का काम नहीं करके, मैं भा.ज.पा. के साथियों को कहना चाहता हूं कि आज जो नये अध्याय जोड़े गये, पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है उनमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो भा.ज.पा. से आपके सांसद हैं उनका नाम हमने दिया है, मेजर डाक्टर सुरेन्द्र पूनिया, जो आप पार्टी से सीकर से चुनाव लड़े, उनका नाम आपने इस पाठ्यक्रम में दिया है। इसके अलावा, सभापति महोदय, चूंकि महाराणा प्रताप और अकबर के बारे में यहां कई बातें हुईं मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पूर्व शिक्षा मंत्री देवनानी जी ने यह बयान दिया कि अब हम लोग पढ़ाएंगे कि अकबर नहीं प्रताप महान।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): लेकिन 9 से 12 की किसी भी कक्षा में, राठौड़ साहब, मैं आपको खुला चेलेंज देता हूं कि किसी भी पाठ्यक्रम में 9 से 12 कक्षा की किसी भी किताब में अगर महाराणा प्रताप के आगे महान लिखा हो उन्होंने तो आप लोग मुझे लाकर दें।

मैं इस सदन के माध्यम से आपका इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वीर सावरकर को लेकर जो बातें यहां हो रही हैं कि हमने उनको पाठ्यक्रम से हटाया। लेकिन सिर्फ जो अध्याय बच गये थे, सिर्फ एक तरफ की बात उस किताब में लिखी गयी। जो माफीनामा उन्होंने अंग्रेजों को दिया, सभापति महोदय, यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उसको आपने जोड़ा है न कि वीर सावरकर के अध्याय को उस पाठ्यक्रम से हटाया है।

श्री सभापति: समाप्त करें। समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्री लाखन सिंह।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): मैं आपका इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अब जब नया पाठ्यक्रम बने तो खेजड़ी के लिए जो 363 लोग शहीद हुए उनको उस पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। जो मानगढ़ का हत्याकांड था जिसमें 1500 आदिवासियों ने शराबबंदी और शिक्षा के लिए अपनी जान दे दी, उनको उस पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए।

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): जो कूदन और डीडवाणा का किसान आन्दोलन था, किसानों की संघर्ष की गाथा उस पाठ्यक्रम में लिखी जाए। इस बात की अपील मैं शिक्षा मंत्री जी से करूंगा।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण मांग पर मुझे शामिल किया। जय हिन्द। जय भारत।

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय सभापति महोदय, आज मुझे मांग संख्या 24 - शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने का अवसर आपने दिया है उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं करौली विधान सभा क्षेत्र से आता हूं जहां पर डांग क्षेत्र है। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत करौली जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 238, माध्यमिक शिक्षा विद्यालय 65 एवं 4 राजकीय माडल स्कूल हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग द्वारा करौली मुख्यालय पर एक अंग्रेजी माध्यम का माध्यमिक गांधी राजकीय विद्यालय भी खोला गया है जिसके प्रथम चरण में एक से आठ संचालित है।

सभापति महोदय, जिले में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय पद खाली है। इसके अतिरिक्त प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापकों के कुल स्वीकृत 309 पदों में से 33 पद विभिन्न विद्यालयों में रिक्त हैं। व्याख्याता स्कूल शिक्षा के 142, वरिष्ठ अध्यापकों के 213, पी.टी.आई. के 24, अध्यापकों के 171 तथा कनिष्ठ सहायकों के 181 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 339 पद रिक्त हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे जो रिक्त पद हैं इनको जल्दी भरने की कृपा करें।

(श्री लाखन सिंह)

माननीय सभापति महोदय, करौली अत्यन्त पिछड़ा जिला है एवं अरावली का डांग क्षेत्र, चम्बल के बीहड़ एवं अधिकांश क्षेत्र डांग क्षेत्र होने के कारण अनेक राजकीय विद्यालय दुर्गम स्थानों पर स्थित हैं जहां पर इनमें पर्याप्त विद्यालय भवन नहीं हैं, कक्ष अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण व जर्जर हैं। इन विद्यालयों में स्टाफ की कमी, बिजली की अपर्याप्तता, पेयजल की कमी एवं आधारभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, पुस्तकालय आदि की इन विद्यालयों में बहुत कमी है इसलिए, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसमें हमारे क्षेत्र में अतिरिक्त बजट देने की कृपा करें।

हाल ही में खोले गये महाविद्यालय, राजकीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय को नवीन भवन की आवश्यकता है, इसके लिए पृथक से बजट आबंटन कर विद्यालय भवन निर्माण करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त खेल प्रतिभाओं को निखारने हेतु विद्यालयों में स्थित खेल मैदानों के विकास हेतु निवेदन है। विज्ञान संकाय वाले विद्यालयों में प्रयोगशालाओं को सुसज्जित एवं सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है।

इसी प्रकार व्यावसायिक से वंचित विद्यालयों में भी वाणिज्य के विषय प्रारम्भ किये जाएं ताकि स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सके।

महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा में कक्षा एक से आठ तक जिले में 1045 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं जिनमें लेवल फर्स्ट अध्यापक, लेवल टू अध्यापक एवं प्रधानाध्यापकों के कुल 4375 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 3472 अध्यापक पदस्थापित हैं तथा 871 अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि इन पदों को भरने की कृपा करें।

करौली जिला डांग क्षेत्र में आता है जो कि शिक्षा की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। इसमें अध्ययनरत छात्रछात्राओं को विद्यालयों में पर्याप्त भवन व आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं अतः ऐसे भवन विहीन विद्यालयों हेतु अतिरिक्त बजट आबंटित किया जाए।

मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से सदन के माध्यम से आग्रह करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र करौली के अन्तर्गत संचालित राजकीय माध्यमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की संख्या अधिक है, इन्हें आगे अध्ययन करने हेतु आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना

(श्री लाखन सिंह)

पड़ता है इस कारण लड़कियां शिक्षा छोड़ देती हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटवास, सिंघान, कोटरा ढहर, गुर्जर गांवडा, भंवाड़ी, खुर्सटपुरा, कुतकपुर, लीलोटी, रीठोली, भऊआपुरा, डूंडापुरा के विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए एवं ग्राम हरिपुरा, देदरोली, मुंडापुरा के प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इन स्थानीय विद्यालयों में भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। छात्र, छात्राओं के कक्षा भवन भी उपलब्ध हैं। प्राथमिक शिक्षा अंतर्गत पोषाहार कार्यक्रम में रसोई गैस कनेक्शन, शौचालय, मैदान आदि विकास करने हेतु बजट की आवश्यकता है।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री लाखन सिंह (करौली): प्रारंभिक शिक्षा से ही राष्ट्र निर्माण की पहली सीढ़ी प्रारम्भ होती है जिसमें पूर्ण बौद्धिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास होता है। मासलपुर में राजकीय महाविद्यालय तथा जिला हैडक्वार्टर पर एग्रीकल्चर कालेज खोला जाए। राजकीय महाविद्यालय करौली डांग, आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्र का एकमात्र सबसे पुराना कालेज है।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। समाप्त करें। श्री कालूराम।

श्री लाखन सिंह (करौली): वर्तमान स्थिति में छात्र संख्या का दबाव भी है।

श्री सभापति: श्री कालूराम।

श्री लाखन सिंह (करौली): महाविद्यालय में इस कारण स्नातक स्तर पर उर्दू, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, हिन्दी, प्राणी शास्त्र आदि विषय खोलने की कृपा करें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। जय भीम।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

श्री कालूराम (अनुपस्थित)। श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): सभापति महोदय, मैं बोल रहा हूं।

श्री सभापति: बोलिए, आप बोलिए।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना जिला झालावाड़ के शिक्षा के क्षेत्र में अति पिछड़ेपन को देखते हुए पिछली सरकार द्वारा महाविद्यालय खोला गया था। उसके अंतर्गत पिछली सरकार ने जमीन भी आबंटित कर दी थी और भवन निर्माण का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया था। आदरणीय वसुन्धरा जी द्वारा जो यह महाविद्यालय खोला गया उसके तहत सैकण्डरी के 3-4 कमरों में यह महाविद्यालय संचालित है। सभी पद भरे हुए थे लेकिन अभी सभी पद रिक्त कर दिये गये हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि शीघ्र ही इन पदों को भरने की कृपा करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र के समस्त विद्यालयों में गत सत्र 2018-19 में श्रम कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों की जो योजना है, उनका लाभ पात्र छात्र-छात्राओं को नहीं मिल पा रहा है। उनसे आनलाइन आवेदन पत्र भरवाये जाते हैं, लेकिन गत सत्र की छात्रवृत्ति बच्चों के खातों में जमा नहीं हुई है। शाला दर्पण पोर्टल पर बार-बार नेट की समस्या आने से टीसी जारी नहीं हो पाती है। इससे छात्र, छात्राओं को अनावश्यक दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। इससे समय बर्बाद होता है। इनके समाधान की कार्यवाही की जाए।

(श्री गोविन्द प्रसाद)

(18.52 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मनोहरथाना बिलकुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। सबसे लास्ट 200 नंबर पर है। यह एमपी बार्डर से सटा हुआ क्षेत्र है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालय बुधवाड़ा को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए। 18 यूपीएस विद्यालय ऐसे हैं जिनको क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है। मैं आपके समक्ष इनके नाम पढ़ रहा हूं पाटलिया लोढ़ान, कंवरिया खेड़ी, गुराड़ी, धड़ावली, रानीपुरा, खेंजड़ा, ढाबली, पाडलिया, भोजपुर, हनोतिया लोढ़ान, झिकनी, रींछड़ी, देवरी मंदिर, पाटड़ी खेड़ा, बालिका बालता और गरड़ा। ये ऐसे विद्यालय हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए हैं। इनमें शिक्षा की बहुत आवश्यकता है।

सभापति महोदय, प्राथमिक विद्यालय भीलखेड़ा, रोजा, छुवाडिया, घोड़ाखेड़ा, सागोड़िया, चारखेड़ा, और डूंगर गांव, ये भी विद्यालय पहाड़ी क्षेत्र में हैं। आपसे निवेदन है कि यूपीएस को माध्यमिक और पीएस को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की कृपा करें।

माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, मुझे आज यह कहने की आवश्यकता है कि जो भी योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में चल रही हैं, उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। जिन माध्यमिक विद्यालयों और सैकण्डरी स्कूलों में कमरों की कमी है, फर्नीचर की कमी है, हमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कमरों और फर्नीचर की बहुत आवश्यकता होती है ताकि हमारे छात्र, छात्राओं को उनका उचित लाभ मिल सके। कई जगह शौचालयों की कमी है। आप शौचालय भी बनवाने की कृपा करें। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन सभी योजनाओं के तहत आने वाली जितनी भी योजनाएं हैं, उनका सही तरीके से क्रियान्वयन कर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। जय हिन्द। जय भारत। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री गजराज खटाणा।

श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): सभापति महोदय, आज शिक्षा, कला और संस्कृति पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

(श्री गजराज खटाणा)

सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके की आवश्यकता है, जिस तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं नैतिक शिक्षा की कमी जरूर महसूस हो रही है। हमें बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बलात्कार, हिंसक घटनाएं, मोटर साइकिलों की दुर्घटनाएं, तेज कार चलाने की दुर्घटनाएं और बहुत सारी ऐसी नेगेटिव बातें हैं जो हमें इस दौर में देखने को मिल रही हैं। कहीं न कहीं हमारी शिक्षा में कोई कमी जरूर है जिसमें कि उनका मानसिक विकास जिस तरह का होना चाहिए और जो उन्हें नैतिकता का पाठ सीखना चाहिए, ताकि वह कोई ऐसी घटना, दुर्घटना न करें, इसके लिए हमें खास तौर से हमारे सिलेबस में नये पाठ जोड़ने चाहिए।

सभापति महोदय, मैं गांव की बात करूंगा। शिक्षा जगत में जहां से मैं आता हूं बांदीकुई दौसा जिले से, वहां के गांवों में परिस्थितियां इस तरह की हैं कि वहां सारी सरकारी स्कूलों में 80 परसेंट बालिकाएं हैं और 20 परसेंट बच्चे हैं। यह व्यवस्था क्यों हो गयी, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह रहा कि आज के सभी माता-पिता अपने बच्चों को, खास तौर से लड़कों को, चाहे उन्हें 20 किलोमीटर दूर जाना पड़े बस से, लेकिन वह कस्बों के प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। 80 परसेंट बालिकाएं सरकारी स्कूलों में पढ़ रही हैं। सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्री महोदय से खास तौर पर कहना चाहूंगा आप एक डिसीजन लें, जिस तरह से बीजेपी सरकार ने किया, उन्होंने अच्छा काम किया तो मैं उनकी बड़ाई भी जरूर करूंगा, उन्होंने यह डिसीजन लिया कि हरेक पंचायत पर हम बारहवीं तक का विद्यालय स्थापित करेंगे। यह एक अच्छा डिसीजन था।

(19.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं आप पूरी स्टडी करा लें। आप देखेंगे बालिकाओं की शिक्षा के लिए अगर सारे आठवीं के स्कूलों को दसवीं तक कर देंगे तो मैं समझता हूं कि आपका नामांकन पूरे प्रदेश में दस, पन्द्रह, बीस लाख तक बढ़ जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे एरिया में खास तौर से बच्चियों की शिक्षा की ऐसी स्थिति बन गयी है कि बच्चियां आठवीं तक की स्कूल में पढ़ती हैं और आठवीं से आगे जब उनको चार-पांच किलोमीटर पर बारहवीं के लिए जाना पड़ता है तो उनमें से पचास-साठ परसेंट बच्चियां ड्रोप हो जाती हैं। इसकी आप चाहें तो किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवा लीजिए। मैं मांग

(श्री गजराज खटाणा)

करता हूं कि आठवीं तक की जितनी भी बालिका स्कूलें हैं उनको आप दसवीं तक करवा दें। खास तौर से जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, उन पर तो विचार कीजिए और इनको आठवीं से दसवीं और बारहवीं करवा दें तो मैं समझता हूं कि यह प्रदेश के लिए बहुत अच्छा डिसीजन आपका होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पूरे एरिया में बहुत सारी पंचायत समितियों में एक बात अभी आयी थी कि आपने प्रत्येक जिले में इंग्लिश मीडियम का बारहवीं तक का एक स्कूल खोला है। मेरे किसी पूर्व वक्ता सदस्य ने कहा था कि इसे आप पंचायत समिति लेवल पर करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह प्रदेश के लिए बहुत अच्छी शुरूआत होगी, सौगात होगी। इस पर भी आप विचार करें और आने वाले समय में आप इसको पंचायत समिति लेवल पर लेकर जाएंगे तो बहुत अच्छी शुरूआत होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि जिन स्कूलों में मिड-डे मील की व्यवस्था है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि यह व्यवस्था एक तरह से बहुत ही लचस्पचर तरीके से चल रही है। वहां मालूम करें तो मिड-डे मील को जो पकाने वाले हैं उनको आप तेरह सौ रुपये प्रति माह दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसे कोई सुनेगा तो अचम्भित होगा कि उनको कितना कम पैसा, तेरह सौ रुपये में क्या होता है। एक आदमी जो वहां मिड-डे मील का पूरा काम देख रहा है, पकाकर बच्चों को खिला रहा है, उसको हम मात्र तेरह सौ रुपये भत्ता दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, यह कितनी कम है। अगर आप मिनिमम वेज के हिसाब से भी देखेंगे तो हमें निश्चित रूप से इसको बढ़ाना चाहिए, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में कई स्कूलें हैं, रूपवास है, खेड़ी है, बूढ़ाकटला है, खूटला है, इनको दसवीं से बारहवीं तक कराएं, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। साथ ही एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, वहां पर जो थर्ड ग्रेड, सैकंड ग्रेड, टीचर्स लगे हुए हैं उनके ट्रांसफर की कोई पॉलिसी नहीं है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो मास्टर स्कूलों में लगे हुए हैं वह दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस साल से एक जगह जमे हुए हैं। हमारे एरिया में तो खास तौर से टीचर्स ने अपना एक अलग तरह से काम बना लिया है, ब्याज पर पैसा देते हैं और राजनीति करते हैं इसलिए

(श्री गजराज खटाणा)

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक पालिसी के तहत किसी भी टीचर को पांच साल से ज्यादा किसी विद्यालय में न रखें, अन्यथा वे वहां गुट बना लेते हैं, हर तरह की राजनीति करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक टीचर को चाहे आप उसको उसी जिले में रखें लेकिन पांच साल से अधिक किसी एक विद्यालय में न रखें। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री लक्ष्मण मीणा।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर मुझे विचार रखने का अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं बस्सी विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। बस्सी विधान सभा क्षेत्र में बालिका शिक्षा बारहवीं कक्षा तक है, वह काफी अच्छी स्थिति में है लेकिन उच्च शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो छात्राएं कालेज में आकर शिक्षा ग्रहण करना चाहती थीं तो वह दो कारणों की वजह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थीं। पहला आर्थिक कारण, पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह जयपुर में महंगे कमरे लेकर नहीं रख सकते थे और दूसरा कारण था कि अपनी जवान बेटी को कोई भी यहां अकेले रखना पसंद नहीं करते थे। परिणामस्वरूप बहुत ब्रिलिएंट लड़कियां जो शिक्षा प्राप्त करना चाहती थीं, शिक्षा से महरूम रहती थीं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे वहां राजकीय महाविद्यालय खोलने की पिछले तीस साल से मांग हो रही थी, कई सरकारें आयीं, गयीं लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत साहब का मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्त जनता तथा मेरी तरफ से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी भावनाओं की कद्र करते हुए वहां राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं और हमारी मांग है कि यह महाविद्यालय इसी सत्र से प्रारम्भ किया जाए ताकि हमारे वहां की जो बच्चियां, बच्चे जो जयपुर नहीं आ पाते हैं जयपुर में शिक्षा ग्रहण करने के लिए और आस पास कोई कालेज नहीं है तो वह इस साल एडमिशन लेकर अपनी हायर एजुकेशन की तरफ अग्रसर हो सकें।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

मानानीय सभापति महोदय, यह सबको विदित है कि दो प्रोफेशन, डाक्टर और अध्यापक का, इतने नोबल प्रोफेशन हैं, इतना अच्छा है कि यदि वह ईमानदारी से और समर्पण भाव से काम करें तो उनको भगवान की तरह से पूजा जाता है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा विभाग है और कहते तो यही हैं दोनों ही तरफ से कि शिक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए लेकिन बहुत दुख की बात है कि जो राजनीति होती है वह शिक्षा पर भी होती है और शिक्षक भी राजनीति करते हैं। माननीय सभापति महोदय, इसका कारण स्पष्ट है कि इसकी ट्रांसफर की कोई स्पष्ट पालिसी नहीं है। जो भी सरकार आती है, वह अपने हिसाब से, जाति के आधार पर, यह एससी का है, यह एसटी का है, यह माइनोरिटी का है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत दूरदराज तक अध्यापकों के ट्रांसफर किये जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, पिछले पांच साल में, पिछली सरकार के समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र के जो स्थानीय टीचर थे जो समर्पित भाव से शिक्षा दे रहे थे, रोज सही समय से स्कूल आते थे, उनको उठा-उठाकर यहां से पांच सौ किलोमीटर, सात सौ किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। यह भी नहीं देखा गया कि कोई विडो है, कोई महिला है, कई सारी घरेलू प्रोब्लम्स होती हैं, लेकिन उनको ध्यान में नहीं रखते हुए उन लोगों को मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगाया गया जो जयपुर शहर में एडजस्ट नहीं हो सकते थे तो उनको बस्सी विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों में लगाया गया। वे लोग कभी भी समय पर नहीं आते हैं। माननीय सभापति महोदय, अगर कोई टीचर या प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल समय पर नहीं आएगा तो जो दूसरा स्टाफ है उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है और वह वहां की लोकल राजनीति में, वहां के पालिटिशियंस से सांठ-गांठ करके वह वहीं रहना चाहते हैं। इससे शिक्षा के स्टैंडर्ड में गिरावट आती है। हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, सस्ती हो, सबकी पहुंच में हो तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे नागरिक का निर्माण कर सकते हैं, कुल मिलाकर अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, अभी तो बात

(श्री लक्ष्मण मीणा)

की जा रही थी कि प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे दो पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं, हिम्मतपुरा और भूड़ला, जहां अभी भी माध्यमिक विद्यालय हैं, वहां उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अभी भी तीन स्कूल ऐसी हैं, एक बिलकुल पास में कानोता जो जयपुर से लगा हुआ है, वहां भी अभी प्राइमरी स्कूल बिना भवन के चल रहा है। इसी तरह बड़वा में एक स्कूल बिना भवन के चल रहा है, हंसमहल में एक स्कूल बिना भवन के चल रहा है पेड़ के नीचे। कभी-कभी जब बरसात आ जाती है तो किसी घर में जाकर स्कूल चलायी जाती है। इस तरीके की शिक्षा दी जाएगी तो उसका कोई सैंस नहीं है। यह सिस्टेमैटिक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अनपढ़ रखने का, उन्हें शिक्षा में पीछे रखने का एक सोचा-समझा षड्यंत्र है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं, 151 स्कूल ऐसे हैं जिनमें आज तक बिजली नहीं आयी है, 54 स्कूल ऐसे हैं जिनमें बच्चे अपना पानी घर से लेकर आते हैं बोतल में और पानी पीने की कोई व्यवस्था आस पास में नहीं है। आधे जो माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें 50 परसेंट विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं हैं। टीचर्स पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। कब वे आते हैं, कब जाते हैं, इसका कोई हिसाब-किताब रखने वाला है ही नहीं। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

यहां तक कि मेरे बस्सी में जो सीबीओ इनका हैड होता है, वह इसकी व्यवस्था देखता है, प्रशासनिक नियंत्रण रखता है, उसका खुद का भी कार्यालय नहीं है। वह भी किसी दूसरे के कमरे में बैठकर चलाता है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जितनी भी ये कमियां हैं, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर है, पहली बात तो खेलों के मैदान हैं ही नहीं, अगर हैं भी तो उन पर अतिक्रमण है। कई बच्चे अपना भविष्य खेलों में भी देखना चाहते हैं, अच्छे खिलाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों से पैदा हो सकते हैं, लेकिन वहां कोई व्यवस्था नहीं है। खेल के मैदान के अलावा कोई साधन नहीं हैं। वहां कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्डिंग टूटी हुई है बरसात के

(श्री लक्ष्मण मीणा)

समय में तो प्रशासन यह चैक करवाता है कि कोई ऐसी स्कूल तो नहीं है जो टूटने की स्थिति में हो। कहीं बच्चों के साथ कैजुअल्टी नहीं हो जाए, अत: नये भवन बनाये जाएं। अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र में रमसा के तहत 85 कक्षा कक्ष और पुस्तकालय स्वीकृत किये गये। अत: माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी टेंडर प्रक्रिया प्रारम्भ कर उनका निर्माण शुरू कराया जाए।

माननीय सभापति महोदय, कई स्कूलें ऐसी हैं, पहले माननीय सदस्यों ने भी बताया कि उनमें कई विषय ही नहीं हैं। कई जगहों पर साइंस नहीं है, भूगोल नहीं है, इकोनोमिक्स नहीं है, इसका इंतजाम किया जाए। कुछ ही स्कूलें ऐसी हैं जो बच्चियों की हैं, उन्हें तो निश्चित रूप से माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जाए ताकि हमारी बच्चियां शिक्षा प्राप्त कर सकें। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री संदीप कुमार।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी का तिजारा क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से हृदय से धन्यवाद करता हूं कि हमारे भिवाड़ी में लंबे समय से चली आ रही कालेज की मांग को उन्होंने पूरा किया।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र तिजारा में भिवाड़ी, खुशखेड़ा, चौपानकी में करीब पांच हजार छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं। इसके साथ ही अनेकों बिल्डरों द्वारा करीब पचास हजार रिहायशी फ्लैट वहां बना दिये गये हैं। वहां पर देश के विभिन्न प्रदेशों के करीब तीन लाख लोग निवास करते हैं। इन सबके कारण वहां के जो किसान हैं, उनकी जमीनें या तो अवाप्त कर ली गयी हैं या फिर बिल्डरों द्वारा खरीद ली गयी हैं। वहां के लोगों का जो मुख्य रोजगार था कृषि, वह धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है और लोग बेरोजगारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो मांग बहुत समय पहले पूरी हो जानी चाहिए थी, वह बहुत लंबे समय के बाद पूरी

(श्री संदीप कुमार)

हुई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि महाविद्यालय में कला संकाय के साथ-साथ वाणिज्य और विज्ञान संकाय भी खोले जाएं और इसके अलावा भिवाड़ी में इंजीनियरिंग कालेज की एक बड़ी मांग है। इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, वहां के युवाओं के रोजगार के लिए एक इंजीनियरिंग कालेज खोला जाए ताकि स्थानीय युवा पढ़ सकें और रोजगार प्राप्त कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा भिवाड़ी में सीनियर सैकंडरी स्कूल है, वहां की जो प्रिंसिपल महोदया हैं, वे लगातार छुट्टी पर रहती हैं, लैक्चरर वहां पर नहीं हैं, इन सभी कारणों से भिवाड़ी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। माननीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तिजारा में एक तरफ मेवात का क्षेत्र लगता है तो दूसरी तरफ औद्योगिक इकाइयों के कारण दोनों तरफ ही अपराधों का बहुत बोलबाला है। बेरोजगारी के कारण जो हमारे स्थानीय युवा हैं, वे अभी अपराधों में लिप्त होने लगे हैं।

भिवाड़ी में अपराधों का लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि हमारे तिजारा में महाविद्यायल है, उसमें भी 23 में से 14 पोस्ट खाली हैं। टीचिंग और नोन-टीचिंग जो स्टाफ है, उसमें कुल नौ पोस्ट भरी हुई हैं। हमारे वहां पर तेरह सीटें अभी भी खाली हैं। माननीय महोदय, अलवर में 2012 में मत्स्य महाविद्यालय खोला गया, जिसमें एडमिशन 2015 से शुरू हुए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं लगातार शिकायतें आती रहती हैं, आये दिन छात्रों को धरनों पर बैठना पड़ता है। विश्वविद्यालय शुरू से ही विवादों के घेरे में है।

महोदय, चूंकि मैं छात्रसंघ का अध्यक्ष रहा हूं और छात्रों से लगातार मेरा जुड़ाव रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि मत्स्य विश्वविद्यालय का ढर्रा सुधारें। वहां हालात ये हैं कि कभी पेपर लीक की घटना हो जाती है, तो कभी फर्जी भर्ती की सूचना मिलती है। इसके अलावा लगातार दो सत्रों से स्थिति ऐसी है कि 2018 में भी रिजल्ट बहुत देरी से आया और 2019 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। वहां पर हालात ये हैं कि यदि छात्रों को अच्छे संस्थान में प्रवेश लेना हो तो रिजल्ट में देरी के कारण अच्छे संस्थानों में प्रवेश नहीं मिल पाता है।

बड़ी विडम्बना की बात है कि विश्वविद्यालय खुल गया, रिजल्ट नहीं

(श्री संदीप कुमार)

आ रहा है, रिजल्ट अच्छा होने पर भी उन्हें अच्छे कालेजों में एडमिशन नहीं मिल पाता है। मैं निवेदन करता हूं कि मत्स्य विश्वविद्यालय में चल रही इन सभी खामियों की तरफ ध्यान देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी कुछ कार्यवाही करेंगे और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री गोपी चन्द मीणा।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, मांग संख्या-24 शिक्षा एवं कला संस्कृति पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मीणा जनजाति और मीणा आदिवासी जाति का इस प्रदेश में सैकड़ों वर्ष शासन रहा है। इतिहास के मुताबिक बहुत से शासक रहे हैं जिनमें कुछ नाम इस प्रकार हैं- राजा श्री आलनसी (खोहगंग, जयपुर), श्री हमीर टाटू (रणथम्भौर, सवाई माधोपुर), श्री विराट मत्स्य (विराट नगर, अलवर), श्री बूंदा मीना ऊसारा (ऊशण व लावा), श्री ऊमाऊराव (छापोला, झुंझुनूं), श्री जैता मीणा (बूंदी), श्री भूपाल सिंह (नादोल)।

स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले भील मीणा आदिवासी जनजाति- श्री सावताराम मीना (सीकर), श्री करणा राम मीणा (सीकर), श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल (जयपुर), श्री भैरूंलाल काला बादल (कोटा बारां), श्री हरसहायजी मीना (नीमकाथाना)।

मीणा जाति के योद्धा- श्री भीमा मीणा (बूंदी), श्री हीदाजी मीना (जयपुर), श्री रघुनाथ सिंह कप्तान (आमेर)।

महाराणा प्रताप के सहयोगी- सरदार पूंजा राणा (भील), वल्लाद रावत (मीना)। सभापति महोदय, जिस जाति ने सैकड़ों वर्ष राज्य पर शासन किया, ऐसी कौनसी परिस्थितियां बनीं कि इन्हें आरक्षण की जरूरत पड़ी। आज तनिक आरक्षण का एक हिस्सा मिला था और लोग तिलमिला गये। मैं सदन से पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े शासक, वीर, योद्धा व देश की आजादी में अग्रणी भूमिका निभाने वालों का आज एक अध्याय भी पाठ्यपुस्तकों में शामिल नहीं किया गया है, यह बड़े ही दु:ख की बात है। सभापति महोदय, मैं सदन से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस बहादुर जाति का वीरतापूर्ण इतिहास किसी न किसी कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए जिससे युवा पीढ़ी पढ़कर गौरवान्वित हो सके।

(श्री गोपी चन्द मीणा)

माननीय सभापति महोदय, मैं जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, मेवाड़ का अंतिम छोर है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ डिमाण्ड रखता हूं। शिक्षा विभाग द्वारा राज्यस्तरीय या राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को खेल प्रमाण पत्र दिये जाते हैं। वे गुम होने पर पुन: जारी नहीं किये जाते हैं अत: माननीय सभापति महोदय, निवेदन है कि खेल प्रमाण पत्र पुन: डुप्लीकेट जारी होने चाहिए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड मुख्यालय कोटड़ी में राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूं। महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, अचरोल के कृषि संकाय के छात्रों को यूपीएससी पात्रता सूची में जोड़ा जाए, उनको न्याय दिलाया जाए। वे अभी धरने पर बैठे हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा विभाग का पूरे राज्य का बजट बढ़ाया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मुख्यालय जहाजपुर में नवीन खेल स्टेडियम खोला जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की समस्या यह है कि सन् 1958 में आदिम जनजाति संघ द्वारा अनुदानित छात्रावास खोला गया था, भवन निर्माण था और 100 बच्चों का नामांकन था लेकिन अभी भवन जर्जर अवस्था में है और बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया जिससे वे दर-दर भटक रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अनुदानित छात्रावास न तो समाज कल्याण विभाग में है, न यह ट्राइबल में है, न सरकार के अण्डर में है तो मांग करता हूं कि किसी भी एजेंसी से इस भवन की मरम्मत करायी जाए ताकि बच्चों को लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में नामांकन के आधार पर यूपीएस ग्राम गढ़बोदिया को सैकण्डरी में क्रमोन्नत किया जाए। सभापति महोदय, नामांकन के आधार पर विद्यालय आगरिया, पंचायत समिति कोटड़ी को सैकण्डरी में क्रमोन्नत किया जाए। बालिका शिक्षा को महत्व देते हुए नवीन बालिका सीनियर सैकण्डरी विद्यालय क्रमोन्नत करने हेतु ग्राम सरशिया, धौड़, गुढ़ा में खोला जाए।

सम्पूर्ण प्रदेश में खेल मैदान तैयार किये जाएं। सभी विद्यालयों के चारदीवारी का निर्माण कार्य पूरा होना चाहिए ताकि खेलों को बढ़ावा मिल सके। नरेगा या अन्य आर.डी. स्कीम में कम्पल्सरी यह शर्त लागू होनी चाहिए कि खेल मैदान तैयार हो क्योंकि आज के बच्चे घर से निकलते हैं, टिफिन लेकर

(श्री गोपी चन्द मीणा)

स्कूल जाते हैं और बस में बैठकर वापस घर आ जाते हैं जिससे समय नहीं मिल पाता है अत: खेल मैदान तैयार होना जरूरी है। सम्पूर्ण प्रदेश के खेल मैदानों का अतिक्रमण हटाया जाए, ऐसा कानून पारित किया जाए।

(19.23 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

अभी वर्तमान में आरपीएससी द्वारा 4500 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती पैण्डिंग चल रही है और सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों के भविष्य को देखकर उनको शीघ्र निर्देशित करें और उनको नियुक्ति दी जाए।

छात्र-छात्राओं के स्कूल बैग का वज़न ज्यादा, छोटे बच्चे जो प्राइमरी शिक्षा के बच्चे हैं उनको मानसिक तनाव रहता है अत: स्कूल बैग का वज़न कम किया जाए और उनको खेलों के आधार पर ज्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, पोषाहार व्यवस्था में एलीमेंट्री सैटअप, प्रारम्भिक शिक्षा या सैकण्डरी के जो व्यवस्थार्थ अध्यापक लगाये जाते हैं इनको अध्यापन कार्य में लगाया जाए। अगर वे अध्यापक पोषाहार में रहते हैं तो बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अत: सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यवस्थार्थ पोषाहार हेतु दो कर्मचारी, अध्यापक लगाये जाते हैं उनको हटाया जाए और उनको अध्यापन कार्य में लगाया जाना चाहिए। इसी तरह प्रारम्भिक शिक्षा में या सैकण्डरी में जो बीएलओ लगाया जाता है, यह कार्य भी अन्य कर्मचारी या अधिकारी से कराया जाए ताकि अध्यापन कार्य प्रभावित नहीं हो। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मिड्डे मील और बीएलओ, इनका काम अन्य से कराया जाए ताकि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो सके।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें, विराजिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल मीणा।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे शिक्षा पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रतापगढ़ जिला सम्पूर्ण आदिवासी क्षेत्र होते हुए अति पिछड़ा क्षेत्र है

(श्री रामलाल मीणा)

और शिक्षा के स्तर पर भी मैं समझता हूं कि यह लास्ट नम्बर पर होगा क्योंकि आज भी वहां शिक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं। पूर्व में साक्षरता अभियान चला था उस समय भी फार्मेलिटी करके, अंगूठे की जगह हस्ताक्षर सिखाकर हमको साक्षर मान लिया गया था और आज भी शिक्षा का स्तर वहां बहुत कमजोर है। ऐसी विषम परिस्थितियों में मैं माननीय मंत्री महोदय से मेरे प्रतापगढ़ जिले में सुहागपुरा, रामपुरिया, सेवना, बेड़मा, अवलेश्वर, देवगढ़, थड़ा, पानमोड़ी, डाबड़ा, अचलपुर, झांसड़ी, लुहारिया एवं देवपुरा में नवीन बालिका प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग करता हूं। प्रतापगढ़ जिले में उंकाला, पीपरोड़ी, सेमलाखेड़ा, ब्लॉक अरनोद एवं छायण, जाम्बुवेला, धावड़ीफला, जहाजपुर, ब्लॉक प्रतापगढ़ को प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं। प्रतापगढ़ जिले में राजकीय माध्यमिक विद्यालय चन्देरा, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय पीपलखूंट, राजकीय माध्यमिक विद्यालय लाम्बा डाबरा एवं राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय पारसोला को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं।

माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र में बच्चों की संख्या तो अधिक है, आज की तारीख में शिक्षा के क्षेत्र में जागृति तो बहुत आई है लेकिन जितने बच्चे जिस स्कूल में हैं उसके अनुरूप पद सृजित नहीं हैं इसलिए सभी विद्यालयों में बच्चों की संख्या को देखते हुए नवीन पद सृजित कराएं जिससे विद्यालय में स्टाफ की पूर्ति की जा सके।

दूसरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दावड़ा में कला वर्ग, दलोट में साइंस, गणित एवं कृषि वर्ग, कूणी में विज्ञान वर्ग, सुहागपुरा में कृषि और एकलव्य बालिका माडल स्कूल टिमरवा में कला वर्ग, आवासीय विद्यालय में विज्ञान विषय खुलवाने की कृपा करें। दलोट में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने जो स्कूल बन्द किये थे उनमें एक महत्वपूर्ण स्कूल दलोट का भी प्राथमिक विद्यालय बन्द कर दिया गया है जिससे आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं दलोट में पुनः प्राथमिक विद्यालय, जो बन्द कर दिया गया है, उसको चालू कराया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रतापगढ़ जिले में इस वर्ष 1394 छात्र साइंस से पास हुए हैं, 1553 बच्चे आर्ट्स से पास हुए हैं, 339 बच्चे कॉमर्स से

(श्री रामलाल मीणा)

पास हुए हैं। इस तरह से 3567 बच्चे और 3870 बच्चियों ने इस बार 12वीं का एग्जाम पास किया है। मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 7437 कुल बच्चे पास हुए हैं और उनकी एवज में 1500 बच्चों को राजकीय महाविद्यालय में एडमिशन मिला है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि 6 हजार के आस-पास बच्चे आज उच्च शिक्षा से वंचित रह रहे हैं जो बहुत गम्भीर मामला है। कुछ समय पूर्व माननीय मुख्य मंत्री महोदय और अन्य मंत्री महोदय का कार्यक्रम वहां हुआ। उसके बाद में सबने मिलकर दो मांग उठाई थीं जिनमें एक तो प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर कन्या महाविद्यालय की और एक हास्पिटल में 150 बैड बढ़ाने की। मैं उस समय खुश हो गया जब कन्या महाविद्यालय की बात आई, उस दिन सी.एम. साहब ने घोषणा की थी कि प्रदेश में जब भी कहीं कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा तो उसमें पहला नाम प्रतापगढ़ का होगा। लेकिन मुख्य मंत्रीजी की जब घोषणा चालू हुई तब प्रतापगढ़ का नाम नहीं आया। चक्कर खाकर नीचे गिरने जैसी स्थिति मेरी हो गयी। माननीय सभापति महोदय, मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं...

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): सभापति महोदय, गंभीर मामला है, मुझे कुछ समय बोलने के लिए दीजिए।

श्री सभापति: आप मिलकर बताना मंत्री जी को। श्री गोविंद राम।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): इसके बाद, माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से आपका कन्या महाविद्यालय हो जाएगा।

श्री सभापति: समाप्त करें। विराजिए आप, विराजिए आप। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए आप, विराजिए। माननीय मंत्री महोदय को मिलकर आप बता देना अपनी बात। विराजिए, विराजिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए, अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। प्लीज विराजिए। श्री गोविंद राम।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): आपने मुझे मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, जब हमारा देश आजाद हुआ, और उससे पहले जो अंग्रेज यहां आए, उनकी यह सोच थी that uncivilized people settled in India. यहां शिक्षा का अभाव था और यदि किसी मुल्क को, आपको पीछे करना हो तो साधारण सा फार्मूला है कि आप शिक्षा से वंचित कर दो। आज भी हमारा दुर्भाग्य है कि पूरे देश में 60 और 70 साल की उम्र से ज्यादा लोगों में एजुकेशन का अभाव है। हमारे देश को 1947 में आजादी मिली थी, 1950 में हमारा संविधान बना और जिन्होंने संविधान बनाया डा. अम्बेडकर साहब उस समय का रिकार्ड था कि उन्होंने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिग्रियां लीं। जब संविधान बनाने की बात आई तो यह तय हुआ कि डा. अम्बेडकर, जो कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जिन्होंने विश्व में सबसे ज्यादा डिग्रियां लीं और विश्व में विद्वान जो 6 थे, इसमें कार्ल मार्क्स भी थे, उनमें नाम उनका आया और संविधान का मसौदा बनाने का काम उनको दिया गया। आज हमें खुशी है कि हमारा विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। एक दलित का बेटा पाठशाला से बाहर बैठकर टाट-पट्टी पर पढ़ने वाला, वह एजुकेशन, चूंकि शिक्षा जो है, शेरनी का दूध है।

इसलिए आजादी के बाद कांग्रेस का राज बनने के बाद हमें बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज देने का काम हुआ, लेकिन 70 साल के बाद भी जो संस्कारित एजुकेशन होनी चाहिए थी, आज उसका अभाव है। आज हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में साधुओं को भेजा जा रहा है, बहुत सारे स्टेट की बागडोर साधुओं को सौंपी जा रही है। ये शिक्षा का कहीं न कहीं संस्कार का अभाव है, इसलिए मैं सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा और लोक सभा में एजुकेटेड लोग, संस्कारित एजुकेटेड लोग आकर विचार करें। देश को कौनसी दिशा देनी है, क्योंकि 1848 में ज्योतिबा फूले ने कहा था कि शिक्षा के बगैर मति नहीं, मति के बिना गति नहीं और गति के बगैर अर्थ नहीं, मतलब रुपया पैसा नहीं आएगा और जब रुपया पैसा नहीं आता है, उसका जीवन खच्चर के बराबर होता है।

आज हमें खुशी है कि हमारे दोनों तरफ से पढ़े-लिखे विद्वान लोग बोलते हैं, चाहे महिला हो या जेन्ट्स हों, जबकि 1848 में महिला स्कूल नहीं जा सकती थी लेकिन, ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्री बाई पहली शिक्षिका

(श्री गोविंद राम)

थीं, जिन्होंने महिलाओं को पढ़ाने का काम किया, जिन्होंने दलितों को पढ़ाने का काम किया। इसलिए आज मैं उनको नमन करना चाहता हूं और साथ ही धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय अशोक गहलोत साहब को जिन्होंने वर्षों से हमारी छतरगढ़ की कालेज की मांग थी, पूर्ण की।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डोटासरा साहब को जिस छतरगढ़ की दसवीं स्कूल, मैं भी दसवीं में फर्स्ट डिवीजन आया, लेकिन वहां आर्ट्स थी मात्र, आज आपने साइंस देने का काम किया। आपके लिए वह छोटा काम हो सकता है, लेकिन छतरगढ़ का हर स्टूडेंट, हर बुजुर्ग आज आपको धन्यवाद दे रहा है कि आपने वहां साइंस देने का काम किया।

हम चाहते हैं कि इस देश में अच्छी शिक्षा आए। धर्म के नाम पर शिक्षा देकर के, हम धर्म के नाम पर साम्प्रदायिकता का जहर घोलकर अगर राज में आते हैं तो जो विश्व शक्ति बनने का हमारे मन में सपना है, वह हमारा सपना धराशायी हो रहा है इसलिए सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो सरकारी स्कूल हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें अच्छी सुविधा हो। पहले एक नारा चला था, ''चाहे हो चपरासी की औलाद, चाहे हो राष्ट्रपति की संतान, सबको शिक्षा एक समान'' इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश में अच्छी शिक्षा आए, चूंकि आजादी से पहले यहां लॉ की डिग्री नहीं हो सकती थी चाहे वे महात्मा गांधी हों, चाहे नेहरू जी हों, चाहे डा. अम्बेडकर हों, इन लोगों को बाहर जाकर पढ़ना पड़ा। बाहर जाने का एक फायदा मिला कि आज जो अमेरिका सबसे बड़ी शक्ति है, वह भी इंग्लैंड का गुलाम था। यह एजुकेशन का ही कमाल है कि आज वह पूरे विश्व के अंदर राज कर रहा है इसलिए हम शिक्षित लोगों को आगे बढ़ाएं। मैं चाहूंगा शिक्षा मंत्रीजी से आज मुझे दुख होता है कि खाजूवाला में पिछले पांच साल में एक भी प्राइमरी स्कूल को मिडिल नहीं बनाया गया। मैं धन्यवाद जरूर देना चाहूंगा पंचायत हैडक्वार्टर्स पर आपने दसवीं के स्कूल दिये। आज क्षेत्र में हम घूमते हैं, हमारी स्कूलों की बिल्डिंगें टूटी पड़ी है। वहां बच्चो को जब बारिश आती है तो बिल्डिंग से बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता है इसलिए मैं कहना चाहूंगा आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, डोटासरा जी एजुकेशन में, आप विदेशों में जाओ, वहां मास्टरों की बहुत इज्जत होती है, शिक्षकों के लोग पैर पकड़कर इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे यहां दूसरा है। यहां धार्मिक शिक्षा दी जाती है, पढ़े लिखे

(श्री गोविंद राम)

लोग यूनिवर्सिटी में प्रेसीडेंट रहे, अच्छे पढ़े लिखे लोग पढ़ने के बाद में जब धार्मिक उन्माद पैदा करके वोट मांगते हैं, जाति व धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं, हमें बड़ा दु:ख होता है। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं आज देश को यदि हम विश्व शक्ति बनाना चाहते हैं तो हमें जातिविहीन समाज की आवश्यकता है। यहां योग्यता की पूछ होनी चाहिए क्योंकि विदेशों में जाओं, वहां देखेंगे योग्यता के आधार पर आदमी को पूछते हैं। हमारे यहां जाति के आधार पर बड़ा मानते हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की विचारधारा है, जिसने इस देश को आजादी दिलाने का काम किया, जिसने ऐसी एजुकेशन दी कि यहां 36 कौम की इज्जत होती है। हमारे देश में भाईचारा होना चाहिए। आज जो हम 200 लोग बैठे हैं, हम सब जाति और धर्म से ऊपर उठकर, अच्छी शिक्षा देकर समाज को ऊपर उठाएं।

श्री सभापति: एक मिनट में बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): हम गांव-गांव में अच्छी शिक्षा देने का काम करें, स्कूल में प्रोग्रेस करने का काम करें। एजुकेशन में प्राइवेट कालेजों में जो लोगों की जाने की आदत पड़ गयी है, हम लोग अच्छी शिक्षा देकर, सबको समान शिक्षा दें, ताकि हमारा गरीब का बच्चा भी उस करोड़पति के बच्चे के बराबर एजुकेशन प्राप्त करके कम्पीटिशन फाइट कर सके, अच्छा आईएएस बन सके, अच्छा नेता बन सके और हमारे देश को विकास की ओर प्रकाश दे सके। आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जब्बर सिंह सांखला।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के इस आधुनिक दौर में आज सदन में पूरे दिन चर्चाएं हुईं अच्छी-अच्छी बातें सुनने को मिलीं, इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में गुलाबपुरा शहर है, जहां उपखण्ड कार्यालय है, रेलवे स्टेशन है, भीलवाड़ा से अजमेर रोड पर मेन हाईवे पर बसा हुआ शहर है जहां कई तरह की इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, बड़ी-बड़ी मील लगी हुई हैं, जिनमें मयूर मील भी शामिल है। वहां पर हिन्दुस्तान जिंक का एक बहुत बड़ा प्लांट

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

लगा हुआ है नगरपालिका क्षेत्र होने के बावजूद वहां पर 25 वार्ड हैं और वहां की आबादी लगभग 25 से 30 हजार की है। 80 प्रतिशत वहां के लोग गरीब और मजदूर तबके के हैं। यहां आज बड़ी-बड़ी डींगे हांकी हैं लोगों ने और बहुत कुछ सुनने को मिला है। ऐसा भी कहा गया है कि पूरे राजस्थान में प्रत्येक पंचायत में 12वीं तक की स्कूल है। माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि गुलाबपुरा इतना बड़ा शहर होने के बावजूद मात्र 10वीं तक की सरकारी स्कूल है। आज भारत की आजादी के 72 साल बाद भी मात्र 10वीं तक, मैंने इस सदन में पिछले दिनों भी महाविद्यालय की मांग की थी और माननीय जितने भी सदस्य यहां विराजित हैं, इन्होंने आदरणीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त किया था, इनमें मैं भी शामिल होता हूं। इस बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र के गुलाबपुरा शहर के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो भेदभाव किया है, इसके लिए मैं इनको प्रणाम करता हूं और इनको नमन करता हूं, मैं भी इनका आभार व्यक्त करता हूं।

साथ ही माननीय मंत्री महोदय जी का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे आसीन्द तहसील में कुछ विद्यालयों की मांगें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान दें। मेरे आसीन्द तहसील में पी.एस. बाजून्दा के हड़मादा गांव में शिक्षक बिलकुल भी नहीं हैं। पी.एस. भैरूखेड़ा वार्ड नं. 1 आसींद में भी शिक्षक नहीं है। ढेढ़ी का बाडिया जो ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा में है, पी.एस. बुलिया का कुआ जो चैनपुरा ग्राम पंचायत में है, पी.एस. बागमाली जो रूपपुरा ग्राम पंचायत में है, पी.एस. कोलीखेड़ा जो बरसनी ग्राम पंचायत में है वहां एक-एक या दो-दो शिक्षक लगे हुए हैं मतलब आधे भी नहीं हैं। साथ ही जो स्कूल के जर्जर भवन हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पी.एस. सांगणी जो ग्राम पंचायत बरसनी में है, पी.एस. मालनास जो ग्राम पंचायत जिन्दरास में है, पी.एस. बाला का बाढ़िया जो चैनपुरा ग्राम पंचायत में है, यहां कक्षा कक्ष भी नहीं है। पी.एस. हाथीसर जो बराना पंचायत में पड़ती है वहां स्कूल की छत पूरी तरह से जर्जर है, बारिश के दिनों में टपकती है और बच्चे दूसरों के घरों में जाकर पढ़ाई करते हैं। सामने एक हनुमान जी का मंदिर है उस मंदिर में पढ़ाई चलती है।

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

साथ ही माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। यू.पी.एस. गोविन्दपुरा आसींद में स्थित है। यू.पी.एस. वार्ड नं. 6 भी आसींद में है, यू.पी.एस. शंकरदेव भारतीय विद्यालय ये भी आसींद में है, यू.पी.एस. जयसिंहपुरा जो ग्राम पंचायत परा में है, यू.पी.एस. जरडू का खेड़ा जो गाम पंचायत परा में है, यू.पी.एस. सुलवाड़ा जो ग्राम पंचायत बराना में है, यू.पी.एस. घायलों का खेड़ा जो बाजून्दा ग्राम पंचायत में है, यू.पी.एस. बादशी जो एक बालिका विद्यालय है। यू.पी.एस. बलेव जो ग्राम पंचायत भोजपुरा में है, यू.पी.एस. झालरा जो ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा में है, यू.पी.एस. नूवालिया जो झालरिया ग्राम पंचायत में है, यू.पी.एस. आकड़सादा वहां भी एक बालिका विद्यालय है। यू.पी.एस. सोनारेल जो लाछूड़ा ग्राम पंचायत में है और यू.पी.एस. झाली जो रतनपुरा ग्राम पंचायत में है, वहां बिलकुल भी अध्यापक नहीं हैं माननीय मंत्री महोदय।

मैं आपका ध्यान इन सब मांगों पर आकर्षित करता हूं और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जो आदरणीय माननीय सदस्यों ने बातें बताई हैं चूंकि मैं तो बिलकुल नया हूं हम लोग नये-नये आये हैं, हमको क्या सीखने को मिलेगा यहां पर। अगर आप पारदर्शिता से काम करना चाहते हैं तो आज ही आप घोषणा करें गुलाबपुरा में महाविद्यालय की, क्योंकि वहां सब मजदूर वर्ग के लोग हैं। आप जांच कराएं, जांच कमेटी बैठाएं। वहां प्राइवेट महाविद्यालय है। वहां लाखों की फीस जमा करानी पड़ती है। सारे लोग वहां मजदूर हैं। 80 परसेंट लोग वहां के मजदूर हैं जो फैक्ट्रियों और माइन्स में नौकरियां करते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में समाप्त करें।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): मैं आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही आप इस महाविद्यालय की घोषणा करें तो मैं आपका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा और साथ ही जो ये छोटीमोटी मांगें मैंने रखी हैं आपके सामने, मेरे वहां के जो विद्यालय हैं उनमें बहुत से विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं। आप एक जांच करवाकर, सर्वे करवा करके वहां अध्यापक लगाएं। साथ ही पर्यावरण के मामले में हम बातें करते हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह करता हूं कि हम पौधारोपण के कार्यक्रम करते हैं बारिश का मौसम है, बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहां बाउण्ड्रीज नहीं

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

है, वहां भी आप बाउण्ड्रीज की घोषणा करें। एक अलग से फंड की घोषणा करें, ताकि जानवरों से उन पौधों को बचाया जाए और पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय श्रीराम। वन्दे मातरम।

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा, कला एवं संस्कृति मांग संख्या-24 पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सदन में सदा ज्ञान का प्रकाश चमकता रहे, सरस्वती मां का आशीर्वाद सदा हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। सम्माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने गुरु का सम्मान किया प्रधानाचार्य जी की कुर्सी पर नहीं बैठ करके, नहीं तो अभी से पहले तो जाकर कुर्सी पर ही बैठते थे, कई बार फोटो देखी है बैठते हुए। आप धन्यवाद के पात्र हैं और उसके बाद धन्यवाद है कि 120 बच्चों से घटाकर पीटीआई आपने 105 पर की, ऐसा नवाचार आप करते रहें। पिछली सरकार में खेल के मैदानों एवं जमीन के पट्टे देने और रिक्त पदों को भरने के लिए स्थगन लगाये, 295 लगाये, प्रश्न लगाये, सभापति महोदय, एक भी काम पर कोई प्रतिक्रिया पिछली सरकार की नहीं आयी। मैं मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि प्रदेश में हजारों विद्यालयों की जमीन ऐसी है जिन पर अतिक्रमण हो रहा है या खातेदारी में नहीं चढ़ी हुई हैं या दूसरी पंचायत में है, दूसरी तहसील में है। इसका एक उदाहरण मेरे यहां भी है कि जमीन मुण्डावर की है और बानसूर का विद्यालय है, रायली गांव है, तो ऐसे में शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग का एक कैम्प लगा करके स्कूलों के नाम सभी जमीनों को करवाएं जिससे वहां पर बाउण्ड्री और कमरे बना सकें।

सभापति महोदय, यह एक बहुत-बड़ी समस्या है। न हमारे विधायक कोष का पैसा लग पाता है, न समसा का, न रमसा का और अपने स्कूलों में जो खाना बनाने वाली लगी हुई हैं उनका मानदेय बहुत ही कम है उसे बढ़ाया

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

जाए। पिछली सरकार के दौरान भी मैंने उठाया था लेकिन कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आयी, सिर्फ कागज का जवाब देकर दूर हो जाते थे। खेल की प्रतियोगिताओं में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी मैंने ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव लगाया था लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पोर्टल बना दिया। मंत्री जी कहने लगे कि पोर्टल पर डालिये, हम शिकायत का समाधान करेंगे। इतनी डाल दी, अगर खोलकर देखें तो बहुत सारी निकलेंगी और पुराने जो विद्यालय हैं जिनकी बिल्डिंग जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है उनका रमसा और समसा से जो प्रक्रिया है, 6 महीने लग जाते हैं तो कृपया करके मंत्री महोदय से निवेदन है कि चारदीवारी, शौचालय या पानी की व्यवस्था नरेगा से जोड़कर करें तो ज्यादा उचित रहेगा। विषय अध्यापक जहां बालिकाएं अधिक हैं, ऐसी स्कूलें हैं, हमीरपुर, बानसूर, नारायणपुर, रामपुर, हरसेरा, छीन्ड जयसिंहपुरा, हाजीपुर, मुण्डावरा, बामनवास कांकड आदि। इस तरीके की जो भी व्यवस्थाएं हैं वे सारी व्यवस्थाएं पहले बालिकाओं के स्कूल में करवाने का कष्ट करें। जो लैपटोप बांटे जाते थे उनमें सेम प्रतिशत वाले कई बच्चे रह जाते थे तो एक ऐसा आधार बनाएं जिससे बच्चों में आपस में भेदभाव की भावना नहीं आए। देवनारायण योजना के तहत नारायणपुर उप तहसील जो है वहां पर बालिका महाविद्यालय खोलें। देवनारायण योजना के तहत आवासीय विद्यालय खोलें। कराना, हमीरपुर, रामपुर, नारायणपुर, मुण्डावरा, हरसोरा, जिन विद्यालयों के पट्टे दिये हुए हैं खेल मैदान के, वहां खेल मैदान बनाने की आवश्यकता है। जहां पर लड़कियां बहुत अधिक हैं उन स्कूलों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है। जैसे गांव है, कोठिया, माजरा डाकोड़ा, तुर्कियावास, ठेकला की ढाणी, नाथूसरलोज, ग्वाड़ा, आलनपुर, ऊंचपुर, ईसरा का बास, धामला का बास, ऐसे स्कूल हैं जिनमें डेढ़ सौ तक की बालिकाएं हैं तो इन्हें क्रमोन्नत करने की कृपा करें और सर्वे करवा लें जहां बालिकाओं की संख्या अधिक है, उन्हें क्रमोन्नत करवाएं।

माननीय सभापति महोदय, संगीत कला जो लुप्त होती जा रही है, 2016-17 में इनकी किताबें छप गयी थीं लेकिन स्कूल में बच्चों को नहीं बांटी गयी थीं। इन अनिवार्य विषयों पर विषय अध्यापकों की भी अगर अपन भर्ती करें तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। बच्चे देश का भविष्य होते हैं लेकिन पार्टियां अपनी छाप छोड़ने के लिए और भारत देश के महान व्यक्तित्व के माध्यम से अपने इतिहास के पन्नों में अमिट लिखा हुआ है उसको उछाल रही

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

हैं। जैसे कि उन महान व्यक्तित्व को, इन नेताओं से जो पिछली सरकार थी, क्या उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि कौन महान था और कौन नहीं था? ये उछाल रहे हैं बड़े शर्म की बात है। इतिहास को इस तरह से उछालते हैं कि कौन ने क्या काम किया, कौन महान था। आप तो महान नहीं थे यह तो समझ लो।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, इधर आसन की तरफ।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): भारत की संस्कृति और संस्कृत को भुलाने की बात कर रहे हैं। शिक्षा को पीपीपी माडल पर दे दिया और संस्कृति की बात करते हैं। संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की ऐसी बात करेंगे जैसे तो इन्होंने ठेका ले लिया हो और पीपीपी माडल पर उनको बेच दिया। यह बड़े शर्म की बात है। सभापति महोदय, ऐसे हालात में संस्कृत स्कूलों में सुविधाएं प्रदान करें। सारे अध्यापक वहां लगाएं। दूध वाली जो बात थी सभापति महोदय, एकदम से इतना दूध कहां से आया? इतनी सारी भैंसें किसके पास आ गयीं? ये कौनसे नेताजी के पास हैं भाजपा वालों के पास में?

श्री सभापति: एक मिनट में बात समाप्त करें आप अपनी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): तो इस चीज को चैक करा, जांच करा कर बांटा जाए अन्यथा यह तो बच्चों के लिए लाभदायक नहीं होगा। बानसूर महाविद्यालय में एग्रीकल्चर, गृह विज्ञान संकाय खोला जाए एवं तुरन्त रिक्त पदों को भरा जाए। जो ऐसी घटनाएं आजकल स्कूलों और कालेजों में होती हैं मंत्री महोदय, मेरा एक अनुरोध है वैसे आपकी इच्छा है, सभी से बात कर लें कि हर महीने, हफ़्ते में एक दिन दस-पन्द्रह बच्चों के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाएं, बच्चों की गतिविधि से उन्हें अवगत कराएं तो शायद ऐसी चीजों पर रोक लगेगी और ये कालेज और स्कूल सभी जगह हों तो ज्यादा अच्छा है। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि भारत शिक्षा में प्राचीनकाल से ही आगे था, आज भी आगे हैं और कल भी आगे रहेगा क्योंकि पहले प्राचीन काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग और फाहियान यहां शिक्षा ग्रहण करने आये थे नालन्दा विश्वविद्यालय में। माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरकारी कालेज में पढ़ाएं। हम और हमारे बच्चे तो सब सरकारी में ही पढ़े हैं, आप इन प्राइवेट को पता नहीं क्यों चढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल कठूमर।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री बाबूलाल कठूमर (अनुपस्थित)। श्री मदन प्रजापत।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा, कला एवं संस्कृति के ऊपर काफी सुझाव आये। नवलगढ़ से आने वाले राजकुमार जी कह रहे थे कि कालेज और स्कूलों को जो व्यवसाय बना दिया गया है उसमें एमएलए का अपमान किया जाता है। यह एमएलए का अपमान नहीं है, यह लोकतंत्र का अपमान है। माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ऐसी जो फर्जी दुकानें हैं...

श्री सभापति: अपने क्षेत्र की समस्या बता दो आप, अन्तरराष्ट्रीय में फंस जाओगे।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): हमारे कोई समस्या नहीं है। माननीय सभापति महोदय, दो मिनट ही नहीं हुए, क्या कहें। (व्यवधान) जो बातें पूर्व मंत्री जी कर रहे थे संस्कार की, योग की, उन्होंने तो अपने कार्यकाल में राजस्थान का गौरव बढ़ाया जो नकल का आरोप लगा। इससे इनकी पूरी पार्टी का और पूरे राजस्थान का गौरव बढ़ा। माननीय सभापति महोदय, योग की गहराई में नहीं जाएं लेकिन कैसे संस्कार हैं, आज से 15 दिन पहले मोबाइल और अखबारों में, मैं तो नाम लेना ही पसंद नहीं करता हूं, पूरे हिन्दुस्तान में चर्चाएं हुईं क्या वैसा योग, वैसा संस्कार देना चाहते हैं? माननीय सभापति महोदय, आज स्कूल बंद करने का काम किया, पूरे पांच साल तक कलर बदलने में समय बर्बाद किया। सरकारें आती हैं, सब स्कूलें खोलती हैं, लेकिन बंद करना, माननीय सभापति महोदय, गुजरात में मैंने देखा पूरी तरह निजी

(श्री मदन प्रजापत)

हाथों में है। मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान में गुजरात से व्यवस्था शानदार है। आज प्राइवेट स्कूलों का जो कल्चर बढ़ा है, अपनी शान समझते हैं कि मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, यह ग़लतफ़हमी है और प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं है। कई प्रतिभाएं हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान का नाम रोशन किया है, बिना सुविधाओं के बावजूद हिन्दुस्तान के उच्च पदों पर गये हैं।

28 में से 18 साल राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और आरोप लगा रहे हैं कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। शायद आपको तो कोई मांग करनी ही नहीं चाहिये, 6 महीनों में तो कुछ बिगड़ा नहीं है। नवोदय विद्यालय हो या माडल स्कूल हो, यह अगर किसी की देन है तो लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी, राजीव गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी की देन है। अभी महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूलें खुलीं, मैं यह कह सकता हूं आप एक भी उपलब्धि बता दें कि यह हमारी राजस्थान में उपलब्धि है। आदर्श स्कूलों का जो नाम दिया, वह स्कूल आदर्श है या नहीं है, इनकी मंशा उस आदर्श से थी कि जहां पढ़ाई से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है।

माननीय सभापति महोदय, नई स्कूलें खोलने से ज्यादा मेरा सुझाव है जो पुरानी स्कूलें हैं, उनमें सुविधाएं बढ़ाई जाएं। चाहे रिक्त पद हो, पानी, बिजली, भवन हो। आज कम उम्र में बच्चों पर कम्पीटीशन और संघर्ष स्थिति है, इतना भार है, मेरा मानना है इससे बच्चों का शारीरिक विकास भी रुकता है और आगे जाकर कद काठी में भी कमजोर होंगे। जन्म से ही उन पर इतना मानसिक तनाव और बोझ होता है। आज अखबारों में जब पढ़ते हैं तो बड़ा दु:ख होता है, गुरु जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है, लेकिन आज इस कलियुग में जब घटनाएं पढ़ते हैं, देखते हैं तो बड़ा दु:ख होता है। गुरु को मां-बाप से भी ज्यादा सम्मान दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा सौ तालों की एक चाबी है। स्कूलों में आरटीई में अपने स्टाफ के 25 परसेंट बच्चे भरकर इतिश्री करते हैं। शिक्षा व्यवसाय बन गया है। सभापति महोदय, गुरु और स्कूल ईमानदार विभाग था, रमसा, समसा और पोषाहार की वजह से भ्रष्टाचार की हवा उसमें भी लग गयी। स्कूल पर कोई प्रकार का आरोप नहीं था। दूसरा निर्माण, दूसरी एजेंसी या इकाई से दिया जाता है। सबकी भावना थी कि महिला पोषाहार पकाती है, जो भी मजदूर लगा

(श्री मदन प्रजापत)

हुआ है, उनकी रेट बढ़े तो सरकार के खजाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस बात पर भी ध्यान दें।

(20.00 बजे)

इसके अलावा कला, संस्कृति की बात आती है। आज राज्य में अलग-अलग संस्कृति है और इनसे भाईचारा बढ़ता है, प्रेम भाव बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है, चाहे मारवाड़ हो, मेवाड़ हो, चाहे हाड़ौती, शेखावाटी, चाहे ढूंढाड़ हो, डांग क्षेत्र हो, तमाम जो पूरा इलाका है, वांगड़ से लेकर अलग-अलग गीत, अलग-अलग नृत्य और मारवाड़ का गैर नृत्य पूरी दुनिया में अपनी पहचान कायम करता है। चाहे रंगों के लोकगीत हों, चाहे पाबू जी फड़ हो। यह संस्कृति और आज नयी पीढ़ी, बड़ा दु:ख होता है कि अंग्रेजी कल्चर में जा रहे हैं। जो संयुक्त परिवार हैं, वे टूट रहे हैं और वे शान समझते हैं। पति को जो परमेश्वर या भगवान के बराबर दर्जा दिया जाता है...

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): एक मिनट, माननीय सभापति महोदय। आज साहब दिन में फोन करते हैं तो मेम साहब की तरफ से जवाब आता है कि तीन-तीन आफिस का लोड है, टाइम नहीं है। यह क्या संस्कृति है? अंग्रेजी संस्कृति की ओर जा रहे हैं। अगर हफ़्ता-हफ़्ता मिलना और मान-सम्मान। अपनी जो संस्कृति है, युवा समझते नहीं हैं। अंग्रेजी संस्कृति में अपने खान-पान बदल गये, रहन-सहन बदल गया और आने वाली पीढ़ी का झुकाव अंग्रेजी फैशन की तरफ जा रहा है। यह अपनी संस्कृति के लिये ठीक नहीं है।

एक मांग करता हूं कि कन्या महाविद्यालय है, इसमें रिक्त पद भरने के अलावा पीजी खोलें। एमबीआर महाविद्यालय, बालोतरा में विज्ञान विषय खोलने की मैं मांग करता हूं। सबने भी कहा कि पूरे राजस्थान में 80 गैर शैक्षणिक अधिकारियों को यूजीसी का वेतनमान नहीं दिया जा रहा। आपसे मैं भी निवेदन करता हूं। मंत्री जी, शिक्षाविद् और जानकार हैं और आपका यह कार्यक्षेत्र रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि नियंत्रक हो, चाहे डिप्टी रजिस्ट्रार हो, रजिस्ट्रार हो, ऐसे अधिकारियों को वेतनमान दिया जाए और अतिशीघ्र कमेटी बनाकर इनके साथ भी न्याय किया जाए, यह मांग करता हूं। पुन: माननीय सभापति महोदय आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवीर सिंह लूथरा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय सभापति महोदय, आजादी के पहले मेरे क्षेत्र में दो बड़े शिक्षाविद् हुए थे, स्वामी केशवानंद और संत फतेहसिंह जी, इन्होंने शिक्षा का बड़ा प्रचार-प्रसार किया। हमारे बड़े बुजुर्ग बताया करते थे कि स्वामी केशवानंद और संत फतेहसिंह जी ने टोकरे में किताब व कापियां रखकर शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया।

आदरणीय सभापति जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में श्रीविजयनगर में सरकारी महाविद्यालय नहीं है, इसकी मांग वर्षों पुरानी चली आ रही है। शिक्षा की अलख जगाने वाले जिन्होंने तीन प्रांतों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में शिक्षा की अलख जगाई, वे थे स्वामी केशवानंद जी। हमारे श्रीविजयनगर कस्बे के पास गांव 40 जीबी में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब है, जिसकी स्थापना संत फतेहसिंह जी ने की थी। इन दोनों ने मिलकर हमारे क्षेत्र में आजादी से पूर्व शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया था और अकाल के समय गुरुद्वारा में लंगर लगाकर इस क्षेत्र के लोगों की भूख मिटाने का काम भी किया था। आज भी स्वामी केशवानंद के नाम से गांव 40 जीबी रेलवे स्टेशन का नाम केशवानगर है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी निवेदन करता हूं कि गांव 40 जीबी में स्थित राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम बदलकर संत फतेहसिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 40 जीबी रख दिया जाए। मेरे क्षेत्र की जनता इसके लिए सदन एवं आपकी आभारी रहेगी।

सभापति जी, श्रीविजयनगर में सरकारी महाविद्यालय नहीं है। इस इलाके की अधिकांश जनसंख्या ओबीसी एवं एससी श्रेणी की है। इस वजह से इस इलाके के गरीब लोग अपने बच्चों को निजी महाविद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। अत: गरीब परिवारों के बच्चे चाहते हुए भी कालेज की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। श्रीविजयनगर में सरकारी महाविद्यालय अनूपगढ़-सूरतगढ़ में स्थित है जो श्रीविजयनगर कस्बे से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए विद्यार्थियों एवं विशेषकर हमारी बेटियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। श्रीविजयनगर में भामाशाहों द्वारा महाविद्यालय के लिए नि:शुल्क भूमि देने की भी व्यवस्था कर रखी है। श्रीविजयनगर में 6 एवं जैतसर में 2 निजी महाविद्यालय चल रहे हैं परंतु सरकारी महाविद्यालय नहीं होने से हमारे गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। एक तरफ हम नारा देते हैं कि "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ"। जब सरकारी महाविद्यालय नहीं होंगे तो

(श्री बलबीर सिंह लूथरा)

हमारी बेटियां कहां पढ़ेंगी? एक तरफ तो सरकार दावा कर रही है कि हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, मगर हमारे श्रीगंगानगर जिले के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है। हमारे जिले को एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं दिया गया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीविजयनगर उपखण्ड कार्यालय है। प्राय: सभी उपखण्डों पर सरकारी महाविद्यालय खोले जा चुके हैं। अत: श्रीविजयनगर में भी एक सरकारी महाविद्यालय खोला जाए, ताकि इस क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सकें।

आदरणीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उपखण्ड रायसिंहनगर एवं उपखण्ड श्रीविजयनगर में स्वामी विवेकानंद माडल स्कूल खोले जाएं, ताकि मेरे क्षेत्र के बच्चों को अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सके। मेरा विधान सभा क्षेत्र सुरक्षित है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या अधिक होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में विज्ञान का विषय नहीं है। आप कम से कम 10 विद्यालयों में विज्ञान विषय प्रारम्भ करवाने का काम करें।

इसी प्रकार रायसिंहनगर के पास गांव रामजीवाला में टीचर ट्रैनिंग सेंटर (डाइट) प्रस्तावित है, परंतु आज तक इसे नहीं बनाया गया। कृपया आवश्यक कार्यवाही कर इस डाइट को शुरू करवाया जाए।

आदरणीय सभापति जी, मैं सदन का ध्यान एक ऐसे मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि अति संवेदनशील एवं सरकार के हित में है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में छात्र संख्या कम अथवा शून्य होने की वजह से पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र में 83 विद्यालय बंद कर दिये गये, जिसमें चार शहरी क्षेत्र में एवं 79 ग्रामीण क्षेत्र में हैं। ये भवन कुछ जर्जर अवस्था में हैं तो कुछ की स्थिति काफी ठीक है, इन भवनों पर कई प्रभावशाली लोगों की नजरें हैं। कुछ भवनों में तो ग्रामीणों द्वारा पशुधन बांधा जा रहा है अथवा चारा-तूड़ी डाला जा रहा है। आपसे निवेदन है कि इन भवनों में जहां विद्यालय पुन: शुरू हो सकते हैं, वहां पुन: विद्यालय शुरू करवाये जाएं अथवा उन भवनों को पंचायतों एवं नगरपालिका के अधीन किया जाए ताकि इन सरकारी सम्पत्तियों पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं हो।

(श्री बलबीर सिंह लूथरा)

आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के निम्नलिखित विद्यालय उच्च प्राथमिक से माध्यमिक करने की आवश्यकता है- ब्लाक रायसिंहनगर में गांव 57 एन पी, 35 एमएल, 50 एनपी, 65 एन पी, 22 पीएस, 26 एनपी, 25 पीएस, 52 एनपी, 67 आरबी, 28 एमएल। ब्लाक श्रीविजयनगर में- 26 जीबी, 6 बीजीडीए, धांधड़ा, गोमावाली, एक एन जेड एम, डबजाल, 13 ए.एस. भागसर, 12 किशनावाली ढाणी। इन सभी विद्यालयों में बच्चों की संख्या 100 से 150 तक है।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): आदरणीय सभापति जी, मैं एक मिनट का समय और लूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा भारत-पाक सीमा पर स्थित है एवं पिछड़ा हुआ है। रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड कार्यालय भी, श्रीविजयनगर में स्टेडियम नहीं है। रायसिंहनगर तहसील के दो बड़े गांव जहां उप तहसील कार्यालय हैं, मुकलावा एवं समेजा, वहां भी स्टेडियम नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में बहुत प्रतिभा है, उसको तराशने की जरूरत है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री पदमाराम।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): एक मिनट, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि तीनों जगह स्टेडियम बनवाने की कृपा करें। इससे सीमान्त क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। इससे क्षेत्र एवं राष्ट्र के प्रति आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): आदरणीय सभापति जी, अंत में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। भारतीय पुरातन संस्कृति एवं विरासत को जिंदा रखने के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सांस्कृतिक एवं कला विद्यालय खोले जाने का निवेदन करता हूं जिससे भारत-पाक सीमा पर रह रहे परिवारों के बच्चों को भारतीय संस्कृति एवं कला से जुड़ने का अवसर मिलेगा। सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। जय जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री पदमाराम।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज जिस मांग पर चर्चा हो रही है, वह मांग समाज का दर्पण है। समाज को मजबूती देने वाला अस्त्र है। इसी शिक्षा से इस समाज का, भारत का, राजस्थान का नेक नागरिक बनने का दायित्व मिलता है, उसके बारे में चर्चा है। इस विषय पर हम सबको मिलकर शिक्षा की बढ़ोतरी, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा से समाज को आगे कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि शिक्षा के अंदर धीरे-धीरे गुणवत्ता की कमी क्यों आ रही है? आज स्कूलों के अंदर गुरुजनों द्वारा जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, उसके अंदर कमी कैसे आ रही है? गुणवत्ता कम क्यों हो रही है? इसके ऊपर सरकार को मंथन करना चाहिए। सरकार को इसके ऊपर नवाचार करने के लिए पहल करनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि सरकारें आयीं, सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने के लिए नई स्कूलें खोलीं, प्राइमरी स्कूल खोली, मिडिल खोली, सीनियर बनायी परंतु स्कूलें क्रमोन्नत होंगी, स्कूलों के अंदर उच्च क्वालिटी की शिक्षा ग्रहण करने के लिए अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, लैक्चरर की समय-समय पर कमी आयी है। कई स्कूलें ऐसी हैं, वहां कई सालों से अध्यापक बंधु विराजमान हैं। वहां अध्यापकों से स्ट्रूडेंट कम हैं, परंतु शहर के नजदीक रहने के लिए एक-एक स्कूल के अंदर बीस-बीस, तीस-तीस विराजमान हैं। जो ग्रामीण अंचल की स्कूलें हैं, वहां अध्यापकों की कमी है। वह वहां रहना नहीं चाहते हैं। पोस्टिंग हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद में दो साल के अंदर वे राजनीतिक एप्रोच लगाकर वापस ट्रांसफर करके सिटी के नजदीक चले जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि ट्रांसफर नीति बनायी जाए। अध्यापकों की जब नियुक्ति होती है, उस समय एक कंडीशन लगायी जाए कि जिस स्कूल में फर्स्ट पोस्टिंग करेंगे वहां तीन साल, चार साल आपको रहना अनिवार्य है।

सभापति महोदय, आपकी मार्फत माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि आज स्कूलों के अंदर जो अध्यापक कार्यरत हैं, सरकार की बड़ी रकम प्राप्त करते हैं, उसके बाद में भी वह साइड बिजनेस के अंदर पूरा समय देते

(श्री पदमाराम)

हैं। स्कूल के विद्यार्थियों का भविष्य सुधारने में वह कम रुचि रखते हैं। आज सरकारी स्कूल के कर्मचारी जो बड़ी-बड़ी पार्टियों के अंदर रिश्तेदार बन गये हैं, पार्टियों का प्रचार करते हैं। जो संघ की शाखा में चले जाते हैं और वहां से गुरु शिक्षा प्राप्त कर स्कूल के विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा देते हैं, भ्रांतियां पैदा करने के लिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने का काम करते हैं। इनके ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इनके ऊपर आपको निगरानी रखनी पड़ेगी। ऐसे अध्यापक जो सरकारी वेतन प्राप्त कर, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा प्राप्त कर स्कूल के अंदर दुराचार करते हैं, स्कूलों के अंदर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है। इस पर विचार करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जो पंचायत हैडक्वार्टर पर दसवीं से बारहवीं सीनियर सैकण्डरी स्कूलें खोलीं, ये धन्यवाद के पात्र हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इन्होंने बारहवीं के अंदर विज्ञान की फैकल्टी लगा दी, वहां इन्होंने संसाधनों की व्यवस्था नहीं की, उपकरणों की व्यवस्था नहीं की, लैक्चरर लगाये नहीं, वरिष्ठ अध्यापक नहीं लगाये और पैटर्न चेंज करके आठवीं के, पांचवीं के जो अध्यापक बंधु थे उनको उन स्कूलों में लगा दिया। पांच साल के अंदर बच्चों का भविष्य इन्होंने खोखला कर दिया। बच्चे स्कूलें छोड़कर जा रहे हैं। प्राइवेट को प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने ये काम किया। मेरा आपसे निवेदन है कि गवर्नमेंट की स्कूल के अंदर जो अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं, वे आरपीएससी से चयनित होते हैं।

श्री सभापति: आप समाप्त करिए माननीय सदस्य।

श्री पदमाराम (चौहटन): मेहरबानी। ये बी.एड. करके स्कूलों के अंदर जाते हैं। प्राइवेट स्कूल के अंदर जो बच्चे बेरोजगार हैं, वे दो हजार, पन्द्रह सौ और पांच हजार के अंदर पढ़ाने वाले हैं, लोग ज्यादा वहां जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सरकारी स्कूलों को मजबूती दें। सरकारी स्कूल के अंदर संसाधन दें। जहां अध्यापकों की कमी है, वहां अध्यापक नियुक्त करें। उच्च क्वालिटी की बच्चों को शिक्षा दें। वे विद्यार्थी ही आगे बढ़कर इस देश के नेक नागरिक बनेंगे।

श्री सभापति: विराजें।

श्री पदमाराम (चौहटन): इस देश के साहित्यकार बनेंगे, इस देश के वैज्ञानिक बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। एक मिनट। मैं माननीय संस्कृत विभाग के मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि संस्कृत विभाग एक अलग विभाग है। उसका जिला हैडक्वार्टर पर आफिस होता है।

श्री सभापति: विराजिए। श्री अमर सिंह। श्री किसनाराम विश्नोई। श्री अमीन खान। विराजिए माननीय सदस्य।

श्री पदमाराम (चौहटन): मेरा उनसे निवेदन है कि ब्लाक स्तर पर इनका शिक्षा केन्द्र करें। दूसरा मेरा निवेदन है कि उर्दू शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मदरसा टीचर्स के लिए सेवा नियम बनाये जाएं।

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य। विराजिए।

श्री पदमाराम (चौहटन): उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। उनको स्थायी करने की व्यवस्था की जाए। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अमर सिंह (बयाना): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज शिक्षा के बारे में देश को जरूरत है क्योंकि शिक्षा एक दुधारू तलवार है। जो इंसान पूर्ण शिक्षित हो जाता है, वह न तो खुद पर अत्याचार सहन करता है और न ही दूसरों पर सहन कर पाता है। मैं सबसे पहले समय को देखते हुए इस न्याय के मंदिर में आया हूं और अपनी मांगें मांगना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना का रूपवास उपखण्ड आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत विशाल है। रूपवास उपखण्ड में 44 ग्राम पंचायतें आती हैं लेकिन सरकार की उपेक्षा के चलते यहां शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है। यहां निवास करने वाली तकरीबन ढ़ाई लाख की आबादी है। रूपवास से प्रति वर्ष हजारों विद्यार्थी सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए 50 किलोमीटर दूर रोजाना भरतपुर जाते हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको यहां महाविद्यालय के अभाव में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। अत: मेरी सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मांग है कि रूपवास में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा करें। रूपवास में आए दिन धरना-प्रदर्शन जारी हो चुका है। पन्द्रह साल से बीजेपी का विधान सभा क्षेत्र पर कब्जा था। लोगों ने पूर्ण

(श्री अमर सिंह)

भरोसा करके कांग्रेस को वोट दिया है इसलिए मैं बजट घोषणा करने की मांग करता हूं।

दूसरी मांग मेरी बयाना राजकीय महाविद्यालय को पी.जी. में क्रमोन्नत किये जाने की है। बयाना राजकीय महाविद्यालय मेरे विधान सभा क्षेत्र का एकमात्र महाविद्यालय है लेकिन शुरू से ही यह महाविद्यालय विभागीय उपेक्षा का शिकार रहा है। बयाना महाविद्यालय से स्नातक करने के बाद स्नातकोत्तर की पढ़ाई हेतु विद्यार्थियों को जयपुर या भरतपुर जाना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बाहर जाकर पढ़ना मुश्किल है जिससे गरीब परिवारों के उत्कृष्ट बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। अत: बयाना महाविद्यालय को पी.जी. महाविद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा की जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के उत्तर प्रदेश बोर्डर पर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, इब्राहिमपुर में विज्ञान संकाय खोला जाए। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मदनपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए। यह विद्यालय 1982 से संचालित है। पूरी पंचायत में एक भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं होने के कारण इस पंचायत के छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता है। इसके साथ-साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना के डांग क्षेत्र में आने वाले अधिकांश विद्यालयों में अध्यापकों की अरुचि के कारण सभी स्कूलों में रिक्त पद चल रहे हैं, जिन्हें जल्दी से जल्दी भरने की कृपा करें। ज्यादा न कहते हुए सभापति महोदय, बयाना विधान सभा क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है। पन्द्रह साल से वहां बीजेपी का विधायक बनता चला आ रहा है। लक्ष्मण रेखा जो तोड़ी है, उन लोगों ने मुझसे वादा किया है और मैंने उनसे वादा किया है। इसलिए ज्यादा नहीं तो इस सत्र में, इस बजट में महाविद्यालय रूपवास में खोला जाए। बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पुखराज गर्ग। श्री किसनाराम विश्नोई। श्री अमीन खान। श्रीमती इन्द्रा।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, आज इस विशेष मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बिना जीवन अधूरा है। भर्तृहरि जी ने नीति काव्य में कहा है कि नर: विद्या विहीन पशु:। नर विद्या के बिना पशु के समान है। सभापति

(श्रीमती इन्द्रा)

महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन्होंने अभी 2019-20 के बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो बड़ी घोषणाएं कीं, उनके लिए मेरे क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। साथ ही विधान सभा क्षेत्र में कुछ विद्यालय क्रमोन्नत होने की श्रेणी में मापदंड पूरे कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि सारे विद्यालय की लिस्ट बनाकर आपको उपलब्ध करवा दूंगी। विद्यालय क्रमोन्नत हो ताकि ग्रामीण बच्चों को पूरी तरह से शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिले।

कई विद्यालयों में सब्जेक्ट टीचर नहीं होने के कारण मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगी कि पिछले सत्र में बालक जो बाई ग्रेस पास हुए हैं क्योंकि विद्यालयों में सब्जेक्ट टीचर्स की बहुत कमी है, मैं उम्मीद करती हूं सब्जेक्ट टीचर्स विद्यालयों में भरे जाएंगे। जितने भी रिक्त पद हैं मैं उनको भरने की मांग करती हूं।

सभापति महोदय, मैं पैराटीचर्स की बात करना चाहूंगी। महोदय, राजस्थान में करीब 6000 मदरसा पैराटीचर्स कार्यरत हैं जिन्हें 7202 रुपये मानदेय दिया जाता है। सभी पैराटीचर्स बीएसटीसी, बीएड हैं, जो मानदेय पैराटीचर्स को दिया जाता है वह बहुत ही कम है। लंबे समय से वह नियमितीकरण की मांग कर रहे है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगी कि पैराटीचर्स को नियमित किया जाए एवं उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए।

सभापति महोदय, मैं भर्ती में खेलों के महत्व की बात करूंगी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकारी भर्ती में खेल के प्रमाण-पत्रों का बोनस अंक देने का प्रावधान था, जिससे युवा खेल की ओर प्रेरित होता था। भाजपा सरकार ने खेल गतिविधियों को बंद कर दिया, जिससे युवा अपराध की ओर जा रहा है। जो बच्चे खेल मैदान में खेला करते थे, वह समय अब अपराध करने व धार्मिक भावनाएं भडकाने में प्रयोग कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं पी.टी.आई. भर्ती की बात करती हूं। सभापति महोदय, स्वस्थ तन होगा तभी स्वस्थ मन होगा। सभी सरकारी स्कूलों में लंबित पी.टी.आई. भर्ती को अतिशीघ्र पूरा करके खेल प्रशिक्षक नियुक्त किये जाएं तथा सभी राजकीय विद्यालयों में खेल प्रशिक्षक के पद सृजित किये जाएं।

(श्रीमती इन्द्रा)

सभापति महोदय, मैं तृतीय श्रेणी शिक्षक 1998 प्रकरण के संबंध में बात कहना चाहूंगी। वर्ष 1998 से तृतीय श्रेणी के सभी जिला परिषदों से विज्ञापन संख्या 6/98 में आवेदन मांगे गये जिसमें 10 राज्य, 10 जिला और 5 ग्रामीण के बोनस अंकों का प्रावधान रखा गया। सभी जिला परिषदों में 28.06.1998 से 30.06.1998 तक साक्षात्कार लिये गये, जिसमें एक अभ्यर्थी ने एक से अधिक जिला परिषदों में आवेदन किया। उस समय 7780 पदों की संख्या थी, बाद में राज्य सरकार द्वारा 29.06.1998 के आदेश से पदों को दुगना कर दिया गया। 01 जुलाई, 1999 को 4000 आवेदकों को नियुक्ति दे दी गयी, जो सिलसिला 2002 तक जारी रहा। इसी दौरान बोनस अंकों को लेकर 10 अक्टूबर, 1999 को उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया कि बोनस अंक अवैध, ज़िले और ग्रामीण। माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि ज़िले व ग्रामीण के बोनस अंक के आधार पर आप राजस्थान के मूल निवासियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, 13 नवम्बर, 1999 के बाद भी विभिन्न जिला परिषदों ने नियुक्तियां जारी रखीं जिनमें करीब 1800 नियुक्ति ही हैं जिसको 5 मार्च, 2005 के पत्र में प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा ने भी स्वीकार किया है।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): 01 जुलाई, 2003 व 1 मार्च, 2006 को राज्य सरकार ने इन आवेदकों को नियुक्ति देने के आदेश जारी किये, जिनकी क्रियान्विति आज तक नहीं हुई। 21 जून, 2008 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ जी ने नियुक्ति की अभिशंसा की। 2018 में मंत्रिमंडलीय उप समिति ने सैद्धांतिक सहमति देते हुए 20 दिन में निस्तारण कर नियुक्ति मार्ग प्रशस्त करने को कहा। आज तक नियुक्ति नहीं मिली। यह युवा आज 21 वर्ष बाद भी वर्तमान सरकार से आशा रखते हैं। इनको न्याय उपलब्ध कराना राजस्थान सरकार का दायित्व है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): एक पाइंट और है। मैं उच्च शिक्षा के बारे में बात करना चाहूंगी। राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में परीक्षा

(श्रीमती इन्द्रा)

नियंत्रक, सब रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, इनके कुल 80 पद हैं और सभी पदों पर अधिकारी व कर्मचारी काम कर रहे हैं। आज तक इन कर्मचारियों को यू.जी.सी. का वेतनमान नहीं मिला है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): सभी मानसिक पीड़ा में हैं। अत: उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि इन मांगों पर सदन में अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

श्री सभापति: विराजिए। श्री किसनाराम विश्नोई।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): एक कमेटी का गठन कर निर्धारित समयावधि में रिपोर्ट देकर इनको यू.जी.सी. वेतनमान का लाभ मुहैया कराएं। सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): सभापति महोदय, मांग संख्या 24 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शिक्षा, संस्कृति और कला पर चर्चा हो रही है। आज देश आजाद हुए 72 साल हो गये।

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): एक जमाना वह भी था, आज से 40-45 साल पहले जिस क्षेत्र में, जिन ढाणियों में हम लोग रहते हैं वहां कोई डाक आती थी, परिवार का कोई आदमी सेना में...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, वक्ता बोल रहे हैं, उनके सामने नहीं आएं।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): तो उस परिवार का मुखिया, मां-बाप, भाई वह पत्र पढ़वाने के लिए गांव-क़स्बे में जाते थे कि मेरे बेटे का पत्र आया है इसको पढ़कर मुझे सुनाओ, इसमें क्या लिखा है, मेरे बेटे का क्या समाचार है, क्या हाल चाल है।

आज देश आजाद हुए 72 साल हो गये, देश 21वीं सदी में जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास हुआ है। राजस्थान में शिक्षा के नये-नये आयाम स्थापित किये गये। शिक्षा के नये-नये नवाचार लाए गये। नये-नये तरीके से, आधुनिक तरीके से राजस्थान में शिक्षा का आयाम स्थापित हुआ।

(श्री किसनाराम विश्नोई)

सभापति महोदय, सब माननीय सदस्यों ने चर्चा की। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। मैं जोधपुर ज़िले के लोहावट विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। यह क्षेत्र हरियाणा के पूर्व मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल की जन्म स्थली, स्वर्गीय परसराम मदेरणा की जन्म स्थली, स्वर्गीय नरपतराम बरवड़ की जन्म स्थली, स्वर्गीय खेतसिंह राठौड़ की जन्म स्थल रही है। उस विधान सभा क्षेत्र में तीन तहसील, तीन पंचायत समिति, तीन उप तहसील हैं, लेकिन आज तक महाविद्यालय नहीं खुल पाया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री से भी निवेदन करना चाहूंगा कि लोहावट विधान सभा मुख्यालय पर महाविद्यालय की स्थापना करायी जाए।

मेरा विधान सभा क्षेत्र छितराई ढाणियों में बसता है। छितराई ढाणियों में आबादी के अनुरूप कांग्रेस सरकार ने 2008, 2013 में, 1998 से 2003 के बीच स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोलीं। वह पाठशालाएं धीरे-धीरे पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर 28 हजार से ज्यादा स्कूलें मर्ज के नाम से बंद कर दीं जबकि छितराई ढाणियों में बच्चा आता है, आप निरीक्षण करने जाते हो, एक ढाणी दूसरी ढाणी से पौन किलोमीटर, एक किलोमीटर दूर होती है, वहां बच्चे आते हैं। आज भी वहां नामांकन है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि वह प्राइमरी स्कूल जो मर्ज हो गयी थी, वापस वरीयता के आधार पर, मैरिट के आधार पर चालू की जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में सीनियर स्कूल है। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में 10 पंचायत समिति मुख्यालय भी ऐसे हैं जहां अभी तक सीनियर स्कूल नहीं खुल पायी है। प्राइमरी स्कूल को आठवीं तक करने की बहुत महती आवश्यकता है, क्योंकि छितराई ढाणियों का इलाका है। साथ ही गुणवत्तापूर्ण जैसे राजीव गांधी जी का टैक्नोलोजी का सपना था...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): टैक्नोलोजी का जमाना है, कम्प्यूटर का जमाना है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी को सुझाव है कि जिस तरीके से आज गांव और ढाणी में, स्कूलों में, नौजवान पढ़कर तैयार होता है वह शारीरिक दक्षता में परिपूर्ण है। शहरों में उसके मुकाबले कोई

(श्री किसनाराम विश्नोई)

परिपूर्ण नहीं हो सकता इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेल को बढ़ावा दिया जाए ताकि ग्रामीण प्रतिभा खेल जगत में अपना नाम रोशन करे।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): बहन कृष्णा पूनियां ने जिस तरह से गांव-ढाणी से आकर अपना नाम पूरे देश में, ओलम्पिक में कमाया, उस तरह से प्रतिभाओं की पूरे क्षेत्र में कहीं कमी नहीं है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि खेल के क्षेत्र में भी आप संसाधन को बढ़ावा दें।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): साथ ही प्रधानाचार्य के, प्रधानाध्यापक के, फर्स्ट-ग्रेड के, सब रिक्त पड़े पदों को भी भरने की कृपा करें। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह आग्रह करना चाहूंगा। साथ ही साथ प्राइमरी के सभी स्कूलों को भी, जहां छितरी ढाणियों में आज भी गांवों में स्कूलों की कमी है, वहां नये स्कूल भी खोलें। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला, संस्कृति, मैं सोचता हूं कि जब से देश आजाद हुआ, सबने प्रयत्न किया कि देश में शिक्षा का स्तर धीरे-धीरे आगे बढ़े। किसी ने कम किया होगा, किसी ने ज्यादा किया होगा लेकिन इसके बिना देश का कोई भविष्य नहीं है। मैं कुछ उन बातों पर आज ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं कि राजस्थान में निजी शिक्षण संस्थाओं के द्वारा देश की आजादी के पहले से ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। आपस में वार्ता नहीं करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जिन लोगों ने विद्यालय प्रारम्भ किये, उसके पीछे उनका कोई उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था। केवल और केवल सेवा भाव से और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिये प्रयत्न करने वाले

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लोगों ने जिन विद्यालयों को खोला, वर्षों तक जिन्होंने सेवा की, अपना स्तर भी बनाये रखा और अपनी ईमानदारी भी बनाये रखी लेकिन दुर्भाग्य से अनुदानित संस्थाओं और उनके अन्दर रहने वाले टीचर्स, जो सरकार के द्वारा 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत, 90 प्रतिशत से अनुदानित थे उनकी प्राब्लम्स को सुलझाते-सुलझाते हमने 2012 में एक निर्णय ले लिया कि जितने भी अनुदानित अध्यापक हैं, उनको हम सरकार में खपा लें। उसके बाद वे विद्यालय उनके भरोसे छोड़ दें। मैं जो आपको फीगर बता रहा हूं आज भी राजस्थान में जितने सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ रहे हैं, लगभग उतने के उतने बच्चे निजी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहे हैं। ये अपने माध्यमिक विद्यालय हैं, 2018-19 की जो आपकी प्रगति रिपोर्ट है, राजकीय विद्यालय हैं 3441, और गैर राजकीय, अर्थात् प्राइवेट 7975 स्कूल हैं। इसी तरह से आपके उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सरकारी विद्यालय 10992 हैं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ये आंकड़े प्रतिवेदन में हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): प्रगति रिपोर्ट में है यह बात?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हां, प्रगति प्रतिवेदन में है। आपके प्रगति प्रतिवेदन से ही मैंने लिये हैं। जो आपने मुझे किताब दी, उसी से मैंने आंकड़े निकाले हैं। उसमें राजकीय विद्यालय हैं 10992 और जो गैर सरकारी विद्यालय 10+2 हैं, वे 7555 हैं। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो राजकीय विद्यालय 14433 हुए और गैर राजकीय 15730 हुए। मेरा कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में आज भी शिक्षा को, सरकार जहां अपनी ओर से शिक्षा की व्यवस्था कर रही है, उतने के उतने बच्चों को, संख्या में कुछ कम-ज्यादा हो सकते हैं लेकिन उतनी की उतनी शिक्षा निजी शिक्षण संस्थाएं दे रही हैं।

प्राइवेट संस्थाओं के बारे में हमारी जो सोच है, केवल उनसे है जो सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त हैं या जिन्होंने अपने आपको अंग्रेजी माध्यम से डाला है, वहीं लेन-देन का धंधा है और वहीं पैसा कमाने का धंधा है। जिन्होंने केवल शिक्षा के लिये संस्था चलाई थी, उन संस्थाओं का यह एटीट्यूड नहीं था

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेकिन जब से हमने सारी अनुदानित संस्थाओं को खतम करने का निर्णय किया, तो हमारे यहां जो विद्या भवन है, जो मोहन सिंहजी मेहता ने बनाया, वह अब जर्जर हालत में आ गया। ऐसे अच्छे से अच्छे विद्यालय, जो देश की आजादी से पहले शुरू हुए क्यों? क्योंकि अब हम उनको कोई अनुदान नहीं देते हैं। जब अनुदान नहीं देते हैं तो उनको स्वयं की अपनी फीस के आधार पर अपने टीचर्स को पेमेंट करना पड़ता है। इससे स्थिति क्या हुई है कि वे कितनी भी कोशिश कर लें, मान लो तीन सौ रुपये पर-स्टूडेंट भी महीने की अगर फीस लगा लें, जो सामान्यत: हिन्दी स्कूलों में नहीं मिलती है, तो टोटल कलेक्शन ही उस सैक्शन से 10-11 हजार आता है। अब उस 10-11 हजार में अध्यापक को रख करके अपनी शिक्षा को कैसे मेन्टेन करेगा। उसके कारण से जो अच्छे विद्यालय थे, किसी जमाने में, आज अनुदान से हटाने के कारण से वे सारे के सारे संकट में आ गये, एक।

दूसरा नुकसान एक और हुआ इसके कारण से, वह यह हुआ कि टीचर्स की सैलरी, मैं सोचता हूं कि आज आप निजी शिक्षण संस्थाओं में 90 प्रतिशत संस्थाओं को दिखवाइये, तो कई स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें मिनिमम वेज भी टीचर को नहीं मिलता है। मैं आपको कह रहा हूं, आप इसको गहराई से लेना। मिनिमम वेज भी आज उस टीचर को नहीं मिलता है जो एक मजदूर को मिलता है। कई बार तो, गांवों की स्थिति ऐसी है, क्योंकि गली-गली में लोगों ने स्कूल तो खोल दिया, लेकिन उस गली-गली में चलने वाले स्कूल में ढाई हजार, तीन हजार, साढ़े तीन हजार रुपये की सैलरी में हमारी पढ़ी-लिखी बहनें या कोई वहां काम करती हैं। मैं चाहता हूं, इस बारे में गहराई से सोचकर कोई कानून लाने की आवश्यकता है। जब हम मजदूर को प्रोटेक्ट करते हैं कि मिनिमम वेज तो कम से कम इसको मिलेगा, वैसे ही कम से कम अध्यापक को भी, चाहे वह कहीं भी पढ़ाये, चाहे कैसे भी पढ़ाये, उसकी भी तनख्वाह का कोई प्रोटेक्शन तो होना चाहिए। आज उसकी मजबूरी है कि वह वहां गया और उस समय एडेड स्कूल था तो थोड़ा-बहुत पैसा उसको ठीक मिल जाता, क्योंकि आधा पैसा तो, 90 प्रतिशत में से, 80 प्रतिशत आप दे देते, आधे टीचर्स की तनख्वाह उससे मिल जाती। आधे टीचर्स की, जो फीस उनके पास आती, उनको बांट करके उनको दे देते। अब वह सारे के सारे विद्यालय एक तरह से मरणासन्न स्थिति में जा रहे हैं। मैं सोचता हूं इस बारे में आपको गहराई से विचार करना चाहिए कि इन संस्थाओं को हमको प्रोटेक्ट करना है और अगर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वह टीचर प्रोटेक्ट नहीं होगा, जो बड़ी भारी, लाखों की तादाद में, लगभग डेढ़ लाख शिक्षक आज भी निजी शिक्षण संस्थाओं में काम कर रहे हैं, उनको भी उनका बेहतर जीवन कैसे मिले, उसके बारे में भी गहराई से विचार करना पड़ेगा।

मैं आपको कुछ फीगर दे रहा हूं। कई बार अपने दिमाग में यह गलतफहमी है कि सरकारी विद्यालय आकर्षण का केन्द्र नहीं हैं। नहीं, जब से आपने अध्यापक ठीक प्रकार से लगाये हैं, जब से आपने संस्था प्रधान लगाये हैं, जब से आपके स्कूल में आये हैं, आपकी निरन्तर संख्या सरकारी स्कूल में बढ़ती जा रही है। ये आंकड़े, आपकी किताब में से निकाले हैं, उसी में से मैं आपको बता रहा हूं। इसलिये यह जो दिमाग में बैठ गया, मैं आज भी आपको गारंटी से कहता हूं कि जो गवर्नमेंट में हमारे पास टीचर हैं, वह नम्बर एक का टीचर है, जो मैरिट के आधार पर सलैक्ट हुआ है। जितनी भी निजी शिक्षण संस्थाएं हैं, जो बचा-खुचा माल है वह उनके पास है। हमारे पास बैस्ट माल उपलब्ध है। इस कारण से, पिछले कुछ समय से, क्योंकि 51-52 प्रतिशत हमारा रिक्त स्थान रहेगा तो पढ़ाई होने का सवाल भी क्या। आप प्रतिशत देखिये। लेकिन जब से हमने टीचर लगाने का काम किया। अब आप में से कई लोग बड़े नाराज हो रहे हैं कि हमने स्कूल बंद कर दिये, स्कूल बंद कर दिये। भगवान के लिये ईमानदारी से बोलना, जिसमें जीरो बच्चे हैं उस स्कूल को जिंदा रखने का मतलब मास्टर के कारण से जिंदा रखना चाहते हो। जिस स्कूल में बच्चे ही केवल 15 हैं, ऐसे 4000 से अधिक स्कूल हैं। आपके पास भी जो 20 हजार स्कूल हैं, इसमें कुल ही बच्चे एक से ले करके 30 तक हैं। मैं सोचता हूं, जहां दूरी है, आपके नियम के हिसाब से कि एक किलोमीटर में बच्चे को पढ़ने का स्कूल मिलना चाहिए, आपके नार्म्स के हिसाब से है उनको आप फिर से खोल दीजिये। कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक ही गांव में एक इस मौहल्ले में स्कूल चल रहा है, एक उस मौहल्ले में चल रहा है। एक बालिका का प्राइमरी स्कूल उस मौहल्ले में, लड़कों का प्राइमरी स्कूल यहां, एक सैकण्डरी स्कूल लड़कियों का यहां, और एक लड़कों का 10+2 यहां, एक गांव में, एक पंचायत में जहां चार-चार स्कूल हैं, उसकी कोई उपयोगिता है क्या? अगर उपयोगिता नहीं है तो उस मेन-पावर का उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर मेन-पावर का उपयोग करके, आज आपकी यह जो संख्या ठीक है, उसका कारण यह है कि यह जो 22 हजार स्कूल बता रहे हैं, इनके जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

टीचर्स सरप्लस हुए, उन टीचर्स को हमने उन स्कूलों में भेजा, जहां उनकी आवश्यकता थी। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि आपने अपने घोषणा पत्र में घोषणा कर रखी है, आप 22 हजार खोलना चाहो या 25 हजार खोलो, हमारे कोई समस्या नहीं है।

(20.39 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन आखिर हमारे पास अध्यापक आएगा कहां से। आखिर हम अध्यापक की पूर्ति कहां से करेंगे। हमारा बजट अपने-आपमें लिमिटेड है। बजट तो आपने बताया सारा का सारा 8 और 10 प्रतिशत, इस 8 और 10 प्रतिशत के बजट में क्या आप वापस यूं ही नये टीचर को भर्ती करोगे तो आप इसकी तनख्वाह भी नहीं दे पाओगे। या तो आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा या कुछ और करना होगा। अब मैं आपको थोड़ा फीगर बताता हूं। सरकारी स्कूल की निरन्तर जो संख्या बढ़ रही है, यह आपको और मुझे इस बात का संतोष देगी कि सरकारी विद्यालय में भी आकर्षण बढ़ा है।

मेरे पास फीगर है 2015 से। माध्यमिक स्कूल में जो परीक्षा में बैठे हैं वर्ष 2015 में बैठे हैं 4 लाख 52 हजार 252 बच्चे और उसके बाद 2016 आया तो यह बच्चे बढ़कर, यह मैं सरकारी विद्यालय के आंकड़े बता रहा हूं वह 4 लाख 64 हजार हो गये। उसके बाद 2017 में मैं देख रहा हूं तो 5 लाख 4 हजार बच्चे हो गये और उसके बाद 2018 में देख रहा हूं तो 5 लाख 32 हजार बच्चे हो गये। इसका मतलब सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। इसके कम्पेरिजन में मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं, जब तक हम अपने दिमाग को ठीक तरह से नहीं बनाएंगे] शिक्षा में कभी भी मैं सोचता हूं कि निजी शिक्षण संस्थाएं जहां 2015 में बच्चे बैठे थे दसवीं के तो 6 लाख 11 हजार बैठे थे और उसके बाद आपने 2016 में देखा तो इसमें बच्चों की संख्या घटी है, 5 लाख 79 हजार 801 बच्चे बैठे थे। उसके बाद 2017 में 5 लाख 79 से फिर घटा है, 5 लाख 50 हजार बच्चे बैठे हैं और उसके बाद 2018 में 5 लाख 20 हजार बच्चे बैठे हैं। यह दोनों आंकड़े मैंने आपको इसलिए रखे हैं कि सरकारी विद्यालय में आकर्षण बढ़ा है। सरकारी विद्यालय में अब बच्चे ज्यादा आ रहे हैं। प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम हो रही है] इसका मतलब निश्चित रूप से अगर हमें प्राइवेट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विद्यालय पर कंट्रोल करना है तो अपनी दुकान को सजाना पड़ेगा। अपनी दुकान सजेगी तो प्राइवेट दुकान को अपने आप काबू कर लोगे लेकिन अपन उलटा सोचकर बातें कर रहे हैं। इसी तरह से आपने देखा, उच्च माध्यमिक का भी मैं फीगर बताता हूं। मैं यह इसलिए आपको बता रहा हूं कि वर्ष 2015 में जो बच्चे हमारे पास बैठे थे टेन प्लस टू में, वह 2 लाख 90 हजार 129 बच्चे थे और उसके एकदम 2 लाख 90 हजार से कम हुआ 2 लाख 84 हजार हो गया। उसके बाद फिर अपना राजकीय विद्यालय में 12वीं में यह एकदम घटकर यहां 3 लाख 61 हजार आया। फिर इसके बाद 3 लाख 60 हजार है और फिर वापस कम हुआ है तो फिर मतलब निरंतर हमारे बच्चों की संख्या टैन प्लस टू में भी सरकारी विद्यालय में बढ़ी है, ठीक उसी तरह से प्राइवेट की घटी है। यानी, प्राइवेट में पहले वाले में 2015 में 4 लाख 97 हजार बच्चे थे, 2016 में आपके 4 लाख 90 हजार हो गये, सात हजार बच्चे कम हुए। उसके बाद 2017 में केवल 4 लाख 80 हजार, एकदम घटकर आया और उसके बाद अभी 4 लाख 39 हजार है। इसका मतलब फिर 40 हजार बच्चे कम हुए हैं। इसका मतलब, परीक्षा में बैठने वाले फीगर यह बता रहे हैं कि वर्ष 2015, 2016, 2017 और 2018 में सरकारी विद्यालय की तरफ आकर्षण बढ़ा है, प्राइवेट विद्यालय में संख्या कम हुई है। इसका मतलब यह है कि हम अपने विद्यालयों को अध्यापक की दृष्टि से परिपूर्ण करें, सब्जेक्ट टीचर की दृष्टि से परिपूर्ण करें तो शायद हम इसका लाभ ले सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस बात के गवाह हैं कि राजस्थान ने साक्षरता को बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किया, उसके कारण से आप पुरस्कार लेने गये थे। जब अपनी 2011 की जनगणना हुई थी उसमें राजस्थान ने साक्षरता की दृष्टि से अपने आपको एकदम आगे बढ़ाया। मैं इसलिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि प्रयत्न नहीं हुआ है। यानी, हमारी 1951 में राजस्थान की साक्षरता थी 8.95 परसेंट, आप 9 मान लीजिए और हमारी महिला साक्षरता थी 3 प्रतिशत। यह वर्ष 1951 की जनगणना है, उसके बाद आपने देखा कि निरंतर आते-आते 1991 में 38 परसेंट की साक्षरता पर राजस्थान आया है और उसमें महिला साक्षरता अपनी 20 परसेंट थी लेकिन 1991 से लेकर 2011 तक जो विभिन्न प्रकार के प्रयोग साक्षरता को बढ़ाने के लिए किये, उनके बारे में मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, उसके कारण से राजस्थान

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

देश में पहला नम्बर बना। 2001 में जो साक्षरता की, मैं 1991 की बता रहा हूं 38 परसेंट और 2001 में जब हुआ तो वह 60.40 परसेंट अर्थात्, जो साक्षरता का परसेंटेज हमारा बढ़ा वह लगभग 20 परसेंट, सारी, 22 परसेंट के लगभग साक्षरता अपनी राजस्थान की बढ़ी तो यह जो राजस्थान में साक्षरता बढ़ाने का और उसके बाद में अभी 2011 में 60 परसेंट से अपन 66 परसेंट पर आए और महिला साक्षरता में भी हम हिन्दुस्तान की साक्षरता के नजदीक जा रहे हैं। यानी, हिन्दुस्तान की साक्षरता महिलाओं की 64 परसेंट है और हमारी साक्षरता 52 परसेंट है। कभी हम 3 परसेंट पर थे और हमारा इतना बड़ा गैप था जो हमने कवर किया। इसका मतलब है कि प्रयत्न हुआ है प्रदेश में साक्षरता को बढ़ाने की दृष्टि से। अब इसमें कई प्रकार के प्रयोग, 1994 में जब मैं शिक्षा मंत्री था, भैरोंसिंहजी दिल्ली की एक बैठक से लौटकर आए थे और रात को मुझे 11.00 बजे बुलाया। कहा कटारियाजी, मैं उस बैठक में अपने आपको इतना अपमानित महसूस करके आया हूं कि आपका राजस्थान साक्षरता की दृष्टि से बहुत पीछे है, आप बहुत पीछे हो तो उन्होंने कहा कि आप चाहे जो करें, मैं आपको पूरा बजट इस साल का, 1994-95 का शिक्षा को समर्पित करता हूं और जरूरत पड़ेगी तो मैं दुनिया में जहां-जहां भी राजस्थानी रहता है, उससे मांगकर भी लाऊंगा, पर इस कलंक से किसी तरह से हमको आप बाहर निकालो। हमारी शिक्षा का जो स्तर है और विशेषकर बालिका शिक्षा में हम 20 परसेंट होकर सबसे नीचे पायदान पर हैं, इसको आप निकालने का प्रयत्न करो। मैं सोचता हूं कि वर्ष 1994 का जो बजट पेश हुआ था, उस बजट में आपने देखा होगा कि हमने बच्चियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पाठ्यक्रम की मुफ्त पुस्तकें छपवा कर दीं पहली से लेकर आठवीं तक। पहली से लेकर पांचवीं के बच्चों को मुफ्त किताबें कीं और उसके बाद फिर वर्ष 2003 और 2008 में हम जब आए तो हमने इसको फिर बढ़ाई। मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करके सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले सारे बच्चे यानी, पहली से लेकर बारहवीं तक के बच्चों को मुफ्त किताबें सरकार की तरफ से छाप कर दीं जिसके कारण से बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए।

मैं सोचता हूं, इसी तरह से आपने देखा होगा कि हमने बिना राजनीतिक भेदभाव के, अगर आप चाहें तो प्रोसीडिंग निकाल लेना, यहां पर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रतिपक्ष के नेता परसरामजी मदेरणा बैठे हुए थे, उनका भाषण निकालकर देखना। उन्होंने कहा कि यह पहली बार, मेरा इतना लंबा राजनीतिक जीवन है लेकिन स्कूलों का खोलने का जो मापदंड और क्राइटेरिया बनाकर आपने खोला है, उसके कारण से मेरे स्वयं के विधान सभा क्षेत्र में इतने सालों में जितने स्कूल नहीं खुले उतने एक साथ खुल गये। क्योंकि हमने नीतिगत यह फैसला किया था कि जो भी रेवेन्यू विलेज है, जिस रेवेन्यू विलेज की आबादी 250 है वहां पर प्राइमरी स्कूल होगा। एक ही कलम से, न किसी को देखा कि कौन एम.एल.ए. है कि कौन नहीं है, एक ही आधार से किया और हर पंचायत में जहां पर आठवीं का स्कूल उस समय तक नहीं बना था, हमने एक कलम से बिना गांव का नाम और पता पूछे आठवीं का स्कूल खोला। उधर किताबें देना शुरू किया और इधर स्कूल खोला। वर्ष 2003 और 2008 में वसुन्धराजी से हमने आग्रह किया तो उन्होंने एक साथ जितनी भी पंचायतें दसवीं के स्कूल से वंचित थीं उनको किया और अभी आपने देखा होगा कि वर्ष 2013-14 से लेकर 2018 तक में एक स्ट्रोक से, आज दिन तक यह कभी नहीं हुआ होगा कि हमने 5300 सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलकर बच्चों को लाने का प्रयास किया। यह बच्चे हैं तो राजस्थान के हैं। यह न तो बी.जे.पी. के हैं और न यह कांग्रेस के हैं। यह जो दिमाग में चश्मा लगाकर करते हैं न, जहां पर आवश्यकता है, उस आवश्यकता के आधार पर हमको निश्चित रूप से चलना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में ऐसा लगता है कि हम यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं।

हम लोगों ने उस समय एक कोशिश की थी, बालिका फाउंडेशन बनाया था। उसमें 1 करोड़ रुपया सरकार ने डाला और कुछ दानदाताओं से भी पैसा लेकर बालिकाओं को स्कूल की तरफ आकर्षित करने के लिए हमने तरह-तरह की योजनाएं बनाई थीं, उसमें यह मुफ्त पाठ्य पुस्तकें भी थीं।

गार्गी पुरस्कार जो हमने शुरू किया था, यह उसी समय शुरू किया था। यानी, जो भी बच्ची आठवीं में अपनी पंचायत समिति में हाइएस्ट नम्बर लेकर आएगी उसको हम दो साल तक का वज़ीफ़ा 9वीं और 10वीं का पढ़ने का देंगे एक-एक हजार रुपया। इसी तरह से 10वीं की जो बच्ची 75 परसेंट से अधिक लेकर आएगी उस बच्ची को भी हम दो साल का 11वीं और 12वीं का और इसी तरह से 12वीं वाली बच्ची को भी देना शुरू किया। केवल 2015 के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आंकड़े ही मेरे पास हैं। क्योंकि आपकी प्रगति रिपोर्ट में वहीं तक है, उसके आगे मैं नहीं जा पाया। यानी, मैं सोचता हूं कि यह जो गार्गी पुरस्कार है वर्ष 2015-16 में जिन छात्राओं को दिया था, वह है 39 हजार 543 और पैसा हमने उसमें दिया था 11 करोड़ 86 लाख। उसके बाद 2016 में यह बच्चियां बढ़कर हो गयीं 57598 और हमारा जो पैसा गया उन बच्चियों को वह 17 करोड़ 27 लाख रुपया गया। उसके बाद वर्ष 2017-18 में इन बच्चियों की संख्या हुई 72547 बच्चियां जो 75 परसेंट से अधिक नम्बर लेकर आईं और उसमें हमारा अमाउंट गया 21 करोड़ 76 लाख। उसके बाद वर्ष 2018-19 में, यह जो अभी परीक्षा 2018-19 में हुई उसमें 75717 लड़कियां 75 परसेंट से अधिक नम्बर लेकर आयीं और उसके कारण से उनको हमने 22 करोड़ 66 लाख रुपया दिया। इस गार्गी पुरस्कार से भी बच्ची को स्कूल की तरफ आकर्षित किया और उसके आगे की पढ़ाई की व्यवस्था की।

आपने अभी जो 28 तारीख को भामाशाह सम्मान समारोह किया, यह राज्य स्तर पर उस समय 1994 में जब मैं शिक्षा मंत्री था, तब मैंने इसको प्रारम्भ किया कि हमारे दानदाता स्कूलों में कमरे बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, सब बनाते हैं, इन लोगों को बुलाकर सम्मानित करें तो इनसे हम अधिक से अधिक उस समय लाभ ले सके। आज तो अपनी कई स्कीम्स आ गयीं जिन स्कीम्स के तहत भी अपने को कमरे बनाने, बाकी में कुछ मिलने लग गया लेकिन उस समय कुछ नहीं मिलता था तो मैं सोचता हूं कि आपका भामाशाह सम्मान समारोह, मेरे पास 2015 के बाद के यह आकड़े हैं, यह चालू तो किया था हमने वर्ष 1994-95 से, तब से लेकर यह निरंतर चल रहा है। 28 जून के दिन, भामाशाह जयंती के दिन, तो 2015 में आपने 77 भामाशाहों का सम्मान किया और 20 करोड़ 24 लाख रुपया आपको मिला था दानदाताओं के द्वारा। उसके बाद आपने 2016 में किया तो 62 को किया और 27 करोड़ 40 लाख रुपया मिला। उसके बाद आपने 2017 में किया, उसमें 109 लोगों को सम्मानित किया और 62 करोड़ रुपया दानदाताओं के द्वारा सरकारी विद्यालयों में काम करने का पैसा मिला। इसके बाद 2018 का अभी आपने मनाया है, वह 116 लोगों का सम्मान किया और 81 करोड़ 51 लाख रुपया राजस्थान के दानदाताओं ने इन विद्यालयों में विभिन्न प्रकार का सहयोग किया तो हमने कोशिश की विद्यालयों के साथ समाज के लोगों को भी जोड़ने की।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विद्‌यार्थी सुरक्षा बीमा भी, हमारे उस समय कभी यह दिमाग में नहीं था कि नेहरू जी के जन्म-दिन पर नहीं करें। यह पता नहीं आपके दिमाग में क्यों आ रहा है इस कारण से। मैंने स्वयं ने सारे 80 लाख बच्चों का बीमा कराया, जो आपके स्कूल में पढ़ते थे और सारे बच्चों की किश्त सरकार की तरफ से उस समय 25 लाख रुपया जमा कराते थे ताकि किसी भी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको एक लाख रुपया मिलेगा। उसको और किसी प्रकार का नुकसान हो जाए तो उसको मिलेगा। उसके तहत हमने निरन्तर बच्चों का एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, 2014-15 में हमने 5 करोड़ 22 लाख रुपया उन बच्चों के परिवार वालों को दिया। उसके बाद 2015-16 में 5 करोड़ 20 लाख दिया, 2016-17 में 5 करोड़ 21 लाख दिया, 2017-18 में भी 5 करोड़ 21 दिया। यह जो पैसा है हमने उनकी इंश्योरेंस स्कीम बनाने का भी काम किया कि चलो, इस कारण से बच्चों का ठीक प्रकार से इश्योरेंस हो।

मैं सोचता हूं हमने एक नहीं, इस प्रकार से अनेक प्रयोग किये जिसके कारण से शिक्षा का किसी प्रकार से स्तर बढ़े। अब मैं बार-बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैंने प्रयत्न किया, लेकिन कई अड़चनें आती हैं। जब तक ट्रांसफर पालिसी नहीं बनेगी, यह विभाग कभी नहीं सुधर सकता। चाहे आप हों, चाहे मैं हूं, चाहे किसी को भी बना देना, जब तक आप एजुकेशन में ट्रांसफर पालिसी नहीं बनाओगे, हमारा आधा समय इसी में बर्बाद हो जाता है। हम सब लोग भीड़ से ही घिरे रहते हैं। न सोच सकते हैं, न दिमाग लगा सकते हैं। हमारे लिये सब अध्यापक बराबर हैं। जो हमारी नीति में जहां आएगा, जिसको जाना होगा, वहां चला जाएगा। जब सब लोग जाएंगे तो कोई किसी से नाराज नहीं होगा। लेकिन चूंकि मेरी बच्ची तो उदयपुर में ही नौकरी करेगी, तो पड़ौसी को भी ध्यान में आएगा कि गुलाबजी की बच्ची उदयपुर में कर सकती है तो मेरी क्यों नहीं करे। आदमी के मन में यह नये-नये विचार पैदा होते हैं और मैं इसलिए बार-बार प्रयत्न करता हूं। मैं सोचता हूं हमने जितनी भी सारी ट्रांसफर पालिसियां, हिन्दुस्तान के विभिन्न राज्यों में हैं, उनको लाकर बनायी हैं और वासुदेव जी के टाइम में हमने इसको फाइनल स्टेज पर बनाकर, मेरे टाइम पर भी पहले बनायी, मैं तो कैबिनेट में भी ले गया। लेकिन केबिनेट में भैरोंसिंह जी ने कहा कि इतना तेज मत चलो, धीरे चलो। क्योंकि अपन राजनीति में करते हैं एकदम ऐसा मत कर दो जिसके कारण से हमारे हाथ में कुछ रहे ही नहीं और हम बिलकुल अपंग हो जाएं। उस कारण से वहीं अटकी रही। फिर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अब की बार भी प्रयत्न किया तो अटका मामला वहीं का वहीं। अपन कोई अधिकार छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि अपने पास जमा रहे न, कि मैं कुछ कर सकता हूं। मैं सोचता हूं भगवान के लिए कृपा करो मेहरबानी करो और कोशिश करो। यह ट्रांसफर पालिसी बनाओ जिसके कारण से हर टीचर को ज्ञात रहे।

अब की बार, पहली बार जितने भी नये बच्चे आये भर्ती होकर, उनको काउंसलिंग से हमने स्थान दिया, कोई नाराजगी नहीं हुई। अगर यह काउंसलिंग से नहीं देते तो एक-दूसरे के सिर फोड़ देते। मैं सोचता हूं काउंसलिंग से हुआ और किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। जहां स्थान बचा, जिसको जहां जाना है, वहां जाना है और उसको पूछकर कहा कि यह खाली है, अगर थोड़ी बहुत कोई बेईमानी की गुंजाइश रही, तो कुछ अच्छे स्थान थे, वह उन्होंने लिस्ट पर दिखाये नहीं, उसको बचाकर छिपाकर रख लिया, यह मन की कमजोरी है। जब कोई काम करते हैं तो सच्चे मन से करने का प्रयास करें तो समस्या का समाधान हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा फिर आपके माध्यम से मंत्रीजी और सारे लोग बैठे हैं, अगर वास्तव में शिक्षा विभाग को शिक्षा विभाग बनाना चाहते हो, तो इसका सबसे कमजोर पाइंट है ट्रांसफर। अभी शिकायत कर रहे थे, यह बात सच है। एक आदमी नौकरी वहीं लगता है और रिटायरमेंट भी वहीं से। वह गांव में आपको और मेरे को क्या गांठे, गांव की राजनीति तो वही करता है। वह अपनी दुकान पर भी जाता है और खेत पर भी चला जाता है। आप पूछो कि कहां गये, कि वहां गये। कई बार लोग मेरे से चिढ़ जाते हैं तो कहते हैं गुलाब जी, आप यह क्या बोलते हो? मतलब वह जीमने जाये तो हमारे खाते में, वह किसी के दाग में जाये तो हमारे खाते में, वह उसके परिवार का काम करे तो हमारे खाते में। तनख्वाह हमारी ले और बच्चों को न पढ़ाकर वह दूसरे कामों में लग जाए तो उसका कारण यह है कि वह लंबे समय तक एक जगह पर रहने के कारण से ऐसा करने लग जाता है। वह नहीं तो उसके लड़के को दुकान खुला देगा, दुकान नहीं तो उसको किसी दूसरे काम में लगा देगा, और किसी काम में लगा देगा। अगर आप इस ट्रांसफर पालिसी में मैक्सिमम पांच साल उसको जिंदगी में जहां रहना है, वह रहे, उसके बाद तो उसे जगह छोड़नी पड़ेगी। तब तो जाकर उसको काम करने की लगेगी और काम की गुणवत्ता के आधार पर भी ट्रांसफर पालिसी में विशेष स्थान दिया जाए। अगर वह 100

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रतिशत रिजल्ट दे रहा है तीन साल तक, तो निश्चित रूप से उसकी प्रायोरिटी बननी चाहिए कि वह जहां जाना चाहेगा, वहां हम अच्छे से अच्छे स्थान पर दे सकें।

मैं सोचता हूं आज की तारीख में सबसे बड़ी जो नाराजगी है, यह सीबीएसई से मान्यता प्राप्त जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, इनके यहां हम तो एक बार एन ओ सी दे देते हैं कि आप सीबीएसई हो जाओ, उसके बाद वह बिलकुल मुक्त हो जाते हैं। न तो आपका डिपार्टमेंट ध्यान देता है, जबकि आपके पास अधिकार है। ऐसा नहीं है आप वापस रिकमण्ड करें कि उनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, उनका काम ठीक नहीं है तो उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी लेकिन इसका प्रयोग कोई नहीं करना चाहता है। इसका जब तक प्रयोग नहीं करोगे तो आप यह जो चला है न, थैला भी यहीं से खरीदो, किताबें भी यहीं से खरीदो, हर चीज यहीं से खरीदो। मतलब यह जितनी भी संस्थाएं बनी हैं न, आज इस शिक्षा को किसी ने बिगाड़ने का काम किया है, इसको व्यवसाय किसी ने बनाया है तो इन संस्थाओं ने अपने व्यक्तिगत कारणों से बनाया जिसके कारण से शिक्षा जैसे पवित्र काम को भी लोग एक तरह से गिरी हुई निगाह से देखने लग गये। बाकी मैं सोचता हूं दुनिया में किसी का सम्मान किया हो आपने और मैंने, लेकिन हमारा गुरु कभी भी मिला होगा न, जिसने हमको पढ़ाया होगा, भले ही उसकी जूतियां फटी हुई होगी, भले ही उसकी धोती फटी होगी, लेकिन उसके प्रति मन में इतना आदर भाव रहता था कि दौड़कर उसके चरण छूने में अपने आपको भाग्यशाली समझते थे, क्योंकि वह गुरू था।

दुर्भाग्य यह है कि हमारे दोनों तरफ से कटौती हो गयी। एक तो उस गुरु ने भी अपने कर्तव्य को, जिस तरीके से वह हमको पालते थे, वह उसका नहीं रहा। अब तो घंटी बजती है और घर जाता है। घंटी बजती है, वह आता है। सवेरे बस से उतरता है और दौड़ता-दौड़ता हुआ स्कूल की सीढ़ियां चढ़ता है। अब स्कूल शुरू हो गया 7.30 बजे, स्कूल बस आयी 8.30 बजे, तो भी उसको कोई नहीं कहता, क्योंकि हैड मास्टर साहब स्वयं भी उसी बस से उतरकर देर से आये। कहां से व्यवस्था होगी? यह जो अप-डाउन वाली बीमारी है न, इस अप-डाउन वाली बीमारी के बारे में सोचो, तब जाकर आप यह शिक्षण की व्यवस्था ठीक कर पाओगे। नहीं तो अधिकांश लोग अप-डाउन के कारण से कितना कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं, मैं जो कह रहा हूं 100 प्रतिशत हो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जाए, लेकिन कहीं न कहीं इस पर हमको रैस्ट्रिक्शन लाने का प्रयत्न करना चाहिए।

एक जो सबसे बड़ी कमी है इस विभाग में निरीक्षण के बारे में कोई चिंता नहीं, कि विद्यालय अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई उसका निरीक्षण करने जाता है कि नहीं जाता है। हमारे पास इतना बड़ा मेन पावर है, अगर हम उस मेन पावर का उपयोग करें तो हर विद्यालय का साल में तीन बार निरीक्षण कर सकते हैं। आपके पास डीईओ की इतनी बड़ी संख्या है। अब तो आपके पास पंचायत समिति पर भी डीईओ लेवल का आदमी है। मैं सोचता हूं कि यह जो आपकी 400-500 की संख्या बनती है, आपके सारे विद्यालय मिलाकर 14 हजार हैं सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी, आप सैकण्डरी को छोड़ दो, हायर सैकण्डरी जितने विद्यालय हैं, यह जो 400-500 डीईओ हैं, जहां यह डीईओ हैं, उनके नीचे के पांच विद्यालय, छह विद्यालय छांटकर उसको दे दो कि साल में आपको तीन बार जाकर इसमें इंस्पेक्शन करना है और दिन भर इसकी रिपोर्ट बनानी है। मैं सोचता हूं उसमें जाएं। जितने प्रिंसिपल हैं उनको सैकण्डरी स्कूल दे दीजिए बांटकर कि इस प्रिंसिपल के नीचे यह दो स्कूल रहेंगे और उसके नीचे सैक्रेटरी वाला है, उसको पांच मिडल स्कूल आएंगे, छह मिडल स्कूल आएंगे, उनको दे दीजिए। 100 प्रतिशत आपका निरीक्षण का काम हो जाएगा और उसके आधार पर गुणवत्ता अपने आप बढ़ेगी।

मैं एक भंडारीजी के ट्रस्ट से कार्यक्रम करता हूं केवल सरकारी विद्यालय के बच्चों को, जिनके 80 परसेंट से अधिक नंबर आये। मैं उदयपुर जिले में लगभग 450 से लेकर 500 लड़के और लड़कियों को 80 परसेंट से अधिक, सरकारी स्कूल में और कई सरकारी विद्यालय की बच्चियां तो 96 परसेंट नंबर लेकर आती हैं। आज की तारीख में आपका जो रिजल्ट मेंटेन कर रही हैं न, वह आपकी सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी में पढ़ने वाली बच्चियां मेंटेन कर रही हैं। आपका जो लड़कों का स्कूल है, उसके रिजल्ट का एनालिसिस करोगे न तो आपको वह 50 परसेंट के आस पास मिलेगा, जबकि लड़कियों के स्कूल का रिजल्ट आपको 90-95 परसेंट मिलेगा। उसके दो कारण हैं। एक तो मां-बाप के दिमाग में ऐसा बैठ गया कि बच्ची को पढ़ाकर क्या करेंगे, इसलिए सीधा का सीधा सरकारी स्कूल उसके लिए एकमात्र स्कूल है और इसके कारण से टैलेंटेड बच्ची हमारे पास आती है। उन टैलेंटेड बच्चियों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

का हम उपयोग करते हैं तो परसेंटेज बढ़ता है। जो बाकी बचता है उसमें तो जिसकी मजबूरी है, वही बच्चा हमारे पास आता है तो उसके कारण से हम कितना भी प्रयत्न करें, कई बार लोग कहते हैं, सरकारी स्कूल का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। क्या अच्छा नहीं आता, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि सरकारी विद्यालय में वह सारे बच्चे आते हैं जो थर्ड डिवीजन हैं, जिनको लिखना आता है, जिनको नहीं लिखना आता है, उनको भी वह भर्ती करेगा। अब उसमें से वह छांटकर निकालकर अगर रिजल्ट मेंटेन करता है और सब के सब 80 परसेंट के बच्चों को एडमिशन देते हैं, फिर उसमें से अगर 100 प्रतिशत रिजल्ट दे दिया तो क्या कर लिया?

(21.00 बजे)

मैं सोचता हूं कि हमारे सरकारी स्कूल का अगर 70 परसेंट, 80 परसेंट भी रिजल्ट आता है तो इन प्राइवेट स्कूल से जो हंड्रेड परसेंट की डींग मारते हैं न, उनसे ज्यादा बैटर रिजल्ट अपना मानता हूं क्योंकि सब प्रकार के गरीब बच्चों को उठा करके देखता है लेकिन हमारे देखने का नजरिया ऐसा है सरकारी स्कूल के बारे में। हममें से कई लोगों ने ऐसे कहा कि सरकारी स्कूल में कोई पढ़ने का आकर्षण नहीं है, मैं सोचता हूं इस प्रकार के आकर्षण की बात नहीं है। मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज 18-19 विश्वविद्यालय तो हमारे हैं और लगभग 45 से 50 हमने निजी विश्वविद्यालयों को दिया। यह निजी विश्वविद्यालयों वालों को अचानक रात को क्या सपना आया कि इस पवित्र काम को करूंगा, इस पवित्र काम को करूंगा। समझ में आता है कि नहीं आपको? यह पवित्र काम करने के लिए आये हैं या धंधा करने के लिए आये हैं? कड़वे शब्दों में कह रहा हूं। ये सेवा करने आते न तो पहले ही आ जाते देश की आजादी के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में लेकिन अपने पास कुछ पैसा है, बिल्डिंग बना लेते हैं, कुछ आपके नोर्म्स पूरे कर देते हैं और उसके कारण से आपने इनकी संस्था को एक बार यहां बिल पास करा करके तो उनके सारे अधिकारी, सारे परिवार के लोग लगे हैं। कोई मां होगी, कोई बुआ होगी, कोई इधर का होगा, कोई इधर का होगा, सारी की सारी वह ही संस्था है और वह संस्था केवल और केवल डिग्री बांटने का काम कर रही है। इसका जब तक निरीक्षण नहीं करोगे न, तो सारा एजुकेशन नीचे बैठ जाएगा।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं आपको कहना चाहता हूं इन वर्षों में आपने जितनी पीएचडी दी हैं आपकी यूनिवर्सिटी की पीएचडी की संख्या को अलग रखो और इन विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री दी हुई संख्या को अलग रखो, आप देख करके हैरान हो जाओगे कि यह क्या है, पीएचडी की डिग्रियां इस तरह से जा रही हैं। कोई हिसाब-किताब भी है? इतनी बड़ी संख्या में पीएचडी की डिग्रियां जा रही हैं। केवल ये संस्थाएं कमाने के लिए, यहां से पीएचडी ले लो, यहां केवल एक बार एडमिशन में नाम लिखा जाओ और उसके बाद चाहे जहां घूमो, वापस आकर परीक्षा दे दो, कोई हाज़िरी की आवश्यकता नहीं, कोई काम की आवश्यकता नहीं। खोली, अपन ने अच्छी भावना से खोली कि राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़े, कोई हर्जा नहीं लेकिन इसका निरीक्षण करने के लिए तो कोई न कोई एजेंसी बनाओ, कोई न कोई इनको गवर्न कर सके या कोई न कोई इनको देख सके, इसके लिए आप कोई न कोई विधेयक लाकर, नियामक आयोग लाओ, चाहे कुछ भी लाओ लेकिन लाकर कम से कम इन विश्वविद्यालयों को कंट्रोल करने का प्रयास करना पड़ेगा। तब तो हम शिक्षा के स्तर को भी उठा लेंगे और मैं सोचता हूं उन लोगों को भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीधी लाइन में लाने के लिए मदद भी कर सकते हैं। जो खुल गयी वह तो खुल गयी, वह आपने भी खोली, हमने भी खोली, कोई चिंता की बात नहीं लेकिन जो खुल गयी है कम से कम उनको सिस्टम में लाने के लिए तो अपन प्रयत्न कर सकते हैं।

संस्कृत एजुकेशन के बारे में तो हालत बहुत ही खराब है। संस्कृत विश्वविद्यालय की तो मैं सोचता हूं आप विचार करो कि संस्कृत विश्वविद्यालय में आज कितना स्टाफ है और कितना होना चाहिए। कितना स्टाफ है? क्या विश्वविद्यालय चलेगा, कैसे विश्वविद्यालय चलेगा? एक कोई ब्रांच है उसकी उसमें तो जितने पद हैं उतने ही सब खाली हैं। अब मैं तो संस्कृत का बहुत ज्यादा विद्वान नहीं रहा हूं। हायर एजुकेशन में भी विशेष करके जो आपका आता है, हायर एजुकेशन में भी यही समस्या है। सभी विश्वविद्यालय इस समस्या से जूझ रहे हैं कि स्टाफ चाहिए। स्टाफ है नहीं। आपकी अपनी मजबूरी होगी, सरकार की अपनी मजबूरी होगी।

एक समस्या की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे विश्वविद्यालय में जो पेन्शन भोगी रिटायर्ड लोग हैं, वे बहुत परेशान हैं। मतलब कई बार जब दस-बीस लोगों का जुलूस लेकर के भी कलेक्ट्री पर आ जाते हैं तो उनकी उम्र

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और उनके हाथ-पैरों को देख करके बहुत शर्म लगती है कि आखिर इस आदमी को क्या जवाब दें। वह कहता है कि इस बुढ़ापे में क्या रोटी खाने का भी अधिकार नहीं है और यह पेन्शन हमें मिलनी चाहिए। हमने कोशिश की उदयपुर की दोनों यूनिवर्सिटी के लिए, हमने जमीन बेच करके भी उनका फंड बनाया लेकिन फिर भी वह पर्याप्त नहीं हुआ क्योंकि जमीनों का दाम घट जाने के कारण से जमीनें बेच करके भी हम उनको कोई फंड में डाल नहीं सके। इसके बारे में भी आपको विचार करना चाहिए कि आखिर उनको पेन्शन कैसे मिले, कहां से मिले, किस तरीके से मिले। भविष्य में तो 2004 से कानून बना दिया कि अब कोई नया पेन्शन का भार आप पर नहीं आएगा लेकिन 2004 के पहले से जो लोग हैं और जो पेन्शन के हकदार हैं उनको आपको पेन्शन तो देनी पड़ेगी।

मैं सोचता हूं यहां आपको यों गिनूं कि हमने यह किया नहीं किया। जो मैं आपको रिजल्ट बता रहा था यह पर-परसेंटेज, रिजल्ट भी आपको इस बारे में अपने आपमें बता देता है कि वास्तव में सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय में रिजल्ट का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे सरकारी विद्यालय में रिजल्ट बिलकुल ही खराब है। मैं आपको बता रहा हूं माध्यमिक विद्यालय में 2015 में हमारा रिजल्ट है 73 परसेंट और उसी साल का प्राइवेट विद्यालय का रिजल्ट है 82 परसेंट। फिर 2016 में हमारा 71 परसेंट और उनका 79 परसेंट। उसके बाद 2017 में हमारा 75 परसेंट, उनका 82 परसेंट और 2018 में हमारा सरकारी विद्यालयों का 77 रिजल्ट है, उनका 83 परसेंट। कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारा सरकारी विद्यालय कहीं कमजोर पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। इसी तरह से आप टैन प्लस टू का भी देखो, हमारा 2015 में 80 परसेंट रिजल्ट था और प्राइवेट विद्यालयों का 87 परसेंट। उसके बाद 2016 में हमारा रिजल्ट था 85 परसेंट और उनका था 89 परसेंट। उसके बाद 2017 में हमारा रिजल्ट था 88 परसेंट और उनका था 91 परसेंट और अब की बार हमारा रिजल्ट है 88 और उनका है 90 परसेंट। इसका मतलब हम लगभग उनके आस पास हैं। हमारे पास सब प्रकार के बच्चे आते हैं, उनके पास छंटे हुए बच्चे आते हैं, अच्छे परिवारों से आते हैं। घर के लोग भी चिंता करते हैं, हमारे यहां घर पर चिंता करने का समय किसके पास है। मजदूरी करके आता है, वह अपने बच्चों को शिक्षा में देख सके, स्वयं नहीं समझता है। इसका मतलब यह है कि हमारे सरकारी विद्यालय के अध्यापक जो काम कर रहे हैं, ठीक दिशा में कर रहे हैं। केवल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उनको और पुश करने की जरूरत है। ट्रैनिंग को आप सख्त करिये। जब तक किसी भी टीचर को साल में एक बार दस दिन का रिफ्रेशिंग कोर्स में जाकर वापस उसकी ट्रैनिंग करके अप टू डेट नहीं करें, तब तक हम शायद उस काम को नहीं कर पाएंगे।

अध्यक्ष जी, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है यह केवल राजनीति का मुद्दा नहीं बनाओ कि इन्होंने कितने लगाये और हमने कितने किये। इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे हो और आपके सरकारी विद्यालय सही दिशा में चल रहे हैं, उनको और संभाल करके उन टीचर्स का और हौंसला बुलंद करें। अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, मैंने उस समय किया था, जिसने तीन साल तक लगातार हंड्रेड परसेंट रिजल्ट दिया, मैंने व्यक्तिगत उस प्रिंसिपल को दस हजार रुपये का अवार्ड देकर सम्मानित करने का फंक्शन किया। मैं सोचता हूं कि अच्छे काम करने वाले लोगों को आप आगे बढ़ाओ, उसी में से अपना कुछ अच्छा बनेगा। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा जी, शिक्षा मंत्री जी। नहीं, सारी, पहले कल्ला साहब बोलेंगे? पहले कल्ला साहब बोलेंगे क्या? चार मंत्री बोल रहे हैं, समय है उस हिसाब से।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): बिलकुल। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आज फ्राइडे है, वह भी ध्यान रखें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने उपयोगी सुझाव और विचार दिये, इसके लिए मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। मैं खास तौर से कला और संस्कृति के पक्ष में अपनी बात कहूंगा।

'**संगीत, साहित्य, कला विहीन:,**

साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीन:'

संगीत, साहित्य और कला के बिना व्यक्ति बिना सींग और पूंछ वाले पशु के समान होता है। सौभाग्य से हमारा देश, हमारा प्रदेश इन चीजों में नहीं आता क्योंकि हमारा देश कला और संस्कृति में बहुत ही ऊंचा है और राजस्थान भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर, अपनी सांस्कृतिक विरासत और अपनी संस्कृति से पूरे देश और पूरे विश्व में अपना प्रमुख स्थान रखता है।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

उत्पादन की जो विविधता आई, उत्पादन का पहले यह तरीका था कि लोग हल और बैल से खेती करते थे और आज वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से खेती करते हैं। यह जो परिवर्तन आया है इसको कहते हैं सभ्यता। हम अपने त्यौहार कैसे मनाते हैं, हमारे क्या रिचुअल्स हैं, हमारा संगीत, हमारा गायन, हमारा नृत्य, हमारा कत्थक, ये हमारी संस्कृति के अंग हैं।

मैं आपको कई उदाहरण देकर बता सकता हूं। हमारे घरों में आप देखते होंगे, आकाशवाणी से आप सुनते होंगे, प्रात:काल में लोग उठते ही कहते हैं :-

'म्हारा जूना जोशी प्रभु जी मिलान कब होसी',

मोतियों सूं जड़ाऊं थारी पोथी,

म्हारा जूना जोशी प्रभु जी मिलान कब होसी,

पता लगता है भोर हो गयी है और माताएं-बहनें काम में लग गयी हैं। उसके बाद जब वे पूजा करती हैं:-

'अब जागो बनवारी म्हारा मोहन अब जागो गिरधारी,

बछड़ा-बछड़ी भीगन लागा, गऊआं आ गई सारी',

एक तरीके से प्रात:काल का वर्णन आ जाता है। शाम के वक्त में जब संध्या होती है तो,

'मन म्हारो संध्या रो सुमिरण कर रे,

संध्या सुमरियो पाप घटत है',

तो एक तरीके से संध्या का वक्त आ गया। हमारे जितने भी राजस्थानी गीत और संगीत हैं, शास्त्रीय संगीत के बिलकुल करीब हैं और उसके कारण उनका बहुत महत्व है। हम आजकल देखते हैं कि इन्टरनेट संस्कृति के कारण हमारी संस्कृति में मिलावट होने लगी है। कभी कोई कहता है डिस्को का कार्यक्रम है, डिस्को कत्थक, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। अपनी संस्कृति की शुद्धता के ऊपर और उसमें जो मिलावट हो रही है उस पर मिलकर सब लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं इस अवसर पर खास तौर से यह कहना चाहता हूं कि we promote tourism through culture. हमने अपने पर्यटन को भी संस्कृति के माध्यम से आगे बढ़ाया है। जितने भी हमारे फेस्टिवल होते हैं, उनमें हमारा

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

लोक संगीत, लोक वाद्य और जितनी भी कलाएं हैं, उनके माध्यम से हमने अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं जब संस्कृति का जिक्र कर रहा हूं तो आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी संस्कृति में **'मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्'** अर्थात् पर स्त्री को मां के समान समझो और पराये धन को चुराये हुए धन के बराबर समझो। इसी तरीके से **'मातृ देवो भव:, पितृ देवो भव:, आचार्य देवो भव:'** यह हमारी संस्कृति रही है। इसके बाद,

'अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः,

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्धर्मो यशो बलम्'

अर्थात् हम अपने से बड़ों को नमस्कार करते हैं तो हमारी आयु, बुद्धि, यश और बल स्वत: ही बढ़ जाते हैं।

इस प्रकार हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश में खास तौर से महात्मा गांधी जी का 150वां वर्ष चल रहा है। इसको एक वर्ष और आगे बढ़ाने की माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। हमारे विभाग को नोडल एजेंसी, नोडल डिपार्टमेंट के रूप में रखा है। मैं आज के संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ हिंसा बढ़ रही है, अराजकता बढ़ रही है, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहे हैं, आतंकवाद बढ़ रहा है और धार्मिक सहिष्णुता की जगह असहिष्णुता बढ़ रही है, ऐसे वक्त में महात्मा गांधी जी के उपदेश, शिक्षा और उनका दर्शन बहुत ही प्रासंगिक है। इसी के कारण हम लोगों ने जून से लेकर 4 अक्टूबर, 2019 तक प्रत्येक जिले में 3 दिनों के कार्यक्रम रखे हैं जिसमें महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन से संबंधित प्रदर्शनियां, संगोष्ठी और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त में यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां 4 विभाग, 2 प्राधिकरण, 6 संस्थाएं, 7 भाषाई अकादमियां काम कर रही हैं। उनके माध्यम से हम कला, संस्कृति, संगीत और साहित्य को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

मैं इस अवसर पर जो घोषणाएं हमारे विभाग ने की हैं, उसके बारे में बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मावली, सागवाड़ा, पचपदरा से आने वाले 3-4 माननीय सदस्यों ने एक तो सांस्कृतिक केन्द्र के लिए कहा कि हम

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

विभाग की तरफ से नहीं खोलते। मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि पंचायत स्तर पर जो एसएफसी का पैसा मिलता है, उससे आप पंचायत हैड क्वार्टर पर एक ओपन एयर थियेटर बनाकर इसको सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में डवलप कर सकते हैं। उसके माध्यम से पंचायत स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। एमएलए अपने कोटे से भी इन सांस्कृतिक केन्द्रों को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब यह बना लेंगे तो पश्चिम सांस्कृतिक केन्द्र से और हमारे यहां के जो भी कार्यक्रम हैं, उनको हम बारी-बारी से हर जिले में भेजने का कार्यक्रम दे सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं यह भी आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम सब लोग हमारी संस्कृति और थाती को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करें।

राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में उपलब्ध राजस्थानी भाषा के अभिलेखों के हिन्दी भाषा में अनुवाद के लिए साफ्टवेयर एवं राजस्थानी भाषा को सिखाने हेतु एक एप बनाया जाएगा।

प्रदेश में बाल साहित्य संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और बाल साहित्य रचनाकारों के सहयोग के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का गठन किया जाएगा। सवाई मानसिंह टाउन हाल (पुरानी विधान सभा) में एक विश्वस्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय बनाया जाएगा।

प्रदेश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण एवं उचित सार-संभाल के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना बनाकर 22 करोड़ के कार्य करवाये जाएंगे। राजस्थान के साहित्यकारों, कवियों, लेखकों और कलाविदों आदि को एक मंच उपलब्ध कराने के लिए जयपुर में राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इस हेतु 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किये जाएंगे। महात्मा गांधी जी के मूल सिद्धांतों पर चलने एवं जन-जन तक पहुंचाने के लिए एक शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।

मैं इस अवसर पर कन्हैया लाल जी सेठिया, जिन्होंने,

'धरती धोरां री,

आ तो सुरगां नै सरमावै,

ईं पर देव रमण नै आवै,

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

ईं रो जस नर नारी गावै,

धरती धोरां री'

यह गीत लिखा है, इस गीत के लेखक की, अब जो वर्ष आ रहा है, उसमें जन्म शताब्दी आ रही है। उनके सम्मान में हमारी राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति अकादमी से कहूंगा कि वे एक विशेषांक प्रकाशित करें।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आप संस्कृति के उत्थान के लिए और संस्कारों के उत्थान के लिए सब मिलकर काम करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: डा. सुभाष गर्ग।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। आज मांग संख्या 24 के अंतर्गत संस्कृत शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर विचार माननीय सदस्यों के माध्यम से आये हैं।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं संस्कृत एजुकेशन को ले रहा हूं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने संस्कृत विश्वविद्यालय को लेकर संस्कृत शिक्षा के ऊपर चर्चा की और अपना मत रखा। मैं सभी सदस्यों के द्वारा दिये गये सुझावों का स्वागत करता हूं। मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता को बताना चाहूंगा कि इस भारत देश में संस्कृत का विकास और विस्तार अगर हुआ है, जितना भी इंस्टीट्यूशनल डवलपमेंट हुआ है, वह कांग्रेस शासन की सरकारों के दौरान हुआ है।

मैं आपकी जानकारी के लिए देना चाहूंगा कि भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संस्कृत की महत्ता को समझते हुए 1 अक्टूबर, 1956 को प्रथम संस्कृत आयोग की स्थापना की। आयोग के सुझाव पर ही पंडित नेहरू के द्वारा 1961 में तिरूपति में प्रथम राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना की गयी। फिर कांग्रेस शासन काल में ही पूर्व प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ मानद विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसी परम्परा का पालन करते हुए पूर्व प्रधान मंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश भर में संस्कृत महाविद्यालय खोलने हेतु दिल्ली में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना की जिसके अंतर्गत वर्तमान में 13 प्रांतों में इस तरह के संस्थान संचालित हो रहे हैं।

(डा. सुभाष गर्ग)

इसी क्रम में राजस्थान के संदर्भ में मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार के संस्कृत शिक्षा के अंदर किये गये प्रयासों के फलस्वरूप, राजस्थान की कांग्रेस सरकार के माननीय पूर्व मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी ने 1958 में प्रदेश के प्रथम संस्कृत निदेशालय की स्थापना राजस्थान में की और एक संस्कृत के युग का सूत्रपात किया। इसी क्रम में हमारी यूपीए सरकार के पूर्व प्रधान मंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्रित्वकाल 2012 में द्वितीय संस्कृत आयोग का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष प्रो. सत्यव्रत शास्त्री को बनाया गया था।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार द्वारा ही 13 मई, 1983 को अपर काशी जयपुर में, जिसको अब छोटी काशी कहते हैं, केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की गयी। जो वर्तमान राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जयपुर परिसर में एक पारंपरिक संस्कृत शिक्षण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है।

इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का विधिवत प्रारम्भ हमारे वर्तमान में लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी के कर कमलों द्वारा 6 फरवरी, 2001 में हुआ। मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में संस्कृत अकादमी की स्थापना 1980 में पूर्व मुख्य मंत्री माननीय श्री जगन्नाथ पहाड़िया ने की।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं संस्कृत शिक्षा के सबसे ज्यादा वकील अपने आपको कहने वाले हमारे माननीय सदस्यों के लिए कहना चाहूंगा। आपके कार्यकाल में, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि अध्यक्ष जी ने मुझे समय बहुत कम दिया है। मैं केवल गत 5 वर्षों का आंकड़ा देना चाहूंगा। 2014 से 2018 के बीच में एक भी संस्कृत स्कूल आपके द्वारा न तो खोला गया और न ही क्रमोन्नत किया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि 2008 से 2013 के बीच में प्राथमिक स्कूल 425 कांग्रेस सरकार के द्वारा खोले गये, उच्च प्राथमिक 26 खोले गये, प्रवेशिका 192 खोले गये, वरिष्ठ उपाध्याय 26 खोले गये, शास्त्री कालेज 1 खोला गया। 1 आचार्य कालेज में क्रमोन्नत किया गया। यह मैं आपकी जानकारी के लिए इसलिए देना चाह रहा हूं कि आप जो संस्कृत के बारे में कहते हैं, जितना भी संस्कृत का विकास और विस्तार हुआ है, वह कांग्रेस शासन के दौरान ही हुआ है।

(डा. सुभाष गर्ग)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब संस्कृत विश्वविद्यालय की बात करना चाहता हूं। इस संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति लाये गये थे कांग्रेस शासन के द्वारा, देवनाथनजी, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं उनकी सेवाओं को जरूर याद करना चाहूंगा। एक ऐसे शिक्षाविद् जो राष्ट्रीय स्तर के थे, को यहां कुलपति बनाया। उसके बाद जो कुलपति आपके द्वारा बनाये गये उसी दौरान का आप लेखा-जोखा कर रहे हैं तो विश्वविद्यालय को जितना अखबारों में छपने का स्थान मिला वह उन्हीं कुलपतियों की देन रही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में अन्य कुलपतियों का भी संदर्भ करना चाहूंगा। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्रीजी अभी यहां हैं नहीं, इस सदन में उन्होंने जिक्र किया था कुलपतियों की नीतियों को लेकर, नियुक्तियों को लेकर, रिमूवल को लेकर, चर्चा चल रही है, वह बिल लेकर आ रहे हैं। मैं माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री को बताना चाहूंगा जिन कुलपतियों की नियुक्ति आपकी सरकार के द्वारा की गयी उसमें उदाहरण देना चाह रहा हूं राजस्थान विश्वविद्यालय का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक अयोग्य व्यक्ति को कुलपति बना दिया गया, कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा और उनको इस्तीफा देना पड़ा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा अभी एमडीएस यूनिवर्सिटी की माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री ने चर्चा की। एमडीएस यूनिवर्सिटी की चिंता से हम भी वाकिफ हैं। एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मालूम है कि क्यों बनाया गया कुलपति जब जोधपुर विश्वविद्यालय में कुलपति थे, उनको एमडीएस में लाया गया। उनके खिलाफ बहुत आरोप थे, एफआईआर तक थी, धारा 302 के तहत मुकदमे दर्ज थे। उनको अजमेर लाया गया और कोर्ट के इंटरवेंशन से उनका कार्य रोका गया तो कुलपतियों की जितनी गिरावट पूर्व भाजपा सरकार में की गयी है और जितना राजनीतिकरण पूर्व सरकार ने किया है उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्लीज।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक संस्कृत शिक्षा के सम्बन्ध में कहा जाता है, इसके विकास के बारे में कहा गया, आपने हमारा जन घोषणा पत्र पढ़ा होगा, उसमें हमने दो बातें कही हैं माननीय मुख्य मंत्रीजी के माध्यम से संस्कृत शिक्षा और संस्कृत

(डा. सुभाष गर्ग)

भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि संस्कृत विश्वविद्यालय का, अभी जो मीटिंग्स हुईं, रिव्यू हुआ लगातार संस्कृत विभाग का, उसके तहत नए कोर्सेज भी हम ऐसे ला रहे हैं जो हमारे बच्चों के हित के हैं और उनकी रोजगार की क्षमता बढ़ाने वाले हैं। इसी क्रम में वैदिक संस्कार शिक्षा बोर्ड की बात जन घोषणा पत्र में कही गयी है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जा रहा है जिसमें संस्कृत और वेद विज्ञान, आयुर्वेद, योग इनके बीच में जो आपसी सम्बन्ध है, संस्कृत विश्वविद्यालय केवल संस्कृत के भरोसे नहीं विकसित किया जा सकता। संस्कृत के साथ-साथ आयुष को भी उससे जोड़ना पड़ेगा। आयुर्वेद, योगा, वेद विज्ञान को देखना पड़ेगा, इनको भी जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है, यह मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तकनीकी शिक्षा पर चर्चा करना चाहता हूं। बड़ी बातें यहां की गयीं। जिस निजी क्षेत्र की चर्चा की माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने, मैं बताना चाहूंगा कि पीपीपी माडल शुरू किया राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा, आपको मैं उनकी प्रोग्रेस बताना चाहूंगा। वर्ष 2007-08 में निजी जन सहभागिता योजना अंतर्गत 'lagging area policy' के अंतर्गत, इसमें हमने इंस्पैक्शन करवाया अभी। इसमें करीब-करीब 24 कालेजों को 400 बीघा से अधिक जमीन बांट दी और 21 करोड़ 37 लाख रुपये दान में दे दिये गये। उन पीपीपी माडल के कालेजों की यह स्थिति है कि बच्चे किसी में तीन नहीं हैं, बंद पड़े हैं आधे से ज्यादा। मैं इसकी इंक्वायरी करवा रहा हूं और आपको विश्वास दिला रहा हूं कि पीपीपी माडल पर जो कालेज दिये गये, अगर जरूरी पड़ा तो कानूनी कार्यवाही उनके खिलाफ की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और तकनीकी शिक्षा के बारे में बताना चाहूंगा। बोर्ड आफ इंजीनियरिंग कालेज की चर्चा करना चाहूंगा, इंजीनियरिंग कालेजों का गठन किया गया, सरकारी क्षेत्र में आटोनोमस स्टेटस के तहत कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में 11 कालेज चल रहे हैं और उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग आपकी भाजपा सरकार में उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रेसीडेंट माननीय मंत्री को बना रखा है और उस कमेटी का मैम्बर उसका चेयरमैन होता है। उसका बताना चाह रहा हूं कि TEQIP (Technical Education Quality Improvement Programme of Government of India),

(डा. सुभाष गर्ग)

जो स्कीम है जिसके तहत प्रत्येक कालेज को दस करोड़ रुपया मिलता है, उस स्कीम के तहत पैसा लेने के लिए प्रत्येक तीन माह में एक मीटिंग होनी चाहिए और साल में दो मीटिंग कम से कम होनी चाहिए। गत भाजपा सरकार के दौरान वह मीटिंग नहीं की गयी, केवल एक की गयी और हमने सरकार का जैसे कार्य भार संभाला, हमारी सरकार में लगातार 1 जनवरी से लेकर जून तक तीनों मीटिंग करके पैसे का रास्ता खोला जो डेढ़ करोड़ रुपये प्रति कालेज की किश्त हमको मिल रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय का इशारा हो रहा है, मैं अनुशासन से बंधा हुआ शिक्षक हूं और रहा हूं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन चर्चा जरूर करना चाहूंगा जितना पोलिटिकलाइजेशन एजुकेशन सिस्टम का यदि किसी ने किया उसके लिए दोषी है तो 1993 में जब आपकी भाजपा सरकार थी जिस तरह से राजनीतिकरण किया गया, आप सब जानते हैं। अभी पूर्व शिक्षा मंत्री ने एक बात कही थी, एजुकेशन और उसको डिफाइन किया था, e for this, and so, मैं आपके लिए एजुकेशन का मतलब जो हमारी राय में है, वह E stands for Employees (BJP Ideology in the education)..., मैं जवाब दे रहा हूं, मुझे दे लेने दीजिए, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्या कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): ...D stands for 'Disturb the peace, harmony and mutual respect', U stands for 'unrest among the society', C stands for 'close the door of knowledge for the youth', A stands for 'Adarshikaran', T stands for 'trading the education', I stands for 'increase the indiscipline', O stands for 'opportunist for the youth' and N stands for 'new model for education'. जो मैंने कहा पीपीपी माडल, थैंक यू सर, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में खेलों की क्या स्थिति है, इसके ऊपर मैं अपनी बात

(श्री अशोक)

रखना चाहता हूं। कट मोशन एवं डिमांड आज डिपार्टमेंट की आई नहीं लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं पहले ऐसे प्लेटफोर्म की उन्होंने घोषणा की जिस प्लेटफोर्म में राजस्थान का खिलाड़ी आज दर-दर भटकता है। जिले की और प्रदेश की संस्थाएं खेल का आयोजन करती हैं, उनमें झगड़े हो जाते हैं, वे कानून का दरवाजा खटखटाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, मुझे तो लगता है कि इससे उन संस्थाओं को कोई नुकसान नहीं होता लेकिन अगर किसी को पीड़ा से गुजरना पड़ता है तो इस राजस्थान के खिलाड़ी को।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एशियन गेम्स की तर्ज पर राजस्थान गेम्स होंगे, यह घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की। मैं समझता हूं हम सभी को माननीय मुख्य मंत्रीजी को इसके ऊपर धन्यवाद देना चाहिए कि एक प्लेटफोर्म हुआ जिस प्लेटफोर्म के ऊपर प्रदेश का युवा, प्रदेश का खिलाड़ी, हर स्पोर्ट्स के अंदर अपनी परफोर्मेंस प्रूव करके भविष्य में देश के लिए दुनिया के सामने राजस्थान का नाम रोशन कर सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इसी साल, आज से पहले डिपार्टमेंट की तरफ से राजस्थान में केवल मात्र साल में गर्मियों में तीन समर कैम्प होते थे लेकिन इसके माध्यम से इस पहले साल में हम लोग हर जिला लेवल पर इस गेम्स को लेकर जाएंगे। जिला और प्रदेश लेवल के गेम्स होंगे तो प्रदेश को जिले से लेकर प्रदेश से लेकर अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। भविष्य में एक साल के बाद में, चूंकि यह नया है, हमारे डिपार्टमेंट के लिए, कभी डिपार्टमेंट ने इतना बड़ा आयोजन नहीं किया। हमारे बहुत सारे सदस्यों ने प्रश्न काल में चिंता जताई कि खेलने के लिए क्या किया, मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन गेम्स को, इस प्लेटफोर्म को हम पंचायत समिति लेवल तक भी ले जाने की मंशा रखते हैं, भविष्य में इसकी भी प्लानिंग होगी। वह दिन दूर नहीं, यदि हमने ईमानदारी से मेहनत की और काम किया क्योंकि खेल केवल एक मेडल के लिए खेला नहीं जाता है, खेल एक जीवन शैली का हिस्सा है। बहुत सारे माननीय सदस्य यहां हैं जिनके रोज की जीवन शैली का खेल एक हिस्सा है। खेल स्वास्थ्य का एक ऐसा द्वार है अपने स्वास्थ्य के लिए ताउम्र यदि कोई व्यक्ति, खिलाड़ी खेल खेलता है तो मुझे लगता है कि उसको कोई और दूसरी चीज करने की जरूरत नहीं है। हमें एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी कि मैडलिस्ट के अलावा गांव-गांव

(श्री अशोक)

के अंदर, हर जिले के अंदर हर ब्लाक के अंदर खेल का वातावरण बने। जब खेल का वातावरण बनेगा तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, मुझे तो याद है जब मैं बहुत छोटा था तो गांव-गांव के अंदर, गांव के लोकल खेल हुआ करते थे। हमारा राजस्थान इतना बड़ा है, सब जगह अलग-अलग लोकल खेल होते हैं। मेवाड़ में अलग खेल होंगे, हाड़ौती के अलग खेल होंगे, शेखावाटी के अलग खेल होंगे, मारवाड़ के अलग खेल होंगे तो उन खेलों का वापस वातावरण हर पंचायत लेवल पर बने, हर गांव में बने, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में, जैसा मुझे बताया गया है, समय थोड़ा कम है, माननीय मुख्य मंत्रीजी पेंशन स्कीम भी लाए, नए बच्चे जो इमर्जिंग एथलीट हैं, इमर्जिंग स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए स्कालरशिप की योजना भी लाए ताकि अंडर-12 के जो बच्चे हैं, अंडर-14 के जो बच्चे हैं, अंडर -17 के जो बच्चे हैं, अंडर-19 के जो बच्चे हैं, जो भविष्य में प्रोडक्ट बनने वाले हैं, जो प्रदेश का असैट बनने वाले हैं, उन्हें उस समय से ही साधन, संसाधन, डाइट, इंस्ट्रूमेंट्स की कमी न हो, इसके लिये स्कालरशिप तैयार की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, जॉब्स में दो प्रतिशत का कोटा है खिलाड़ियों का। आउट आफ टर्न का भी नियम है, लेकिन मुझे बड़ा दुःख है सदन को यह बताते हुए कि दो प्रतिशत कोटे में आज से पहले जो भर्तियां हुईं उनमें चालीस प्रतिशत बच्चे भी उस दो प्रतिशत के कोटे को पूरा नहीं कर पाये।

आउट आफ टर्न के नियम इतने सख्त बना दिये गये कि ओलंपिक मैडलिस्ट, एशियन मैडलिस्ट, सभी अन्तरराष्ट्रीय मैडलिस्ट आज तक एक भी नौकरी आउट आफ टर्न इस राजस्थान प्रदेश में नहीं ले पाये। बहुत जल्दी उन नियमों को साधारण करके, और वे मैडलिस्ट जो अपना सारा खून-पसीना सारी जिंदगी उस मैडल के लिए लगा देते हैं, उनका भविष्य सुरक्षित हो, इसके ऊपर काम करके बहुत जल्दी मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बच्चों को आउट आफ टर्न भी मिलेगी और दो प्रतिशत में एक भी सीट खाली नहीं रहेगी। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट राजस्थान में ऐसी व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री जी और आपके निर्देशानुसार करेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, छोटे-छोटे गांवों से आने वाले स्टेट और नेशनल लेवल के खिलाड़ियों के लिये बड़े दुर्भाग्य की बात है, पूर्ववर्ती सरकार पर मैं

(श्री अशोक)

कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता, मुझे पता है कि ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है। अब हमारी सरकार है, जो करना है, हमें करना है। साढ़े 11 करोड़ रुपया छोटे-छोटे बच्चों का, उनमें से ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों के थे, जो स्टेट के मैडलिस्ट थे, नेशनल मैडलिस्ट थे, 2015 से उनका साढ़े 11 करोड़ रुपया रुका हुआ था। 2015 से चार साल हो गये, उन्हें मैडल की जो पुरस्कार राशि सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली। अभी पंद्रह-बीस दिन पहले साढ़े 11 करोड़ माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी के समय में पास होकर उन्हें मिले हैं। आज उनमें खुशी की लहर है।

माननीय अध्यक्ष जी, एक चीज के लिये मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। 17 से 18 साल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का एसएमएस स्टेडियम क्रिकेट के लिए इस्तेमाल होता आया है, लेकिन इन 17 सालों में नियमों की क्लीयरिटी नहीं होने की वजह से न तो आरसीए, न ही आईपीएल की किसी एजेंसी ने आज तक एक रुपये का भुगतान भी स्टेडियम को किया। इस बार, पहली बार इतिहास में एक करोड़ चालीस लाख रुपये आईपीएल के पिछले साल के सात मैचों के बिल, डिपार्टमेंट के अकाउंट में आ चुका है और इस साल के दो करोड़ रुपये रेज हो चुके हैं। जिस स्टेडियम को 17 साल में एक रुपया नहीं आया, आपके आशीर्वाद से उसमें आईपीएल के प्रति मैच का बीस लाख रुपया आने लगा। मैं इसके लिये सदन की तरफ से आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, भविष्य में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी विशेष इंटरेस्ट ले रहे हैं और राजस्थान में खेल बढ़ेगा, आप सबके सहयोग से बढ़ेगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवर सिंह भाटी।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष जी, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति पर आज सदन के 50 से भी अधिक माननीय सदस्यों ने भाग लिया और अपने-अपने सुझाव दिये। माननीय सदस्यों के उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित जो कटौती प्रस्ताव आये हैं, मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि उक्त सभी कटौती प्रस्तावों के जवाब अतिशीघ्र आप सबके निवास स्थानों पर भिजवा दिये जाएंगे।

(श्री भंवर सिंह भाटी)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में पिछले छह माह की अवधि में किये गये कार्यों और नवाचारों की उपलब्धियों तथा इस वर्ष आरम्भ की जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं के बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहले मैं राज्य के माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपनी बात इन पंक्तियों के साथ आरम्भ करना चाहता हूं-

बैर-शिकायत क्या करूं,
सही-गलत अवाम को देखने दो,
मैं सिर्फ अपना काम करूं,
यही मेरी पहचान हो।

अध्यक्ष जी, कांग्रेस की विगत सरकार द्वारा राज्याधीन किये गये 8 महाविद्यालय, जिन्हें पिछली सरकार ने बिना गुण-अवगुण देखे दूषित मानसिकता रखते हुए निरस्त कर दिया था, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जन भावना का सम्मान करते हुए इन 8 महाविद्यालयों को पुन: राज्याधीन कर दिया है। इसी प्रकार कांग्रेस की विगत सरकार द्वारा ही खोले गये महाविद्यालयों में से तीन महाविद्यालयों- जहाजपुर, पहाड़ी और सांचौर को इस वर्ष अनुमति प्रदान करने के लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष जी, पिछली सरकार ने अपने शासन के अंतिम वर्ष में नये महाविद्यालय खोलने की जल्दबाजी दिखायी। बिना वित्तीय प्रावधान के न भवन का पैसा स्वीकृत किया गया, न जमीन की कोई पुख्ता व्यवस्था की गयी और चुनावी साल होने की वजह से बड़ी संख्या में राजकीय महाविद्यालय खोल दिये गये। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में ऐसे सभी 18 कालेजेज को भवन निर्माण हेतु बजट आबंटित कर दिया है ताकि ये सभी महाविद्यालय भी यथाशीघ्र ही अपने-अपने भवन में संचालित हो सकें।

माननीय अध्यक्ष जी, आज के पांच साल पहले जब सामने विराजे हुए प्रतिपक्ष के सदस्यों की सरकार बनी थी तो उस समय 2013 में हमारे माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा जो 46 राजकीय महाविद्यालय खोले गये थे, उन्हें इन्होंने समीक्षा के नाम पर बंद करने का काम किया, लेकिन मैं

(श्री भंवर सिंह भाटी)

माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बड़ा हृदय रखते हुए राज्य हित में, विद्यार्थियों के हित में इन महाविद्यालयों को न सिर्फ चालू रखा, बल्कि इनके भवन के लिए बजट का प्रावधान भी इस वर्तमान बजट में किया।

हमारी सरकार बनने के बाद 13 उपखंड ऐसे थे, जहां पर राजकीय अथवा कोई निजी महाविद्यालय नहीं था, सरकार के पास नये राजकीय महाविद्यालय खोलने के लिए सदन के माननीय सदस्यों द्वारा अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी दो दिन पहले ही 32 और नये राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। पिछले छह माह की अवधि में हमारी सरकार 35 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा कर चुकी है।

अध्यक्ष महोदय, अभी तक किसी भी सरकार द्वारा एक साथ खोले गये नवीन राजकीय महाविद्यालयों की संख्या की दृष्टि से संभवत: यह सर्वाधिक संख्या है। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी का विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं। इस बजट घोषणा में खोले गये कृषि महाविद्यालय समय की मांग भी है और विद्यार्थियों को कृषि के क्षेत्र में अध्ययन की आवश्यकता की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। अत: इस बार की बजट घोषणाएं राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास की दृष्टि से वरदान की तरह हैं। विभाग के मंत्री होने के नाते मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि इन घोषणाओं की शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्विति करवाई जाएगी ताकि इनका अविलम्ब फायदा मिल सके।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, विकास और स्वस्थ वातावरण के प्रति वचनबद्ध है। हमने पहली बार यह नवाचार भी किया है कि महाविद्यालयों के विकास की योजनाओं पर मंथन और उन्हें तैयार करवाने के काम को भी विकेंद्रीकृत किया जाए ताकि महाविद्यालय अपनी आवश्यकतानुसार योजना में प्राथमिकता तय कर सकें। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने फरवरी, 2019 के बजट में अनुदान के समय राज्य के सभी महाविद्यालयों के लिए Resource efficience and college with excellence raise की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिला मुख्यालय के एक बड़े कालेज को नोडल एजेंसी नामित करवाते हुए कुल 33 संसाधन सहायता समितियों का गठन करवाया। इनके माध्यम से राज्य में

(श्री भंवर सिंह भाटी)

कालेज शिक्षा के क्षेत्र में संसाधन पुनर्वितरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हुए महाविद्यालयों के विकास का नया अध्याय आरम्भ करवाया है। इसके अतिरिक्त हम पहली बार यह कार्य करने जा रहे हैं कि राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों का वार्षिक मूल्यांकन करवाया जाए ताकि महाविद्यालयों की परफोर्मेस का वार्षिक मूल्यांकन हो और तदनुसार महाविद्यालयों के विकास की मानिटरिंग की जा सके। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने फरवरी, 2019 के बजट में अनुदान के समय राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालय के लिए एनुअल आडिटिंग प्रोग्राम की घोषणा की है जिसकी शीघ्र क्रियान्विति किये जाने की पूर्ण तैयारी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां सदन के पटल पर एक तथ्य रखना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय उच्च शिक्षा को बजट में कोई आकर्षक प्रोत्साहन नहीं दिया गया था। पिछले पांच वर्षों में सरकार ने जो बजट कालेज शिक्षा को दिया उसका वार्षिक औसत 997.6 करोड़ था। हमारी सरकार ने पहले ही वर्ष में कालेज शिक्षा को 1232 करोड़ से अधिक का बजट स्वीकृत किया है जो पिछली सरकार के वार्षिक औसत से लगभग 23.5 प्रतिशत अधिक है। अत: हमारी सरकार की उच्च शिक्षा के विकास के प्रति प्राथमिकता की मन्शा साफ है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष जी, मुझे यह उल्लेख करते हुए खुशी भी है कि उच्च शिक्षा में प्रतिभावान दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुख्य मंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना आरम्भ करने की घोषणा कर दी है। हमारी सरकार ने जनता से किये गये वादों की क्रियन्विति में भी निम्नलिखित कार्यक्रम आरम्भ किये हैं:-

हमने महाविद्यालयों में चल रही दीर्घकालीन उन परम्पराओं को बदलने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अध्यक्ष महोदय, एक जुलाई से आरम्भ हो रहे नये शैक्षणिक सत्र के पहले दिन से ही नियमित कक्षाएं लगवाई जाएंगी। यद्यपि सदन को इस बात पर आश्चर्य होगा कि एक जुलाई से कक्षाओं के आरम्भ होने में नई बात क्या है, पर मैं सदन के पटल पर यह बात रखना चाहता हूं कि महाविद्यालयों में एक जुलाई से कक्षा प्रारम्भ होने की परम्परा लम्बे समय से नहीं थी। हमने एक जुलाई से आरम्भ करवाने की

(श्री भंवर सिंह भाटी)

रणनीति बनाई जिसमें पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार 30 जून को प्रवेश का कार्य पूरा कर लिया गया और एक जुलाई से कक्षाओं को प्रारम्भ कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालयों में वर्षों बाद एक जुलाई से नियमित कक्षाएं आरम्भ होना विभाग की एक बड़ी उपलब्धि है और महाविद्यालयों में एक जीवंत वातावरण साकार हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, राजकीय महाविद्यालयों में नियमित कक्षाओं का संचालन योजनाबद्ध तरीके से सुचारु हो, इसके लिए विभाग के स्तर पर हर माह प्रत्येक विषय में पढ़ाये जाने वाले टोपिक्स को सूचीबद्ध करवाया जाकर माहवार कलैण्डर जारी किया गया है। इससे समय पर कोर्स पूरा होना, विद्यार्थियों को विषय समझ के लिए पर्याप्त समय मिलना तथा महाविद्यालयों में पूर्णकालिक अध्यापन सुनिश्चित होगा।

अध्यक्ष महोदय, नियमित कक्षाओं के सुचारु संचालन के साथ-साथ हमने यह भी प्रयास किया है कि महाविद्यालयों में संचालित होने वाले सभी सह-शैक्षिक गतिविधियों में भी राज्य सरकार के स्तर पर समानता लाई जाएगी। इसके लिए पहली बार स्कूल शिक्षा का जो शिविरा कलैण्डर है उसकी तर्ज पर सभी राजकीय महाविद्यालयों के लिए आकाशि कलैण्डर 2019-20 जारी किया गया है। इसके साथ ही महाविद्यालयों में पहली बार सभी विद्यार्थियों के लिए सदन की व्यवस्था, हाउस की व्यवस्था लागू करवाई गयी है जिसमें प्रत्येक महाविद्यालय के विद्यार्थियों को पांच सदनों में विभाजित किया गया है- पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु में विभक्त किया गया है। मैं यह बताते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूं कि पहली बार कालेज शिक्षा विभाग की पहचान के रूप में एक लोगो तैयार करवाकर जारी किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने युवाओं को उनके भविष्य निर्माण के लिए महाविद्यालयों में 12 जनवरी, 2019 को स्वामी विवेकानन्द जी की जयंती के अवसर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की नि:शुल्क तैयारी करवाने हेतु राजकीय महाविद्यालयों में प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम आरम्भ करवा दिया है जिसमें सिविल सेवा से लेकर, बैंक, पुलिस, शिक्षक, एसएससी आदि अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की नि:शुल्क तैयारी करने की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। इनमें नियमित विद्यार्थियों के साथ-साथ स्थान उपलब्ध होने पर अन्य युवा भी प्रवेश ले सकते हैं। साथ ही इसके पीछे मन्शा यह है कि जो विद्यार्थी कालेज समय में कोचिंग संस्थाओं में जाते हैं उनके मां-बाप के पास पैसे नहीं

(श्री भंवर सिंह भाटी)

होने पर भी वे इसके लिए मजबूर होते हैं। हमने उनकी मदद की है अध्यक्ष महोदय। अभी हमारी पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कोचिंग कक्षाओं के लिए जिस दिशारी प्रोग्राम की बात की है, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उस प्रोग्राम के लिए बच्चों से 500 रुपये फीस ली गयी, वह क्लासेज कालेज टाइम के बाद लगवाई। परिणाम आपने खुद देखा है कि आपके समय से कक्षाएं केवल दस कालेजेज में ही चल पाईं और उसमें कितने विद्यार्थी आए, यह हम सब लोग जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, फिर ये कक्षाएं अपने आप बन्द हो गयीं। मैं पूर्व मंत्री महोदया को बताना चाहूंगा वर्ष 2015 में भी आपसे पूर्व आपकी सरकार ने श्रीविद्या के नाम से कोचिंग क्लासेज शुरू करवायीं, उनका हश्र शायद आपको पता नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, हमने इन कोचिंग क्लासेज को नि:शुल्क करवाया और विद्यार्थियों की मांग के आधार पर इनको कालेज समय में लगवाया। चूंकि समय की बात अभी माननीय पूर्व मंत्री जी कर रही थीं, कालेज में विद्यार्थी दूर-दराज के इलाकों से पढ़ने के लिए आते हैं जिनको बस या अन्य साधन से वापस घर जाना होता है इसलिए यदि उनकी सेवा और सहायता करनी है तो बेहतर है कि कालेज टाइम में इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाएं।

अध्यक्ष महोदय, हालांकि समय काफी हो गया है और बहुत सारे इश्यूज हैं लेकिन मैं थोड़ा शोर्ट करने की कोशिश करता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम के साथ-साथ जो नि:शुल्क पुस्तकों का वितरण करवाया गया उनके लिए पूर्व मंत्री जी ने जिस प्रकार कहा कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या एक लेखक की पुस्तकों का इसमें दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, वे सारी पुस्तकें, किताबें जो जी.के. की हैं वे अलग-अलग भामाशाहों के द्वारा, दानदाताओं के सहयोग से नि:शुल्क उनके द्वारा बांटी गयी थीं। इसके साथ-साथ 13 जुलाई को पूरे प्रदेश में, राजस्थान के पूरे 252 गवर्नमेंट कालेज में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और पहली बार 31 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया। इसका रिजल्ट आने पर जिला स्तर पर, सम्भाग स्तर पर और महाविद्यालय स्तर पर इस प्रकार के जो मेधावी विद्यार्थी सर्वोच्च वरीयता में आएंगे उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम भी कालेज शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा करवाया जाएगा।

(श्री भंवर सिंह भाटी)

खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए अर्जुन दृष्टि क्रीड़ा और खेलकूद कार्यक्रम हम आयोजित करने जा रहे हैं। उसमें अलग-अलग जिलों के अलग-अलग कालेजों को हमने खेलवार नोडल एजेंसी के रूप में चिह्नित किया है। अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालयों में छात्र निधि कोष में जो पैसा है उसका समुचित उपयोग करने के लिए एक लम्बे समय से एक निश्चित राशि तय की गयी थी। हमने प्राचार्य स्नातक महाविद्यालय को प्रदत्त जो 8 लाख रुपये की सीमा है उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपये, प्राचार्य पी.जी. कालेज की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने का प्रावधान किया है। इसी क्रम में आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान को प्रदत्त मद से राशि की स्वीकृत सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। इस मद में 50 लाख से अधिक की स्वीकृति के प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर अनुमोदित किये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक मंत्री जी को और बोलना है। ऐसे नहीं, घोषणा कर दें आप।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ घोषणाएं करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों ने नवीन महाविद्यालय खोलने की मांग की है। मैं सभी सदस्यों को कहना चाहूंगा कि उनकी राय को पूरा महत्व दिया जाएगा। पहले भी 35 राजकीय महाविद्यालय एक वर्ष में खोलने की माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। जो दूसरे सदस्यों ने मांग की है उनको भी पूरा महत्व दिया जाएगा और चरणबद्ध रूप से उनके महाविद्यालय खोलने की सरकार कार्यवाही करेगी। हमारे पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अलग-अलग महाविद्यालयों में विभिन्न विषय, संकाय खोलने और महाविद्यालय को क्रमोन्नत करने की मांग की है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस पर पूरी तरह से विचार किया जाएगा और गम्भीरतापूर्वक विचार करके गुणावगुण के आधार पर नहीं, अलग-अलग जो सुझाव आये हैं, सुझाव बड़ी संख्या में आये हैं, कटौती प्रस्ताव के माध्यम से आये हैं। राठौड़ साहब और अन्य लोगों ने अपने विचारों में भी व्यक्त किये हैं, लिखित में भी आये हैं तो मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसमें जो नवीन विषय, संकाय खोलने की

(श्री भंवर सिंह भाटी)

बात है उस पर कार्यवाही करके इसी सत्र में हम कोशिश करेंगे कि अधिकाधिक महाविद्यालयों को इसका लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालयों में टीचिंग और नोन टीचिंग पदों को भरने की बात सभी माननीय सदस्यों के द्वारा की गयी है। अध्यक्ष महोदय, एक हजार पदों को भरने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा बजट में घोषणा की गयी है। अतिशीघ्र इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण करवाकर रिक्त पदों को भरा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, राजकीय विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक और अन्य पदों पर कार्यरत अधिकारियों को यूजीसी वेतनमान देने तथा उनकी वेतन विसंगतियों को दूर करने के संबंध में मांग रखी गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा, जिन-जिन ने भी यह बात रखी है, उक्त कार्मिकों की मांगों के संबंध में उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर रिपोर्ट आने पर वित्त विभाग को सिफारिश भिजवाकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाने की दिशा में हम कार्य करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट घोषणा 2019 में खोले गये 35 राजकीय महाविद्यालयों को इसी शैक्षणिक सत्र में चालू करने की मांग सभी माननीय सदस्यों के द्वारा की गयी है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि 29 जुलाई को बजट पारित होने के बाद में उक्त सभी राजकीय महाविद्यालयों को प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जाएगी, जिससे कि उपखण्डों के छात्र-छात्रों को लाभ मिल सके।

मैं सभी माननीय विधायकों से कहना चाहूंगा कि संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर को विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा एक बार अस्थाई भवन चिन्हित करने के लिए सरकार के द्वारा निर्देशित कर दिया जाएगा। सम्माननीय विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में कालेज भवन की व्यवस्था के लिए सहयोग करें ताकि इसी सत्र में ये 35 राजकीय महाविद्यालय हमारे शुरू किये जा सकें।

अध्यक्ष महोदय, निजी विश्वविद्यालयों में अनियमितताओं और मनमानी पर नियंत्रण की बात कटारिया साहब ने और बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कही है। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इनकी

(श्री भंवर सिंह भाटी)

मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए, इन पर नियंत्रण करने के लिए, जो भी सरकार के द्वारा प्रभावी कार्यवाही हो सकती है निश्चित रूप से सरकार गंभीरतापूर्वक उस पर कार्यवाही करेगी। निजी विश्वविद्यालयों की जिस प्रकार की शिकायत माननीय सदस्यों के द्वारा की गयी है, उन तमाम शिकायतों का परीक्षण करवाएंगे, हम पूरी जांच करवाएंगे और जो भी उसमें ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इफैक्टिवली हम करवाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर में अनियमितताओं और परीक्षा परिणामों में देरी आदि की बात कई माननीय सदस्यों के द्वारा उठायी गयी। मैं उन तमाम सदस्यों के उठाये गये वक्तव्य पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर, अलवर के इस विश्वविद्यालय में जो भी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करवाने के लिए जांच करवाएंगे। आगामी समय में हमारे विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम आदि में देरी का सामना नहीं करने पड़े, उसके लिए भी हम सुनिश्चित करेंगे कि आगामी समय में हमारा अलवर का विश्वविद्यालय, जो शिड्यूल है उसके अनुसार चले और हमारे विद्यार्थियों को अच्छा शिक्षण कार्य करवा सके।

अध्यक्ष महोदय, भवन विहीन राजकीय महाविद्यालयों को भवन और भूमि उपलब्ध करवाने की मांग की गयी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बजट पारित होने के बाद पिछली भाजपा सरकार के अंतिम समय में, जो 18 राजकीय महाविद्यालय खोले गये, उन 18 राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में प्रस्ताव पारित कर दिया और बजट पारित होने के बाद उन तमाम 18 राजकीय महाविद्यालयों के भवन बनाने का काम हमारी सरकार करेगी।

राजस्थान में उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, पूरे सदन का मैं सहयोग चाहूंगा और पूरा प्रयास करूंगा। पूरी सरकार और हमारी मुख्य मंत्रीजी पूरा प्रयास करेंगे कि राजस्थान देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल हो। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पूरा समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: गोविन्द डोटासरा जी। माननीय मंत्री जी, सदन की भावना को देखकर भाषण दें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय अनुदान की मांग संख्या 24 पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: सदन का समय अनुदान की मांग संख्या 24 पारित होने तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आसन का आदेश कभी नहीं टाल सकता, पूरी चेष्टा करूंगा कि मैं इसको आधे घंटे, पैंतीस मिनट में...

श्री अध्यक्ष: मैंने कल डिबेट को रैगुलर सुना है। माननीय सदस्यों की भावना समझें और बहुत विस्तृत विभाग है, सबकी भावना है, चार मंत्री बोल चुके हैं, चार पार्ट तो उसके पूरे हो चुके हैं, एक बटा पांच भाग बचा है, एक बटा पांच भाग को कितना बढ़ा सकते हैं उसको देखें। माननीय मंत्री जी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): जैसा आसन का आदेश। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 330 कटौती प्रस्ताव मेरे विभाग को प्राप्त हुए जिसमें से 78 कटौती प्रस्ताव थे, वे आधारभूत सुविधाओं के बाबत थे, 41 ऐसे थे जो रिक्त स्थान हैं शिक्षकों के उनको भरने के लिए और 26 जो मर्ज हुए विद्यालय थे, उनको खोलने के लिए थे। करीबन 282 ऐसे कटौती प्रस्ताव हैं, जो लगभग इन तीन-चार विषयों के ऊपर है। 52 माननीय सदस्यों ने इसके ऊपर अपने विचार रखे, तकरीबन सभी 52 सदस्यों ने शिक्षा विभाग को छुआ है, अपने अमूल्य सुझाव दिये हैं।

मैं सदन को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जितने भी कटौती प्रस्ताव हैं, वे 24 घंटे में आपको भेज दिये जाएंगे और जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, मैं मेरे विभागीय अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि वे प्रोसीडिंग निकालें, देखें, समझें और क्या सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, उन पर ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से उनकी समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, उन सुझावों को किस प्रकार से अंगीकृत किया जा सकता है, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक शिक्षक का पुत्र होने के नाते, मैंने उस वातावरण को देखा है, उसमें पला हूं, बढ़ा हूं, शिक्षित हुआ हूं यहां तक पहुंचा हूं कि शिक्षक की अपनी क्या समस्याएं हैं सरकारी विद्यालयों की क्या समस्याएं हैं, लोग सरकारी स्कूलों से क्या अपेक्षा करते हैं, शिक्षकों से क्या अपेक्षा करते है और किस प्रकार का वातारण हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को देना चाहिए, इस बारे में मैं जितना जान पाया, 6-7 महीने में जितना इस विभाग को देखा। मैंने मेरे अतीत में जाकर भी झांका कि मैं खुद सरकारी विद्यालय में पढ़ा था, मेरे पिताजी टीचर थे, रोजाना जो भी समस्याएं आती थीं, घर में चर्चा होती थी तो निश्चित रूप से उसको मैं भलीभांति जानता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी सौभाग्य है कि माननीय अध्यक्ष के रूप में आप विराजमान हैं। आप भी इस विभाग को आशीर्वाद दे चुके हैं। इस विभाग को संभाल चुके हैं। आपका आशीर्वाद भी और साथ में यहां पर सात माननीय सदस्य आप सहित हैं, जो सारे इस विभाग को मेरे से पहले संभाल चुके हैं, उन्होंने अपना-अपना योगदान शिक्षा विभाग के माध्यम से सेवा के रूप में इस प्रदेश को दिया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष हों, चाहे माननीय बी.डी. कल्ला जी हों, चाहे माननीय मास्टर भंवरलालजी हों, चाहे माननीय वासुदेव देवनानीजी हों, चाहे माननीय शान्ती धारीवालजी हों, मैं समझता हूं सबने अपना-अपना योगदान दिया। आज जो वातावरण का निर्माण हुआ, उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं, आसन को बहुत-बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज 10 साल के बाद में पहला वातावरण था, चाहे हम विपक्ष में रहे, चाहे हम सत्ता पक्ष में रहे, इतनी शानदार डिबेट हुई, सबने अपने अमूल्य सुझाव इस विभाग को ठीक करने के लिए दिये। मैं उनका भी इस मौके पर आभार प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद में पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में देश आगे बढ़ने लगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जैसे शिक्षा मंत्री हुए, कोठारी आयोग बना, नई शिक्षा नीति आयी, डा. राधाकृष्णन आयोग बनाया। मैं समझता हूं, उन्होंने एक नींव रखी और उस नींव के ऊपर हम सब चल पड़े। आज देश और प्रदेश में जो शिक्षा का वातावरण बना उसमें लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जब-जब, जिस-जिस दल की सरकार आयी, जिस-जिसको दायित्व मुख्य मंत्री का मिला, शिक्षा मंत्री का मिला, उन सबने अपने-अपने प्रयास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुझे वह दिन भी याद है, जब मैं शिक्षा मंत्री का दायित्व लेने के बाद में सबसे पहले आपसे आशीर्वाद लेने गया।

(22.00 बजे)

तो आपने एक बात कही थी कि गोविन्द, दो चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस एलीमेंट्री एजुकेशन को ठीक करने की आवश्यकता है। हमारी डाइट्स को मजबूत करने की आवश्यकता है क्योंकि इस डाइट के माध्यम से हमारे शिक्षक शिक्षा देते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी को अच्छी गुणात्मक नालेज होनी चाहिए और आपने यह भी कहा था कि अगर सरकारी विद्यालयों में हम विषय अध्यापक दे देंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम हम इस समाज के लिए कर पाएंगे। मुझे वह बात पूरी अच्छी तरह से ध्यान में है लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वातावरण बना वह एक दिन में नहीं बना। कोई समय था जब केवल सरकारी विद्यालय ही थे जिनसे पढ़कर हम सब लोग यहां तक आए। कोई प्रोफेसर कहला रहे हैं, कोई डाक्टर कहला रहे हैं, कोई इंजीनियर कहला रहे हैं, कोई मंत्री कहला रहे हैं, कोई मुख्य मंत्री कहला रहे हैं। धीरे-धीरे समय परिवर्तित हुआ और उस समय में जो सरकारी विद्यालय थे उनसे लोग टूटते गये, उनसे दूरियां बढ़ती गयीं। जो आने वाला समय था, आने वाली पीढ़ी क्या चाहती थी उस बात को हमने कहीं स्वीकार नहीं किया और उसका परिणाम यह हुआ कि आज हमको हमारे सरकारी स्कूलों की जो दशा और दिशा है उसके लिए इतनी लंबी-चौड़ी बातें करनी पड़ती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं किसी की भी सरकार रही चाहे हमारी रही, चाहे आपकी रही, जो आधारभूत सुविधाएं हैं, सबने अपने-अपने स्तर पर निर्माण करने की चेष्टा की। अध्यापक भी भर्ती किये। वातावरण का भी निर्माण किया, लेकिन कहीं हम समय की इस आवश्यकता को नहीं समझ पाये और हमसे एक चूक हुई और उस चूक का परिणाम आज यह हुआ कि 22-22 हजार विद्यालय जो हमने खड़े किये थे उनको बंद करना पड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यूपीए की सरकार थी, डा. मनमोहन सिंह जी थे तो आरटीई एक्ट आया। इसके पीछे मंशा एक ही थी कि हमारे देश का कोई

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

भी गरीब का, किसान का, मजदूर का, दलित का बेटा पढ़ाई के बगैर नहीं रहना चाहिए। उसको क्वालिटी की एजुकेशन होनी चाहिए, वह ड्राप आउट नहीं होना चाहिए। जो काम हुआ वह उल्लेखनीय काम है और उसी के आधार पर आज जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे कि हमारी सरकारी स्कूलों की यह स्थिति हो गयी, हम प्राइवेट से कहीं पीछे नहीं हैं तो इस सबमें कहीं न कहीं हमारी 1986 की राष्ट्रीय नीति का, कहीं न कहीं जवाहर लाल नेहरू जी, राधाकृष्णन आयोग का योगदान रहा है। हमारी एनडीए सरकार ने आज जो शिक्षा नीति दी है उस शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट आया है, अभी शिक्षा नीति पूरी तरीके से लागू नहीं हो पायी है। मैं समझता हूं कि हमारी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके इर्द गिर्द घूमने का काम करती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे, बहुत बड़ी चुनौती है बहुत बड़ा विभाग है उस चुनौती के लिए हमको वापस उन विद्यालयों से जो लोगों की, समुदायों की दूरियां बढ़ गयी हैं, उसके लिए काम करना पड़ेगा। हमारा तीन महीने का समय आचार संहिता में निकल गया लेकिन हमारे विभाग ने इसके लिए एक ऐसा अभियान चलाया बाल सभा के नाम से कि लोग जुड़ते गये, जुड़ने लग गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 9 मई को एक बाल सभा की जिसमें पूरे प्रदेश में 65 हजार विद्यालयों में सब लोग इकट्ठे हुए। गांव के चौपाल में विद्यालय की बाल सभा की गयी और गांव के चौपाल में जब की गयी तो लोग जुड़ गये। जुड़ने के बाद में आपने देखा जो 9 मई की बाल सभा थी उसमें सात करोड़ रुपये जनता ने हमारे सरकारी स्कूलों को सहयोग दिया भामाशाह के रूप में। हम यहीं नहीं रुके आगे लोगों को जोड़ना पड़ेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक लोग सरकारी विद्यालयों से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, उस लक्ष्य को नहीं भेद पाएंगे इसलिए हमने 2 जुलाई को फिर बाल सभा की और आपने देखा कि 1 लाख 28 हजार 800 व्यक्तियों को मैंने व्यक्तिगत पत्र लिखे चाहे किसी भी दल का हो। वार्ड पंच से लेकर एमपी तक और मुख्य मंत्री जी को स्वयं निवेदन करके आया। वे नहीं आ पाये दिल्ली होने के कारण से लेकिन प्रत्येक माननीय सदस्य को हमने कहा कि आप इस बाल सभा में जाइये। सरकारी स्कूलों को ठीक करने का काम कीजिये। मैं समझता हूं कि इस ओर हम सबको कदम बढ़ाना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनको कोई कैरियर कोचिंग गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। इस दिशा में भी हमने आगे बढ़ने का काम किया और हमने जो आईटी की क्रांति लेकर के आये थे स्व. प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी उनके नाम से राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल लाने का काम किया। इस पोर्टल के माध्यम से 9वीं से 12वीं के तमाम बच्चों को हमने आईडी लॉगइन दिया और 14 देश, 10 हजार संस्थाओं के बारे में जानकारी उन बच्चों को मिलने लगी। मैं बहुत ही हर्ष के साथ कहना चाहता हूं कि 1 लाख 18 हजार 81 बच्चों ने उस पोर्टल का लाभ उठाया है। देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज हमारा बच्चा कहां जाए, उसको क्या करना चाहिए, कौनसी संस्था में कहां किस विषय की ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, उसको 12वीं के बाद में कहां पर किस कालेज में एडमिशन लेना चाहिए, उसके पास में गाइडेंस नहीं होता है इसलिए वह भटक जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारी सबसे बड़ी आज की आवश्यकता है कि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, हम इंग्लिश के बगैर कुछ भी नहीं हैं। लेकिन हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2014 में बजट में एक घोषणा जरूर की थी माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने कि हम इंग्लिश मीडियम की स्कूलें सरकारी स्तर पर खोलेंगे, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। हमने एक कदम आगे बढ़ाते हुए जमाने को भांपा। लोगों की भावनाओं को समझा कि हमारा बच्चा, हमारे अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे वैल क्वालिफाइड टीचर हैं उसके बावजूद भी प्राइवेट में जहां उतनी अच्छी गुणवत्ता से नहीं पढ़ाते हैं तो हमने पाया कि इंग्लिश मीडियम स्कूल की बहुत आवश्यकता है, कि मेरा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए। हर गरीब जिसको शाम को खाने को नहीं मिलता, वह यह चाहता है कि मैं एक वक्त का खाना नहीं खाऊं लेकिन मेरा बच्चा भी, वह दलित भी सोचता है जो झोंपड़ी में रहता है कि मेरा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने चेष्टा की, काम हाथ में लिया और 33 जिलों में हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर उनको समर्पित करते हुए खोलने का काम किया। उसका परिणाम यह हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि आज 11086 बच्चे एडमिशन पा चुके हैं इन 33 विद्यालयों में, जिनमें आप समझ सकते हो कि 1706 तो पहली क्लास में एडमिशन हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको और आगे चलना पड़ेगा। हमको इसको आगे

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

ले जाना पड़ेगा, ब्लाक स्तर पर जाना पड़ेगा क्योंकि जब यूपीए सरकार थी तो माडल स्कूलों की घोषणा की थी सीबीएसई तर्ज की, उसके बाद में एनडीए सरकार आ गयी, 134 ब्लाकों में तो वह खोली लेकिन उसके बाद में काम रुक गया जिसके कारण से लोगों को इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाने का मौका नहीं मिला और उसी का कारण है कि ये निजी विद्यालय पनपे हैं। हमने लोगों की भावनाओं को नहीं समझा, समय की आवश्यकता को नहीं समझा, इस कारण से हम पिछड़ गये। आज हम सबको इस बात की चर्चा करनी पड़ रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग को ठीक करने के लिए, हमारे बच्चों को क्वालिटी की एजुकेशन मिले, इसके लिए हमें उन गुरुजनों को जिनके आशीर्वाद से, जिनके कारण से हम सब यहां आये हैं उनको भी ठीक करना पड़ेगा। उनके लिए भी काम करना पड़ेगा। उनको सम्मानित करना पड़ेगा। उनको सम्मान देना पड़ेगा। उनको सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेंगी। यह सारा काम अगर हम करेंगे तो शिक्षक राज़ी होगा, वह खुश होगा तो हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराएगा। इसके लिए भी हमने माननीय अध्यक्ष महोदय, शाला दर्पण के माध्यम से, इंटीग्रेटेड शाला दर्पण जो हमारा है उसमें एक स्टाफ कोर्नर पोर्टल लांच किया और उसके माध्यम से वे तमाम सुविधाएं जो उसको मिलनी चाहिए, उसकी अपनी कोई भी चाहे परिवेदना हो, चाहे कोई भी शिकायत हो, वह आनलाइन आये, उसको जाना नहीं पड़े।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री बनते ही एक महीने के अन्दर ही बीकानेर गया। मैंने डाइरेक्ट्रेट में आधा घंटे मीटिंग ली तो पता लगा कि साढ़े आठ हजार से ज्यादा परिवेदनाएं हैं जो कोई पांच साल से है, कोई चार साल से है, कोई तीन साल से है, तो मैंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि बांसवाड़ा या उदयपुर का आदमी आपके डाइरेक्ट्रेट में क्यों चक्कर लगाये? हम क्यों नहीं इसको आनलाइन ले जाना चाहते, हम इन परिवेदनाओं का निस्तारण क्यों नहीं करना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे अधिकारियों को कि तत्काल उन्होंने इस बात को समझा और तीन कैम्प लगाये। संभाग स्तर पर कैम्प लगाकर 85-90 परसेंट परिवेदनाओं का निस्तारण करने का काम किया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी घोषणा की कि स्टाफ कोर्नर है, उसके

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माध्यम से अब आनलाइन परिवेदनाएं वे घर बैठे कर सकते हैं। उनको अधिकारियों और आफिसेज के ज्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं जो भर्तियों की बात पूर्व मंत्री माननीय वासुदेव देवनानी जी ने कही, बात सही है कुछ आपने किया, कुछ हमने किया, कुछ फिर हम करेंगे, यह कारवां बढ़ता रहेगा। अगर विषय अध्यापक नहीं होगा तो हमारे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय कभी नहीं चल पाएंगे। बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है, अगर उसको फिजिक्स का टीचर नहीं मिलेगा, उसको मैथ्स का टीचर नहीं मिलेगा तो कोई गरीब से गरीब हो, चाहे कितने भी अभाव में हो, वह अपने बच्चे को नहीं भेजेगा। जो आपने आंकड़ा दिया 1 लाख 48 हजार, पूरे सदन को अचंभित कर दिया कि यह कहां से आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं जो कांग्रेस द्वारा विज्ञप्ति जारी की गयी थी, इन्होंने जो भर्तियां बाद में कीं वह 43663 हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम उधर बैठते थे, आपने अपने समय में जो विज्ञप्तियां जारी कीं और नियुक्ति दी वह केवल 61043 का आंकड़ा है। आप आराम से दुरुस्त कर लीजिए, कभी भी आपकी मर्जी आये तब बात कर लीजिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं इन 6 महीनों में, तीन महीने हमारे चले गये आचार संहिता में। लेकिन आपने जो कोर्ट में अटकाया, सुप्रीम कोर्ट के वकील ला रहे थे, हमने केवल सरकारी एडवोकेट से ए जी के माध्यम से कोर्टों से उन भर्तियों को निकाला और 30554 इन तीन महीनों में, तीन महीने आचार संहिता के घटा दीजिए, हमने नियुक्ति देने का काम किया है। जब हम आये थे तो लगभग 82 हजार थर्ड ग्रेड के शिक्षक फील्ड में नहीं थे, केवल मैपिंग के आधार पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आंकड़ा बताया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं जो आखिरी के बजट में आपने 21600 भर्तियों की बात की थी, उसमें से एक भी भर्ती आप नहीं कर पाये। अध्यक्ष महोदय, आज मुझे आपके माध्यम से सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने गुर्जरों के आरक्षण को भी निपटाया, हमने उनको भी आरक्षण दिया और आज 2752 की सूची जारी हो चुकी है। जो 1200 प्रधानाध्यापक सैकण्डरी स्कूल के थे, उनका आरपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है, जल्दी से जल्दी हमारे विद्यालयों में बच्चों को सैकण्डरी स्कूल के प्रधानाध्यापक मिलने का काम होगा।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें केवल तीन महीने मिले हैं लेकिन 499 अनुकम्पा नियुक्ति दे दी। वह बच्चा जिसका बाप खतम हो गया या उसकी मां खतम हो गयी, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, वह अटका हुआ था तो 499 लोगों को दिया। हमने केवल इन तीन महीनों में, छह महीनों में से तीन महीने घटा दीजिए, तीन महीनों में जो आप बड़ी बात करते हो तो 44 शहीदों के नाम से हमने विद्यालयों का नामकरण करने का काम किया है। जो शिक्षा नीति आपने पहले से पिटारे में बंद कर रखी थी कि वोटों के चक्कर में चुनाव में कहीं नुकसान न हो जाए, नहीं निकाली और एनडीए गवर्नमेंट के बनते ही दुबारा निकाली तो उसके लिए भी हमने एक समिति बना दी जो यह देखेगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा, आपने भी कहा हमारा नामांकन यह हो गया, आपका जो प्रारंभिक का आंकड़ा था वह 2013-14 का था 45.01, 2014-15 में हुआ 41.18, 2015-16 में हुआ 42.50 और 2016-17 में हुआ 40.03 और 2017-18 में हुआ 41.27 और शिक्षक 2013-14 में 1.58 और 2017-18 में 1.09, मतलब प्रारंभिक शिक्षा आप मजबूत नहीं करोगे तो आप माध्यमिक में बच्चे कहां से लाओगे। हमारे जो पूर्व मंत्री जी हैं, उन्होंने 2018 में जो भाषण दिया था, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपने एस्सार की रिपोर्ट बताई थी, उस रिपोर्ट को भी मैं आगे चलकर कोट करूंगा लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका और हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। आज सबसे बड़ी लड़ाई विचारधारा की है। आप अपनी विचारधारा से अपने आपको वह साबित करना चाहते हैं जो आप नहीं हैं। आप अपनी विचारधारा को नहीं चाहते हुए भी पाठ्यक्रम के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से बच्चों में थोपने का काम करना चाहते हैं, जो चीज ठीक नहीं है। शिक्षा में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बड़ी-बड़ी बातें हुई कि पाठ्यक्रम में यह कर दिया, वह कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं मैं माहौल को किसी तरह से उत्तेजित नहीं करूंगा लेकिन एक बात जरूर बतानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पूर्व मंत्री जी ने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की थीं, जो पाठ्यक्रम था वह एनसीआरटी का सिलेबस था। आपने क्यों बदला, अपनी विचारधारा के लिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वासुदेव देवनानी साहब कह रहे थे कि पाठ्यक्रम के लिये बोर्ड के अध्यक्ष ने यह कर दिया, वह कर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

दिया। मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं आपने जो पाठ्यक्रम चेंज किया, एनसीआरटी जो पूरे देश में है उसको समाप्त करके नया पाठ्यक्रम लाये, आपने एक वर्कशाप आयोजित की और उस वर्कशॉप में यह निर्देश दिये विद्या भारती की तर्ज पर पाठ्य पुस्तकें लिखाई जाएं। विद्या भारती एक आरएसएस का एनजीओ है, उसके आधार पर आपने पाठ्यक्रम बदलने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कभी नहीं होता, अपनी विचारधारा उस कोमल बच्चे पर ऐसे नहीं थोपी जाती। वह बच्चा कुछ समझता नहीं है और उसको आप पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्या भारती जो आरएसएस का एनजीओ है, उसकी विचारधारा के मुताबिक पाठ्य पुस्तकें लिखाकर थोपना चाहते हो और जिनका आजादी में योगदान रहा, आजादी के बाद देश के निर्माण में योगदान रहा, उसको आप कुछ भी नहीं मानना चाहते हो। मैं समझता हूं आपकी तकलीफ, क्योंकि जब देश आजाद हो रहा था, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो आपके लोग गिने चुने थे, ज्यादा कांग्रेस के लोग थे, उन्हीं का बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए आपकी मजबूरी हो गयी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, आपको उनका महिमा मंडन करना जरूरी हो गया और जिनका वास्तव में देश को आजादी दिलाने में योगदान था, उनका महिमा मंडन कम करने के लिए आपने पाठ्यक्रमों में बदलाव किये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं पाठ्यक्रमों में पहले जो मुगल शासन में युद्ध हुए, उसको आपने ऐसा चित्रित करने की चेष्टा की कि यह हिन्दू और यह मुस्लिम का धर्म का युद्ध था। वह धर्म के युद्ध नहीं थे, वह सत्ता के संघर्ष थे। चाहे आप पानीपत का युद्ध ले लीजिए, चाहे खानवा का ले लीजिए, राणा सांगा का कौन तोपची था, पानीपत के युद्ध में मराठा का कौन था और हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का कौन सेनापति था, आप सब जानते हैं। लेकिन आपने जानने के बावजूद एक इस तरह का पूरे प्रदेश में माहौल क्रियेट कर दिया कि महाराणा प्रताप को तो केवल हम मानते हैं, महाराणा प्रताप तो केवल हमारे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं गत सरकार ने कक्षा दस की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक थी उसमें अनिर्णीत व परिणामविहीन हल्दीघाटी के युद्ध को बताया था, इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। जबकि आज जो पाठ्यक्रम है उसमें कहीं भी महाराणा प्रताप को नहीं दिखाया गया है। कक्षा 9वीं में जो सामाजिक विज्ञान थी, उसके 115,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

116, 117 पेज पर सिक्किम को अपने देश से ही अलग दिखा दिया और ऐसे ऐसे लोगों का महिमा मंडन कर दिया, किसी को वीर बता दिया, किसी को कुछ बता दिया कि देश की आजादी में महात्मा गांधी का कोई योगदान नहीं, जवाहर लाल नेहरू का कोई योगदान नहीं, इंदिरा गांधी का कोई योगदान नहीं। आप अगर देखेंगे तो पायेंगे, आपने किताबें पढ़ी नहीं, आपने तो 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान में चन्द्रशेखर आजाद के बारे में लिखा कि साथियों को फांसी देने के बाद उसका साहस टूट गया था। यह उस आजादी के दीवानों के बारे में आपने लिखने का काम किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विचारधारा थोपने के लिये जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया, 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान और इतिहास में आपने लिखा आरएसएस से जुड़े हुए संगठन जैसे राष्ट्रीय सेविका समिति, भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच को महिमा मंडन करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी का देश की आजादी में योगदान नहीं था? शहीद भगत सिंह का योगदान नहीं था? क्या जवाहर लाल नेहरू का योगदान नहीं था? यह संघ कहां से आ गये? आपने यहां तक भी कर दिया कि 'नोटबंदी भ्रष्टाचार पर विमुद्रीकरण का प्रभाव' नाम करके पुस्तकों में छपवा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस नोटबंदी के कारण से पूरे देश को 10 हजार करोड़ का नुकसान हुआ और सैकड़ों लोग लाइन में लगकर मर गये, उसके लिए आप बताइए क्या करना चाह रहे थे, इस पाठ्यक्रम में किस प्रकार से छेड़खानी करना चाह रहे थे, क्या-क्या करना चाह रहे थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। जो पाठ्यक्रम में है, मैं किताब साथ लेकर आया हूं, अगर आपको कहीं शक हो तो आप आजमा लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि हमने यह कर दिया, शिक्षा में यह कर दिया। आपकी सबसे बड़ी कमी क्या है? मैं निवेदन करना चाहता हूं जो मुझे लगी है आप अपनी चीज को ऐसे बेहतर दिखाते हैं, चाहे वह लोहा ही हो, आप उसे सोना दिखाना चाहते हैं। दूसरे का सोना हो तो कहते हैं कि यह तो पीतल है, इस सोने की तरफ मत जाना। आपमें यह कमी है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे। उन्होंने एक शब्द भी यह नहीं बोला कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में इतना कुछ दिया है, विद्यालयों के लिए यह काम किया है। नहीं, केवल एक बात, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया मैंने प्रोसीडिंग्स में पढ़ा है कि आप जब शिक्षा मंत्री थे, हमारे परसराम मदेरणा जी जब नेता, प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने आपकी वाहवाही की थी। आपकी बड़ाई की, आपने, गुलाबचन्द कटारिया, शिक्षा मंत्री रहते हुए अच्छा काम किया है। मैं समझता हूं, हम सबको करना पड़ेगा। ये चीजें करनी पड़ेंगी। जो संसाधन थे, आपने उसका सही सदुपयोग नहीं किया। उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं। आप देखिए, सौ से ज्यादा विज्ञान विषय में, वहां पर जीरो नामांकन, विज्ञान के अध्यापक और प्राध्यापक बैठे हैं। उर्दू के बच्चे 24, जहां एक भी बच्चा नहीं वहां उर्दू के लैक्चरर बैठे हैं। जहां कामर्स का एक भी बच्चा नहीं, वहां पर 33 बैठे हैं। दो साल में स्टाफिंग पैटर्न करना था। न आपने एलीमेंट्री का स्टाफिंग पैटर्न किया, न आपने माध्यमिक का स्टाफिंग पैटर्न किया। ये सब चीजें, जब आप विषय अध्यापक नहीं देंगे, जहां बच्चे हैं तो आप पढ़ाई की क्या उम्मीद करते हो। शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा? विशेष शिक्षक, जो मैंटली रिटायर्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए थे, उनको आपने जनरल के अगेन्स्ट लगा रखा था। ये सब चीजें करने की आवश्यकता थी, लेकिन आपका ध्यान केवल पाठयक्रमों के आधार अपनी विचारधारा थोपने पर रहा।

केवल इस तरह की चीज लेकर आये कि इसके ब्रांड एम्बेसडर हम, यह हमारा पेटेन्ट, मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब चीजों को हम लोगों को समझना होगा। 1999 में जब 21453 राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोली थीं, आपने क्या किया? पहले तो आते ही नाम चेंज कर दिया और दुबारा आते ही उन स्कूलों को बंद कर दिया। भाई, राजीव गांधी जी से इतनी चिढ़ क्यों है, वे भारत रत्न प्राप्त देश के प्रधान मंत्री थे। हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहीं कोई तकलीफ नहीं है। हमें मोदी जी से कहीं कोई तकलीफ नहीं है। केवल तकलीफ है तो विचारधारा से है। जिस गांधी परिवार ने, जिस महात्मा गांधी ने, जिस इंदिरा गांधी ने, जिस राजीव गांधी ने देश की एकता-अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये, उनके नाम बदल दो। उनकी योजनाओं के नाम बदल दो। पंडित दीनदयाल जी की बदल दो। अब नयी चीज लाइये न। पंडित दीनदयाल जी का

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कीजिये न, कौन मना कर रहा था, जब आपका समय था। आपने किया? क्यों नहीं किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने शिक्षाविदों को इसलिए ही नहीं हटाया कि पढ़ाइये, कहीं तकलीफ नहीं। यह जरूर सोचना पड़ेगा कि कहीं न कहीं इस शिक्षा को तो छोड़िए महाराज। इस शिक्षा के साथ तो राजनीति मत कीजिए। अगर शिक्षा के साथ राजनीति करेंगे तो अपने साथ गद्दारी करेंगे। इसके लिए ईश्वर हमें कभी माफ नहीं करेगा।

मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे शिक्षकों को चिकित्सक बनाना पड़ेगा। बच्चों को चिकित्सक बनाकर स्कूलों में भेजना पड़ेगा कि नब्ज टटोलिये यह बच्चा क्या चाहता है? उन गांव के लोगों को, अभिभावकों को विद्यालय तक लाना पड़ेगा। उनको सोशल आडिट करानी पड़ेगी, शिक्षकों का सम्मान करना पड़ेगा। जब सरकार जा रही थी तो शिक्षा का एक भी वर्ग चाहे शिक्षक हो, प्रिंसीपल हो, टीचर हो, बाबू हो, पैराटीचर हो, सारे के सारे हड़ताल पर बैठे थे, आपकी सरकार के खिलाफ धरना दे रहे थे। यह तो आचार संहिता लग गयी, वरना आज तक बैठे रहते। सरकार बदल गयी है, आज एक भी शिक्षक कहीं धरने पर है? एक भी शिक्षक कहीं प्रदर्शन कर रहा है? आपने जो कैलेंडर था, उसको चेंज करने का काम किया। आपने क्या किया, समय का परिवर्तन अपने हिसाब से कर लिया कि सुबह-सुबह शाखा में जाना पड़ेगा इसलिए थोड़ा-सा समय आगे-पीछे, इस तरीके से कर लो। अब जाइये न। इस स्वतंत्र भारत में सबको अधिकार है। शाखा वालों को है, शाखा लगाइये। जिसको सिनेमा जाना है सिनेमा जाइये। जो काम करना है, वह कीजिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। गलत बात नहीं। प्लीज। आप पेशेंस रखिए। आप नहीं बोलेंगे। आप सीनियर लीडर हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, दिक्कत यहीं पैदा हो गयी और कोई दिक्कत नहीं है। आपने भी ठीक काम किया है, कोई बुरा काम नहीं किया है। शिक्षा को कुछ न कुछ दिया ही है। आगे बढ़ाया है, स्कूलों में नामांकन भी हुए हैं। हमने उन नामांकन को आगे बढ़ाने के लिए, उन बच्चों को पर्यावरण प्रेमी बनाने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जितने नामांकन प्रदेश में बढ़ेंगे, उतने हम पेड़-पौधे लगाएं, यह आदेश दिया और आज उस आदेश की पालना हो रही है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने शाला दर्पण के माध्यम से सिटीजन विंडो दिया। इससे आप और हम देख सकते हैं कि हमारे प्रदेश में शिक्षा विभाग में क्या-क्या हो रहा है? हमने कहीं कुछ छिपाने का काम नहीं किया है। हम ट्रांसफर पालिसी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमने शाला दर्पण में एक पोर्टल दिया कि स्थानान्तरण भी आनलाइन लिये जाएंगे। ये जो रोज पर्चियां ले-लेकर आते हैं, इससे पूरे प्रदेश की बदनामी होती है और शिक्षक भी आहत होता है। इसलिए हमने कहा कि जब स्थानान्तरण होंगे तो आपको घर बैठे आनलाइन आवेदन करने की छूट रहेगी। यह हमने करने का काम किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना निवेदन करूंगा एक बात चली कि साहब, प्राइवेट स्कूल ऐसा कर रहे हैं। हमारे समय में माननीय न्यायाधिपति की अध्यक्षता में जब कमेटी बनी हुई थी, आपने 2016 में उसको क्यों चेंज किया? 2016 में हम वहां से खड़े-खड़े कहते थे कि यह मत कीजिए, यह ठीक नहीं है। प्राइवेट वालों को अपने आप फीस करने का अधिकार मत दीजिए। ये उसको पूल कर लेंगे और वही हुआ। आपने 2016 में इतना कमजोर बिल बनाया, मुझे निवेदन करना पड़ रहा है कि वह चार महीने बाद हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने एक आर्डर पारित किया कि इसको बलपूर्वक लागू नहीं किया जाए। यानी वह वहीं का वहीं खतम हो गया। जहां बना, वहीं का वहीं खतम हो गया। बलपूर्वक नहीं करो, इसका क्या मतलब हुआ? मैं समझता हूं, हमने ए.जी. को कहा कि यह आदेश हमारे समझ में नहीं आ रहा है। किसी एक्ट पर, आप एक धारा चैलेंज कर सकते हो, दो पर कर सकते हो, तीन पर कर सकते हो, लेकिन आप यह कहो कि राजस्थान की विधान सभा ने यह कानून बनाया, इस कानून पर आप कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, इससे गलत कोई बात नहीं हो सकती है। नेता, प्रतिपक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने साहस किया, हम किसी के दबाव में नहीं आये। ये जो बड़ी-बड़ी दुकानें चल रही हैं, जिनको आप दुकान बोलते हो, जिन्होंने भी गड़बड़ की हमने उनका लाइसेंस, उनकी मान्यता रद्द करने का काम किया। सीबीएसई से भी मान्यता निरस्त कराने का काम किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, वरना यह काम चलने वाला नहीं है। हमें हमारे डाइट्स को मजबूत करना पड़ेगा। आपने एक पैसा नहीं दिया। वहां से हटाकर पांचवीं और आठवीं का बोर्ड

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दे दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे कहा था कि डाइट मजूबत होगी तब तुम्हारे शिक्षक अच्छे होंगे और शिक्षक अच्छे होंगे तो हमारे बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की एजुकेशन मिलेगी। इसलिए हमने हमारी जो DL.Ed. की एग्जाम थी, जो कभी कोई यूनिवर्सिटी कराती थी और कभी कोई और कराती थी। हमने शिक्षा विभाग की इस संस्था के माध्यम से कराने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो पैसा डाइट मांगेगी, वह पैसा हम देने की स्थिति में होंगे। हमें वित्त विभाग की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। हमें दूसरे की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। ये काम आप भी कर सकते थे। लेकिन यूनिवर्सिटीज थीं, आ गयीं, ढोक लगा गयीं। अब की बार हमें दे दो, अब की बार मेरे को दे दो। ये कोई सीढ़ी थी क्या? कभी इस पड़ौसी को दे दो, कभी दायें वाले को दे दो, कभी बायें वाले को दे दो। हमारा विभाग भी तो यह कर सकता था, लेकिन हमने करने का काम नहीं किया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो चीज हमें करनी है, उसमें आपके सहयोग की पूरी अपेक्षा है। आपके सहयोग के बिना सम्भव नहीं है। यह बहुत बड़ा विभाग है। हमको उन बच्चों को खेल भी खिलाना पड़ेगा, उन टीचर्स को सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी। विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा भी मजबूत करना पड़ेगा। बच्चों को महापुरुषों की जीवनी के लिए हमें पुस्तकालय भी उपलब्ध कराना पड़ेगा, पुस्तकें भी उपलब्ध करानी पड़ेंगी। हमें खेल के लिए सामग्री भी देनी पड़ेगी। हमें अच्छे प्रशिक्षण भी देने पड़ेंगे। हम सबको क्वालिटी की एजुकेशन देने के लिए जो काम कर सकते हैं, वह सारा काम करना पड़ेगा और जो आने वाली शिक्षा नीति है, उसे हमें समझना पड़ेगा कि कहीं उसमें भी.. माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पर्यावरण की किताब है, उसमें बच्चे को फूल समझना था कि यह फूल होता है, तो वहां पर कमल का फूल 32 बार प्रयोग किया गया। उस पाठ्यक्रम में आप इससे ज्यादा और क्या कर सकते थे?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय नीति आ रही है, उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ घोषणाएं करना चाह रहा हूं कि हम...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): हम राज्य में 167 ब्लाक्स में चरणबद्ध रूप से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माध्यम) की स्थापना करने का कार्य करेंगे क्योंकि यूपीए सरकार के समय 186 माडल स्कूल थे, उसके बजाय 134 आपने स्कूल खोल दिये तो जो वंचित रह गये, उन 167 ब्लाक्स में हम अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय खोलने का काम करेंगे। हमारा मुख्य बिंदु किसान है। किसान को मजबूत करेंगे तभी हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हम सब मजबूत होंगे, हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। इसके लिए कृषि विषय ही नहीं है, कृषि संकाय ही नहीं है, इसलिए वर्तमान में संचालित कृषि विषय के स्थान पर विद्यालयों में पृथक से कृषि संकाय की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में संचालित कृषि विषय के स्थान पर विद्यालयों में पृथक से कृषि संकायों की स्थापना की जाएगी, 398 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हम लोग यह काम करेंगे।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणाएं कीं। पहले बजट में इतने विद्यालय नये क्रमोन्नति का, आज तक के इतिहास में तो कभी हुआ नहीं है। आपने तो जाते-जाते की थी, उसमें से भी 74 तो आप खोल ही नहीं पाये। आपकी वह लिस्ट पढ़ी थी, मैंने देखी थी, वह लैप्स ही हो गयी। जो आपने बजट में घोषणा की वह खोल ही नहीं पाये। राजकीय विद्यालय भवनों का सुदृढ़ीकरण, निर्माण एवं मरम्मत कार्य करवाने के लिए वर्ष 2019-20 में नाबार्ड आरआईडीएफ-15 अंतर्गत राज्य के 970 विद्यालयों में 3400 कक्षों एवं 134 सीडब्ल्यूएसएन शौचालयों के निर्माण हेतु राशि रुपये 400.09 करोड़ की परियोजना नाबार्ड को स्वीकृत करवाई जाकर निर्माण कार्य करवाए जाएंगे।

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में राशि रुपये 1181 करोड़ की लागत से विद्यालय सुदृढ़ीकरण हेतु 10651 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, स्मार्ट रूम, कम्प्यूटर कक्ष, आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त 23 नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण तथा 83 विद्यालयों के जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्म्त कराई जाएगी।

उत्कृष्ट कार्य हेतु शिक्षकों को सम्मानित करना जरूरी है। बिना शिक्षक को मजबूत किये, उसको बिना खुश किये हम ये लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पचास-साठ शिक्षकों को स्टेट लेवल पर सम्मानित किया जा रहा था, अब सरकार ने फैसला किया कि उत्कृष्ट कार्य हेतु शिक्षक दिवस पर सम्मानित किए जाने वाले शिक्षकों में वृद्धि करके पूरे प्रदेश में कुल 1101 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के सहयोग से श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं निर्धारित मानदंडों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को विभिन्न स्तरों पर श्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पूर्व में राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर एक माध्यमिक विद्यालय एवं एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को ही पुरस्कार दिये जाते थे। अब हमने फैसला किया है कि राज्य स्तर पर तीन, उच्च माध्यमिक विद्यालय एक लाख रुपये, माध्यमिक पचास हजार, जिला स्तर पर दो, पच्चीस हजार और उच्च माध्यमिक में भी पच्चीस हजार, माध्यमिक में भी पच्चीस हजार, ब्लाक स्तर पर एक यानी 301 ब्लाक्स में एक-एक, दस हजार रुपये उच्च माध्यमिक और माध्यमिक दोनों में करने का काम किया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसमें लोग जाते हैं। कोई भी काम होता है तो लोग घूमते रहते हैं। कभी कोई मिलता है, कभी कोई नहीं मिलता है इसलिए हमने शुरूआत की है कि हम विद्यार्थी हित में, विद्यार्थियों की सुविधा हेतु शुरूआत कर रहे हैं। सीकर और जोधपुर से लगभग पचास लाख रुपये की लागत से विद्यार्थी सेवा केन्द्र के भवनों का निर्माण करेंगे जिसको चरणबद्ध रूप से पूरे राज्य में ले जाएंगे जिससे किसी भी बच्चे को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जाकर भटकना नहीं पड़े।

स्टूडेंट पुलिस क्रेडेट योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। पहले केवल 39 विद्यालय थे, अब 930 राजकीय विद्यालयों और 70 केन्द्रीय विद्यालयों में संचालित किये जाने का निर्णय लिया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की क्रमोन्नति कर उच्च माध्यमिक किया जाएगा। शगुनोत्सव के अंदर राजकीय विद्यालयों का मूल्यांकन किया जाएगा।

आरटीई जिसके माध्यम से 25 परसेंट उस गरीब के बेटे को एडमिशन मिलता था, उसका क्राइटेरिया पहले ढाई लाख रुपये था, हमारी सरकार ने किया। आपने उसको बीपीएल पर किया। लोग हाई कोर्ट में गये। हाई कोर्ट ने आपके तमाचा मारा। आप फिर भी नहीं माने। आपकी ऐंठ नहीं गयी। उन गरीब बच्चों को नहीं देखा। अब हमारी सरकार ढाई लाख रुपये तक की आय की घोषणा करती है कि हम ढ़ाई लाख रुपये तक के बच्चों को लेंगे।

आंगनबाड़ी समन्वित राजकीय विद्यालयों एवं मॉडल स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का भी हम संचालन करेंगे। बालिकाओं के लिए विद्यालयों में इन्सीनेरेटर स्थापित किये जाएंगे। पर्यटकों से शिक्षा संवाद हेतु तंत्र विकसित किये जाएंगे। विद्यार्थियों के खेलकूद गतिविधियों में भाग लेने हेतु जो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

प्रोत्साहन राशि थी उसमें हमने वृद्धि करने का फैसला किया है। जिला एवं राज्य के ऊपर जो दैनिक भत्ते थे, वह 100 से 150 करेंगे। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दैनिक भत्ते 200 से 250 करेंगे और गणवेश की जो राशि थी खिलाड़ियों की, वह 750 से 1000 करेंगे जिला स्तर के लिए और राष्ट्रीय स्तर के लिए 1000 से 1500 करेंगे।

राज्य के 10176 आदर्श विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए वृहत स्तर पर आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता/भामाशाहों को आमंत्रित किया जाएगा। राजकीय विद्यालयों में कोई वार्षिकोत्सव नहीं होता था, केवल प्राइवेट में होता था, जिसको देखने के लिए आप और हम जाते थे। फीता काटने भी चले जाते थे। अब हमने निर्णय लिया कि उनका भी सम्मान होना चाहिए। गरीब के बच्चे ने क्या अन्याय किया है कि उसकी स्कूल में एनुअल फंक्शन नहीं होगा। इसलिए हमने फैसला किया कि इसके लिए भी हम बजट देने का काम करेंगे।

राज्य में राजकीय विद्यालयों के समस्त शिक्षकों को शिक्षक की पहचान पत्र एवं शिक्षक डायरी देने का काम करेंगे। शिक्षक की जेब में होना चाहिए, अगर वह कोई गड़बड़ करे तो भी उसका नाम, अगर अच्छा करे तो भी उसका नाम, उसकी जेब में रहना चाहिए कि मैं शिक्षक हूं, इससे उसका सम्मान बढ़ेगा। जिला कलेक्टर को भी जब वह कहेगा कि मैं शिक्षक हूं तो उसको बुलाना पड़ेगा, उसकी बात को सुनना पड़ेगा। हमने कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए एक्सपोजर आफ वोकेशनल एजुकेशन कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बढ़िया योजना हम लांच करने जा रहे हैं। शिक्षा विभागीय हितकारी निधि से प्राप्त अंशदान से इस वर्ष विभागीय कार्मिकों के पुत्र-पुत्रियों हेतु दो नई प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ करने की घोषणा मैं करता हूं। प्रथम योजना में राज्य के शिक्षा विभागीय कार्मिकों, जिसमें शिक्षक-बाबू सब आएंगे, के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर में कक्षा दस की बोर्ड परीक्षा में 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पुत्र-पुत्रियों के प्रोत्साहन के लिए, जिसमें प्रतिवर्ष स्कूल शिक्षा/संस्कृत शिक्षा के कुल 1000 विद्यार्थियों को एकमुश्त 11000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह बहुत बड़ा निर्णय है क्योंकि

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जब तक उसको नहीं लगेगा तो सरकारी स्कूलों में कौन आएगा? वह टीचर क्यों पढ़ाएगा? अब अपने आप वह टीचर वहां पर बच्चों को पढ़ाएगा कि मेरे को पढ़ाना भी है, विषय अध्यापक भी उपलब्ध होंगे और छात्रवृत्ति भी अलग से मिलेगी।

विद्यार्थियों के लिए युवा क्लब की स्थापना करनी पड़ेगी। जब तक बच्चा खेलेगा नहीं उसका शारीरिक विकास नहीं होगा। इसके लिए भी युवा क्लब विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सामूहिकता की भावना विकसित करने हेतु प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में युवा क्लब शुरू किए जाएंगे। कक्षा 9 से 12 के सभी छात्र क्लब में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 14027 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रति वर्ष युवा क्लब के तहत की जाने वाली गतिविधियों के लिए 25000 रुपये प्रति विद्यालय, कुल बजट 35.06 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने किया है। आप तो युवा-युवा बात करते हैं, हम युवा के लिए काम करते हैं। आप शिक्षक-शिक्षक बात करते हैं, हम शिक्षक के वैलफेयर के लिए काम करते हैं।

बाल मैग्जीन की सुविधा भी हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। विद्या भारती की तर्ज पर पढ़-पढ़कर ही तो काम खराब हो गया। जब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा तब तक नहीं ठीक होगा। प्रत्येक मनुष्य की पुस्तक अच्छी मित्र होती है। इसलिए हम 2019-20 के लिए 532.52 लाख रुपये का व्यय करेंगे और मैग्जीन छपवाकर उन विद्यालयों में बांटेंगे जिससे वह बच्चा पढ़ सके।

एक ओर घोषणा करना चाह रहा हूं एकल-द्वि पुत्री योग्यता पुरस्कार योजना। यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा संचालित योजना एकल-द्वि पुत्री योग्यता पुरस्कार योजना के तहत उच्च माध्यमिक से सभी संकायों एवं माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली पुरस्कार राशि बढ़ाये जाने की घोषणा करता हूं। राज्य स्तर पर उच्च माध्यमिक 31 हजार से 51 हजार, राज्य स्तर पर माध्यमिक 21 हजार से 31 हजार, जिला स्तर पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक 5 हजार से 11 हजार और एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट लूंगा। एक जंगल था, उसमें आग लग गयी। सब लोगों ने प्रयास किया कि मैं आग कैसे बुझाऊं, कैसे बुझाऊं और वहां जंगल में एक चिड़िया भी थी। वह चिड़िया भी एक बूंद चोंच भरे पानी की और आग बुझाने में लग गयी। चोंच भरे और आग बुझाने में पानी को डालने लग गयी। जब सब कुछ हो गया तो उसके बाद में कोई वृद्ध

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सज्जन थे उन्होंने कहा कि हे बेटी चिड़िया, तेरे से आग थोड़े ही बुझ रही थी, हम हजारों लोग लगे हुए थे, कितने संसाधन लगे हुए थे? तू यह काम क्यों कर रही थी? उसने कहा जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह लिखा जाएगा कि जब जंगल में आग लगी थी तब वह चिड़िया भी उस आग को बुझाने का प्रयास कर रही थी इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमेशा आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, सबको साथ लेकर, शिक्षा विभाग में माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा काम करेंगे कि जब आने वाला इतिहास होगा तो यह भी होगा कि एक मास्टर के बेटे को कभी शिक्षा मंत्री बनने का सौभाग्य मिला था और उसने शिक्षा की बाधा को ठीक करने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मौका दिया, मुझे तसल्ली से सुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,28,25,39,77,000 (तीन सौ अट्ठाइस अरब पच्चीस करोड़ उनतालीस लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 24 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,28,25,39,77,000/- (तीन सौ अट्ठाईस अरब पच्चीस करोड़ उनतालीस लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 22 जुलाई 2019 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 22.41 बजे सोमवार, 22 जुलाई 2019 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

श्रमिक कार्ड के प्रावधान

231. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के श्रमिकों को श्रमिक कार्ड जारी किये जाने के क्या प्रावधान हैं तथा कार्डधारी को क्या-क्या सुविधाएं/लाभ देय हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में कितने श्रमिक कार्ड जारी किये गये तथा इस अवधि में कार्डधारियों को क्या-क्या सुविधाएं/लाभ दिये गये? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में श्रमिक कार्ड जारी किये जाने हेतु कितने आवेदन लम्बित हैं? जिलेवार कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार लम्बित आवेदनों के निस्तारण के साथ ही श्रमिक कार्ड जारी किये जाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-12 एवं राजस्थान नियम, 2009 के नियम-44 के अन्तर्गत श्रमिकों का पंजीयन कर पहचान पत्र दिये जाने का प्रावधान हैं (परिशिष्ट-1)। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए 8 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। निर्माण श्रमिक का पंजीयन होने के बाद उक्त कल्याणकारी योजनाओं में पंजीकृत हिताधिकारी द्वारा आवेदन करने पर पात्रता की जांच उपरांत ''पहले आओ पहले पाओ'' के सिद्धांत पर लाभ दिया जाता है। संचालित योजना का विवरण परिशिष्ट-2 पर है।

(2) प्रदेश में गत 5 वर्षों में कुल 23,08,647 निर्माण श्रमिकों को हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत किया गया है (परिशिष्ट-3)। इस अवधि में कुल 4,43,670 हिताधिकारियों को मण्डल की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-4 पर है।

(3) प्रदेश में अब तक कुल 3,66,638 आवेदन लम्बित हैं। लम्बित

(राज्य मंत्री, श्रम)

आवेदनों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-3 में समाहित है। मुख्यत: निर्माण श्रमिकों द्वारा अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना, वांछित दस्तावेजों को आनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं करना एवं युक्तियुक्त समय में उनके द्वारा आक्षेप पूर्ति नहीं किए जाने के कारण आवेदन लम्बित है। इसके अतिरिक्त विभाग में श्रम निरीक्षकों के 188 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 85 पद रिक्त हैं तथा अधिकारियों के 83 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 51 पद रिक्त हैं। श्रम निरीक्षक/अधिकारियों के परिवीक्षाकाल में होने एवं विभाग के अन्य कार्य औद्योगिक संबंध, विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत प्राधिकारी का कार्य, प्रवर्तन आदि कार्य भी होने के कारण भी आवेदन लम्बित हैं। लम्बित आवेदनों का निस्तारण वरीयता के आधार पर ''पहले आओ पहले पाओ'' पद्धति से किया जा रहा है।

(4) श्रमिक कार्ड जारी करने की निश्चित समयावधि का निर्धारण भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं राजस्थान नियम, 2009 में यद्यपि नहीं किया गया है, तथापि नियमों में पंजीयन अधिकारी के इस आशय की सन्तुष्टि कि आवेदनकर्ता निर्माण श्रमिक है, होने पर पंजीयन किये जाने का प्रावधान है। मण्डल के आनलाइन पोर्टल पर ''पहले आओ पहले पाओ'' सिद्धान्त पर प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जाता है परन्तु वर्तमान में विभाग में अधिकारियों/निरीक्षकों की कमी, गत एक वर्ष में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के प्रभाव में होने के कारण पंजीयन कार्य का स्थगित रहने के कारण एवं बड़ी संख्या में विभाग के पोर्टल पर पंजीयन आवेदन प्राप्त होने के कारण लम्बित आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई है जिसके कारण युक्तियुक्त समय सीमा में श्रमिक कार्ड जारी होने का कार्य प्रभावित हुआ है। विभागीय स्तर पर पंजीयन व योजना आवेदनों के निस्तारण हेतु नियमित रूप से समीक्षा की जाकर गति लाई जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मुण्डावर में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाएं

232. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं?

(2) क्या उक्त सभी आंगनबाड़ी केन्द्र पक्के भवनों में संचालित हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बिजली, पानी व शौचालय आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो ऐसे कितने केन्द्रों पर उक्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जिन केन्द्रों पर उक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं वहां सरकार सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में कुल 363 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं जिसमें 345 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र व 18 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। इस विधान सभा क्षेत्र में नीमराना परियोजना का आंशिक क्षेत्र व मुण्डावर परियोजना का सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है, जिसमें नीमराना परियोजना के 68 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र व 7 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र, कुल 75 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं तथा मुण्डावर परियोजना के 277 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र व 11 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र, कुल 288 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं।

(2) जी हां। सभी आंगनबाड़ी केन्द्र पक्के भवनों में संचालित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	**भवन**	**केन्द्र संख्या**	**मिनी केन्द्र संख्या**
1	विभागीय भवन	70	0
2	विद्यालय भवन	167	11
3	नि:शुल्क सामुदायिक भवन	41	02
4	किराये के भवन	27	02
5	पंचायत/चिकित्सा भवनों में संचालित	14	0
6	नि:शुल्क भवन	26	03
	कुल	**345**	**18**

(3) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

क्र.सं.	सुविधाओं का विवरण	संख्या
1	पेयजल सुविधा वाले केन्द्र	204
2	शौचालय सुविधा वाले केन्द्र	185
3	बिजली सुविधा वाले केन्द्र	0

विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) जी हां। समय-समय पर सुविधाविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वित्तीय संसाधन एवं बजट की उपलब्धता पर पेयजल व शौचालय की व्यवस्था करवायी जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किसान के कर्ज माफी की राशि को किसानों के खाते में जमा कराने की योजना

234. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसानों की कर्जमाफी की गई है? कर्जमाफी की राशि अब तक किसानों के खातों में जमा क्यों नहीं की गई? इसमें विलम्ब के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के किसानों की ऋण माफी की जा रही है। राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 के प्रावधान अनुसार कृषक द्वारा आधार आधारित अभिप्रमाणन किये जाने के पश्चात् खाते में प्रविष्टि की जाकर ऋण माफी प्रमाण-पत्र जारी करते हुए ऋण माफ किये जा रहे हैं।

झाड़ोल में संचालित ग्रामीण बस सेवा

235. श्री बाबुलाल (झाड़ोल): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्रामीण बस सेवा संचालित की जा रही है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के किन-किन गांवों में बस सेवा संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिन गांवों की बस सेवा बन्द है उन गांवों में पुन:

(श्री बाबुलाल)

बस सेवा चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के जिन गांवों में राजस्थान परिवहन निगम द्वारा वर्तमान में बस सेवा संचालित की जा रही है उनका विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) राजस्थान सरकार की जन घोषणा में "ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर-दराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना" का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मुकन्दरा टाइगर रिजर्व में बाघों को बसाने की योजना

236. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा के मुकन्दरा टाइगर रिजर्व में बाघों को बसाकर पर्यटन के लिए कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

(2) उक्त कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं?

(3) मुकन्दरा टाइगर रिजर्व में बाघों के अलावा कौन-कौन से जीवों को रखा जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कौन-कौनसे कार्य करवाये जाएंगे?

(5) उक्त क्षेत्र के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने अब तक कितना बजट आबंटित किया है तथा उसमें से कितनी राशि के कौन-कौनसे कार्य हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की सहमति प्राप्त होने के उपरान्त मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व उद्घोषित किया गया। वर्तमान में इस टाइगर रिजर्व में चार बाघ हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की मार्गदर्शिका दिनांक 15.10.2012 के अनुरूप इस रिजर्व में पर्यटन योजना प्रस्तावित है।

(राज्य मंत्री, वन)

(2) बाघ पुनर्स्थापित करने का कार्य अत्यन्त दुष्कर, जटिल एवं समय लेने वाले होता है, क्योंकि क्षेत्र का पर्यावास सुधार (Habitat improvement) एवं प्रे-बेस सुधार का कार्य किया जाना होता है। उक्त कार्य में विलम्ब इसी कारण से हुआ है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की मार्गदर्शिका दिनांक 15.10.2012 के अनुरूप इस रिजर्व में पर्यटन योजना प्रस्तावित है।

(3) वर्तमान में मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघों के अलावा संलग्न परिशिष्ट-I के अनुसार वन्यजीव विचरण कर रहे हैं।

(4) मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की मार्गदर्शिका दिनांक 15.10.2012 के अनुसार कार्य पूर्ण कर पर्यटन योजना में प्रस्तावित कार्यों को कराया जाएगा।

(5) मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र का गठन वर्ष 2012 में हुआ है। गठन होने के पश्चात् केन्द्रीय प्रवर्तित योजना 1259.05 लाख रुपये के विरुद्ध 867.48 लाख रुपये, कैम्पा योजना में 3501.50 लाख रुपये के विरुद्ध 2400.95 लाख रुपये, एफ.पी.एम. योजना में 53.83 लाख रुपये के विरुद्ध 29.705 लाख रुपये, नाबार्ड योजना में 1359.65 लाख रुपये के विरुद्ध 1239.86 लाख रुपये, फोर वाटर कांसेप्ट योजना में 62.85 लाख रुपये के विरुद्ध 55.89 लाख रुपये, आरपैक योजना में 2955.484 लाख रुपये के विरुद्ध 2817.87 लाख रुपये, राज्य योजना में 94.18 लाख रुपये के विरुद्ध 90.14 लाख रुपये, तेरहवीं वित्त आयोग योजना में 156.70 लाख रुपये के विरुद्ध 151.76 लाख रुपये, ईको टूरिज्म योजना में 100.38 लाख रुपये के विरुद्ध 83.93 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। किये गये कार्यों का योजनावार विवरण परिशिष्ट-II पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैतून की कृषि को प्रोत्साहन

238. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में जैतून की कृषि की जा रही है? यदि हां, तो कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जैतून की कृषि में रूचि रखने वाले काश्तकारों को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से

(श्री पब्बाराम)

लाभान्वित किया जा रहा है? यदि हां, तो किन-किन योजनाओं के द्वारा एवं किस प्रकार से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फलोदी के जैतून की कृषि में रूचि रखने वाले काश्तकारों को प्रोत्साहन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे? कब तक एवं नहीं, तो क्यों

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में जैतून की कृषि की जा रही है। निम्न जिलों में वर्तमान में जैतून की कृषि की जा रही है-

1. बीकानेर 2. श्रीगंगानगर 3. हनुमानगढ़ 4. नागौर 5. चूरू 6. जैसलमेर 7. अलवर 8. बारां 9. सीकर 10. जोधपुर 11. झुंझुनूं 12. झालावाड़ 13. जयपुर

(2) जी हां। वर्ष 2012-13 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा वर्ष 2015-16 से नेशनल मिशन आन आयल सीड्स एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-वृक्ष जनित तिलहन योजना तथा वर्तमान में वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-वृक्ष जनित तिलहन के माध्यम से जैतून की कृषि में रूचि रखने वाले काश्तकारों को प्रोत्साहन देने हेतु लाभान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-वृक्ष जनित तिलहन अन्तर्गत निम्नानुसार अनुदान देय हैः-

1. पौधरोपण सामग्री पर अनुदान:- बगीचों की स्थापना के लिए पौधरोपण की वास्तविक लागत या अधिकतम राशि रुपये 48000/- प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो, का अनुदान देय है।
2. पौधों के संधारण पर अनुदान:- जैतून के उद्यानों के रख-रखाव एवं उर्वरक, पौध संरक्षण रसायन आदि पर राशि रुपये 3200/- प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष की दर से प्रथम चार वर्षों तक दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुदान सीधा किसान के बैंक खाते में देय है।
3. अन्तरशस्य पर अनुदान:- जैतून से उत्पादन शुरू होने तक फसलों

(कृषि मंत्री)

की अन्तरशस्य रूप में खेती करने हेतु राशि रुपये 1000/- प्रति हैक्टेयर की दर से प्रथम चार वर्षों तक महत्वपूर्ण आदानों पर अनुदान सीधा किसान के बैंक खाते में देय है।

(3) जी हां। सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र फलौदी के जैतून की कृषि में रूचि रखने वाले काश्तकारों को प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष 2017-18 से जोधपुर जिले को शामिल कर दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुदान दिया जा रहा है।

श्रमिकों को शुभशक्ति योजनान्तर्गत देय सहायता

239. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों अथवा हिताधिकारी श्रमिक महिला के विवाह पर सरकार द्वारा शुभशक्ति योजना के माध्यम से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है? यदि हां, तो उक्त योजना कब से प्रभावी है? योजना में पात्र व्यक्तियों के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? नियम व शर्तों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के प्रारम्भ होने से लेकर अब तक जिला चित्तौड़गढ़ में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा प्राप्त आवेदनों में से कितने श्रमिकों को उनकी पुत्रियों एवं हिताधिकारी महिलाओं को उनके विवाह पर सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है? जिन आवेदनों को निरस्त किया गया है उसका क्या कारण रहा? उक्त जिले के विधान सभा क्षेत्रवार आवेदकों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बढ़ती महंगाई को देखते हुए उक्त योजना में सहायता राशि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों अथवा महिला हिताधिकारी के विवाह पर सहायता दिलाने हेतु मण्डल की योजना हिताधिकारी की पुत्री/ महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना दिनांक 31.12.2015 को समाप्त कर दिनांक 01.01.2016 से शुभशक्ति योजना लागू की गई थी। इस योजना में प्रोत्साहन राशि लड़की अपने विवेकानुसार आगे शिक्षा या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, स्वयं का व्यवसाय या सूक्ष्म उद्योग प्रारम्भ कर सके या कौशल विकास करने हेतु दी जाती है। उक्त योजना में लड़की को स्वयं के विवाह हेतु राशि व्यय करने की छूट भी प्रदान की गई है। योजना के लाभ हेतु पंजीकृत महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की पुत्रियां वयस्क, अविवाहित एवं शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम आठवीं कक्षा पास होना आवश्यक है। शुभशक्ति योजना का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी शुभशक्ति योजना के अन्तर्गत चित्तौड़गढ़ जिले में कुल 7,358 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा 1,853 श्रमिकों की पुत्रियां एवं महिला हिताधिकारियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। हिताधिकारी का निर्माण कार्य में नियोजन नहीं पाये जाने, पुत्री विवाहित होने, अवयस्क होने, आठवीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं होने, प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों में काट-छांट होने अथवा पंजीयन तिथि से 3 माह पूर्ण होने से पूर्व आवेदन किये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त करने के प्रमुख कारण रहे हैं। विधान सभा क्षेत्रवार आवेदकों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा उपकर राशि से प्राप्त फण्ड का उपयोग अधिनियम 1996 में किये गये प्रावधान एवं धारा-60 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार मण्डल की अनुमति से ही किया जा सकता है। वर्तमान में मण्डल की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सहायता राशि बढ़ाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

240. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा बीकानेर जिले में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं?

(श्री सुमित गोदारा)

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितने केन्द्रों में स्वयं के भवन हैं?

(3) क्या सरकार भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा बीकानेर जिले में 1314 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 142 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र, कुल 1456 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं।

(2) बीकानेर जिले में कुल 1456 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। जिनके भवनों की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विवरण	संचालित केन्द्र संख्या
1	विभागीय भवनों में संचालित	631
2	किराये के भवनों में संचालित	167
3	विद्यालयों में संचालित	319
4	अन्य सरकारी भवनों में संचालित	300
5	नि:शुल्क भवनों में संचालित	39
	योग	**1456**

(3) आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/ स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग दवारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर पंचायती राज एवं स्थानीय निकायों से आंगनबाड़ी भवन निर्माण करवाया जाता है।

लावारिस पशुधन का पुनर्वास

241. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पशुधन, विशेषकर गौवंश लावारिस हैं? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

(2) प्रदेश में लावारिस पशुओं के पुनर्वास/पोषण हेतु सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्राय: अनुत्पादक, अनुपयोगी, रोगग्रस्त, वृद्ध एवं अपंग गौवंश को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों/गौपालकों द्वारा लावारिस छोड़ दिया जाता है।

(2) लावारिस गौवंश के पुनर्वास हेतु प्रदेश की गौशालाओं/गौपुनर्वास केन्द्रों में संरक्षित किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सड़क पर घूमने वाले आवारा नर गौवंश हेतु नंदी गौशाला जनसहभागिता योजना तथा बीकानेर में निराश्रित गौवंश के पुनर्वास हेतु गौअभयारण्य की स्थापना की जा रही है।

सड़कों पर विचरण कर रहे निराश्रित गौवंश को गौशाला के रूप में एक आश्रय स्थल मिला है, जिससे सड़क दुघर्टनाओं में कमी आयी है तथा किसानों की फसल नष्ट होने से बची है। लगभग 3 लाख निराश्रित गौवंश गौशालाओं में आ गया है। निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में उपचार एवं कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध हो सकी है, जिससे गुणात्मक रूप से नस्ल संवर्धन के कार्य में वृद्धि हुई है। इन लावारिस गौवंश के लिये निधि नियम 2016 के अंतर्गत पोषण हेतु सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।

आमेर में बसों का संचालन

243. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान पथ परिवहन निगम की कितनी बसों का संचालन हो रहा है? क्या सरकार इनमें से बंद की गयी बसों के संचालन को पुन: शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान परिवहन निगम की संचालित वाहनों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है। आमेर विधान सभा क्षेत्र की एक मात्र जैतपुर-खींची संचालित निगम वाहन को कम आय/यात्रीभार आने के कारण दिनांक 16.03.2015 से बंद किया गया है जिसका छह माह का आय/यात्रीभार का विवरण निम्नानुसार है:-

(परिहवन मंत्री)

क्र.सं.	**माह**	**आय प्रति कि.मी. (रुपये)**	**यात्रीभार (प्रतिशत)**
1	अक्टूबर	15.78	45
2	नवम्बर	17.72	51
3	दिसम्बर	17.54	50
4	जनवरी	18.43	53
5	फरवरी	17.17	49
6	मार्च	17.86	51

वित्तीय साध्यता के आधार पर बस संचालन पर विचार किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजनान्तर्गत श्रमिकों का पंजीयन

247. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना 2019 में प्रदेश के प्रत्येक संभाग में कितने श्रमिकों का पंजीयन किया गया? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को जीवनवृति (पेंशन) लाभ की उक्त योजना का प्रदेश के श्रमिकों को अधिकतम लाभ मिले, इसके लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(3) प्रदेश में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के कल्याण के लिए विगत पांच वर्षों में उनसे लाभान्वित श्रमिकों की संभागवार संख्या और ऐसी प्रत्येक योजना पर किये गये कुल परिव्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना 2019 केन्द्र सरकार की एक योजना है, जिसका क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) तथा अधिकृत Common Service Centre e-Governance Services India Ltd. (CSC SPV) के माध्यम से किया जाता है। श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक संभाग में पंजीयन किये गये श्रमिकों की जिलेवार संख्या परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(श्रम मंत्री)

(2) हालांकि योजना का पूर्ण संचालन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है फिर भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जीवन वृत्ति (पेंशन) लाभ की इस योजना का प्रदेश के श्रमिकों को अधिकतम लाभ देने संबंधी राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयास परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) निर्माण श्रमिक भी असंगठित क्षेत्र में आते हैं। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार की वर्तमान योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। विगत 5 वर्षों में लाभान्वित निर्माण श्रमिकों की सम्भागवार संख्या परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। प्रत्येक योजना पर विगत 5 वर्षों में किया गया कुल परिव्यय परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों के लिए बीमा योजना

248. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत मानदेय कर्मियों के कल्याण हेतु सामूहिक बचत आधारित बीमा योजना में देय अंशदान समाप्त किया गया है? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितनी-कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाभान्वित हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना में सभी महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभान्वित किया जा चुका है? यदि नहीं, तो किस-किस जिले में कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाभान्वित होने से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में उक्त योजना से लाभान्वित सभी महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व वंचित कार्यकर्ता का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत मानदेय कर्मियों के कल्याण हेतु सामूहिक बचत आधारित बीमा योजना में मानदेय कर्मियों द्वारा देय अंशदान को समाप्त किया जा चुका है तथा अब सम्पूर्ण अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। जिलेवार लाभान्वित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत मानदेय कर्मियों के कल्याण हेतु सामूहिक बचत आधारित योजना में 01.01.2014 से पूर्व नियुक्त समस्त मानदेय कर्मियों को लाभान्वित किया जा चुका है। 01.01.2014 तथा

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

इसके पश्चात् नियुक्त मानदेय कर्मी इस योजना के लाभ से वंचित हैं। जिलेवार वंचित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में इस योजना से लाभान्वित महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या 272 तथा इस योजना से वंचित होने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या 17 है जिनका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

माण्डलगढ़ में बनास नदी में अवैध बजरी खनन

249. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में सुप्रीम कोर्ट का स्टे होने के उपरान्त भी बनास नदी में अवैध रूप से बजरी खनन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में माण्डलगढ़, बिजौलिया व कोटड़ी तहसील के पुलिस थानों में अवैध बजरी दोहन को लेकर बजरी माफियाओं के विरुद्ध गत दो वर्षों में कोई कार्यवाही हुई है? यदि हां, तो कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही हुई? थानावार एवं अपराधियों के नामवार सहित खनन की जगह तथा उस पर हुई कार्यवाही का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उक्त विधान सभा क्षेत्र की बनास नदी में हो रहे अवैध बजरी खनन पर पूर्णत: रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कैसे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.11.2017 से प्रदेश में नदी-नालों से खनिज बजरी खनन पर रोक लगाने के पश्चात् विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध की गई कार्यवाही के दौरान बनास नदी से भी चोरी-छिपे अवैध रूप से बजरी का खनन किये जाने के प्रकरण सामने आये हैं।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में माण्डलगढ़, बिजौलिया एवं कोटड़ी तहसील के पुलिस थानों में बजरी के अवैध खनन, निर्गमन एवं भण्डारण के विरुद्ध गत दो वर्षों में 216 एफ.आई.आर. दर्ज की गयीं। थानावार

(खान मंत्री)
अपराधियों के नाम, खनन की जगह तथा उस पर हुई कार्यवाही का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। राज्य सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बनास नदी में अवैध खनन पर पूर्ण रोक लगाने हेतु कृत संकल्प है। इस हेतु जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा द्वारा आदेश दिनांक 31.05.2018 से विशेष जांच दल का गठन किया गया एवं दिनांक 21.06.2019 से खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की रोकथाम हेतु राजस्व, वन, परिवहन, खान एवं पुलिस विभाग को शामिल करते हुए जिले में 6 दलों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा समस्त जिले के साथ-साथ विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में भी कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.07.2019 से एक माह की अवधि के लिये राज्य व्यापी अभियान चला रखा है, उसके अन्तर्गत भी माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कार्यवाही की जा रही है। विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रोक दिनांक 16.11.2017 से 30.06.2019 तक अवैध बजरी खनन, निर्गमन व भण्डारण के 659 प्रकरण बनाये गये हैं, जिनसे शास्ति राशि रुपये 445.68 लाख वसूल की गई एवं 216 मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मालपुरा के किसानों को कृषि ऋण माफी

250. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों के कृषि ऋण माफ किये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के किसानों के कृषि ऋण माफ किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के किसानों के भी कृषि ऋण माफ किये गये? यदि हां, तो इस योजना से कितने किसान लाभान्वित हो चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऋण माफी योजना से वंचित किसानों को लाभ दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। किसानों के ऋण माफ करने की पात्रता एवं प्रक्रिया

(सहकारिता मंत्री)

निर्धारित करते हुए राज्य सरकार ने दिनांक 07.02.2019 को निम्न दो योजनाएं जारी की हैं:-

1. राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019
2. मध्यकालीन/दीर्घकालीन कृषि ऋणों के लिए "राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019" (सहकारी मध्यकालीन/दीर्घकालीन कृषि ऋण माफी)

दोनों योजनाओं की प्रतियां परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के 15953 किसानों के कृषि ऋण माफ किये गये हैं।

(3) योजना की पात्रता अनुसार ऋण माफी का लाभ दिया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नोखा के पांचू ग्राम में नवीन बस स्टैण्ड का निर्माण

251. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या विधान सभा क्षेत्र नोखा के ग्राम पांचू में बाजार में बसों के ठहराव के कारण यातायात बाधित रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में नवीन बस स्टैण्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की विधान सभा क्षेत्र नोखा पांचू गांव में निगम की स्वयं की कोई भूमि नहीं है। फिलहाल निगम के सीमित संसाधनों के कारण पांचू गांव में बस स्टैण्ड बनाने का कोई विचार नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बामनवास में संचालित पशु चिकित्सालय

270. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में पशु चिकित्सालय खोलने के मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वर्तमान में कुल कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां संचालित हैं तथा क्या उक्त पशु चिकित्सालयों में सभी सुविधाएं हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में पशु चिकित्सालय खोलने के मापदंड की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में स्वीकृत पशु चिकित्सालयों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय**	**पशु चिकित्सालय**
1	बामनवास	सुकार
2	बौंली	भांवरा
3	बरनाला	बाटोदा
4		मित्रपुरा
5		पीपल्दा

उक्त में से पशु चिकित्सालय भांवरा एवं पीपल्दा, पशु चिकित्सा कर्मियों के पद रिक्त रहने के कारण अक्रियाशील हैं। शेष पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा एवं नस्ल सुधार संबंधित समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(पशुपालन मंत्री)

(3) जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोली जाती हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अधिक कृषि उपज हेतु संचालित योजनाएं

271. श्री रूपा राम (मकराना): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कृषि विस्तार हेतु कृषि अनुसंधान द्वारा अधिकाधिक उपज हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषकों को सुविधाएं प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र मकराना व नावां के कृषकों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कृषि विस्तार हेतु अधिकतम उपज हेतु निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं :-

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
2. राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन
3. परम्परागत कृषि विकास योजना
4. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
5. सबमिशन आन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन
6. राष्ट्रीय बागवानी मिशन

(2) जी हां। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें कृषकों को विभिन्न जैविक गतिविधियों यथा- भूमि का जैविक परिवर्तन, फसल पद्धति एवं जैविक बीज, जैविक आदान उत्पादन इकाई, हरी खाद, प्रोम आदि हेतु योजनान्तर्गत तीन वर्षों में प्रथम वर्ष में 12000, द्वितीय वर्ष में 10000 एवं तृतीय वर्ष में 9000 रुपये की सहायता देय है। इसी प्रकार केन्द्रीय प्रवर्तित योजना, राष्ट्रीय

(कृषि मंत्री)

बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिये जाने हेतु विभिन्न कार्यक्रम जैसे जैविक खेती अपनाने, जैविक प्रमाणीकरण, वर्मी कम्पोस्ट इकाई/जैविक आदान उत्पादन एवं एचडीपीई वर्मी बेड इकाई क्रियान्वित किये जा रहे हैं। जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन कृषकों को राज्य स्तर पर एक-एक लाख रुपये राशि के पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

(3) कृषि विभाग द्वारा परम्परागत कृषि विकास योजना तथा उद्यान विभाग की योजनाओं से लाभान्वित विधान सभा क्षेत्र मकराना व नावां के कृषकों का विवरण परिशिष्ट-**1** पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ऊंट पालकों को संरक्षण

272. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार ऊंट पालकों को ऊंटों के संरक्षण के लिए कोई सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या ऊंटों को राज्य पशु घोषित करने के बाद इनके राज्य से बाहर बिक्री पर रोक लगाई गई है? यदि हां, तो क्या सरकार ऊंटों की बिक्री पर लगी रोक को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या प्रदेश में ऊंटों को राज्य पशु घोषित करने के बाद उनके चरागाह के लिए किसी तरह की भूमि अथवा वन क्षेत्र में उनके चरने के लिए भूमि को आरक्षित किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां, किस किस्म की और कितनी भूमि का आरक्षण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में ऊंटों के संरक्षण एवं ऊंट पालकों को ऊंटों के प्रजनन हेतु प्रोत्साहित करने के लिये प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत ''उष्ट्र विकास योजना'' 2 अक्टूबर, 2016 से प्रारम्भ की गई है जिसमें ऊंटनी के ब्याने पर उत्पन्न प्रति नर/मादा टोरडिये हेतु तीन किस्तों में राशि रु. 10000/- प्रति टोरडिये की सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

(पशुपालन मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

भीलवाड़ा जिले में संचालित गौशालाएं

273. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भीलवाड़ा जिले में कितनी गौशाला संचालित की जा रही हैं उन गौशालाओं में कितनी गायें एवं बछडे वर्तमान में रह रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संचालित गौशाला में गायों व बछड़ों के लिए खाने-पीने एवं छाया व्यवस्था किस प्रकार की जा रही है? सरकार द्वारा प्रति गाय कितना अनुदान दिया जा रहा है? अनुदान राशि देना कब से प्रारम्भ किया गया है? इन संचालित गौशाला में से कितनी रजिस्टर्ड हैं और कितनी अनरजिस्टर्ड चल रही हैं? अनरजिस्टर्ड को रजिस्टर्ड करने की कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी एवं नयी गौशाला खोलने पर सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता एवं किस-किस मद में उपलब्ध करवायी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में 45 गौशालाएं संचालित हैं। इन गौशालाओं में वर्तमान में कुल 9492 बड़े एवं 3856 छोटे गौवंश संधारित हैं।

(2) समस्त संचालित गौशालाओं में गायों एवं बछड़ों के लिए खाने पीने एवं छाया व्यवस्था गौशाला संचालकों द्वारा की जाती है।

सरकार द्वारा गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 के तहत 200 या अधिक गौवंश संधारित करने वाली तथा दो वर्ष या अधिक अवधि से पंजीकृत गौशालाओं/कांजी हाउस में आवासित गौवंश के पालन-पोषण के लिए चारा-पानी एवं पशुआहार हेतु बड़े गौवंश हेतु रु. 32 तथा छोटे गौवंश हेतु 16 रु. प्रतिदिन, प्रति गौवंश की दर से वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में 90 दिवस हेतु सहायता राशि दी गई।

वर्ष 2018-19 में दिवसों की संख्या को 90 से बढ़ाकर 180 दिवस कर दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में गौशालाओं में संधारित गौवंश को सहायता राशि की दर बड़े गौवंश हेतु रु. 32 से बढ़ाकर रु. 40 प्रति गौवंश प्रतिदिन एवं

(गोपालन मंत्री)

छोटे गौवंश हेतु रु. 16 से बढ़ाकर रु. 20 प्रति गौवंश प्रतिदिन किये जाने के संबंध में आदेश प्रसारित किया जा चुका है।

इन संचालित गौशालाओं में समस्त 45 गौशालाएं पंजीकृत हैं।

नई गौशाला खोलने पर सरकार द्वारा सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है।

शेरगढ़ के बालेसर क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों का निर्माण

274. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के बालेसर क्षेत्र में खनिज सेण्डस्टोन के खनन पट्टा क्षेत्र में विभिन्न सम्पर्क सड़कों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के खनिज क्षेत्रों में सड़कें, पेयजल, स्वास्थ्य केन्द्र जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के बालेसर के खनन क्षेत्र में बालेसर तिबना खिरजा सड़क (ओ.डी.आर.) किलोमीटर 0/0 से 10/0 तक (राज्य सड़क निधि योजना में) सुदृढ़ीकरण हेतु रुपये 856.10 लाख तथा अमृत नगर से डेरडी किलोमीटर 0/0 से 2/0 तक (मिसिंग लिंक योजना 2018-19 में) नवीन सड़क निर्माण हेतु रुपये 40.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त है जिसका कार्य प्रारम्भ होना शेष है।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के खनन क्षेत्रों में सड़क निर्माण/ सुदृढ़ीकरण के विचाराधीन प्रस्ताव का विवरण प्रश्न के भाग संख्या 1 के जवाब में उल्लेखित अनुसार है। इसके अतिरिक्त गांव बालेसर, सियान्दा व तिबना में पेयजल हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल की व्यवस्था की हुई है। खनिज क्षेत्र में श्रमिकों के पीने के पानी की व्यवस्था खान

(खान मंत्री)

धारकों द्वारा की जाती है। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में 12 चिकित्सा संस्थान हैं जिन पर मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना के अन्तर्गत निर्धारित जांचें तथा मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत सभी औषधियां (आवश्यक दवा सूची अनुसार) उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में 108 एम्बुलेंस व 104 जननी एक्सप्रेस की सुविधा उपलब्ध है।

उपरोक्त के अतिरिक्त सड़क, पेयजल एवं स्वास्थ्य केन्द्र जैसी बुनियादी सुविधाओं का अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रिफाइनरी क्षेत्र में सुविधाएं विकसित करने हेतु आबंटित बजट

275. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में रिफाइनरी का कार्य कब तक पूर्ण कर उत्पादन कब तक प्रारम्भ हो जायेगा? वर्ष 2018-19 व 2019-20 में रिफाइनरी हेतु कितनी राशि शेयर कैपिटल व ऋण के रूप में जारी की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रिफाइनरी के आसपास सरकार ने इण्डस्ट्रियल कोरिडोर, टाउनशिप आदि सुविधाएं विकसित करने का कोई नीतिगत निर्णय लिया है? यदि हां, तो इस हेतु कितना बजट आबंटित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में रिफाइनरी का कार्य अक्टूबर, 2022 तक पूर्ण होने की संभावना है। रिफाइनरी के पूर्ण हो जाने के 6-9 महीने के पश्चात् उत्पादन प्रारम्भ होने की संभावना है। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में रिफाइनरी हेतु शेयर केपिटल निम्नानुसार जारी किये गये हैं:-

क्र.सं.	**वर्ष**	**कम्पनी/ राज्य सरकार**	**(राशि करोड़ रुपये में)**
1	2018-19	एच.पी.सी.एल.	701.668
		राज्य सरकार	246.532
		कुल	**948.200**

(खान मंत्री)

क्र.सं.	वर्ष	कम्पनी/ राज्य सरकार	(राशि करोड़ रुपये में)
2	2019-20 (माह जून, 2019 तक)	एच.पी.सी.एल.	259.00
		राज्य सरकार	91.00
		कुल	**350.00**

आदिनांक तक ऋण के रूप में कोई राशि जारी नहीं की गई है।

(2) जी हां। सरकार ने रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स परियोजना पर आधारित प्लास्टिक, रबर, डिटर्जेंट, फाइबर, ल्युब्रिकेंट, डाई, ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स, पेंट, कास्मेटिक्स आदि उद्योगों को राज्य में स्थापित करने के उद्देश्य से रीको के माध्यम से इन्टीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल जोन विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु रीको द्वारा एक कन्सल्टिंग एजेन्सी की सेवाएं ली जा रही हैं जिस पर अनुमानित रुपये 8.5 करोड़ (कर अतिरिक्त) की स्वीकृति रीको बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की बैठक में जारी की गई। कन्सल्टिंग एजेन्सी द्वारा वायबिलिटी स्टडी कर इन्टीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल जोन की वृहद् परियोजना रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करने के उपरान्त ही परियोजना रिपोर्ट अनुसार आवश्यक बजट का प्रावधान किया जायेगा।

जयपुर में ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति का अंकेक्षण

276. श्री गोविन्द राम (खाजूवाला): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर द्वारा पंजीयन के समय समिति के कार्यक्षेत्र का एरिया कहां तक था, वर्तमान में कहां तक है एवं उक्त समिति द्वारा अब तक कौन-कौनसी आवासीय व कामर्शियल योजनाएं कहां-कहां पर बनाई गई व उनमें कितने भूखण्ड काटे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समिति का पंजीयन कब हुआ? पंजीयन के समय समिति की कार्यकारिणी के सदस्य एवं अध्यक्ष, मंत्री कौन-कौन थे? उक्त समिति की कार्यकारिणी के चुनाव कब-कब करवाये गये एवं वर्तमान में कार्यकारिणी में कौन-कौन सदस्य हैं? पंजीयन से अब तक के सदस्यों के नाम, पद, पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समिति का अंकेक्षण कब-कब व किस-किस के द्वारा

(श्री गोविन्द राम)

करवाया गया? अंकेक्षण में क्या-क्या कमियां पाई गई? क्या सरकार उक्त समिति के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) क्या उक्त समिति वर्तमान मे कार्यरत है या नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर का कार्यक्षेत्र समिति के पंजीकृत उपनियमों के अनुसार निम्न प्रकार है-

1 पंजीयन के समय:- समिति का कार्यक्षेत्र नगर परिषद् क्षेत्र जयपुर तक सीमित होगा।

2 वर्तमान में:- इस समिति का कार्यक्षेत्र जयपुर नगर निगम के सीमाक्षेत्र के अन्तर्गत केवल स्वीकृत योजना / स्वीकृत योजनाओं तक सीमित रहेगा। विभाग के पास उपलब्ध समिति रिकार्ड के अनुसार समिति की सृजित योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है-

1 समिति द्वारा वर्ष 1999 में सहकारिता प्रकोष्ठ, जयपुर विकास प्राधिकरण में कुल 10 आवासीय योजनाओं का रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है तथा सहकारिता प्रकोष्ठ के पृथ्वीराज नगर उत्तर कार्यालय में कुल 4 एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के पृथ्वीराज नगर के दक्षिण कार्यालय में कुल 1 आवासीय योजना का रिकार्ड प्रस्तुत हुआ है। योजना की सूची मय भूखण्ड परिशिष्ट "01" पर संलग्न है।

2 विभाग में संधारित समिति की अंतिम आडिट रिपोर्ट वर्ष 1981-85 के साथ संलग्न प्रपत्र "अ" के अनुसार समिति द्वारा दिनांक 30.06.1985 तक 13 योजनाओं का सृजन किया जाना दर्शाया गया है। प्रपत्र "अ" में ही दिनांक 30.06.1985 तक सृजित आवासीय एवं व्यवसायिक भूखण्डों का संख्यात्मक विवरण अंकित है। प्रपत्र "अ" परिशिष्ट "02" पर संलग्न है।

3 समिति के पूर्व अध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई समिति की सृजित योजनाओं की सूची परिशिष्ट "03" पर संलग्न है।

(2) ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर का पंजीयन दिनांक 15.05.1973 को किया गया है। पंजीयन के समय से वर्तमान की प्रबन्धकारिणी की सूची विभाग में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार परिशिष्ट "04" पर संलग्न है।

(सहकारिता मंत्री)

(3) ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के संधारित आडिट रिपोर्टों के अनुसार वर्षवार आडिट/वर्षवार आडिटर का विवरण परिशिष्ट "05" पर संलग्न है।

वर्षवार आडिट रिपोर्टों में अंकित महत्वपूर्ण आक्षेप परिशिष्ट "06" पर संलग्न है।

समिति द्वारा वर्ष 1985 से अभी तक आडिट नहीं करवाये जाने के कारण समिति को दिनांक 29.09.2017 के द्वारा अवसायन में लाये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट "07" पर संलग्न है।

(4) ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर को उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर) के आदेश दिनांक 29.09.2017 द्वारा अवसायन में लाया गया। इस आदेश के विरुद्ध समिति द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के समक्ष अधिनियमान्तर्गत अपील की गई है जो वर्तमान में विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के विधान सभा नगर, धौलाई में जारी पट्टे

277. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति, झोटवाड़ा द्वारा जयपुर में विधान सभा नगर ग्राम धौलाई मानसरोवर में भूखण्डों के पट्टे जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कितने? संख्या व ब्लाकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त के डी ब्लाक के प्लाट नं. 40 से 45 तक के पट्टे कब जारी किये गये? पट्टे साइट प्लान की प्रतियां सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लि., झोटवाड़ा द्वारा विधान सभा नगर ग्राम धौलाई में ब्लाक "ए" से "एच" तक भूखण्डों के पट्टे जारी किये गये हैं जिनकी संख्यावार व ब्लाकवार सूची परिशिष्ट "01" पर संलग्न है।

(2) विभाग में उपलब्ध रिकार्ड में विधान सभा नगर ग्राम धौलाई के डी ब्लाक के भूखण्ड संख्या 40 से 45 के पट्टे, साइट प्लान नहीं हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सहकारी समितियों के ऋण अनियमितताओं की जांच

278. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत 2 वर्षों में प्रदेश की किन-किन को-आपरेटिव सोसायटीज में कहां-कहां पर ऋण अनियमितता के प्रकरण दर्ज किये गये? उक्त अनियमितताओं की जांच कब-कब करवायी गयी तथा किन-किन अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट सरकार को कब-कब प्राप्त हुई? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अनियमितताओं में कौन-कौन दोषी पाये गये व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में विगत 2 वर्षों में बैंकवार सहकारी समितियों के नाम (जिनमें अनियमितताओं के प्रकरण दर्ज हुए हैं) एवं समितिवार जांच की स्थिति की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) दोषी पाये गये कार्मिकों व उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किसान कर्ज माफी योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों की कर्ज माफी

279. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2018 में की गई किसानों की कर्ज माफी योजना में कितने सरकारी कर्मचारियों ने पात्र न होने के बावजूद कर्जा माफ करवा लिया? इससे कितनी राशि की हानि हुई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2019 से उक्त माफ की गई राशि में से कितनी राशि वापस वसूल की गई? शेष राशि वसूल न होने के क्या कारण हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त गलत तरीके से लाभ उठाने वाले कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ऋण माफी योजना-2018 दिनांक 19.04.2018 को जारी हुई किन्तु योजनान्तर्गत अपात्र व्यक्तियों की सूची दिनांक 25.04.2018 व दिनांक 01.06.2018 को जारी हो पाई। उक्त प्रक्रियागत कारणवश 7893 सरकारी कार्मिकों के ऋण प्रकरणों का संधारण ऋण माफी पोर्टल पर हुआ (परिशिष्ट-1)।

विभाग के आदेश दिनांक 22.01.2019 व 12.07.2019 द्वारा अपात्र व्यक्तियों के ऋण माफी की प्रविष्टियों को निरस्त (कैंसिल) किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। योजना मे लाभ देय नहीं था तथा नहीं दिया गया। बैंक को कोई हानि नहीं हुई।

(2) योजनान्तर्गत ऋण माफी का लाभ ऋण खातों में प्रविष्टियां कर दिया जाना प्रावधित है। अपात्र व्यक्तियों के ऋण खातों में प्रक्रियागत कारणों से हुई प्रविष्टियों को निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 22.01.2019 व 12.07.2019 को जारी कर दिये गये हैं। अत: वसूली कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(3) बिन्दु संख्या 1 में वर्णित प्रक्रियागत कारण से अपात्र ऋणियों के ऋण खातों में हुई प्रविष्टियों को निरस्त किये जाने के आदेश उपरोक्तानुसार जारी कर दिये गये हैं। योजना के तहत किसी प्रकार का लाभ देय नहीं था तथा दिया भी नहीं गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कपासन के शहीद स्मारकों का सौन्दर्यीकरण

280. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शहीद स्मारकों के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु मानदण्ड व नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कपासन में निर्मित शहीद जगदीश वैष्णव स्मारक मातृकुण्डिया (राशमी) व शहीद राजेन्द्रसिंह स्मारक-राजेन्द्र सिंह नगर (भदेसर) का सौन्दर्यीकरण, जीर्णोद्धार एवं रखरखाव करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सैनिक कल्याण विभाग में इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं हैं, किन्तु भूमि आबंटन हेतु राजस्व विभाग द्वारा नियम बनाया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

बजट भाषण वर्ष 2018-19 के बिन्दु संख्या 176 के द्वारा राज्य में जिन जिला मुख्यालयों पर शहीद स्मारक नहीं बने हुए हैं, उन सभी जिला मुख्यालयों पर प्रत्येक के लिए रुपये 20 लाख की लागत से शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की गयी है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं। सैनिक कल्याण विभाग में शहीद स्मारकों के सौन्दर्यीकरण, जीर्णोद्धार एवं रखरखाव के कोई नियम नहीं बने हुए हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मावली की पंचायतों में परिवहन निगम की बसों का संचालन

281. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली की प्रमुख पंचायतें घासा, पलाना, खेमली, भानसोल, जावड, थामला, सिन्दु, जेवाणा, खरताणा, खेमपुर व औमली मार्गों पर निगम की कितनी बसें संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पंचायतों को निगम द्वारा संचालित बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली की प्रमुख पंचायतें घासा, पलाना, खेमली, भानसोल, जावड, थामला, सिन्दु, जेवाणा, खरताणा, खेमपुर व औमली मार्गों पर राजस्थान परिवहन निगम की वाहनों का संचालन वर्तमान में नहीं किया जा रहा है।

(2) राजस्थान सरकार की जन घोषणा में "ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर-दराज के गावों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना" का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में निर्णय वित्तीय संसाधनों के आधार पर लिया जायेगा।

राजस्थान परिवहन निगम में वित्तीय अनियमितताओं की जांच

282. श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) रा.रा. पथ परिवहन निगम द्वारा गत पांच वर्ष में किस-किस सरकारी बैंक से कब-कब एवं कितनी-कितनी राशि निकालकर कौन-कौनसे प्राइवेट बैंक में तथा किस-किस दर पर जमा करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि परिवहन निगम समस्त वित्तीय भुगतान सरकारी बैंक से नहीं करवाकर प्राइवेट बैंकों द्वारा करवाये जाते हैं? यदि हां, तो किस-किस बैंक से तथा क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रबंधन द्वारा उक्त फण्डिंग/जमाओं हेतु कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित की गईं? यदि हां, तो किस-किस प्रस्तावक द्वारा कितनी-कितनी दर पर जमा के प्रस्ताव प्राप्त हुए? यदि नहीं, तो निगम को हुई हानि के लिए कौन जिम्मेदार है एवं निगम को विगत पांच वर्षों में कुल कितनी हानि हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त राजकोष में जान बूझकर की गई हानि की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम की संचालन व्यवस्था सुचारु रखने के लिए निगम द्वारा दिन-प्रतिदिन एक बैंक की जमाएं दूसरे बैंक में स्थानान्तरित की जाती हैं। निगम द्वारा बैंक आफ राजस्थान (वर्तमान में आईसीआईसीआई), एसबीबीजे, इलाहाबाद बैंक, ओबीसी एवं सीबीआई बैंक में चालू खाते (Current Account) खाते खोले गये थे एवं डी.सी.बी. व आईसीआईसीआई बैंक में बचत खाते (Saving A/c) खोले गये थे। निगम के व्यवहार वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा त्वरित भुगतान प्रणाली (I.P.S.) के माध्यम से किये जाते हैं। निगम के अन्य बैंकों से आवश्यकता पड़ने पर राशि आईसीआईसीआई बैंक में अंतरित की जाकर त्वरित भुगतान प्रणाली के माध्यम से आगारों को फण्ड स्थानान्तरित किया जा रहा है। अन्य बैंकों से आईसीआईसीआई बैंक में अन्तरित की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इन सभी बैंकों में चालू खाते (Current Account) खोले गये हैं जिन पर ब्याज देय नहीं होता है।

(परिवहन मंत्री)

(2) निगम द्वारा प्रारम्भ में बैंक आफ राजस्थान (वर्तमान में आईसीआईसीआई) व एस.बी.बी.जे. में खाते खोले गये थे। इसके अतिरिक्त निगम के खाते इलाहाबाद बैंक, ओबीसी एवं सीबीआई बैंक में खुले हुए हैं। उक्त सभी बैंक निगम के मुख्य बैंकर हैं। निगम द्वारा वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक व उक्त अन्य बैंकों के द्वारा ही व्यवहार किये जाते हैं।

(3) निगम द्वारा विभिन्न बैंकों में संचालन व्यवस्था के अनुरूप चालू खाते (Current Account) खोले गये हैं। उक्त खातों पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है। इस कारणवश निगम द्वारा किसी भी प्रकार की कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित नहीं किये गये हैं।

(4) प्रश्न का उत्तर खण्ड "3" में दिया जा चुका है। निगम को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वक्फ बोर्ड के अधीन संचालित आर.सी. सेन्टर, शास्त्री नगर के चुनाव

283. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वक्फ बोर्ड के अधीन कार्यरत संस्थाओं में चुनाव कराने हेतु क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त बोर्ड के अधीन आर.सी. सेण्टर, शास्त्री नगर जयपुर संस्था के आज तक चुनाव नहीं कराये गये हैं? यदि हां, तो क्यों एवं किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्था में चुनाव कराने हेतु जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा भी पत्र लिखा गया है? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार समाज हित में उक्त संस्था का चुनाव कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वक्फ बोर्ड द्वारा संस्थाओं के चुनाव कराने हेतु कोई नियम नहीं

(वक्फ मंत्री)

है। केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 18 के तहत वक्फ जायदादों की व्यवस्था व देखभाल के लिए बोर्ड द्वारा कमेटियों का गठन किया जाता है। परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 18 के तहत वक्फ जायदादों की व्यवस्था और देखभाल के लिए बोर्ड द्वारा वक्फ कमेटियों का गठन किया जाता है। बोर्ड द्वारा उनके चुनाव नहीं कराये जाते हैं। वक्फ सम्पत्ति मोचियों की छबील (आर.सी. सेन्टर शास्त्री नगर, जयपुर) की वर्तमान में व्यवस्था कर रही कमेटी के खिलाफ प्राप्त शिकायत को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड मीटिंग दिनांक 19 जनवरी, 2019 में पारित रिजोल्यूशन संख्या 27/2019 द्वारा बोर्ड के सदस्य जनाब मोहम्म्द शौकत कुरेशी को आब्जर्वर बनाया गया है।

(3) जी नहीं। उक्त संस्था के चुनाव कराने के संबंध में जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा लिखा गया कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) बोर्ड केवल केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 18 के तहत वक्फ जायदादों की व्यवस्था और देखभाल हेतु वक्फ कमेटियों का गठन करता है, संस्था के चुनाव नहीं करवाये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा में अल्पसंख्यकों के छात्रावास हेतु भूमि आबंटन

284. श्री मुरारी लाल (दौसा): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यकों हेतु कौन-कौनसी योजनायें संचालित हैं?

(2) विगत पांच वर्षों में उक्त संचालित योजनाओं में किस-किस योजना में कितने-कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला दौसा में अल्पसंख्यकों हेतु छात्रावास के लिए भूमि आबंटित हुई थी? यदि हां, तो किस स्थान पर? क्या उक्त पर छात्रावास भवन निर्मित हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनायें संचालित की जा रही हैं:-

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

केन्द्र प्रवर्तित योजना :-

1- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत राज्य के 15 ब्लाक्स, 17 कस्बों तथा 2 जिला मुख्यालयों में संचालित है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास आदि से जुड़े आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य करवाएं जाने का प्रावधान है।

2- नया सवेरा: योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों /विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग।

3- "नई रोशनी" अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व-क्षमता विकास की योजना है।

4- अवसंरचनात्मक विकास के लिये योजना (IDMI)

5- अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स योजना अन्तर्गत छात्रवृति दी जाती है।

राज्य प्रवर्तित योजना :-

1 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिये नि:शुल्क आवासीय छात्रावास की योजना।

2 अनुप्रति योजनान्तर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं IIT's AIIMS, IIS (Bangalore), AICTE certified NIT,s CLAT, IIM's, IISAR (Kolkata & Bangalore), GOI/MCI Certified मेडिकल कालेजों आदि में प्रवेश हेतु परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

3 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को मान्यता। (इस योजना के तहत वित्तीय अनुदान का प्रावधान नहीं है अपितु अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उनकी पात्रता के आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है)

4 अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण योजना संचालित है।

मदरसा शिक्षा योजना:- राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं:-

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

1. आदर्श मदरसा योजना:- इस योजना के अन्तर्गत मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किये जा रहे हैं तथा मदरसों को अन्य सुविधायुक्त बनाया जा रहा है।
2. जन सहभागिता योजना:- इस योजना का मूल उद्देश्य मदरसों की आधारभूत संरचना एवं विकास में जनभागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाना है।
3. मदरसा आधुनीकरण योजना:- इस योजना के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री, स्कूल बैग्स, अभ्यास पुस्तिकाएं, पैराटीचर स्टाफ के लिए फर्नीचर, बच्चों के लिए ड्यूल डेस्क एवं बैंच, खेल सामग्री व कम्प्यूटर इत्यादि सुविधाएं दी जा रही हैं।

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के सहयोग से अल्पसख्यकों हेतु निम्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है:-

1 ऋण योजनाएं

(ए) टर्म ऋण योजना

(बी) शिक्षा ऋण योजना

(सी) माइक्रो ऋण योजना

2 महिला समृद्धि योजना

(2) <u>केन्द्र प्रवर्तित योजना :-</u>

1. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत शिक्षा, चिकित्सा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विवरण की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। उक्त योजनान्तर्गत कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं दिया जाता है।
2. नया सवेरा:- उक्त योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है। संस्थाओं/लाभार्थियों का चयन भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है। समस्त रिकार्ड भी भारत सरकार द्वारा ही संधारित किया जाता है। निदेशालय स्तर से आवेदन,एन.पी.आर. प्रेषित करना आदि कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।
3. "नई रोशनी":- उक्त योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है। संस्थाओं/लाभार्थियों का चयन भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है। समस्त रिकार्ड भी भारत सरकार द्वारा ही

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

संधारित किया जाता है। निदेशालय स्तर से आवेदन, एन.पी.आर. प्रेषित करना आदि कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

4. अवसरंचनात्मक विकास के लिये योजना (IDMI) योजनान्तर्गत अवसंरचनात्मक विवरण की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। उक्त योजनान्तर्गत कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं दिया जाता है।
5. अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स योजना अन्तर्गत जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट - "अ" पर संलग्न है।

राज्य प्रवर्तित योजना:-

1. अनुप्रति योजना:- योजनान्तर्गत जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट- "ब" पर संलग्न है।
2. अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को मान्यता:- योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को मान्यता दी जाती है। उक्त योजनान्तर्गत कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं दिया जाता है।
3. कौशल विकास कार्यक्रम वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक कुल 4622 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया जिसका जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट - "स" पर संलग्न है।
4. मदरसा शिक्षा योजना:- मदरसों में चलाई जा रही योजनाओं में अध्ययनरत 1,94,375 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। जिलेंवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट - "द" पर संलग्न है।

1. आदर्श मदरसा योजना:- योजना वर्ष 2019-20 से प्रारम्भ की गई है। उक्त योजनान्तर्गत कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं दिया जाता है।
2. जनसहभागिता योजना:- योजनान्तर्गत मदरसों की आधारभूत संरचना व विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। उक्त योजनान्तर्गत कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं दिया जाता है।
3. मदरसा आधुनिकरण योजना:- उक्त योजनान्तर्गत कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं दिया जाता है।

5. आरएमएफडीसीसी:- पिछले पांच वर्षों में टर्म योजना, शिक्षा ऋण योजना, माइक्रो ऋण व महिला समृद्धि योजना अन्तर्गत क्रमश: 11107, 1867, 279 व 20 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट -"य" पर संलग्न है।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

(3) जी हां। जिला दौसा में अल्पसंख्यक बालक व बालिकाओं के छात्रावास हेतु भूमि आबंटित है। अल्पसंख्यक बालक छात्रावास हेतु ग्राम दौसा कला तहसील दौसा, स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नं. 3205 रकबा 0.30 हैक्टेयर एवं अल्पसंख्यक बालिकाओं के छात्रावास हेतु ग्राम दौसा कला तहसील दौसा, स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नं. 3205 रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि आबंटित की गई है। आवंटन आदेश परिशिष्ट-"र" पर संलग्न है। जिला दौसा में अल्पसंख्यक बालक व बालिकाओं के छात्रावास हेतु आबंटित भूमि पर छात्रावास भवनों का निर्माण नहीं हुआ है। विभाग द्वारा उपलब्ध बजट प्रावधान अनुसार फेजवार छात्रावास भवनों का निर्माण करवाया जायेगा।

दौसा जिले में अल्पसंख्यक बालक व बालिका छात्रावास के लिए जिला कलेक्टर दौसा द्वारा 0.30-0.30 हैक्टेयर भूमि का आबंटन दिनांक 26-06-2013 को किया गया। भूमि का कब्जा दिलाने एवं नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही तहसीलदार दौसा के स्तर पर लम्बित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली में आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण

285. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले की पाली शहर एवं रोहट पंचायत समिति के किस-किस गांव में कितने-कितने समय से आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हो रहे हैं एवं इनमें से किस-किस केन्द्र पर कितने-कितने बच्चे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस-किस केन्द्र के सरकारी भवन बने हुए हैं परन्तु क्षतिग्रस्त होने के कारण बैठने योग्य नहीं हैं एवं कौन-कौनसे केन्द्र भवन रहित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण करवाने एवं क्षतिग्रस्त भवनों के स्थान पर नये भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर एवं कितनी-कितनी अवधि में तथा नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले की पाली शहर एवं रोहट पंचायत समिति में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन की स्थिति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

पाली जिले की पाली शहर एवं रोहट पंचायत समिति में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) पाली जिले की पाली शहर एवं रोहट पंचायत समिति के क्षतिग्रस्त भवनों एवं भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/ स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मुख्य मंत्री राजश्री योजना के तहत पंजीकृत बालिकाएं

286. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में मुख्य मंत्री राजश्री योजना प्रारम्भ की गयी है? यदि हां, तो कब और इसकी पात्रता क्या है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में अब तक लाखों बालिकाओं को पंजीकृत किया जा चुका है? यदि हां, तो अब तक पंजीकृत बालिकाओं की जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं तो माह दिसम्बर, 2018 से जून, 2019 तक कितनी बालिकाओं का पंजीयन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 1 जून, 2016 से प्रदेश में मुख्य मंत्री राजश्री योजना प्रारम्भ की गई है। पात्रता सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। योजना में 1722663 कन्याओं को पंजीकृत किया गया है, जिसकी जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। इस योजना को बन्द नहीं किया गया है। माह दिसम्बर,

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)
2018 से जून, 2019 तक 244833 बालिकाओं को पंजीकृत किया गया है। पंजीयन का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार वितरण

287. श्री संजय शर्मा (अलवर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अलवर जिले की समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर कितने बालक/ बालिकाएं पंजीकृत हैं? विधान सभावार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बालक/बालिकाओं को पोषाहार का वितरण सही मात्रा में किया जा रहा है? यदि हां, तो कितनी-कितनी मात्रा में व क्या-क्या सामग्री वितरित की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले की समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत बच्चों की संख्या सूची का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत बच्चों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित पोषणीय मापदण्डों के अनुरूप पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत श्रेणीवार लाभान्वित बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे पूरक पोषाहार का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल में प्रस्तुत आवेदनों का निस्तारण

288. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में प्रस्तुत आवेदन पत्रों (CTE/CTO) अंतर्गत वाटर एक्ट और एयर एक्ट के निस्तारण की समय सीमा तय की गई है? यदि हां, तो कितनी अवधि? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री खुशवीरसिंह)

(2) वर्तमान में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में कितने आवेदन पत्र (CTE/CTO) कितनी अवधि से लंबित हैं? आठ माह से एक वर्ष तक एवं एक वर्ष से अधिक लंबित प्रकरणों की संख्या इकाइयों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने उक्त आवेदन पत्रों की कोई कैटेगरी निर्धारित कर रखी है? यदि हां, तो कौन-कौनसी कैटेगरीवार एवं माहवार लंबित प्रकरणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार समय सीमा के पश्चात् भी लम्बे समय तक आवेदन पत्रों के निस्तारण न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जल अधिनियम, 1974 की धारा 25(7) एवं वायु अधिनियम, 1981 की धारा 21(4) के अनुसार राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को प्राप्त आवेदन यदि पूर्ण हो तो चार माह की समय सीमा में निस्तारित करना आवश्यक है।

(2) वर्तमान में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में कुल 5096 आवेदन लंबित हैं। इसमें से 8 माह से एक वर्ष के 912 आवेदन एवं एक वर्ष से अधिक के 1232 आवेदन लंबित हैं। लम्बित आवेदनों की सूची राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। पर्यावरण विभाग के अधीन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा आवेदनों की कोई कैटेगरी निर्धारित नहीं की गई है।

(4) जी नहीं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में प्राप्त अधिकांश सम्मति आवेदनों को निर्धारित समय सीमा में नियमानुसार निस्तारित किया जा रहा है जिसमें प्रक्रियागत देरी होना स्वाभाविक है। अत: उक्त परिप्रेक्ष्य में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

झाड़ोल में वर्षा जल एकत्रीकरण हेतु एनीकटों का निर्माण

289. श्री बाबु लाल (झाड़ोल): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बाबु लाल)

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वन क्षेत्र में वर्षा जल रोकने हेतु एनीकटों का निर्माण कराया गया है। यदि हां, तो विगत 10 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में कहां-कहां कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? कार्यवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। झाड़ोल विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग के कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर), उप वन संरक्षक, उदयपुर तथा उप वन संरक्षक, उदयपुर (वन्यजीव) द्वारा अधीनस्थ वन क्षेत्रों में वर्षा जल रोकने हेतु निर्मित एनीकटों संबंधित विवरण क्रमश: संलग्न परिशिष्ट ए, बी एवं सी अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

औद्योगिक प्रदूषण रोकने की कार्य-योजना

290. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के शुष्क नदियों में औद्योगिक इकाइयों का ठोस एवं तरल कचरा प्रवाहित किया जाता है? यदि हां, तो प्रदेश की कौन-कौनसी नदियों में प्रदूषित तत्व प्रवाहित किये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राज्य सरकार को प्रदेश की शुष्क नदियों की समीक्षा कर इनमें प्रवाहित औद्योगिक प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस कदम उठाने का आदेश दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार ने समीक्षा कर ली है? सरकार उक्त के संबंध में कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यावरण विभाग के अधीन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा किसी भी औद्योगिक इकाई को शुष्क नदियों में औद्योगिक उच्छिष्ठ एवं ठोस एवं तरल कचरे को प्रवाहित करने की अनुमति नहीं दी जाती है तदापि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के संज्ञान में समय-

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

समय पर इकाइयों द्वारा तरल कचरे को नदियों में प्रवाहित करने की जानकारी आती है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा इन प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

उद्योग विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार रीको द्वारा विकसित किये गये पाली के औद्योगिक क्षेत्र पाली प्रथम चरण, द्वितीय चरण, मंडिया रोड एवं पुनायता मे कार्यरत टैक्सटाइल्स इकाइयों से निष्कासित दूषित जल संयुक्त उपचार संयंत्र से उपचारित होने के पश्चात राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा निर्धारित क्षमता तक बांडी नदी में प्रवाहित हो रहा है।

रीको द्वारा विकसित किये गये जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्र बासनी एवं स्थानान्तरित औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत टैक्सटाइल्स एवं स्टील आधारित इकाइयों से निष्कासित दूषित जल आंशिक मात्रा में संयुक्त उपचार संयंत्र से उपचारित होने के पश्चात एवं शेष जल अनुपचारित जोजरी नदी में प्रवाहित हो रहा है।

(2) जी हां। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने विचाराधीन मूल आवेदन संख्या 329/2015 ग्राम पंचायत अराबा बनाम राजस्थान सरकार में जारी आदेश दिनांक 10/05/2019 के द्वारा राज्य की सभी शुष्क नदियों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि इन नदियों का दुरुपयोग औद्योगिक इकाइयों का ठोस एवं तरल कचरा निस्तारण हेतु नहीं किया जाए।

प्रदेश की शुष्क नदियों में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अनुपचारित जलीय अपशिष्ट के नदियों में प्रवाह के रोकथाम के लिए रीको द्वारा जोधपुर, पाली, बालोतरा, भिवाड़ी एवं जयपुर में औद्योगिक इकाइयों के निकलने वाले जलीय अपशिष्ट के उपचार हेतु संयुक्त उपचार संयंत्रों की स्थापना करने के लिए आवश्यक भूमि का आबंटन इकाइयों द्वारा गठित ट्रस्ट को किया जाता है। आज दिनांक तक उक्त औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 60.7 हैक्टेयर भूमि का आबंटन संयुक्त उपचार संयंत्र की स्थापना हेतु किया जा चुका है।

निर्धारित मापदंडों की पालना सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा ही संयंत्रों का औचक एवं नियमित निरीक्षण भी किया जाता है।

बीकानेर जिले में वन कर्मियों के रिक्त पद

291. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

बीकानेर जिले में विभाग में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद किस-किस कार्यालय में स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद भरे हुए हैं तथा कितने रिक्त हैं? श्रेणीवार व संवर्गवार स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बीकानेर जिले में वन विभाग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का कार्यालयवार, श्रेणीवार एवं संवर्गवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-क अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर शहर में RSLDC के तहत संचालित प्रशिक्षण केन्द्र

292. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर शहर में आर.एस.एल.डी.सी. के माध्यम से कितने प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं? संख्या एवं केन्द्र का नाम सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों पर कितने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? ट्रेडवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान कौशल एवं आजीविका निगम द्वारा अजमेर शहर में सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता के माध्यम से कुल 6 कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की संख्या एवं नाम निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम
1	ड्रीमलैंड इमीग्रेशन कापरेटिव प्राइवेट लिमिटेड
2	हिन्दुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रोमोशन ट्रस्ट
3	हिन्दुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रोमोशन ट्रस्ट
4	राज सेवा संस्थान
5	श्री मिश्री लाल दूबे संस्थान
6	वोल्क्सी टेक्नोलोजीज

(कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता राज्य मंत्री)

(2) उक्त केन्द्रों पर कुल 651 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेडवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धरियावद के लसाड़िया में निर्मित ITI भवन

293. श्री गोतमलाल (धरियावद): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र धरियावद के लसाड़िया में नवनिर्मित आई.टी.आई. भवन की वर्तमान स्थिति क्या है वहां पर प्रवेशार्थियों को अध्ययन कहां से कराया जा रहा है एवं क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

आईटीआई लसाडिया के भवन का ढांचा पूर्ण हो गया है एवं भवन का फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है। लसाडिया में राजकीय आईटीआई में प्रथम प्रवेश सत्र 2018-19 में इलैक्ट्रीशियन व्यवसाय में 16 प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश प्रदान कर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत निकटतम राजकीय आईटीआई धरियावद में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

नोखा में स्टेडियम का निर्माण

294. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र नोखा में एक नगरपालिका नोखा तथा दो पंचायत समितियां नोखा व पांचू है? क्या सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए नोखा में आउटडोर-इन्डोर स्टेडियम का निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समन्वित स्टेडियम (खेल संरचना) विकास कार्यक्रम-2015 के तहत तहसील/पंचायत समिति मुख्यालय पर एथेलेटिक्स, बास्केटबाल, वालीबाल, खो-खो/कबड्डी के मैदान सहित स्टेडियम निर्माण का प्रावधान किया गया है। चरणबद्ध तरीके से बजट की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर

(युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा इनके निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की जाती है। वर्तमान में नोखा में आउटडोर-इण्डोर स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में यूथ आइकन योजना के तहत लाभान्वित

295. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार द्वारा यूथ आइकन योजना चलाई जा रही है? इसमें क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं? उक्त योजना से कौन-कौन लाभान्वित हो सकते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा में यूथ आइकन योजना की घोषणा की गयी थी। इस योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई राशि स्वीकृत नहीं की गयी जिससे इसका क्रियान्वयन नहीं हो सका। इस योजना के मुख्य प्रावधान परिशिष्ट-क पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण

296. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किस आधार पर किया जा रहा है? अंतिम बार न्यूनतम मजदूरी में परिवर्तन कब किया गया था?

(2) असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिए सरकार क्या कार्य कर रही है एवं इन कार्यों पर विगत 05 वर्षों में कितना परिव्यय हुआ?

(3) असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के संबंध में क्या कोई विशेष संस्थागत संरचना बनाई गई है? यदि हां, तो इसका कार्यक्षेत्र क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए राज्य सरकार की नीति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1. राज्य सरकार द्वारा बढ़े हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर राजस्थान न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मण्डल के समक्ष विचार-विमर्श के उपरान्त मण्डल की सहमति से राज्य में न्यूनतम मजदूरी की दरों का निर्धारण किया जाता है।

(राज्य मंत्री, श्रम)

2. प्रदेश में अन्तिम बार न्यूनतम मजदूरी में परिवर्तन 1 जनवरी, 2018 को किया गया था।

(2) निर्माण श्रमिक भी असंगठित क्षेत्र में आते हैं। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिये सरकार की वर्तमान योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। विगत 5 वर्षों में लाभान्वित निर्माण श्रमिकों की सम्भागवार संख्या परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। प्रत्येक योजना पर विगत 5 वर्षों में किया गया कुल परिव्यय परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। असंगठित क्षेत्र में आने वाले निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ ''भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल'' तथा समस्त असंगठित श्रमिकों के लिये ''असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड'' गठित है। इनका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राज्य है।

(4) राज्य सरकार की नीति असंगठित मजदूरों के लिए बनाये गये केन्द्रीय कानून ''असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008'' की पूर्ण पालना करवाने की रही है। इसके लिए धारा 6 के अनुसार प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा मंडल तथा धारा 9 के अनुसार ''सुविधा एवं सूचना केन्द्रों'' की स्थापना कर दी गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शुभ शक्ति योजना के तहत लाभान्वित श्रमिक

297. श्रीमती जाहिदा खान (कामां): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए विभाग के माध्यम से कौन-कौनसी योजनाएं चलायी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) शुभ शक्ति योजना में किस श्रेणी के श्रमिकों को लाभान्वित किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) असंगठित क्षेत्र में ''भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित'' अथवा ''निर्माण श्रमिकों'' हेतु श्रम विभाग के भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा 8 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जिसमें

(राज्य मंत्री, श्रम)

शुभ शक्ति योजना भी शामिल है, में असंगठित क्षेत्र में ''भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित'' अथवा ''निर्माण श्रमिकों'' को लाभान्वित किया जाता है। निर्माण श्रमिकों की श्रेणी का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झालावाड़ जिले में शुभ शक्ति योजनान्तर्गत बालिकाओं का लम्बित भुगतान

298. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

झालावाड़ जिले में शुभ शक्ति योजनान्तर्गत कितनी बालिकाओं को राशि का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो कब से तथा अब कब तक भुगतान कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

श्रम विभाग के भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा संचालित शुभ शक्ति योजनान्तर्गत झालावाड़ जिले में कुल 6,440 प्राप्त आवेदनों में से 1,713 आवेदन स्वीकृत, 381 आवेदन निरस्त, 2,423 आवेदन विभागीय स्तर पर तथा 1,923 आवेदन आवेदनकर्ता के स्तर पर आक्षेपपूर्ति हेतु लम्बित हैं।

विभाग द्वारा करायी गयी सोशल आडिट एवं भौतिक सत्यापन में विशेषकर शुभ शक्ति योजना के आवेदनों में अपात्र निर्माण श्रमिकों अथवा ऐसे श्रमिक जो निर्माण कार्य में नियोजित नहीं हैं, के द्वारा आवेदन करने का तथ्य सामने आया है। इसके समाधान हेतु प्रत्येक आवेदन में हिताधिकारी का भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त पात्र व्यक्ति को सहायता दिये जाने का निर्णय लिया गया है। संवेदनशीलता एवं पेन्डेन्सी की दृष्टि से सिलिकोसिस सहायता, मृत्यु सहायता, प्रसूति सहायता एवं शिक्षा सहायता के प्रकरणों को वरीयता देते हुए पहले निस्तारित करने की नीति अपनाई गयी है तथा शुभ शक्ति के आवेदनों का चरणबद्ध रूप से वरीयता अनुसार निस्तारित किये जाने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है। सत्यापन का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। योजना आवेदनों का निस्तारण ''पहले आओ पहले पाओ'' (फीफो) पद्धति से आनलाइन किया जा रहा है।

होम गार्डों को प्रदत्त मानदेय एवं सुविधाएं

299. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने होमगार्ड कार्यरत हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के होमगार्डों को कितना मानदेय और क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? उक्त होमगार्डों के मानदेय में कब-कब वृद्धि कर कौन-कौनसी सुविधाएं दी गईं?

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश के होमगार्डों को वर्षभर नियमित ड्यूटी नहीं मिल पा रही है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार प्रदेश के होमगार्ड को नियमित ड्यूटी और वेतन भत्तों में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में नियोजित होमगार्ड जवानों की जिलेवार सूची परिशिष्ट-अ अनुसार है।

(2) वर्तमान में राजस्थांन होमगार्ड जवान को पुलिस कांस्टेबल के समान ड्यूटी करने व वाहन चालक का कार्य करने पर रु. 693/- दैनिक डयूटी भत्ता एवं इनके अतिरिक्त अन्य ड्यूटियों हेतु रु. 590/- प्रति दिवस की दर से दैनिक ड्यूटी भत्ता देय है। (प्रति संलग्न)

विगत 10 वर्षों में होमगार्ड के मानदेय में वृद्धि का विवरण परिशिष्ट-ब के अनुसार है।

होमगार्ड को मानदेय के अतिरिक्त विभाग द्वारा राजकोष से निम्न सुविधाएं दी जा रही हैं:-

1. स्वयं सेवक को 15 किमी दूरी पर नियोजित किये जाने पर नियमानुसार पुलिस कांस्टेबल के समान यात्रा भत्ता देय है।
2. प्रति 5 वर्ष में एक बार एक वर्दी सैट (पैन्ट, शर्ट, बैल्ट, टोपी, जूते, मौजे, विसिल, लेनयार्ड) देय है।
3. सामूहिक दुर्घटना बीमा राशि 1.50 लाख देय है।

(3) जी हां। होमगार्ड स्वयं सेवकों को विभिन्न ड्यूटियों में मांगकर्ता विभागों/एजेंसी की मांग के आधार पर नियोजित किया जाता है। जिलों में नियोजन की सीमित मांग होने के कारण होमगार्डों को वर्षभर नियमित ड्यूटी नहीं मिल पा रही है।

वर्तमान में मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

जमवारामगढ़ वन्य क्षेत्र में जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सरकार द्वारा सैंक्चुअरी (वन अभयारण्य) क्षेत्र में आने के कारण दिनांक 28 जनवरी, 2013 से ग्राम विठलपुर, सुरेठी बिशनपुरा, कैलनवास, गोपालगढ़, नौपुरा, भिवास, घाटी घनश्यामपुरा, साहू, साहू शीरा, जमवाघाट, रासावाला, बस्सी, काली बरकड़ी, डगोता, काणीखोर, दांतली, पावटा, महंगी, गुढा-हरुका, बामनवाटी, महंगौर, नांगल तेजसिंह, रायसर, रामजीखुरा, कुशलपुरा, डारोलाई, चैनपुरा, नीम्बी, रायपुर, घोरेठ खरहड व लोठीपुरा पावटा इत्यादि लगभग 33 गांवों की ज़मीनों की खरीद फरोख्त (रजिस्ट्री) पर पूर्णतया तथा लगभग 50 गांवों की जमीनों की खरीद फरोख्त पर आंशिक रोक लगा दी गयी है। इस रोक के लगने के बाद आज उक्त क्षेत्र का किसान बुरी तरह संकट में पड़ गया है। किसानों को जिन संस्थाओं से कर्ज के रूप में वित्तीय सहायता मिलती थी उन संस्थाओं ने कर्ज देना बंद कर दिया है। उक्त क्षेत्र में रहने वाले लोग न तो किसी प्रकार का वहां निर्माण करवा सकते हैं, न ही कोई कुआं वगैरह खुदवा सकता है और न वहां कोई विकास कार्य करवाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त गांवों में रहने वाली जनता में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है जबकि उक्त दिनांक 28 जनवरी, 2013 से वहां पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं थी।

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय वन मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वन्य क्षेत्र में स्थित उक्त गांवों की जमीनों की रजिस्ट्री पर लगी रोक को हटाने के आदेश जारी कर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

गोपाल लाल मीना

(जमवारामगढ़)

राजस्थान जल निकास अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना से परेशानी

महोदय,

राजस्थान राज्य के सिंचाई तथा जल निकास अधिनियम 1955 के नियम-11 में विद्यमान उप नियम (2). (3), (4) में राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 17 मई, 2010 को जारी की गई अधिसूचना को विड्रा किया जाना चाहिए। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य की सिंचाई प्रणालियों में 17.5.2010 से पूर्व राजस्थान सिंचाई तथा जल निकास अधिनियम 1955 के नियम-11 विद्यमान उप नियमों में प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप निकायों या जलीय संरचना की आकृति व अवस्थिति से या नहर के माध्यम से जल वितरण के लिये स्थापित प्रक्रिया में परिवर्तन के लिए अधिशासी अभियंता/अधीक्षण अभियंता सक्षम थे, जिस कारण मोघों में संशोधन, भूमि ट्रांसफर आदि अधिशाषी अभियंता/अधीक्षण अभियंता के स्तर पर काम हो जाता था । परन्तु दिनांक 17.5.2010 के बाद राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर उक्त अधिनियम में संशोधन प्रतिस्थापित किया गया है कि निकायों या जलीय संरचनाओं की आकृति, आकार और अवस्थिति से या नहर के माध्यम से जल वितरण के लिए स्थापित प्रक्रिया में राज्य सरकार के आदेश के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से 17.5.2010 की अधिसूचना के पश्चात् नहरी पानी जल वितरण हेतु स्थापित मोघों में परिवर्तन एक चक से दूसरे चक में भूमि परिवर्तन, एक चक से दूसरे चक में भूमि स्थानान्तरण मोघा शिफ्टिंग, चकों का विभाजन व एकीकरण संबंधी प्रकरणों पर राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त ही क्रियान्विति की कार्यवाही की जाती है। इससे किसानों की समस्या के निराकरण में विलम्ब होता है।

महोदय, आप राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान सिंचाई तथा जल निकास अधिनियम 1955 के नियम में संशोधन के संबंध में जारी अधिसूचना को विड्राल करवाकर पूर्व की भांति व्यवस्था करवाएं जिससे कि मोघों में संशोधन रकबा स्थानान्तरण, नहर के छोटे-बड़े कामों में संशोधन अधिशासी अभियंता/अधीक्षण अभियंता के स्तर पर हो सके।

गुरदीप सिंह

(संगरिया)

रतनगढ़-जयपुर मार्ग स्थित धार्मिक स्थलों पर रेल सेवा का संचालन

महोदय, रतनगढ़ से सालासर, सालासर से खाटूश्याम जी, खाटूश्यामजी से रींगस-जयपुर, इन धार्मिक स्थलों को रेलमार्ग से जोड़ने की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये दोनों धार्मिक स्थल पूरे एशिया में पूजनीय हैं। इन धार्मिक स्थलों में पूरे वर्ष धर्मप्रेमी आते रहते हैं। पैदल यात्री संघ बसों से व अपने-अपने साधनों से पहुंचते हैं। इन धार्मिक स्थलों के चारों तरफ से आने वाली सड़कों के टोल टैक्स की आय व मेलों में आने वाले वाहनों की गणना कराएं तो आश्चर्य होगा कि देश का कितना फ्यूल खर्च होता है। अगर ये दोनों धार्मिक स्थल रेल मार्ग से जुड़ जाएं तो सामान्य श्रेणी मध्यमवर्गीय यात्री महंगी यात्रा से बच जाएगा। इससे भारत व राजस्थान सरकार की आय भी बढ़ेगी क्योंकि रेल मार्ग के कारण व्यापार बढ़ेगा।

पडिहारा हवाई पट्टी के विस्तार की घोषणा के बाद यदि यह रेल मार्ग भी बन जाता है तो यात्रियों को हवाई यात्रा के बाद रेल की सुविधा से भी लाभ मिल सकेगा।

मेरा अनुरोध है कि राजस्थान सरकार भारत सरकार से इस मार्ग पर भी रेलवे लाइन डालकर रेल चलाने की सिफारिश करने की कृपा करें।

अभिनेश महर्षि

(रतनगढ़)

सूरतगढ़ नगरपालिका में सीवरेज कार्यों में भ्रष्टाचार

महोदय,

मैं आपका ध्यान नगरपालिका सूरतगढ़ में हुए भ्रष्टाचार की तरफ दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की नगरपालिका सूरतगढ़ में सीवरेज के कार्य में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। कम्पनी व नगरपालिका दोनों की मिलीभगत से मोके पर जो सीवरेज लाइन डाली गयी है, वह तकमीना के मुताबिक नहीं डालकर मनमर्जी से डाल दी गयी है पूरे शहर में जगह-जगह सड़कों में खड्डे पड़े हैं व जो चैम्बर लगाये गए उनके ढक्कन भी रोड लेवल से ऊपर लगाने के कारण से आये दिन मोटरसाइकिल, स्कूटर व साइकिल वाले गिर जाते हैं एवं हाथ पैर टूट जाते हैं। कम्पनी ने सेप्टिक टैंक खाली करके 5 कि.मी. दूर डालकर ऊपर बालू मिट्टी डालकर समतल करके जमाने का फर्जी

पेमेन्ट उठा लिया है व करोड़ों रु. सेप्टिक टैंक खाली करने का पेमेन्ट फर्जी उठाया है। एक भी टैंक खाली नहीं किये। सिर्फ कागजों तक ही कार्य करना बताया गया है। इसी तरह से सीवरेज डालते टाइम पानी की पाइप टूटी हुई दिखाकर लाखों रु. का बिल उठा लिया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की नगरपालिका में हुए भ्रष्टाचार की तरफ दिलाना चाहूँगा।

सधन्यवाद।

रामप्रताप कासनियां

(सूरतगढ़)

खाजूवाला में बीएडीपी योजनान्तर्गत विकास कार्यों के दायरे में बढ़ोतरी

महोदय,

अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान बीएडीपी योजना की ओर आकर्षित कर निवेदन है कि बीकानेर जिले की खाजूवाला पंचायत समिति में बीएडीपी योजना के अन्तर्गत पिछले 10 सालों से पाकिस्तान की सीमा से मात्र 10 किमी. तक ही बीएडीपी योजना के करोड़ों रुपयों की पूर्ण राशि खर्च की जा रही है, जिस कारण खाजूवाला पंचायत समिति के शेष क्षेत्र विकास कार्य से वंचित रह रहे हैं तथा 10 किमी. में उक्त खर्च राशि का सदुपयोग नहीं हो रहा है। इस कारण इस योजना का पैसा विकास के लिए जो खर्च होना चाहिये वह सही ढंग से नहीं हो पा रहा है एवं इस कारण खाजूवाला का विकास नहीं हो रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में भी बीकानेर जिला कलेक्टर महोदय एवं मुख्य मंत्री कार्यालय को विकास कार्य की सीमा 10 कि.मी. बढ़ाकर 50 किमी. करने हेतु लिखा गया था। विकास कार्य की सीमा 50 किमी. नहीं करने पर यहां के निवासियों में भयंकर आक्रोश है तथा विकास अवरूद्ध है। यह है कि 10 वर्ष पूर्व से बीएडीपी की राशि बीकानेर जिला मुख्यालय तक ही खर्च की जाती थी।

अतः मेरी मांग है कि बीएडीपी योजना के अन्तर्गत विकास कार्य की सीमा 10 किमी. से बढ़ाकर 50 किमी की जाए ताकि बीएडीपी योजना की राशि का सदुपयोग हो सके। इसी प्रकार खाजूवाला पंचायत समिति में पेयजल, खाला निर्माण, बिजली, डामर सड़क तथा और भी बहुत सारे विकास कार्य क्षेत्र

में होने चाहिये, वे नहीं हो रहे हैं। इसलिये मांग है कि पाकिस्तान की सीमा से सटे खाजूवाला क्षेत्र में बीएडीपी योजना के अन्तर्गत विकास कार्य की सीमा 10 किमी. से बढ़ाकर 50 किमी. करें, ताकि बीएडीपी राशि का सदुपयोग हो सके।

गोविन्दराम

(खाजूवाला)

ब्यावर शहर में अवैध नक्शे की स्वीकृति

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में डीएलबी जयपुर व ब्यावर नगर परिषद् में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से ब्यावर शहर में अवैध नक्शे स्वीकृत किये जा रहे हैं जिसके कारण ब्यावर शहर के रोड सकड़े होते जा रहे व यातायात की समस्या बढ़ती जा रही है जबकि बढ़ते हुए यातायात के दबाव को ध्यान में रखते हुए रोड चौड़े करने की आवश्यकता है लेकिन डीएलबी व ब्यावर नगर परिषद् की मिलीभगत के कारण व्यावर शहर का सौन्दर्य व यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है, साथ ही सीवरेज लाइनों के कारण भी शहर की सभी सड़कों व गलियों को खोदा गया व उन्हें तुरन्त दुरुस्त न करने से भी आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खोदी गयी सड़कों व गलियों की भी पुनः सीसी रोड बनवायी जाना आवश्यक है।

हमारी मांग है कि ब्यावर शहर नेशनल हाईवे-8 पर बसा हुआ है। हाईवे की नियमानुसार चौड़ाई के आधार पर किये गये अवैध नक्शों को अस्वीकृत कर अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही कराएं। अतः उक्त समस्या के समाधान के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

कृपया सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करें।

शंकर सिंह रावत

(ब्यावर)

उदयपुर यू आई टी पैरीफेरी क्षेत्र के गांवों का पुन ग्राम पंचायतों में हस्तांतरण

महोदय,

निवेदन है कि उदयपुर जिले में मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की

पंचायत समिति बड़गांव में उदयपुर यू.आई.टी. पैरीफेरी अन्तर्गत ग्राम पंचायतें लोयरा, बडगांव, थूर, लखावली, कविता आती हैं जिनकी 500 वर्ष पुरानी बिलानाम आबादी है, जिस पर वर्षों से मकान बने हुए हैं। ये जमीनें उदयपुर यू.आई.टी. के खाते में दर्ज की गयी हैं। इन बिलानाम आबादी पर बसे हुए लोगों को बापी पट्टे देने का अधिकार पूर्व में ग्राम पंचायत के पास था। आज की स्थिति में ये अधिकार किसके पास हैं तथा किस संस्था द्वारा ये बापी पट्टे दिये जाएंगे या फिर इन ग्राम पंचायतों के लोग बिना बापी पट्टे के ही रहेंगे। मेरे क्षेत्र की इन पैरीफेरी की ग्राम पंचायतों में विधायक मद या सांसद मद के कार्य भी बाधित होते हैं क्योंकि हर कार्य के साथ पटवारी रिपोर्ट मांगी जाती है जिसमें ग्राम पंचायत का अधिकार क्षेत्र नहीं होना बताया जाकर कार्य को निरस्त कर दिया जाता है। छोटे-छोटे जायज कार्यों के लिए भी आमजन को यू.आई.टी. के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जानकारी के अभाव में बड़ी दिक्कत आती है। विभागों द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं की दर भी यू.आई.टी. पैरीफेरी में बहुत ज्यादा है। अतः उक्त सभी जमीनें यथा आबादी बिलानाम, बिलानाम, चरागाह व रास्ते जो कि यू.आई.टी. उदयपुर के खाते में दर्ज हैं, को पूर्व की भांति ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित करने का आग्रह करता हूं।

धन्यवाद।

प्रताप लाल भील (गमेती)

(गोगुन्दा)

पंचायती राज में एलडीसी भर्ती, 2013 में नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी

मैं विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पंचायती राज एलडीसी भर्ती, 2013 में लगभग 19,200 पदों पर एलडीसी भर्ती निकाली गयी थी किन्तु कुछ त्रुटिपूर्ण नियमों के कारण लगभग 10,000 पदों पर आज दिनांक तक भर्ती पूर्ण नहीं हो सकी है जिस संदर्भ में सरकार द्वारा अभी हाल में ही लोक सभा चुनावों के पूर्व भर्ती का कलेन्डर जारी किया गया था किन्तु लोक सभा चुनावों में आचार संहिता के चलते वह समय रहते पूर्ण नहीं किया जा सका, जिसके पश्चात् सरकार द्वारा निकाले गये भर्ती कलेन्डर निरस्त कर पुनः भर्ती का नवीन

कलेन्डर जारी करने का आदेश जारी किया जो कि आज दिनांक तक जारी नहीं किया गया है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द नवीन भर्ती कलेण्डर जारी कर बिना कोई काट-छांट किये विज्ञापित सम्पूर्ण पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। साथ ही तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती, 2004 में नियुक्ति प्रक्रिया में RPSC अजमेर की गलती के कारण निकाले गये पदों पर आरक्षण से अधिक पुरुष अभ्यर्थियों की जगह महिला अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी गयी जिसमें न्यायालय द्वारा भी उन पुरुष अभ्यर्थियो को नियुक्ति देने का आदेश दिया गया है किन्तु RPSC अजमेर द्वारा पहले पदों की स्वीकृति की बात कहकर मना किया जा रहा है। जबकि तृतीय श्रेणी अध्यापक 2006 में समान मामले में RPSC अजमेर द्वारा कोर्ट के आदेश पर पुरुष अभ्यर्थियों को 686 पदो पर नियुक्ति प्रदान की गयी है। अतः सरकार से निवेदन है कि वंचित अभ्यर्थियों को न्याय प्रदान कर नियुक्तियां प्रदान की जाएं।

खुशवीर सिंह

(मारवाड़ जंक्शन)

मालपुरा में ट्रोमा चिकित्सालय की स्थापना

महोदय,

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड मालपुरा से राष्ट्रीय राजमार्ग एसएच 37-ए (दूदू-छाण वाया मालपुरा) एवं एसएच-12 (जयपुर-भीलवाड़ा वाया मालपुरा) गुजरते हैं जिसके कारण यातायात की अधिकता रहती है। आये दिन कई लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं जिसमें अधिकांश की मौत हो जाती है और अधिकांश अपंगता का शिकार हो जाते हैं। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में वर्ष 2017 में 80 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें 46 लोगों की मौतें हुईं और 66 लोग घायल हुए। वर्ष 2018 में 103 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें 54 लोगों की मौतें हुईं और 82 लोग घायल हुए तथा 1 जनवरी, 2019 से 30 जून 2019 तक 62 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें 41 लोगों की मौतें हुईं और 33 लोग घायल हुए हैं। आसपास के अस्पतालों में उचित एवं पूर्ण चिकित्सा सुविधा एवं संसाधनों की कमी की वजह से जयपुर रैफर किये जाने वाले गंभीर रूप से घायलों में से अधिकांश लोगों की तो रास्ते में ही

मौत हो जाती है और कई समय पर उपचार शुरू नहीं होने की दशा में मौत का शिकार हो जाते हैं। यदि मालपुरा में ट्रोमा अस्पताल खोला जाता है तो मेरी विधान सभा के साथ-साथ किशनगढ़, केकड़ी, दूदू एवं पीपलू विधान सभा क्षेत्र के दुर्घटनाग्रस्त लोगों को भी दूरी कम होने से समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।

अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र एवं आस पास के लोगों की आवश्यकता को देखते हुए मालपुरा में शीघ्र ही ट्रोमा अस्पताल खोलने की कृपा करें।

कन्हैया लाल

(मालपुरा)

आयुष नर्सेज को ऐलोपैथी नर्सेज के समान वेतन एवं भत्ते

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि केन्द्र और राज्य में एलोपैथी नर्सेज और आयुष नर्सेज को समान वेतनमान दिये जाने का समझौता है। आयुष विभाग में नर्सेज को एलोपैथी नर्सेज से कम वेतनमान दिया जा रहा है। अतः निवेदन है कि राज्य में केन्द्र के समान आयुष विभाग के नर्सेज को वेतनमान एवं नर्सिंग भत्ता दिया जाए।

प्रदेश में सरकार द्वारा 7 वर्ष पूर्व आयुष नर्सिंग कौंसिल का विधिवत गठन किये जाने के उपरान्त भी आज तक नर्सेज का रजिस्ट्रेशन कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है जिससे प्रदेश के सेवारत नर्सेज की परेशानियों के साथ ही बेरोजगार नर्सेज को भी प्रदेश से बाहर व केन्द्रीय भर्तियों में रोजगार प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अतः शीघ्र ही आयुष नर्सेज का रजिस्ट्रेशन कार्य प्रारम्भ कराया जाए।

महोदय, प्रदेश में आयुष नर्सेज का कैडर रिव्यू कार्य लम्बित है जिससे आज तक प्रदेश का आयुष नर्सेज जिस पद पर नियुक्त किया जाता है उसी पद से सेवानिवृत्त होता आ रहा है। अतः आयुष नर्सेज का कैडर रिव्यू करवा कर पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारम्भ करके पदोन्नति दी जाए। इसके साथ ही निवेदन है कि ऐलोपैथी एवं आयुष नर्सेज में ग्रामीण कैडर की 2008 में भर्तियां की गयीं किन्तु मेडिकल में इस कैडर की सेवाएं मर्ज कर दी गयीं

जबकि आयुर्वेद में अद्यावधि तक नहीं की गयी है। अतः आयुष नर्सेज का ग्रामीण कैडर समाप्त कर आयुष विभाग में मर्ज किया जाए।

धन्यवाद।

नारायण सिंह देवल

(रानीवाड़ा)

रेवदर के ग्रामों में इंटरनेट हेतु मोबाइल टावर की मांग

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि आज आनलाइन का युग है। सरकारी सेवाओं से लेकर व्यापार, व्यवसाय, कृषि, पढ़ाई -लिखाई से लेकर रसोईघर तक मोबाइल एवं इन्टरनेट की विशेष भूमिका बन चुकी है। आपसी संवाद के अतिरिक्त आज सरकारी स्कीमों, योजनाओं, सुविधाओं का लाभ लेने के लिए भी इन्टरनेट, मोबाइल सुविधा होना अति-आवश्यक हो चुका है। मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर की पंचायत समिति रेवदर के गांव रोउआ, केसुआ, बड़वज, रायपुर, नन्दगांव-गौशाला, मूलीया खेड़ा, बारी खेड़ा, बोखी डेरली, बापूड़ा एवं पंचायत समिति आबूरोड के गांव जाम्बुड़ी, दोइतरा, आबा व नीचला गढ़ आदि में बीएसएनएल या किसी भी अन्य कम्पनी का नैटवर्क मौजूद नहीं होने से मेरे विधान सभा क्षेत्र के उक्त घनी आबादी के गांवों का विकास प्रगति बाधित हो रही है। यहां के नागरिक बन्धु, छात्र वर्ग, बेरोजगार युवा साथी व अन्य सभी वर्ग के लोग अपनी राजधानी, राज्य, देश-विदेश की गतिविधियों से अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। सरकारी स्कीमों, योजनाओं, व्यक्तिगत लाभ की स्कीमों का फायदा पात्र आमजनों को समय पर नहीं मिल पा रहा है। अपनी पानी-बिजली की समस्याओं के समाधान हेतु समय पर सम्बन्धित अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों को अवगत नहीं करा पा रहे हैं। इमरजेंसी हालातों, आकस्मिक दुर्घटनाओं में पीड़ितों को किसी प्रकार की राहत मिलने में अनावश्यक देरी हो रही है।

अतः लोक महत्व के उक्त विषय पर गौर फर्माकर मेरे विधान सभा क्षेत्र के उक्त वर्णित घनी आबादी गांवों में इन्टरनेट एवं मोबाइल सेवा के लिये पर्याप्त टावर सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाए।

जगसीराम

(रेवदर)

रिदि्ध-सिदि्ध काम्प्लैक्स के वेस्टेज पानी की निकासी का स्थायी समाधान

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में गिरिजा व्यास पैट्रोल पम्प के पीछे रिद्धि सिद्धि काम्प्लैक्स वर्षों से संचालित है और उसके वेस्टेज पानी की निकासी नहीं है क्योंकि उसका पानी यू.आई.टी. की कन्वर्ट कालोनियां बसी हुई हैं उसमें जाकर जमा होता है और गंदे पानी से अनेक बीमारियां हो रही हैं जैसे स्वाइन फ्लू, मलेरिया, डेंगू आदि बीमारियां हो रही हैं और अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया है। इस पानी को लेकर मैंने प्रयास किया, आश्वासन मिला, पर अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ। इसको लेकर कालोनी वालों ने पानी को बंद भी कर दिया जिससे मरने मारने तक की नौबत आ गयी जिसको बहुत मुश्किल से निपटाया। इसी तरह मनवाका खेड़ा एवं काम्प्लेक्स व द्वारका अपार्टमेन्ट, सुलभ कॉम्प्लेक्स, करणीनगर, राजेश्वरी गार्डन सैक्टर 6-7 का आनेवाला गंदा पानी रेलवे ब्रिज के नीचे आकर जमा होता है। इसकी वजह से लाइलाज बीमारियां हो रही हैं जिससे कई जानें जा चुकी हैं। इस समस्या को देखते हुए तुरंत समाधान नहीं किया गया तो जन आंदोलन भी हो सकता है। इसीलिए समय रहते इस समस्या का तुरंत समाधान करवाने की कृपा कराएं जिससे आम जनता को राहत मिल सके और सभी बीमारियों से छुटकारा मिल सके।

फूल सिंह मीणा

(उदयपुर ग्रामीण)

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-24 मुख्य शीर्षक **शिक्षा, कला एवं संस्कृति** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत कराने एवं नवीन भवन बनाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
2. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में ग्राम पंचायत पदमपुरा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय पदमपुरा को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

4. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा-छीपाबड़ौद में स्थित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवीन विषय प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के सभी बालिका विद्यालयों में पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

6. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में स्थित जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों की स्थिति खराब है, उनमें नवीन भवन बनाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिणधरी, पादरू, मोकलसर विद्यालय में विज्ञान संकाय, सिवाना विद्यालय में संस्कृत साहित्य विषय तथा सिणधरी बालिका विद्यालय में भूगोल विषय प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिकाओं हेतु अलग से विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. विधान सभा क्षेत्र सिवाना उपखण्ड का सिरमौर कुमठाण दुर्ग का संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बाड़मेर को दो भागों में करके एक कार्यालय बालोतरा मुख्यालय पर सिवाना, समदड़ी, पाटौदी, बालोतरा, कल्याणपुर सिणधरी ब्लाकों को सम्मिलित कर पद सहित सृजित कर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

11. राजकीय महाविद्यालय मावली का भवन निर्माण करवाने और उसमें वाणिज्य व विज्ञान संकाय भी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. लोकसंत बावजी चतुरसिंह जी से जुड़े स्थल नऊआ व हवा मगरी (सुखेर) के संरक्षण व विकास की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13. मोरडी व वाजवियर (मावली) के विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

14. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पर ध्यान देने व निरन्तर निगरानी रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. जवाहर कला केन्द्र के विकास पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. शिक्षा के साथ अनुशासन हेतु NCC पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. प्रदेश के संभागीय मुख्यालय पर जवाहर कला केन्द्र की तरह कला केन्द्र का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

18. राज्य के सभी विद्यालयों में पानी की पर्याप्त व्यवस्था करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त रूप से कम से कम 2-2 अध्यापक और तुरन्त लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

20. छीपरवाड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. कुण्डली, आलाव 'ए', देवावाडी सेदरिया में प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

22. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में रमसा के द्वारा निर्मित कक्षा-कक्षों की घटिया निर्माण के संबंध में विभिन्न स्कूलों से आ रही शिकायतों पर चर्चा के लिए।

24. गोविन्दगढ़ जयपुर के B.E.O. के कार्यालय में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निपटाने में शिक्षा विभाग की पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बलेखना, गौरी का बास को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलीसर, किशनमानपुरा, बोसा आदि विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

27. प्रदेश के प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की कक्षाओं में कला शिक्षा-चित्रकला तथा संगीत विषयों के अनिवार्य होने के बावजूद भी इन विषयों का अध्ययन नहीं कराये जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के राजकीय महाविद्याल में रिक्त पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में जहां पर छात्राओं की अधिकता है, उन विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के विद्यालयों में पानी बिजली की व्यवस्था एवं चारदीवारी भी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

31. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती व महाराणा प्रताप के इतिहास को शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमीन खां (शिव):

33. सीमावर्ती जिला बाड़मेर में मदरसों में आधुनिक शिक्षा दिलाने में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

34. जिला बाड़मेर की तहसील गडरा रोड के ग्राम सौलंकिया व लालासर में सैकण्डरी स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. जिला बाड़मेर की तहसील गडरा रोड के गांव में कन्या पाठशाला खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. सीमावर्ती बाड़मेर जिले में बन्द किये गये प्राथमिक विद्यालयों को पुन: प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. जिला बाड़मेर की तहसील गडरा रोड की मोउज स्कूल में कई विषयों के अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

38. ब्यावर में महिला महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरूपा, मेडिया, मालीपुरा, रामपुरा दुदा, सेलीबेरी, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बराखन, बड़ाखेड़ा को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. राजकीय माध्यमिक विद्यालय ददालिया, राजकीय माध्यमिक विद्यालय खोडमाल, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, जवाजा, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय टाटगढ़ एवं राजकीय बालिका

माध्यमिक विद्यालय बड़ाखेड़ा को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

41. शिक्षक भर्ती, 2012 में वंचित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दिलाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

42. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बोथिया, बान्दरों की ढाणी छापरी, लूणू खुर्द, गुडीसर, गेहूं, परो, हाजाणियों की ढाणी, मूलाणियों की ढाणी चंवा, सरकाणर बान्दरा, डूंगरों का तला को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

43. राजस्थान की कला एवं संस्कृति को सहेजने वाली मांगणियार, लंगा जाति के संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में चर्चा के लिए।

44. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर में स्नातकोत्तर में हिन्दी विषय शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

45. जुडा रामा (रेलिया गुडा) उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मुरारी लाल (दौसा):

46. राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, दौसा को आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

47. राज्य में अनिवार्य शिक्षा कानून की पालना निजी विद्यालयों द्वारा न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

48. सिरोही जिले के सरकारी विद्यालयों में अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने में शिक्षा विभाग द्वारा पहल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. सिरोही जिले में विज्ञान संकाय की सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. चन्द्रावती नगरी के संरक्षण एवं विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

51. स्कूली छात्र-छात्राओं की पोशाक की अनिवार्यता के कारण सरकारी

विद्यालय में बच्चों के प्रवेश लेने में उदासीनता के बारे में चर्चा के लिए।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल):

52. जयपुर शहर के दरबार स्कूल के नये भवन का निर्माण कराने एवं खाली पड़ी जमीन पर कन्या महाविद्यालय खोले जाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

53. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के बन्द उच्च प्राथमिक विद्यालय देवपुरा, खण्डेरिया ग्राम फतेहपुर को पुन: चालू करवाकर सैकण्डरी में क्रमोन्नत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

54. राजकीय महाविद्यालय जहाजपुर हेतु आबंटित भूमि पर भवन व चारदीवारी निर्माण करवाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के लुहारी कला, सरशिया, गुढ़ा तथा घौड़ बालिका सैकण्डरी स्कूल को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद):

56. राजसमंद जिले के रेलमगरा S.D.O. मुख्यालय पर सरकारी महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

57. विधान सभा क्षेत्र कपासन में विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने तथा विद्यार्थियों की संख्यानुसार नये कक्षों के निर्माण कराये जाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना):

58. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में पूर्व में बन्द की गयी स्कूलों को पुन: प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती मंजु देवी (जायल):

59. राजकीय महाविद्यालय जायल में परीक्षा केन्द्र खोलने एवं विज्ञान संकाय की प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय हेतु भवन निर्माण के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

60. कठूमर उपखण्ड मुख्यालय पर कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पड़े पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र कठूमर की खेरली (कठूमर) नगरपालिका क्षेत्र में रोनीजाथान में अंग्रेजी माध्यम की माडर्न स्कूल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

63. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोनीजाथान (कठूमर) का परिणाम मात्र 40 प्रतिशत रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र कठूमर (अलवर) की उच्च माध्यमिक विद्यालय रोनीजाथान एवं खुड़ियाना में परीक्षा केन्द्र चालू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

65. विधान सभा क्षेत्र नोखा के बाबा छोटूनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में खेल परिसर के निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. विधान सभा क्षेत्र नोखा के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र नोखा के प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में तथा माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र नोखा में स्थित सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कला संकाय की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

69. तहसील मुख्यालय नोखा स्थित राजकीय मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय में स्नातक में नये विषय गृह विज्ञान, भूगोल, अंग्रेजी

साहित्य एवं स्नातकोत्तर में समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, रसायन शास्त्र एवं व्यवसाय प्रबन्ध चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री संजय शर्मा (अलवर):

70. अलवर शहर में स्थित मत्स्य विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

71. अलवर शहर स्थित मत्स्य विश्वविद्यालय में पीएचडी पाठ्यक्रम/संकाय परिणाम आदि में हो रही अनियमितताओं की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. अलवर शहर स्थित राजर्षि महाविद्यालय में विज्ञान विषय के साथ-साथ कृषि विषयों में स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं को प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. अलवर शहर स्थित सभी राजकीय महाविद्यालयों में खेलकूद हेतु आधुनिक व्यवस्थाओं को विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

74. अलवर शहर स्थित सभी महाविद्यालयों में लम्बे समय से चल रहे रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

75. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

76. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थानागाजी में विज्ञान व कला वर्ग में स्नातकोत्तर विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के सभी स्तर के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में संस्कृत विद्यालय व नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

80. वाद्य, नृत्य (लोकनृत्य) एवं गायक कलाकारों को प्रशिक्षण हेतु बालोतरा में कला केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में विद्यमान संस्कृति धरोहरों के संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के राजकीय कन्या महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में विभिन्न महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के विभिन्न विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

85. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सभी विद्यालयों में खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये खेल मैदान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गिगला, केजड एवं सेमारी में विज्ञान वर्ग, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरपुरा में कृषि वर्ग, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सगतडा में कला वर्ग, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईटाली खेडा, सल्लाडा में वाणिज्य वर्ग, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झाडोल में विज्ञान वर्ग, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जावद में कला वर्ग एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अदबास में वाणिज्य वर्ग खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सभी विद्यालय भवनों की जर्जर अवस्था को देखते हुए पुनः निर्मित करवाये जाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सभी प्राथमिक विद्यालय, उच्च

प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

90. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के सभी राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. मालपुरा उपखण्ड की राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के सभी विद्यालयों में खेल मैदानों की चार दीवारी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के सभी विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर):

94. स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर में विज्ञान के विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

95. प्रदेश में बी.एड. एवं डी.एल.एड. में छात्रों की रूचि देखते हुए महाविद्यालयों में सीट्स बढाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. जयपुर शहर में कम से कम दस इंग्लिश माध्यम के सरकारी विद्यालय और खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

97. विधान सभा क्षेत्र बाली में माध्यमिक विद्यालयों व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नये कक्षा-कक्ष बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. विधान सभा क्षेत्र बाली के राजस्व ग्राम छोड़ा व गुणा में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत कर माध्यमिक विद्यालय बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. बाली उपखण्ड स्तर पर विवेकानन्द माडल स्कूल खुलवाने हेतु जमीन

स्वीकृत करने के उपरान्त भी स्कूल नहीं खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

100. विधान सभा क्षेत्र बाली में स्थित राजकीय महाविद्‌यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र बाली के देसूरी में नया राजकीय महाविद्‌यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर):

102. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के विद्‌यालयों के एकीकरण में बन्द कर दिये गये विद्‌यालयों को पुन: चालू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की राजकीय प्राथमिक विद्‌यालय अनापुर, बांसवाड़ा (जैतावाडा), राजपुरा को उच्च प्राथमिक स्तर तक क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की राजकीय स्कूलों में फर्नीचर, दरी पट्टियां आदि की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

105. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के बौंली में सरकारी कालेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में स्थित विभिन्न सरकारी स्कूलों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में स्थित विभिन्न सरकारी स्कूलों में पोषाहार वितरण में घटिया सामग्री वितरण की जांच करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में स्थित विभिन्न सरकारी विद्‌यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत करने एवं अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के विभिन्न सरकारी स्कूलों को क्रमोन्नत करने एवं संस्कृत विद्‌यालयों को क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी):

110. बून्दी जिला मुख्यालय पर राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन):

111. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन एवं रामगंजमण्डी में स्थित माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिए।

112. राजकीय विद्यालयों में रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रणाली विकसित करने हेतु चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन व रामगंजमण्डी के राजकीय विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के अनुपात में कक्षा-कक्षों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

114. विधान सभा क्षेत्र दूदू के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने तथा विद्यालयों में छात्रों की संख्या के आधार पर कक्षा-कक्षों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115. प्रदेश के विद्यालयों में कक्षा 9वीं से आई.टी. व ब्यूटी एवं वैलनैस विषय को प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. प्रदेश में मिडिल स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में रोजगार आधारित पाठ्यक्रम लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. निजी विद्यालयों में ली जाने वाली मनमानी फीस व फीस वृद्धि विनियम एक्ट 2016 को पूरी तरह से लागू कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र दूदू के खण्ड फागी की राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय सुलतानिया को प्रवेशिका के रूप में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां):

119. विधान सभा क्षेत्र कामां में विद्यालयों में उर्दू विषय के अध्यापक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र कामां में समायोजन के नाम पर बंद किये प्राथमिक विद्यालयों को पुन: खोलने पर चर्चा के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

121. विधान सभा क्षेत्र आमेर के विद्यालयों में नये संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र आमेर में विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र आमेर में विद्यालयों में खेल मैदान विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. आमेर उपखण्ड में महाविद्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

125. राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय सुखेर (उदयपुर) में वाणिज्य व गृह विज्ञान संकाय खोलने की स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लाडिया खेड़ा (गिर्वा) उदयपुर को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

127. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत व राजकीय माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में पोषाहार पकाने वालों का मानदेय 1200/- प्रतिमाह करने, प्रत्येक विद्यालय में सहायक कर्मचारी का रिक्त पद भरने तथा विद्यालयों में कमरों के उचित संधारण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

129. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में श्रीविजयनगर उपखण्ड कार्यालय में सरकारी महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

130. पीलीबंगा उपखण्ड व रावतसर उपखण्ड में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

131. बागरा में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र आहोर में देलदरी के फाफडिया में विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

133. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के सूरजगढ़ कस्बे में बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के समस्त सरकारी विद्यालयों में स्वीकृत अध्यापकों व अन्य कार्मिकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के सूरजगढ़ कस्बे में शारदेय बालिका छात्रावास स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन दिलावर (राजगंजमण्डी):

138. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में बन्द किये गये विद्यालयों को पुन: प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

139. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में स्थित विद्यालयों में रमसा के तहत कमरों के निर्माण व हाल निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

140. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में स्कूलों में छात्र-छात्राओं व शिक्षकों के लिए पूर्ण सुविधा युक्त नये शौचालय बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

141. स्कूलों में मिड-डे-मील, पोषाहार व दूध वितरण में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के स्थान पर अलग से पर्याप्त संख्या में पर्याप्त वेतन पर कर्मचारी अथवा एजेन्सी लगाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में राजकीय महाविद्यालय की घोषणा करने के क्रम में चर्चा के लिए।

143. कोटा की तरह राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों में शिक्षा के नये हब बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी):

144. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मुंगवा, हरियाखेडी, सेढवाना को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नालवा, नयाखेड़ा, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मंगलवाड़ को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने तथा राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय निकून में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

145. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में जहां अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं की संख्या अधिक है वहां उर्दू शिक्षक उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में स्थित कोठी कोल्यान उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा पहाड़ माध्यमिक विद्यालय जयपुर के भवनों की जर्जर हालत होने व शौचालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

147. जयपुर शहर में प्राइवेट विद्यालयों में आर.टी.ई. में एडमिशन में हो रही अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिए।

148. शिक्षण संस्थानों में FIRE FIGHTHING SYSTEM लगाने में विभाग की पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149. राजकीय विद्यालयों को सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों की कम सप्लाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

150. प्रतापगढ़ जिले में रूण्डीया, ग्राम पंचायत बेड़या, भुतिया ग्राम पंचायत देवपुरा, चन्दाना फला ग्राम पंचायत गयासपुर में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. प्रतापगढ़ जिले में सुहागपुरा, रामपुरिया, सेवना, बेड़या, अवलेश्वर, देवगढ़, थड़ा, पानयोड़ी, डाबड़ा, अचलपुर, झांसड़ी, लुहारिया एवं देवपुरा में नवीन बालिका प्राथमिक विद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. प्रतापगढ़ जिले में उंकाला, पीपरोड़ी, सेमलाखेड़ा, ब्लाक अरनोद एवं छायण, जाम्बुवेला, धावड़ीफला, जहाजपुर, ब्लाक प्रतापगढ़ प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. प्रतापगढ़ जिले में राजकीय माध्यमिक विद्यालय चन्देरा, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय पीपलखूंट, राजकीय माध्यमिक विद्यालय लाम्बाडाबरा व राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय पारसोला को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सन्दर्भ में चर्चा के लिए।

154. प्रतापगढ़ जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालय, पडुनी, बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुलथाना, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेणदा, हथुन्निया, खुटवास, धारियाखेड़ी, मोय मायंग्या, लापरीयाकण्डी, बड़वास कला, बरखेड़ी, बमोतर, पटेलिया, तलाया (मोरा धामनिया), निनोट, करमदीखेड़ा (पांच ईमली) एवं प्यारजी का पखर को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सन्दर्भ में चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):

155. जनजाति क्षेत्र में संचालित होने वाले कालेजों में शिक्षकों के 40 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त होने से आदिवासी क्षेत्र में शिक्षकों के अभाव में हो रही शिक्षा के स्तर की कमी के संबंध में चर्चा के लिए।

156. सरकारी विश्वविद्यालयों की तुलना में निजी विश्वविद्यालयों में Ph.D प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

157. प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रभावशाली कानून बनाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

158. राज्य में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के संबंध में चर्चा के लिए।

159. प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में राज्य के बाहर से अत्यधिक छात्रों द्वारा अध्ययन करने के कारणों यथा-वहां इस प्रकार के पाठ्यक्रम का न होना, अध्ययन हेतु उस प्रदेश की अनुमति लेना एवं उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

160. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विभिन्न राजकीय विद्यालयों का क्रमोन्नयन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

161. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

162. अजमेर में संचालित महिला इंजीनियरिंग कालेज को स्ववित्त पोषित योजना से हटाकर सरकार द्वारा संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

163. अजमेर इंजीनियरिंग कालेज बहल्या में पैट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग आरम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

164. अजमेर शहर में संचालित महिला पोलीटैक्निक कालेज में नये कोर्स संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

165. अजमेर दक्षिण में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका पहाड़गंज में विज्ञान एवं वाणिज्य विषय प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166. प्रदेश में संचालित निजी विश्वविद्यालयों के संचालन हेतु एक रेगुलेटरी आथोरिटी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना):

167. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रानीपुरा, पाटलिया लोढ़ान, भोजपुर व गुराड़ी को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संदर्भ में चर्चा के लिए।

168. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बुधवाड़ा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

169. राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय 24-ASC घड़साना को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 18 P के ग्राम 14K(B) के बन्द राजकीय प्राथमिक विद्यालय को पुन: चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय वार्ड नं. 4 रावलामण्डी को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

173. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संकाय व्याख्याताओं एवं माध्यमिक विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रूपा राम (मकराना):

174. विधान सभा क्षेत्र मकराना के मकराना ब्लाक शिक्षा कार्यालय में विभिन्न श्रेणी के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थित पर चर्चा के लिए।

175. विधान सभा क्षेत्र मकराना में राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत पाठशालाओं में अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

176. बीकानेर जिले के ग्राम किरतासर तहसील नोखा में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

177. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के गांव कुनतासर तहसील डूंगरगढ़ में भामाशाह द्वारा निर्मित भवन में राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

178. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के गांव दुलचासर तहसील डूंगरगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के बड़ी तहसील डूंगरगढ़ को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

180. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के गांव दुलचासर तहसील डूंगरगढ़ के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

181. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय व माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत कर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

182. विधान सभा क्षेत्र जालौर पंचायत समिति सायला के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोरवाड़ा, लुम्बाकी ढाणी व सायला गोलिया को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

183. विधान सभा क्षेत्र जालौर की पंचायत समिति सायला की राजकीय प्राथमिक विद्यालय पूनराऊ, अजारनाड़ी, खेतलावास, ककाड़ीनाड़ी व सायला को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

184. विधान सभा क्षेत्र जालौर की पंचायत समिति जालौर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोक, धवला, नयानारणावास, रानीवाड़ा काखा, रणछोड़नगर, लेटा राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोड़ी जी जालौर को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

185. विधान सभा क्षेत्र जालौर के सायला में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

186. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, शिवाजी नगर, जालौर को महात्मा गांधी विद्यालय में सम्मिलित नहीं कर उसका बालिका विद्यालय स्वरूप बरकरार रखने पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत):

187. विधान सभा क्षेत्र सोजत के राजकीय महाविद्यालय सोजत को स्नातकोत्तर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

188. विधान सभा क्षेत्र सोजत के सोजत किले के सौन्दर्यीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

189. विधान सभा क्षेत्र सोजत के बालिकाओं के लिए पृथक् महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

190. विधान सभा क्षेत्र सोजत के गोदेलाव विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

191. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के श्रीविजयनगर उपखण्ड पर सरकारी महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल):

192. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के विद्यालय भवनों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

193. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

194. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में नवीन विद्यालय भवन निर्माण करवाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर):

195. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर विषय के अध्यापकों का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

196. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर कला विषय शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

197. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के राजलदेसर में राजकीय महाविद्यालय खोलने व रतनगढ़ के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गणित व जीव-विज्ञान विषय के एक-एक अतिरिक्त सेक्शन स्थाई रूप से पद पढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

198. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के "न्यामा" (सुजानगढ़) गांव के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

199. प्रदेश के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों से पढ़ाने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

200. रतनगढ़ नगरपालिका के वार्ड नं. 26 शास्त्रीनगर में स्थित राजकीय नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय को पुन: शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

201. प्रदेश के तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 में तीसरी वरीयता सूची जारी होने के बाद शेष लगभग 3500 रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला):

202. प्रदेश के शहरों और गांवों में प्रत्येक एक किलोमीटर पर राजकीय विद्यालय खोलने तथा अध्यापक व पर्याप्त स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

203. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों तहसील मुख्यालयों पर कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

204. प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में छात्रों हेतु शुद्ध पोषाहार, पेयजल तथा आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

205. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने व विद्यालय भवनों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण):

206. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जैतारण में स्नातकोत्तर के लिए विज्ञान, कामर्स व कला वर्ग विषयों की भी स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

207. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

208. प्रदेश के आदिवासियों की संस्कृति को बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

209. प्रदेश में आदिवासी बहुल क्षेत्र में कोठारी आयोग की सिफारिश के

अनुसार मातृ भाषा में 5वीं कक्षा तक शिक्षण कराने पर चर्चा के लिए।

210. प्रदेश में विद्यालयों से 200 मीटर की सीमा तक धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

211. प्रदेश में मिड-डे मील में व्याप्त अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।

212. प्रदेश के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में कला को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामप्रसाद (सागवाडा):

213. प्रदेश के आदिवासियों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये अनुसूचित क्षेत्रों में स्थापित सरकारी कार्यालयों के भीली भाषा बोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

214. प्रदेश में आदिवासी समुदाय संस्कृति को जिन्दा रखने पर चर्चा के लिए।

215. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण):

216. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के सभी जर्जर विद्यालय भवनों की रमसा योजना के तहत मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

217. विधान सभा क्षेत्र सार्दुलशहर के सरकारी विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

218. प्रदेश में बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था व आधारभूत संरचना किये महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

219. प्रदेश के विद्यालयों में पाठ्यक्रम में निर्धारित नियमों के पालन किये बिना परिवर्तन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

220. प्रदेश के 12 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वर्तमान में कुलपति न होने व अजमेर के एम.डी.एस. विश्वविद्यालय के कार्य बाधित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

221. प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षकों को एक वर्ष से ज्यादा समय से वेतनमान का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

222. प्रदेश के विद्यालयों में संस्कृत शिक्षा के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा उत्तर):

223. कोटा शहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशोरपुरा को भूमि आबंटित कर भवन निर्माण करवाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

224. कोटा के प्राचीन धार्मिक स्थानों कंसुबा व इमारते मीणा का महल, व 5 मंजिला झाला हाउस, प्राचीन दरवाजों आदि प्राचीन धरोहरों के संरक्षण हेतु बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

225. कोटा के महाविद्यालयों में छात्रों की सुविधा के लिए खेल मैदान, कैन्टीन आदि सुविधाएं न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

226. विधान सभा क्षेत्र चूरू के विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

227. विधान सभा क्षेत्र चूरू के विद्यालयों में विद्यार्थियों हेतु कमरों (कक्षा-कक्षों) का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

228. विधान सभा क्षेत्र चूरू के शहरी विद्यालयों में खेल मैदान व खेल सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

229. विधान सभा क्षेत्र चूरू के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाये जाने की आवश्यक्ता पर चर्चा के लिए।

230. विधान सभा क्षेत्र चूरू के विद्यालयों में पीने के मीठे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

231. विधान सभा क्षेत्र भादरा के विद्यालयों में नये विषय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

232. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

233. विधान सभा क्षेत्र भादरा सहित प्रदेश के विद्यालयों में अध्यापकों व व्याख्याताओं के पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

234. विधान सभा क्षेत्र भादरा के गोगामेड़ी मेले में कला व संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

235. प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए कालेज व यूनिवर्सिटी का बजट बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

236. विधान सभा क्षेत्र पाली में पूर्व में बंद किये गये विद्यालयों को जिला शिक्षा अधिकारी पाली द्वारा भेजे गये प्रस्तावों के अनुसार पुन: प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

237. पाली जिले की पंचायत समिति रोहट में संचालित स्वामी विवेकानन्द माडल विद्यालयों में रिक्त सीटों में मैरिट के आधार पर प्रवेश देने हेतु न्यूनतम अंकों की आवश्यकता में शिथिलता देने पर चर्चा के लिए।

238. पाली जिले की पंचायत समिति रोहट में संचालित स्वामी विवेकानन्द माडल विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा की कक्षाएं प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

239. विधान सभा क्षेत्र पाली में संचालित शारदा एवं कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

240. विधान सभा क्षेत्र पाली के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रावास निर्माण एवं जिन विद्यालयों में छात्रावास संचालित हैं, उनमें मांग अनुसार सीटें बढ़ाने पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

241. जिला भीलवाड़ा में समानीकरण एवं एकीकरण योजना के अन्तर्गत बन्द किये गये विद्यालयों को पुन: चालू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

242. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में शिक्षा विभाग के

अधीन आने वाले विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

243. जिला भीलवाड़ा में शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले विद्यालयों में सभी श्रेणी के रिक्त पदों पर पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

244. जिला भीलवाड़ा में शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले विद्यालयों में मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था किये जाने पर चर्चा के लिए।

245. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत तथा नवीन विद्यालय भवनों के निर्माण के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीराराम (बिलाड़ा):

246. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्कूलों को क्रमोन्नत करने एवं बालिका विद्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

247. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

248. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के राजकीय कन्या महाविद्यालय में विज्ञान संकाय को नियमित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

249. बारहवीं तक के स्कूलों में कम्प्यूटर अध्यापक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

250. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की पंचायत समिति सुमेरपुर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बांगड़ी व बिठुड़ा पीरान को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

251. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के समस्त राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

252. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों के रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

253. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के विद्यालयों में प्रिंसिपल, व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

254. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं हेतु भवन एवं शौचालय निर्माण के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

255. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के उपखण्ड कार्यालय स्तर पर अलग से कला केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

256. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गनोडा संस्कृत कालेज के रिक्त पदों को भरने एवं भवन निर्माण पूर्ण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

257. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में बालिका छात्रावास खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

258. सभी विद्यालयों में सरस्वती मां की मूर्ति लगावाई जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

259. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के विद्यालयों में खेल मैदान, खेल की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करवाने तथा मैदानों की चार दीवारी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाडा):

260. राजकीय महाविद्यालय, रानीवाड़ा में अर्थशास्त्र, इतिहास व अंग्रेजी विषयों के व्याख्याताओं के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

261. राजकीय महाविद्यालय, रानीवाड़ा में गैर शैक्षणिक संवर्ग के स्वीकृत 13 पदों में से रिक्त 12 पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

262. विधान सभा क्षेत्र रानीवाडा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेवाडिया, मौखातरा, डीगांव, लूणियासर, वासन देवडान, सांवलावास, कीलुपिया, डाडोकी एवं वाडा भावजी को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

263. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई):

264. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में शिक्षकों व व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

265. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्रामीण इलाकों में नये संस्कृत विद्यालय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

266. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के गांव रूपवास के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

267. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोहनपुरा-बालाजी (किशनगढ़-रेनवाल) को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

268. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के नरैना स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय तथा क्षेत्र के अन्य उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी नये संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

269. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की सांभरलेक स्थित राजकीय महाविद्यालय के भामाशाहों द्वारा निर्मित भवन की सार-सम्भाल तथा मरम्मत के संबंध में चर्चा के लिए।

270. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

271. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के ग्राम काल्या (पंचायत समिति दूदू) तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय दोबड़ी (पंचायत समिति दूदू) के राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करना तथा ग्राम घीसा बाबा की ढाणी (ग्राम पंचायत तेज्या का बास) में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

272. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के राजकीय शार्दुल बालिका माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़, राजकीय बद्रीनारायण दरगड़ बालिका माध्यमिक विद्यालय हरमाड़ा तथा राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, ढाणी पुरोहितान तथा राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय दादिया को क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिए।

273. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के विभिन्न श्रेणी के विद्यालयों में अध्यापकों तथा स्टाफ के अन्य रिक्त पदों को शीघ्र भरने पर चर्चा के लिए।

274. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की राजकीय शार्दुल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ में कला संकाय में हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान व भूगोल विषय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पुराने किशनगढ़ में कृषि संकाय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलेमाबाद तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरांई में विज्ञान संकाय खोलने पर चर्चा के लिए।

275. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मोहनपुरा (खातोली), आहेड़ा, चोसला, झाडोल, माण्डयावर खुर्द, नयागांव को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

276. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की विश्व प्रसिद्ध कृति बणी-ठणी (राधा) के चित्रकारों की कला के प्रदर्शन हेतु आर्ट गैलरी बनाने एवं इनके जीविकोपार्जन की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिए।

श्री राकेश पारीक (मसूदा):

277. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने तथा इनमें रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

278. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

279. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के उपखण्ड भिनाय में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

280. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

281. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाई में विज्ञान विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

282. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के राजकीय उच्च माध्यमिक

विद्यालय गोवर्धन विलास उदयपुर में वाणिज्य विषय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

283. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में ग्राम पंचायत झामर कोटड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सठ पुर मिनान में अध्यापक लगवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

284. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की कमी को पूरा करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

285. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के स्कूलों में अध्यापक के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लाखन सिंह (करौली):

286. विधान सभा क्षेत्र करौली में प्रवेशिका विद्यालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

287. विधान सभा क्षेत्र करौली में सरकारी विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

288. विधान सभा क्षेत्र करौली की तहसील मासलपुर में राजकीय स्नातकोत्तर कालेज खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

289. विधान सभा क्षेत्र करौली में राजकीय कन्या महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

290. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

291. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में एकीकरण से बंद विद्यालयों को पुन: चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

292. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

293. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के विद्यालयों में पेयजल व शौचालयों की स्थायी व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

294. विधान सभा क्षेत्र डग के सभी महाविद्यालय व विद्यालयों में व्याख्याता, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

295. विधान सभा क्षेत्र डग के ग्राम पंचायत गुढ़ा के उच्च प्राथमिक विद्यालय सरकनिया को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

296. विधान सभा क्षेत्र डग के ग्राम पंचायत पिपलिया खुर्द के गांव उमरिया के उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

297. विधान सभा क्षेत्र डग के ग्राम पंचायत सुनारी के लूनियाखेड़ी में स्कूल के नये भवन बनवाने एवं लूनीयाखेड़ी में जर्जर भवन को ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

298. विधान सभा क्षेत्र डग के भवानीमण्डी में कलाकारों के लिये नया रंगमंच बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

299. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

300. राजकीय महाविद्यालय मुण्डावर को भूमि का आवंटन एवं रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

301. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में संस्था प्रधानों व अन्य शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

302. मुण्डावर के सभी राजकीय विद्यालयों में मीठे पीने के पानी एवं बिजली की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

303. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के राजकीय विद्यालयों में चार दीवारी व भवन एवं खेल मैदान का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

304. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में स्थित स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के संबंध में चर्चा के लिए।

305. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के समस्त विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

306. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोजवाड़ी में जीव विज्ञान संकाय तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसखोह में कृषि विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

307. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में एकीकरण/समानीकरण के नाम पर बंद किये गये सभी विद्यालयों को पुन: प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

308. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में अध्यापकों के स्थानान्तरण के कारण पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं):

309. विधान सभा क्षेत्र लाडनूं के राजकीय स्कूलों में संकाय व विषय बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

310. विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

311. प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में डिजिटल क्लास रूम विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

312. विधान सभा क्षेत्र लाडनूं के राजकीय विद्यालयों में खेल मैदान बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

313. प्रदेश में मिड-डे-मील में कुक-कम-हैल्पर का मानदेय बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल):

314. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल जयपुर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खुलवाने के साथ राजकीय उच्च प्राथमिक बेसिक माडल विद्यालय, जालूपुरा का नया भवन बनाकर विद्यालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा):

315. विधान सभा क्षेत्र महुवा के रसीदपुर एवं बालाहेड़ी में विज्ञान संकाय खुलवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

316. विधान सभा क्षेत्र महुवा के राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

317. विधान सभा क्षेत्र महुवा के ग्राम पंचायत मुख्यालय गगवाणा, सालिमपुर, टीकरी किलानोत बाड़ा बुजुर्ग सैकण्डरी स्कूल को क्रमोन्न्त कर सीनियर सैकण्डरी स्कूल करने के संबंध में चर्चा के लिए।

318. विधान सभा क्षेत्र महुवा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुवा में कृषि संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

319. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आरवाडी, माजीपुरा, गोपालगढ़, सरजौली, छापरवास को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

320. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय इन्द्रगढ़, रूपवास, बिलोड, राम्मावाला, राहोटी, नांगल तुलसीराम को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाडी):

321. राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में विज्ञान एवं वाणिज्य विषय खोलने एवं स्वीकृत/रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

322. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

323. अलवर जिले के बहरोड़ में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कायसा में विज्ञान और कामर्स संकाय की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

324. राजकीय महात्मा गांधी महाविद्यालय बहरोड़ में स्नातक कोर्स में गृह विज्ञान, लोक प्रशासन एवं दर्शनशास्त्र विषय तथा स्नातकोत्तर के लिए हिन्दी साहित्य, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र लोक प्रशासन व विज्ञान संकाय के फिजिक्स और मैथ्स विषय शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

325. अलवर जिले के बहरोड़ में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंडाला (06080107415) में भूगोल और गृह विज्ञान विषय चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

326. अलवर जिले के बहरोड़ में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोहनपुरा और राजकीय माध्यमिक विद्यालय, महतावास को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

327. अलवर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांदण और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मांदण में कामर्स संकाय के अध्ययन की सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर):

328. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवांची गेट में जीव-विज्ञान विषय आरम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

329. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवांची गेट में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय आरम्भ करने एवं कला वर्ग में भूगोल विषय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

330. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय अल्पभाषा राजमहल (जोधपुर) एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय बलदेव नगर मसूरिया (जोधपुर) को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

331. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, 14 सेक्टर चौपासिनी हाउसिंग बोर्ड राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेमे का कुआं व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शोभावतों की ढाणी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

332. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवांची गेट का भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

333. प्रदेश में भवन विहीन व जर्जर भवनों वाले विद्यालयों हेतु बजट आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

334. प्रदेश के विद्यालयों में मिड-डे मील बनाने वाली महिलाओं का मानदेय बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

335. विधान सभा क्षेत्र फलौदी की पंचायतों में स्थित माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

336. प्रदेश के मदरसा टीचर्स का मानदेय बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

337. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में स्थित मेवात बालिका विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

338. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ जिला अलवर के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

339. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरतसिंहपुरा, मनोफरसर, घीरेरा स्टेशन, राणीसर, छाटासर, कागासर व बखूसर को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

340. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय खारी, राजकीय माध्यमिक विद्यालय नकोदेसर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राणीसर, खोड़ाला, मनाफरसर व छटासर के भवन स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

341. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के किस्तरीया, करणीसर बीकाण, मादवा, नोहड़ा चाक व चक असरासर को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

342. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्राम रावासर, खारडा, डेलाणाबडा, ढाणी छिपलाई, खारी व नकोदेसर के माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

343. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरेरा, लूणकरणसर, मालामर, जैतपुर व नापासर के खेल मैदान हेतु बजट आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण):

344. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक

विद्यालय में, उच्च प्राथमिक को माध्यमिक विद्यालय में और माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

345. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के निमाज, निम्बोल, बर, जैतारण व अन्य किसी भी विद्यालय में विज्ञान संकाय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन):

346. विधान सभा क्षेत्र चौहटन की सेडवा तहसील में कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

347. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के बंद प्राथमिक विद्यालयों को शुरू करने तथा रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

348. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

349. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के विद्यालयों में खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमर सिंह (बयाना):

350. विधान सभा क्षेत्र बयाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इब्राहिमपुर (रूपवास) में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

351. विधान सभा क्षेत्र बयाना के राजकीय माध्यमिक विद्यालय मदनपुर को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

352. विधान सभा क्षेत्र बयाना के स्कूलों में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

353. विधान सभा क्षेत्र बयाना के उपखण्ड रूपवास में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

354. विधान सभा क्षेत्र बयाना के महाविद्यालय बयाना को स्नातकोत्तर करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री वाजिब अली (नगर):

355. विधान सभा क्षेत्र नगर के महाविद्यालयों में व्याख्याताओं की कमी को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

356. विधान सभा क्षेत्र के कस्बा सीकरी और गुलपाड़ा तथा डायनाबास के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

357. सीकरी में महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

358. विधान सभा क्षेत्र नगर में उर्दू के अध्यापकों की नियुक्ति व नये पद सृजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

359. विधान सभा क्षेत्र नगर के पूर्व में बन्द किये गये स्कूलों को पुन: चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

360. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

361. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के विभिन्न विद्यालयों में नए संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

362. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के विभिन्न विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

363. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के विभिन्न विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर):

364. प्रदेश के संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय के शिक्षकों को यू.जी.सी. वेतनमान के संबंध में चर्चा के लिए।

365. प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के प्रचार-प्रसार के संबंध में चर्चा के लिए।

366. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ में विज्ञान व वाणिज्य संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

367. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के विभिन्न विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने तथा नये संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
